

Fourth Series, Vol. XVII No. 51

Friday, April 26, 1968
Vaisakha 3, 1890 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Fourth Session



सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT
New Delhi

CONTENTS

[Fourth Series, Vol. XVII—Fourth Session]
No. 51—April 26, 1968/Valsakha 6, 1890 (Saka)

	Columns
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 1467 to 1469, 1471 to 1473	1—31
Short Notice Question No. 26	31—43
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 1470, 1474 to 1496	43—56
Unstarred Questions Nos. 8538 to 8544, 8546 to 8580, 8582, 8583, 8585 to 8589, 8591 to 8729	57—173
Correction of Answer to USQ No. 7915 dt. 19.4.68	173—74
Question of Privilege	174—252
Shri Rabi Ray	174—80
Shri Ranga	180—85
Shri Amrit Nahata	187—89
Shri Kanwar Lal Gupta	190—95
Shri Chandra Jeet Yadav	196—202
Shri Madhu Limaye	202—06
Shrimati Tarkeshwari Sinha	207—13
Shri S. M. Banerjee	213—15
Shri Govinda Menon	215—21
Shri J. B. Kripalani	221—24
Shri Umanath	224—28
Shri P. Venkatasubbaiah	228—30
Shri Srinibas Misra	230—33
Shri F. A. Ahmed	234—38
Papers Laid on the Table	253—54
Committee on Government Assurances—	
Minutes, Evidence and Second Report	254
Estimates Committee—	
Fifty-fifth Report	254
Committee on Public Undertakings—	
Nineteenth and Twentieth Report	254—55
Business of the House	255—61
Union Territories (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill— <i>Introduced</i>	261—62

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

Committee on Private Members' Bills and Resolutions— Twenty-ninth Report	262
Bills Introduced—				
1. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 217) by Shri M. Narayan Reddy				262
2. Labour (Participation in Management) Bill By Shri Srinibas Misra	...			263
3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 90, 92 etc.) By Shri Srinibas Misra	...			263
Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of New section 86A) by Shri S. S. Kothari				267
Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill— (Amendment of section 6) by Shri Manibhai J. Patel				
Motion to introduce— <i>Negatived</i>		263—67
Salaries and allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill— <i>Withdrawn</i> (Amendments of sections 3, 6 etc.) by Shri P. L. Barupal		267—301
Shri P. L. Barupal	...			267—68
Shri Gadilingana Gowd				269—70
Shri Tenneti Vishwanatham				271—74
Shri Sezhiyan				274—76
Shri Madhu Limaye				276—82
Shri Chengalraya Naidu				282—84
Shri S. M. Banerjee	...			284—86
Shri Gulam Mohammad Bakshi	...			286—91
Shri Tulshidas Jadhav	...			291—93
Shri Samar Guha	...			293—94
Shri Umanath				294—97
Shri Sheo Narain		297
Dr. Ram Subhag Singh		298—300
Motion <i>Re.</i> Salaries and Allowances and other Amenities to Members of Parliament— Dr. Ram Subhag Singh	...			301—03 301—02
All India Ayurvedic Medical Council Bill By Shri A. T. Sarma	...			303—06
Motion to Circulate— Shri A. T. Sarma	303—06
Half-an-Hour Discussion <i>Re.</i> Suspension of Production of Films in Bombay— Shri George Fernandes		306—24 306—14
Shri K. K. Shah	317—24

LOK SABHA

Friday, April 26, 1968 | Vaisakha 6, 1890
(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.

[Mr. Speaker in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance given to Himachal Pradesh

*1467. SHRI PREM CHAND VERMA:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be
pleased to state :

(a) the extent of annual financial assistance given to the Himachal Pradesh Government out of the Central Revenues ;

(b) the Himachal Pradesh's share in the Central Taxes, if it were given the status of full Statehood ;

(c) whether Government propose to bring up their financial assistance to Himachal Pradesh to the level of its share, if it were a full State till such status is granted to it ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The following amounts of Central assistance have been given to the Government of Himachal Pradesh from 1964-65 onwards :

(Rs. in lakhs)

Year	Grants-in-aid	Loans
1964-65	792.50	467.42
1965-66	895.96	535.49
1966-67	1495.86	700.63
1967-68	1816.47	1226.57

(b) The share of a State in the Central Taxes is determined on the basis of the

recommendations of the Finance Commission as required under the Constitution. The Commission make their recommendation after taking into account a number of factors, viz., population, collection, backwardsness, etc., of the State concerned. It is, therefore, not possible to indicate what Himachal Pradesh would have got from the Central Taxes, if it had been given the status of full Statehood.

(c) and (d). In view of the fact that the entire gap in the annual budget of the Government of Himachal Pradesh is at present met by means of Central assistance--grants-in-aid for revenue items and loans for the net capital expenditure, the question of giving to them any financial assistance beyond that level does not arise.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश 1948-49 में बना था, तब इसकी आमदनी केवल 87 लाख रुपये थी, लेकिन इस वक्त 14 करोड़ रुपये है, जब कि इसका खर्च 21 करोड़ रुपये हो गया है। इस खर्च के बढ़ने की एक वजह यह है कि पंजाब के विभाजन के बाद 6 हजार सरकारी कर्मचारी, जिनमें अफसरों की तादाद ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश की जरूरत से ज्यादा भेज दिये गये हैं। इन में से काफी तादाद खुद ही हिमाचल प्रदेश में नहीं रहना चाहती है। मैं जानना चाहता हूँ क्या भारत सरकार इन फालतू सरकारी कर्मचारियों को वापस पंजाब और हरियाणा भेजने पर विचार करेगी या इन को केंद्र में बुलायेगी ? अगर हाँ, तो कब तक इस पर विचार करेगी, क्योंकि इस वक्त हजारों सरकारी मुलाजिम बेकार बैठे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार को उन्हें तनखाह देनी पड़ रही है, भंग नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रामदनी काफी बढ़ी है। यह भी ठीक है कि उनका खर्च भी काफी बढ़ा है। लेकिन खर्च बढ़ने का कारण केवल यह नहीं है कि वहां फालतू सरकारी कर्मचारी हैं। हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी मात्रा में ऐसे कर्मचारी हों, जिनके पास पर्याप्त काम न हो, लेकिन वहां जो विकास कार्य और दूसरे कार्य हो रहे हैं, उनके कारण वहां का खर्च बढ़ा है। जैसा यह सदन जानता है कि वहां जितनी ग्रामदनी होती है, उससे कहीं ज्यादा, दुगुना, तिगुना वहां का खर्च है और उसे हम लोगों को यहां से पूरा करना पड़ता है। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के कारण वहां खर्च ज्यादा है, तो हम जरूर उसकी जांच करेंगे।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर ने भारत सरकार से मांग की है कि प्रदेश की जनता और स्टेट असेम्बली एक राय से हिमाचल प्रदेश को स्टेट-टूड का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे हैं? क्या इस सिलसिले में माननीय गृह मंत्री जी को कोई स्मरण-पत्र भी भेजे गये हैं और क्या यह भी दुरुस्त है कि चीफ़ मिनिस्टर की तरफ़ से केन्द्र सरकार को यह भरोसा दिलाया गया है कि यदि हिमाचल प्रदेश को मुकम्मिल स्टेट का दर्जा दे दिया जाय तो भारत सरकार जो मदद इस वक्त दे रही है, वह उससे ज्यादा की मांग नहीं करेंगे? यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश को मुकम्मिल सूबे का दर्जा दिये जाने में कौन सी रुकावटें हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस के बारे में कई बार इस सदन में बताया गया है और जब पंजाब का विभाजन हुआ था, उस समय भी इसके बारे में यहां पर चर्चा हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के प्रति-निधि और खास कर माननीय सदस्य श्री प्रेम चन्द वर्मा, जो इस समय इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, उन्होंने इस बात की बड़ी कोशिश की है कि

हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का स्तर मिले। इसके बारे में राज्य के मुख्य मंत्री ने भी कई बार हम लोगों को पत्र लिखा है। लेकिन जैसा मैंने अभी प्रश्नोत्तर में बताया कि वहां की जितनी ग्रामदनी है, उससे दुगुना, तिगुना वहां का खर्च है, जिसे हमको यहां से पूरा करना पड़ता है। इसलिए जब राज्य के साधन इतने बढ़ जायेंगे कि वे खुद एक राज्य के रूप में काम कर सकेंगे, तब इस प्रश्न पर अवश्य ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा न देने का एक तर्क यह दिया है कि आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आत्म-निर्भर नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की भूमि के अन्दर जो बड़े-बड़े बांध हैं, जैसे पॉंग डैम, सतलुज व्यास लिंक, जिनके बनने से हिमाचल प्रदेश के हजारों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा था, उनको वह जगह छोड़नी पड़ी थी, आज उन बांधों की आय का कोई भी भाग हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलता है। यदि इन बांधों की आय का भाग हिमाचल प्रदेश को भी मिले, तो यह प्रदेश भी आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर समझा जा सकता है। क्या सरकार इस दृष्टि से इस पर विचार करेगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हर तरह से इस पर विचार किया गया है और यह ठीक हो सकता है कि बड़े-बड़े बांधों के बनने से कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ा हो। मुझे यह नहीं मालूम है कि उनकी आय को किस तरह से बांटा जाता है। लेकिन यह बात ठीक है कि जब इस पर विचार किया गया था, तब इन सब बातों को ध्यान में रखा गया था।

SHRI HEM RAJ : May I know whether it is a fact that the Chief Minister of Himachal Pradesh has represented to the Government that a share of betterment levy that is collected by the States which are the beneficiaries of the waters of Sutlej

and Beas, should be given to Himachal Pradesh, and if so, what action has been taken on that ?

Secondly, may I know whether any reference has been given to the Fourth Finance Commission, which has just been set up, to find out what would be the share of Himachal Pradesh in the taxes which will be levied by the Central Government, excise duty, etc. ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :

At present I am not aware of this betterment levy.

SHRI HEM RAJ : What about my second question, whether any reference has been given to the Fourth Finance Commission ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :

If the hon. Member gives me notice, I will find out.

श्री प्रताप सिंह : क्या यह सच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो माली-इमदाद हिमाचल प्रदेश को देती है, उसमें से 90 फीसदी उन स्कीमों पर खर्च किया जाता है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों हैं, जैसे—वार्डर पुलिस, एस० एस० पी०, फ़ैमिली प्लानिंग, डी० जी० बी० ग्रार०, खादी कमीशन, भारत आदिम जाति संघ, वगैरह ? अगर यह बात सही है तो फिर सरकार को इस बात के मानने में कौन सी अड़चन है कि वह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने दे ?

दूसरे—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति दूसरी यूनिन टैरिटोरिज के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया था, उस वक्त सरदार पटेल ने यह बात साफ़ कर दी थी कि यह पहले कमिश्नर का राज्य होगा, उस के बाद लेफ़्टीनेन्ट गवर्नर का और जब सफ़िसियन्टली डवेलप हो जायेगा तो इसको पूरे राज्य का स्टेट्स दे दिया जायेगा मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसमें सरकार के सामने कौन सी अड़चन है ?

तीसरे—क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में 20 साल के अग्रे के बाद भी कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई गई है जबकि वहां पर काफी पोटेन्शियल रा-मेटीरियल मौजूद है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रदेश को इस बात से खास तौर पर नजर-अन्दाज किया, जब कि करोड़ों रुपया 20 साल के अन्दर इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट वालों की पे ग्रौर टी० ए०, डी०ए० पर खर्च हो चुका है ?

श्री विशाचरण शुक्ल : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि केन्द्र जो सहायता देता है, उसको हिमाचल प्रदेश सरकार किस तरह से खर्च करती है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ—फ़ैमिली प्लानिंग या दूसरी चीजों के बारे में, जो केन्द्र की योजनाएं हैं, उनके लिए अलग से एलोकेशन किया जाता है। वार्डर सिक्वोरिटी फोर्स, इत्यादि पर स्टेट के शेअर से खर्च नहीं होता है, उसका खर्च अलग से बजट में दिखाया जाता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है—एसी कोई एशोरेन्स दी गई थी, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा है किसी भी राज्य को पूरे राज्य का स्तर देने के लिए हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया पर जब हिमाचल प्रदेश का सवाल आ जायेगा, तब ही हम उसपर विचार करेंगे।

Declaration of Tons Valley in U.P. as Prohibited Area

*1468. **SHRI INDRAJIT GUPTA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Tons Valley in Uttar Pradesh has been declared a prohibited notified area under the Foreigners Act, 1946 or the Criminal Law (Amendment) Act, 1961 ; and

(b) if so, the grounds for such action ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the

House. [Placed in Library. See No: LT-1047/68].

SHRI INDRAJIT GUPTA : I find from the copies of the various orders which have been laid on the Table of the House that several of them were passed or issued during 1962-63. May I know whether during these five or six years since the orders were passed, it is a fact that certain foreigners have been permitted by being given special permits, to enter this area or to reside there, and whether it is a fact that some of them are reported to be living there in houses which they have rented and so on and are carrying on certain activities which are rather suspicious ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as my information goes, at least I have no information about whether anybody is staying there. Naturally, under the Act, the State Government do consider individual cases.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Nothing has come to his notice ?

MR. SPEAKER : He has said 'No'.

SHRI INDRAJIT GUPTA : This order of 1963 notifies certain restricted areas including this particular area in UP. There are also other areas including five districts of West Bengal, Darjeeling and all that area. May I know whether the hon. Minister's attention has been drawn to the reported representation made by the Governor of West Bengal to the Central Government that this order should be withdrawn from these five northern districts because he thinks that the prohibition of foreigners going there in the form of tourists is causing a lot of economic loss to that area ? May I understand from that that while the Home Ministry is interested in security, Mr. Dharma Vira is more interested to tourism ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I have not seen any report from Mr. Dharma Vira to this effect.

SHRI INDRAJIT GUPTA : No such thing has been received ?

SHRI Y. B. CHAVAN : At least I have not seen it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : These things get published in the press.

श्री सुदामाजी सिंह मास्ती : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह जो टोंस घाटी में जहाँ-जहाँ प्रतिबन्ध लगा है, क्या यह सब वही इलाका है जहाँ टोंस नदी को बांधने वाला बांध बनने वाला था और जिसको लेकर वहाँ के लोगों के अन्दर थोड़ी बेचैनी थी कि उनके खेत उसके अन्दर आ जायेंगे, क्या यह वही इलाका है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I really do not know whether it is the same *ilaaka* to which the hon. Member is referring. What is Tons valley is very well known. Of course, there are two Tons rivers ; one in Faizabad, Azamgarh, Ballia and nearby areas ; the other one is in Uttarkashi district, and that part of the Tons Valley which is in Uttarkashi district has been declared as prohibited area.

Kidnapped Indians in Pak Custody

*1469, **SHRI V. NARASIMHA RAO :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news-item appearing in the 'Patriot' of the 23rd March, 1968 to the effect that the Assam's Finance Minister made a statement that 29 kidnapped Indian nationals were still in the custody of Pakistan ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

• **THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) :** (a) Yes, Sir.

(b) The Border Security Force and the Government of Assam lodged protests with their Pak counterparts. Four of these 29 persons have since returned to India. Efforts to secure the release of the remaining 25 persons are continuing.

SHRI V. NARASIMHA RAO : May I know whether there have been any talks by the High Commissioner to have these Indian persons released and if so, when ?

SHRI RANGA : Were any representations made by our High Commissioner, and if so, when ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The information that I have got is this. In these matters the procedure during the last so many years, which has proved effective also is that these matters are taken up with the counterpart police officers. In the courses of the last seven or eight years, we have had many cases of kidnapping, and we have secured the release of a large number of people from that side. This is being done only at that level.

श्री हुकम चन्द कल्लवाय : मंत्री जी ने बताया कि ऐसे 25 लोग हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 25 व्यक्ति क्या हमारे सेना के जवान हैं जो कि सीमा पर रहते हैं या पुलिस के जवान हैं या नागरिकों में से हैं और अभी तक उनके छुड़ने की क्या कोशिश की है ? और जो हमारे भारतीय हाई कमिश्नर हैं क्या उन्होंने भी पाकिस्तान से कोई बातचीत की है ? यदि नहीं की है, तो अब केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : This kidnapping is of people living in the border areas: sometimes government employees also are included in this.

SHRI RANGA : What has happened in regard to these people ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am just giving the information. Out of these 29 persons, in the case of four, they have secured their return. About the other 25 they are making efforts and they are hopeful that possibly they will succeed.

SHRI RANGA : Were they military people ?

श्री हुकम चन्द कल्लवाय : इसके पहले आप ने क्या-क्या कार्रवाई की है ? हमने कोई पाकिस्तानी बन्दी बन्धक रखे हैं ? कितने पकड़े हैं, बतइये ? अगर के हमारा एक भारतीय पकड़े तो हम उनके बाद भारतीय पकड़ लें, तभी उनको अकल प्रायेगी ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I have already said that the matter was not taken up through the High Commissioner. From the record that I have got I find that this matter has been going on for years with the counterpart police officers on the other side, and they have met and discussed the facts of the cases....

SHRI RANGA : For how long has this been going on ? Will it be now taken up at a higher level ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I personally have started feeling that it is high time that we certainly take it up through the High Commissioner. I quite agree there.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : May I know from which districts of Assam these 29 persons were kidnapped ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I have got detailed information about every case, and there are 29 cases. If the hon. Member wants, I am prepared to give her the information.

SHRI HEM BARUA : Apart from these 25 persons kidnapped from the Assam-East Pakistan border, who are even now in the custody of the Pakistanis, there are some 79 Indian persons in the custody of the Pakistanis whom we have not succeeded in getting released. In spite of the policy of appeasement followed by our Government so far as Pakistan is concerned, Pakistan continues to be intransigent. In the context of this, and in view of the fact that this behaviour of Pakistan is a challenge to the Tashkent agreement, may I know whether our Government have discussed this matter with Mr. Kosygin when he air-dashed to India and wanted de-escalation of Indo-Pakistani tensions ? He made certain suggestions for the de-escalation of Indo-Pakistani tensions. May I know whether this particular thing that Pakistan continues to kidnap our people even after the Tashkent agreement and detains them was discussed with the Russian leader or not ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would certainly like to assure the hon. Member that there is no question of any appeasement in these matters. These incidents do take place on the border areas. I have

seen the papers, and I find that this is a continuous problem. Kidnapping and the taking away of people from this side is taking place. I have found that this method of discussion between the counterpart police officers and the Border Security Force etc. has succeeded in getting back a large number of people.

SHRI HEM BARUA : It has not succeeded so far.

SHRI Y. B. CHAVAN : Even then, I feel as far as these 25 persons are concerned that it will be necessary to take up the matter through the High Commissioner also. That is what I have felt.

SHRI HEM BARUA : The reply to my question has not come. I may say that there were some Pakistanis in our custody also and we have released all of them lock, stock and barrel, but Pakistan has not released so far 79 persons who are in their custody, besides these 25 persons whom they have kidnapped. So, how does the hon. Minister say that our efforts have succeeded at the level of the police ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know to which category of people the hon. Member is referring, because there are different categories of people. I do not want to commit myself here without that information being available with me here. I do have full information only about these 29 persons. I can tell the hon. Member that there are some Pakistanis also in our custody.

SHRI HEM BARUA : We have released them all.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : The statement of the Finance Minister of Assam is dated the 23rd March. May I know for how long these people are in the custody of Pakistan and whether Government have any machinery to see that as soon as people are kidnapped, proper steps are taken at the earliest opportunity to get them released ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I see from the facts that are detailed that some were kidnapped in 1965 ; some were kidnapped on the 23rd September, 1965 ; some were

kidnapped on 20th November, 1965 ; some were kidnapped in 1966 and some in 1967 as well. This is a sort of accumulation from 1965, 1966 and 1967.

SHRI HEM BARUA : I think you will agree with me that at this rate Pakistan would kidnap our Home Minister also.

MR. SPEAKER : The Home Ministership may not be vacant then.

SHRI RANGA : Has the hon. Minister heard the very good question asked by Shri Supakar ? What is the procedure laid down in order to see that as soon as our people are kidnapped they are brought back ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The normal procedure followed is this. These matters are discussed with the counterparts, if it is the DIG on this side with the DIG on the other, if it is the DSP on this side with the DSP on the other. Sometimes the police say they are involved in certain offences and the cases are being tried. These matters have to be gone into.

I do not think I need reply to Shri Hem Barua. But I can assure him that he need not fear that this Home Minister is likely to be kidnapped. I can also assure him that we will see that he is also not kidnapped.

श्री कंबर लाल गुप्त : असम में लाज स्केल पर पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेशन हो रहा है और वह कई साल से है। लगभग 5 लाख पाकिस्तानी असम में अभी तक मौजूद हैं और रोजाना कितने और घुसते आते हैं। उस की कब्र से किडनैपिंग के कैसेज भी होते हैं। वहां पर एंटी नेशनल ऐक्टिविटीज भी होती हैं। उन को लिक पाकिस्तान और चीन के साथ भी है। क्या यह सही है कि भारत सरकार ने असम सरकार को यह कहा है कि जो पाकिस्तानी इनफिल्ट्रेटर्स यहां पर आते हैं वह अगर यहां पर चार, पांच साल रह जाय तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए कि जो यह जांच करे कि किन को पाकिस्तान वापिस भेजना है या

किन को नहीं भोजना है इसकी वजह से असम गवर्नमेंट इस चीज पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इसके लिए क्या आप असम गवर्नमेंट को खुली छुट्टी देंगे कि वह जो इन-फिल्ट्रेशन वहां पर हो रहा है उसे रोकने और समाप्त करने के लिए जैसे चाहे कदम उठये ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member is either misinformed or wants to put his own intepretation of facts—I do not know. There is no question of giving any instrutions or even suggesting to the Assam Government that infiltrators, if they have stayed for 4 or 5 years should be allowed to stay on. That is not so. There are no instructions like that. The Assam Government is certainly free to deal with the infiltrators.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He has issued instructions that a tribunal may be set up. That tribunal may decide whether they are Pakistanis or not.

SHRI Y. B. CHAVAN : I would suggest to him to table a separate question. I will discuss the whole matter with him.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We have a vulnerable border in Assam with China and Pakistan engaging in subversive activities. In the case of these 29 kidnapped persons, has Pakistan come out with old story that they have been indulging in spying activities after transgressing into their territory ?

SHRI Y. B. CHAVAN : No, Sir.

SHRI GIRRAJ SARAN SINGH : You have the privilege of calling any Member and you call them by name. I was a member of this House from 1952-57. My name is Girraj Saran Singh and I represent Mathura. I hope in future you will kindly remember me also. You are able to pronounce even the most extraordinary names.

MR. SPEAKER : If the hon. Member will attend the House more frequently, it will be easy for me. After all, I cannot remember all the 520 names. I can easily

remember the names of those who are regularly in the House. In the case of Members who attend the House only occasionally, I forget their names.

SHRI GIRRAJ SARAN SINGH : We have surely a certain number of Pakistanis in our custody whom the Pakistani Government wish us to release. Is it not possible to arrange for some form of exchange ?

SHRI Y. B. CHAVAN : It is a good suggestion.

SHRI N. K. SANGHI : Are Government going to do anything for the families of the kidnapped persons ? I understand certain of these families are in a difficult pecuniary condition and they have also came and seen some of our Ministers to represent that they are in great distress. Is something going to be done for them ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think the Assam Government is doing the needful in the matter. But certainly I will also take up the matter with that Government.

SHRI S. S. KOTHARI : In view of frequent kidnapping cases, would the Home Minister kindly consider requests from those living on the border, I mean our citizens, for arms, and would he supply them with arms ?

SHRI Y. B. CHAVAN : This is a rather very complicated question. Supply of arms in border areas is a double-edged weapon. One has to be very careful about it. Naturally individual cases are considered on merits.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Apart from kidnapping being absolutely in contravention of the Tashkent spirit, is not kidnapping absolutely illegal ? If so, would the Home Minister give a categorical assurance to the House that not only would this be prevented in future but that the safety and safe return of those who are kindnapped will be given top priority ?

SHRI Y. B. CHAVAIN : Of course I entirely agree with the hon. Member.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : The hon. Minister said that we have some

Pakistanis in our custody. What is their number and have we any means of knowing how our kidnapped persons are treated in Pakistan ?

SHRI PILOO MODY : Also whether they are males or females ?

SHRI Y. B. CHAVAN : We do get information about the treatment given to them etc. But I cannot say that it is 100 per cent reliable.

SHRI HEM BARUA : Of these 29, how many are women ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Looking at the list, I must say there is one woman.

SHRI HEM BARUA : My information is that there are 2.

MR. SPEAKER : He will find out.

Advisory Committee for Indian Airlines

+

*1471. **SHRI D. C. SHARMA :**
SHRI JUGAL MÓNDAL :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether an Advisory Committee has been constituted to advise the Indian Airlines on the improvement of service and other facilities;

(b) if so, the constitution and terms of reference of the said Committee; and

(c) when it is likely to submit its report and whether a copy of the same will be laid on the Table ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH): (a) The Advisory Committee for Indian Airlines set up under Section 41 of the Air Corporations Act, 1953 was reconstituted with effect from 9th February, 1968.

(b) The functions of the Committee are laid down in Rule 50 of the Air Corporations Rules, under which the Committee is to advise the Corporation, *inter alia*, on provision of amenities for air travel, timetables of air services and matters of general

public interest or public convenience, provided that matters relating to staff, discipline and appointment are not to be referred to the Committee for advice. The Committee consists of 17 members representing various interests.

(c) The Committee is a standing advisory body and is not required to submit any report to Government.

SHRI D. C. SHARMA : If the Committee is not to tackle the problems of the promotion, transfer and upgrading of the staff, what useful purpose it is going to serve so far as IAC is concerned ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): Problems of promotion and so on are within the sphere of the Corporation itself; it is not something which an Advisory Committee can handle. But the Advisory Committee does have a useful role because it gives an opportunity to the representatives of the travelling public to get to know the functioning better; it gives an opportunity to the Corporation to receive comments and suggestions from members of the public.

SHRI D. C. SHARMA : Whenever we fly abroad in other airlines such as KLM, Air France and BOAC, we are given certain forms which we are asked to fill up in which we are asked to state our opinion about the working of those airlines very freely and frankly. Here we are not asked to sign such forms. Has the hon. Minister introduced something of that kind in Indian Airlines and Air India International. If so, may I know how it has worked so far and whether those things will come within the purview of these advisory committees or not.

DR. KARAN SINGH : Even Air India has always had a system of this sort like every other international airline. Very recently in the Indian Airlines also we have introduced a questionnaire. I think it was just a few days ago, and it is too early yet to assess what is the impact, but we have already begun receiving a large number of useful and valuable suggestions.

SHRI RANGA : Is the hon. Minister aware of the fact that while the fares are

going up, the kind of food that is being supplied there is going down, I mean the quality of the food. Except on occasions when the Minister himself is found to be on the plane, the *somosas* are as cold as dead and the rest of the food is uneatable. I am glad that they are having this advisory committee, but are they having this committee at all the principal airports so that the local people would be able to give the benefit of their advice in the same way as the Air India Committee does ?

DR. KARAN SINGH : The advisory committees include Members of Parliament, representatives of the Chambers of Commerce from the four main areas and various other travel agents and so on. I am sorry that the hon. Member has had a bad experience with the Indian Airlines.

SHRI RANGA : Ask anybody. It is not my experience alone.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पेट भी नहीं भरता ।

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*

MR. SPEAKER : I think all of them are hungry now.

DR. KARAN SINGH : I can only assure the hon. House through you that efforts are constantly being made to improve the food and I hope a marked improvement will be visible shortly.

SHRI K. K. CHATTERJEE : The hon. Minister has stated that so far as promotions and other service conditions are concerned, the advisory committee has no role to play. In view of the fact that on promotion and other service conditions there have been a considerable number of complaints about the injustice done by this Corporation, will the hon. Minister think about the advisability of giving this advisory committee some powers in the matter ?

DR. KARAN SINGH : I do not think it would be correct administrative procedure for an advisory committee of this sort to really get concerned with matters of promotion. These are within the sphere of the Corporation which is an

autonomous body. If there are any complaints certainly they will be looked into.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : With regard to the questionnaire introduced by the hon. Minister recently in the Indian Airlines, is the hon. Minister aware that Members generally do not fill up those forms because whatever item is filled, it will be uncomplimentary to the Airlines ?

DR. KARAN SINGH : The whole idea of inviting the suggestions is to hear the uncomplimentary remarks.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : While I admit that the advisory committees are unfortunately necessary evils of democracy, may we first know, first of all, what is the estimated cost of this advisory committee ? Secondly, will the report of this advisory committee be made available to anybody or will it be just put into the archives of the department or the Ministry ?

DR. KARAN SINGH : I would venture to differ from the hon. lady Member when she describes it as a necessary evil. I think that an advisory committee of this sort in a democratic system can play a very useful role. As I submitted earlier, the advisory committee does not give any separate report. The reports of the two Corporations are placed every year on the Table of both Houses of Parliament. The advisory committees are a continuing body which meet under the chairmanship of the General Manager of the Corporation, and they constantly give suggestions. I am told by the General Manager that the new advisory committee that has been constituted has so far, in the first meeting, proved to be very valuable and useful.

With regard to the actual expenses incurred, I do not have the figures. But I would not think that they are in any way very great.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : How much would they be ?

श्री श्रीकार लाल बेरवा : पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में जो परिचारिकाएँ होती हैं वह लड़कियाँ ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं

होते। दूसरी बात यह है कि क्या सलाहकार समिति इस बात के ऊपर भी विचार करेगी कि जो परिचारिकायें होती हैं, वह पैसेजरो के पास बैठ कर खूब सिगरेट फूंकती हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।

श्री श्रींकार लाल बेरवा : बिल्कुल गलत नहीं है। तीसरी चीज यह है कि वहां पर जो टाइम टेबल वगैरह होते हैं वह सारे अंग्रेजी में होते हैं, अखबार वगैरह भी सारे अंग्रेजी में होते हैं। वहां पर यह चीजें हिन्दी में भी हो, क्या इसके ऊपर सलाहकार समिति सोचेगी ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न तो यह था कि लड़कियां ही परिचारिकायें क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। इस के सम्बन्ध में तो मैं यहीं कह सकता हूँ कि सभी एअर लाइन्स में यही प्रणाली चली आ रही है, हिन्दुस्तान में भी और विदेशों में भी। जो यह माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर हिन्दी पत्र पत्रिकायें नहीं होती, तो पहले भी दो तीन माननीय सदस्यों ने मुझ से इस के सम्बन्ध में कहा है। मैंने एयरलाइन्स को यह आदेश भी दिया है कि हिन्दी के पत्र पत्रिकायें भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब माननीय सदस्य को शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा।

SHRI K. NARAYANA RAO : Mr. Speaker, Sir there appears to be a lot of distinction between the services rendered in the different airlines from route to route nowadays. I travelled, for instance, from Vizagapatam to Hyderabad and Hyderabad to New Delhi. I found as though I had been travelling in two distinct Air Corporations. For instance, Mr. Speaker, when I asked for a copy of the *Shanker's Weekly* on my travel from Vizag to Hyderabad, I was furnished with a three week's old *Shanker's Weekly*, and I told the air hostess that they were old copies. Immediately came the reply that they were the latest ones ; that was perhaps out of ignorance. Now, when I travelled from Hyderabad to New Delhi in a Caravelle, I asked for

Shanker's Weekly and I got the latest copy.

MR. SPEAKER : This is all general complaint.

SHRI K. NARAYANA RAO : This is not a complaint, but I have given just an illustration.

MR. SPEAKER : It is all complaints. This is Question Hour, unfortunately ; it is not a complaint hour.

SHRI K. NARAYANA RAO : It is only by way of an illustration of the existing disparities in the various items. In view of this, will the Government see that there is uniformity in the services in all the airlines ?

DR. KARAN SINGH : It is always our attempt to provide the latest facilities on all the planes. Naturally, the trunk routes where the Caravelles operate, they are more expensive routes and therefore it is usually found that to some extent the services there are superior. But it is always our attempt to see that in every service there is uniform facility. (*Interruption*).

SHRI RANGA : So far as food is concerned, let there be uniformity.

SHRI PILOO MODY rose—

SHRI HARDAYAL DEVGUN : What is the fare for him ? (*Interruption*).

SHRI PILOO MODY : The Minister said just now that the new committee constituted had made several valuable suggestions to the Corporation. I would like to know when we are likely to see the results of such suggestions in the actual service performed.

As far as the food is concerned, I certainly sympathise with my hon. friend Shri Kachwai about the quantity. But as far as the quality is concerned, the only remedy that I can suggest is that the Council of Ministers should be made to eat nothing but IAC food for a month, and I guarantee that the food will be improved presto. Is there any such move in the mind of the Minister ?

DR. KARAN SINGH : The first question was, when will the results of these suggestions become visible. As I said, this is a continuing process. It is not as if there is any particular dead-line. It is a constant process to improve the services. In any public utility service like the airlines the idea is to be constantly trying and keeping aware of what the public feel and to try to make improvements.

SHRI PILOO MODY : The time-lag between the suggestion and the implementation.

DR. KARAN SINGH : It is impossible to say at present. Suggestions are made and many of those things are already in the process of being implemented.

SHRI PILOO MODY : What is "the process of being implemented" ?

DR. KARAN SINGH : Running any commercial organisation, as the hon. Member perhaps knows, is a process where these things have got to be constantly done. It is not as if you lay a date with regard to this question.

About food, the hon. member is a frequent air traveller and I think it is fairly clear that he has not suffered in any way by taking that food. I myself am a frequent traveller.

SHRI RANGA : The hon. minister cannot take umbrage on the fact that he has been a frequent traveller. First of all, he has been a Raja and after that, he is a minister.

MR. SPEAKER : Next question.

Road Bridge over Pamban

+

*1472. **SHRI KAMALANATHAN :**
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to construct a Road Bridge over Pamban across Palks Strait in Madras State ;

(b) whether it is a fact that the Late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri had stressed the importance of this road

bridge while inaugurating the Tuticorin Port Project ; and

(c) whether it is also a fact that the priority has been pushed down after his death ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Late Shri Lal Bahadur Shastri had desired that the question of including this bridge in the Third Five Year Plan itself might be considered ; but it could not be done due to financial stringency. The rough estimated cost for the bridge proper and approaches comes to Rs. 5 crores.

Its inclusion in the Fourth Five Year Plan also depends on the availability of resources, and relative priorities of demand against such resources.

SHRI KAMALANATHAN : If I remember airtight, Sir, when you were Transport Minister, the then Prime Minister while inaugurating the Tuticorin port, realised the importance of this bridge and immediately suggested that it should be taken up. Estimates were prepared. But so far it has not been taken up. The policy of the Government of India is to give first priority to the missing links. Is this not a missing link in National Highway 48 between Mandapam and Danushkodi ? Priority has been given to other projects, but this has not been taken up. Will the Minister assure us that it will be taken up immediately ?

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, in November 64 the late Prime Minister had expressed the desire, during his inaugural address at Tuticorin, that this matter may be examined. Immediately in January 65, estimates for detailed survey were sanctioned. They were ready by April 65 through the State Government. In the meantime, we were in the last year of the third plan and nothing could be included in it. As far as the Fourth Plan is concerned, the House is aware that everything is in the melting pot.

SHRI KAMALANATHAN : This is a very important bridge and it can form a link to Ceylon also. It can form part of

the international roadways. Moreover, it will be the shortest route to Ceylon because it will connect Thalaimannar also. So, will the minister make efforts to make it a part of the international roadways ?

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, this point of view will be taken into consideration.

SHRI MAYAVAN : Is it a fact that the train service has been discontinued and if so, the reasons thereof ?

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, according to my information, after the recent cyclone, the train services were dislocated for sometime. After that, they have started functioning.

SHRI G. VISWANATHAN : The minister said this project could not be taken up due to financial stringency. Under "National Highways" during 1967-68, out of Rs. 15½ crores, Madras was given only Rs. 12 lakhs. Under "State Roads of economic or industrial importance", out of Rs. 236 lakhs, only Rs. 7 lakhs were given to Madras. Under "Central Road Fund" out of Rs. 67 lakhs, only Rs. 1 lakh were given to Madras. Thus, so much expenditure has been incurred by the Central Government, but Madras was completely neglected. Is this not discrimination ? How does the minister reconcile this ?

SHRI BHAKT DARSHAN : Sir, there is no discrimination whatever against Madras or any other State. We take a decision according to the demands of the various State Government and the availability of funds. If the hon. member wants, I can explain it to him at length.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : If it is a new construction, the question of financial stringency can be raised. But this bridge was in existence and it was washed away. So, trains could not move. It is a question of rescue operation. Am I to understand that even for rescue operations, financial stringency is considered ? Rama constructed this bridge for going to Ceylon. This Ravana should not stand in the way of its restoration.

MR. SPEAKER : There are no Ravana's in this House ; all are Ramas. Next question.

Mizos Going to Burma

+

*1473. **SHRI CHENGALRAYA NAIDU :**

SHRI ANBUCHZHIAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press report that 200 Mizos are heading towards Burma ;

(b) if so, whether Burma Government has been requested not to allow them to enter and also to hand them over to the Indian authorities ;

(c) if so, the reaction of the Burma Government thereto ; and

(d) the steps taken to prevent them from escaping to Burma ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir. But there is no information available with Government to confirm the press report.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Border posts have been alerted. The Security Forces are maintaining constant vigilance to check the movement of hostile elements across the border.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Is it a fact that in the past also, our Government have made several requests to the Burmese Government to take effective steps against those Mizos who cross into Burmese territory and hand them over to us ? If so, may I know how many Mizos or Nagas have been handed over to us so far ?

SHRI Y. B. CHAVAN : At least I know one case when immediately after this rebellion in Mizoland started, some families did move to Pakistan and some to Burma. The Burmese Government did send those Mizo families back.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Is it a fact that our security men first saw these 200 Mizos infiltrating into the area

of Churachandpur sub-division and they were also sighted at Simzol in March 68? If so, why did not our security forces intercept them then and there instead of allowing them to cross the border?

SHRI Y. B. CHAVAN : As I said, there is no confirmation of the information that they have crossed the border. But certainly in March, some incidents did take place in which the post of the volunteers in a village nearby was attacked. But it is not true, at least there is no confirmation that any of them have crossed the border.

SHRI R. BARUA : This has been going on for a long time and the army also is there. But till now there is no sign that this situation is under control. This has created a very disturbing psychology in the entire area. May I know whether any positive steps are going to be taken to see that the entire situation is brought under control within a short time, so that the divisive forces in that area do not get encouragement from the activities of these people?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. member has certainly raised legitimate question. It is true that the whole thing is not yet under complete control. But that only shows the complexity of the problem. Certainly as far as the Mizo area is concerned we have taken serious steps which have certainly brought some order in parts of that area. To begin with, there were many encounters with those who were very active rebels and they were forced to take shelter sometimes in the most interior and difficult areas or to cross over to other countries. Recently I had informed the House that a considerable population was grouped in a number of villages. The idea was to take away the bases for the rebels to operate. It has partly succeeded. I cannot say the whole thing has yet completely succeeded. This question will certainly take some time. When I said complexity, I meant, this is not a problem which could be solved with the guns of the army.

There are certain economic aspects of it, there are certain social aspects of it and there are certainly some political aspects of it also.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Sir, the Mizo area is a continuous area to Pakistan on one side and Burma on the other. We have been told very often that these people have been going to Pakistan and also Burma for one reason or the other. Whenever it has been asked why they are not stopped the argument given is that the terrain is very difficult. May I know whether we are a peculiar country where the terrain is such that we cannot stop people going outside for hostile purposes and are the laws for going out and coming in only meant for law-abiding citizens? If that is the reason why Government so far have not been able to stop it and if the regular methods have not succeeded, have they thought of clearing the border area upto an extent of five or ten miles in breadth of all population and taking other steps so that this daily occurrence of people going to Burma, Pakistan and China can be checked and this going and coming as if they go out of one parlour to the other and come back is stopped?

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not as easy as going from one parlour to another and coming back. That is exactly the difficulty. If that had been the position we could have easily sealed the border. Very often this phrase 'sealing the border' is used. Particularly this terrain, the Naga terrain and the Mizo terrain, is very difficult. I wish the hon. Member sometimes pays a visit to that area and finds for himself, the position there. But that is no excuse for not doing anything. I am not putting that forward as an excuse for not doing anything. On the other hand, a large number of persons have been arrested and a large number of persons were killed in action while crossing the border. This kind of action is being taken about it.

SHRI BEDABRATA BARUA : Conventional deterrents to this, what they call 'China traffic' have not been effective and this House is obliged to get reports after reports about their going to China and coming back. In view of, also, the fact that the Burma Government cannot be expected to co-operate in a very substantial manner and they are afraid even to be known that they have talked with us about this traffic, may I know, in view of the regrouping that the hon. Minister has re-

ferred to, which means that there would be no movement of people and all movements outside the regrouped areas are illegal, whether it is in the public interest for the Government to tell this House whether they have decided to ban movements in those areas which are outside the regrouped villages ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would certainly make a request to hon. Members that we should not discuss some of our friendly countries when we are trying to make some settlement with them. In some areas in that part the tribals were supposed to go freely from one area to the other. That also has been done with very much restriction and under severe watch.

SHRI N. K. SOMANI : We have been hearing about this clandestine and illegitimate traffic between some of our border areas and other foreign countries so regularly that it seems some people are systematically using this as a free way for their own purposes. While it is impossible for the Government to hermetically seal the border would it be too much to expect the border security force to be provided with helicopters and tele-communication equipment so that their mobility and ability to check them could be increased and this traffic is put an end to once for all ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The border security force does not function on the borders of Burma—this is just for the information of the hon. Member. As far as the security forces which work in this area are concerned, they have been equipped with necessary wireless communication equipment.

SHRI N. K. SOMANI : What about helicopters ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think we should leave these matters of operational requirements to those persons concerned. Merely having helicopters is not enough because to keep them operative, the hon. Member must learn, there must be adequate arrangement for their maintenance and also fuel supply etc. Helicopter is not a thing that can be used as a permanent weapon in that part of the country. I do not want to give any final opinion in this

matter. This is a question in which we must go by the advice of those who are in charge of operation.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : May I know whether the Government is aware of the possibility of a combination of Mizos and Nagas and that combination indulging in a concerted effort to have the movement from India to China and vice versa ? May I also know whether the Government border security forces or check posts maintain any liaison with the check posts in Burma ? As the hon. Minister is aware, they all go through Burma. The terrain in Burma is also very difficult. Do you maintain regular contact with the border check posts in Burma ? If so, which are the border check posts in Burma with which you maintain contact ? May I also know whether this matter was discussed with Gen. Ne Win when he came here as to how to stop this going and coming in of Naga hostiles and Mizo hostiles ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I think the hon. Member is asking my opinion about a matter which is beyond me. I do not think I can give any information about it. All that I can say is that we can take effective steps to prevent this movement by intensifying our patrolling in depth on our side. That is being done.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : When GEN. Ne Win came here it was expected that this matter would be taken up because it concerns India and Burma both. Now, do we not expect the Home Minister would be aware of what transpired between the Prime Minister and Gen. Ne Win ?

MR. SPEAKER : It is for the Prime Minister to say about this and not the Home Minister.

SHRI SAMAR GUHA : May I know whether it is a fact that the press Mynamati in the district of Comilla in East Pakistan is printing propaganda material on Mizos ? May I know whether it is also a fact that the Mizos have now diverted their attention to a very large extent to Tripura area adjoining Mizo Hills, they are creating a lot of trouble there and about that a number of reports have appeared in Tripura papers ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would answer the second part first. The Mizo cookies have been attacking the villages on the Tripura border. The Tripura police are taking necessary steps about it. About the first part of his question, I think we will need a little more notice to get further information.

SHRI SAMAR GUHA : This has appeared in the press there.

श्री ब० ना० कुरील : मिज़ो लोगों का बर्मा और पाकिस्तान में जाना बहुत दिनों से जारी है और सरकार उसको रोकने में करीब-करीब असफल रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार के सामने कौन सी मुख्य दिक्कत है, जो अब तक अनुभव में आई है;

क्या उस दिक्कत को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है और क्या उस में कोई सफलता मिलने की आशा है।

SHRI Y. B. CHAVAN : I have already explained whatever steps we are taking. The only thing we can do is to intensify our petrolling in that area and prevent them going in any large number. That is being done.

SHRI HEM BARUA : The Mizo hostiles together with the Naga hostiles marched into the Karen area in Burma. They were given open hospitality there and from there they were transported in motor trucks to Peking. That is the liaison going on between the Karens in Burma and the Mizo hostiles and Naga hostiles in India. In view of that may I know why is it that the Government did not ask specifically General Ne Win when he visited this country to ask his countrymen the Karens not to offer hospitality to our rebels the Naga hostiles and Mizo hostiles to stop it altogether? Secondly, is it not a fact that Chinese troops are already being airlifted from Peking to Dacca in East Pakistan from where they march to Mizo Hills and the Mizo National Front has already adopted a resolution allowing Chinese troops to be stationed in Mizo Hills District of Assam for three years in order to step up the revolution

which is going to intensify by the second half of June?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member is quite right in his anxiety, I can understand that. It is true that these people who crossed the border did pass through the Karen area. But let us understand one thing, that the Burmese Government also is facing a similar problem in Northern Burma. It is not merely a question of taking up a matter and making them aware of their own problems. It is presumed that they are aware of their problems.

SHRI HEM BARUA : Sir, he has not replied to my question. I had asked for specific information from him. I know the Karens are revolting against their own government. Our people are also revolting against our government—the Mizos and the Nagas. I am not concerned with the problem of the Burmese; I am concerned only with our problem and how far the Burmese Government is in a position to help us in stopping the Mizo and Naga hostiles going to Peking via the Karen area of Burma. The second part of the question was also very specific, about the Chinese troops being airlifted to Dacca in East Pakistan from where they march to the Mizo hills and the Mizo National Front adopting a resolution that they are prepared to offer Mizo Hills to be occupied by the Chinese troops for another three years in order to step up the revolution which is to be intensified by the middle of June.

SHRI Y. B. CHAVAN : I have also heard about it. But there is no confirmation of this proclamation or agreement.

SHRI J. N. HAZARIKA : May I know to what extent the effective dealing with the Mizos by the Government is being hampered on account of the fact that every Mizo, wherever he lives, either in Burma or elsewhere, is a Burmese citizen under the Burmese Constitution and also because of the fact that the tribals living in the border can freely travel to the other side of the country to a depth of 25 miles and, if so, what steps are the Government taking to get over this difficulty?

SHRI Y. B. CHAVAN : I really do not know what question he is asking me.

SHORT NOTICE QUESTION

Death of Students of Nursing College Attached to Irwin Hospital, New Delhi

+
SNQ. 26. SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI KANWAR LAL
GUPTA :
SHRI NIHAL SINGH :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI MADHU LIMAYE :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four students of the Nursing College attached to the Irwin Hospital, New Delhi died within 3-4 months under mysterious circumstances.

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the steps taken to prevent similar occurrence in the case of Nurses and Nursing students ?

THE MINISTER OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI SATYA NARAYAN SINHA):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Police is investigating into the causes of death under the normal law. It has also been decided to have a judicial enquiry into the matter. Suitable action would be taken when the report of the enquiry is available. With your permission, I may add that the SDM, Daryaganj is also holding an administrative inquiry into the circumstances leading to these successive deaths.

SHRI BAL RAJ MADHOK : This problem of suicides and mysterious deaths of nursing students in Delhi hospitals has assumed a very dangerous proportion. There have been about six cases in the last few months, four in the last few weeks, and the main reason for it is that till recently the nursing profession was mainly staffed by people or women coming from a particular community and a particular region but of late because of socio-economic circumstances and conditions the girls from other communities and areas are also

coming and joining the profession in large numbers. But the atmosphere in hospitals continues to be what it used to be, even though there were complaints about it. Though a certain committee made certain recommendations on this matter, they were never implemented. In the circumstances, may I know whether probe, not only into this particular incident but into the entire system of nursing, the teaching of nurses, their educational and working conditions in the hospitals, will be made and for that purpose a commission consisting of some educationists and some medical specialists will be appointed ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : As I said, when the judicial inquiry report is submitted, the suggestion made by the hon. Member will also be taken into consideration.

SHRI BALRAJ MADHOK : The reports are that these suicides were mainly due to cases of misbehaviour by a number of doctors and senior nurses, the so-called matrohs. I have just now before me a report which says that the doctors are so possessive in their relations with the students that the slightest rebuff to their advances by the young girls makes them retaliatory in their action. It is there in this report. Then, some of the doctors are missing; they are not available. The Sub-Divisional Magistrate who was holding the inquiry was not able to get at some of the doctors there. If some doctors are found to be guilty, may I know whether they will be given deterrent punishment so that such things are not repeated again ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I have also read the report which the hon. Member has mentioned in some of the newspapers. I cannot rule it out; I cannot say that it is not happening. But we must wait for the report of the judicial inquiry. If any doctor is found guilty, he will be seriously dealt with because this is a very serious matter.

SHRI HEM BARUA : Guilty of what ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Making advances.

SHRI HEM BARUA : Could that be a guilt ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Yes, if it is done without mutual consent and agreement.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह जो काण्ड हुआ है, यह एक बहुत जबरदस्त रिकेट है इस के अन्दर इरविन हास्पिटल के बड़े-बड़े डाक्टरों, दिल्ली के बड़े-बड़े पैसे वाले लोग और बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जो वहाँ के डाक्टरों की मदद से इन नर्सों पर यह दबाव डालते हैं कि वह उनका काम करें और एक तरह से काफी बड़े पैमाने पर उनके ऊपर दबाव डाल कर उन से वह काम कराया जाता है, एक तरह से वोमनाइजिंग खुले आम वहाँ पर हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि यह जो कमेटी आपने बनाई है—इसकी कौन इन्क्वायरी करेगा, इस की टर्मजं आफ रेफ्रेन्सक्या होगी ?

दूसरे वहाँ पर नर्सों की जो कन्डीशन्ज है, जो उनकी सर्विस कन्डीशन्ज हैं या जो भी वहाँ पर व्यवस्था है बहुत खराब है तथा इरविन हास्पिटल में नर्सों की संख्या बहुत ही कम है, सरकार उनकी संख्या बढ़ाने के लिये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ग्रान्ट नहीं देती है। आज नर्सों की जो संख्या आल इण्डिया मॅडिकल इंस्टीचूट में है, उससे करीब 33 परसेन्ट नर्सों यहाँ पर कम हैं, हालांकि इरविन हास्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हास्पिटल है। क्या सरकार इरविन हास्पिटल की वर्किंग के बारे में तथा उनकी सर्विस कन्डीशन्ज के बारे में भी जांच करायेगी ?

श्री सत्यनारायण सिंह : मैंने अभी बताया है कि जो नार्स आपने कहीं हैं, हो सकता है कि सही हों, गलत हों—मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो जूडीशियल इन्क्वायरी कमेटी बैठेगी उन के सामने ये सब मसले भी, जो मेम्बर साहबान ने उठाये हैं, पेश किये जायेंगे, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उन पर गौर किया

जायेगा। जब जूडीशियल इन्क्वायरी होती है तो उस के मायने ही यह है कि जांच करने वाला कोई जज होगा। अब जहाँ तक उमकी डिटेल्ज का सम्बन्ध है माननीय सदस्य को मालूम है कि यह मामला दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा सम्बन्ध रखता है, उन के अख्तियार में है—मैंने कल ही लैफ्टीनेन्ट गवर्नर साहब से बात की थी, एक्जीक्यूटिव कान्सिलर को भी सुझाव दिया था कि वहाँ पर जूडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और मुझे खुशी है कि उन्होंने उस को मान लिया है। अब टर्मजं आफ रेफ्रेन्स क्या होगी, यह उन से राय कर के ही तय करेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा दूसरा सवाल यह था कि इरविन हास्पिटल में नर्सों की संख्या बहुत कम है, उनकी सर्विस कन्डीशन्ज बहुत खराब हैं—क्या इस को इन्क्वायरी करा कर ठीक करायेगे ?

श्री सत्यनारायण सिंह : यह ठीक है - लेकिन इस वक्त जो शार्ट नोटिस क्वेश्चन है इस का उस से सीधा सरोकार नहीं है। मैंने जवाब दिया है कि इस इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा पता लगेगा कि और चीजों को भी देखना है, तो जरूर देखा जायेगा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इन के मन्त्रालय का सवाल है, इन्होंने कहा है कि जांच करायेगे और जज के सामने कौन से विषय रखे जायेंगे, टर्मजं आफ रेफ्रेन्स क्या होगी, इस के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इधर एक अर्स से दिल्ली में कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है और इस का कुछ हद तक सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से आता है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ.....

MR. SPEAKER : The question is being answered by another Minister. Only, the Home Minister happens to be here. How could he address it to him ?

श्री मधु लिमये : मैं क्या करूँ, आप हमारे ऊपर अन्याय न होने दीजिये। आप हमारे

[श्री मधु लिमये]

रक्षक हैं। मैं सत्य नारायण सिन्हा जी से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन यदि वह उत्तर न दें, तब क्या हो? ये मिले-जुले प्रश्न होते हैं अब मैं क्या करूँ आप रास्ता दिखाइये।

MR. SPEAKER : Let him ask the question. He will get the information.

श्री मधु लिमये : मृत्यु के कारण क्या है क्या यह स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे, इस का तो पुलिस से सम्बन्ध आता है।

MR. SPEAKER : The concerned Minister will give information in consultation with other Ministers.

श्री मधु लिमये : मेरा प्रश्न यह है कि इन के कार्य काल में कानून और व्यवस्था का मामला इन दिनों में बहुत बिगड़ा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 31 दिसम्बर को 12 बजे, मध्य रात्री में कनाट-प्लेस में क्या हुआ, उस के बाद पुलिस वालों के खिलाफ जो केसेज किये जा रहे हैं, उम् में भी बांबली चल रही है। इस लिये मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था सुधारने के लिये वे कौन से ठोस कदम इन केसेज की रोशनी में उठा रहे हैं?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) rose—

MR. SPEAKER : For my own clarification... (Interruption).

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, वह तो जवाब देने के लिये तैयार हैं।

MR. SPEAKER : This time he is ready. I do not mind if he answers.

श्री मधु लिमये : आपको हमारे अधिकारों की रक्षा मंत्री महोदय से ज्यादा करनी चाहिये।

MR. SPEAKER : Let him answer if he wants to; I have no objection, but the point is that if the question is addressed

to the Health Minister, he must come ready after consulting other Ministers.

श्री मधु लिमये : हाँ, तो ठीक है, वह जवाब दें।

MR. SPEAKER : Let me try to understand so that I will follow the same procedure in future. If a question is put and the Ministers are ready to answer it, I have no objection. From tomorrow I will ask all of them to be here so that anybody may put any question and they answer it.

श्री मधु लिमये : असल में यह काम प्रधान मंत्री को करना चाहिये था। इनके पिताजी करते थे, ये क्यों नहीं करती हैं।

MR. SPEAKER : My understanding of the Question Hour is that if the question is addressed to a particular Minister, all the information pertaining to that question the concerned Minister must get. Shri Chavan is ready to answer it. He may answer it.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Sir, I have a submission to make.

श्री रवि राय : क्या इनका व्यवस्था का प्रश्न है?

SHRI MORARJI DESAI : If a question legitimately arises from another question, it is certainly the right of my hon. friend or any other Member to ask that question, but if the question does not directly arise from it and arises only indirectly and other Ministers are concerned with it—Shri Chavan is present and he may answer it or he may not answer it; that is his own look-out... (Interruption).

श्री मधु लिमये : इसी लिये मैंने कहा कि वे तैयार होकर आयें।

SHRI MORARJI DESAI : But this should not become a precedent afterwards, so that if there is a question like that other Minister should be present.

MR. SPEAKER : The Chair is helpless. The Minister is ready to answer. That is the position.

SHRI MORARJI DESAI : I am not saying that you should disallow the Home Minister from answering it. I am only saying that this should not become a precedent.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप प्रधान मन्त्री ने जो कहा है, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने जो धमकी बयान दिया है मेरा व्यवस्था का प्रश्न उस के बारे में है। प्रश्नोत्तर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि उप प्रधान मन्त्री ने जो कहा है, उसके संबंध में है। आपने एक व्यवस्था यह दी कि सम्बन्धित मंत्री सारे मन्त्रालयों से जानकारी हासिल करके जवाब दें। लेकिन वे ऐसी स्थिति में न हों तो फिर सम्बन्धित मन्त्री ही जवाब दें।

MR. SPEAKER : He is answering ; why are you worried ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I will certainly answer the question which he has raised. I do not want to start a new procedure, but may I point out our difficulties also ? A challenging question is raised and it goes on record. If we do not give a reply to that, it will look as if we have no reply. If you reject the question, certainly I do not want to start any new procedure.

MR. SPEAKER : The concerned Minister, I think, should be ready to reply.

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member has raised a general question of the law and order situation in Delhi in the context of... (Interruption).

SHRI MADHU LIMAYE : Arising out of this.

SHRI Y. B. CHAVAN : Arising out of this. He made a general statement that the law and order situation has deteriorated in the last year and a half since I took over. He cited a case that we have started cases against the police. Here is

an instrument of law and order, the police (Interruption).

श्री मधु लिमये : मैं ने घांघली के बारे में कहा है। केसेब में घांघलियां हो रही हैं, यह मैंने कहा है, केस चलाने के बारे में मैं नहीं कहा है।

SHRI Y. B. CHAVAN : No. There also I have said that some of those who failed in their normal duties have been suspended. Therefore the action certainly is taken. But I want to point out to the hon. Member that if there is a deterioration in the situation, there are certainly some political attitudes of some of the hon. Members opposite responsible for it..... (Interruption).

श्री मधु लिमये : बिल्कुल नहीं। यह भी कोई जवाब हुआ ? 31 दिसम्बर को कनाट सर्कंस में जो कुछ हुआ उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? कौनसा राजनीतिक दल उसके लिये जिम्मेदार है, क्या यह मन्त्री उसकी सफाई करेंगे ?

श्री सु० शं० शर्मा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर । यह जो इस तरह से प्वाइन्ट उठाना चाहते हैं, हम इसके सिलसिले में आपका निर्णय चाहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उठाने देने की नीयत ही नहीं आने देनी चाहिये। आप उनको एलाऊ ही न करें कि वे इस तरह के क्वेश्चन करें।

MR. SPEAKER : I have understood your point. I am myself not clear in my mind. I still feel that except on a rare occasion the concerned Minister should get up and say that this is not relevant, because tomorrow they may demand that all the Ministers must be here and they must answer. It will arise... (Interruption).

SHRI SONAVANE : The question of relevance is to be decided by you.

MR. SPEAKER : In the middle of a sentence you get up and start speaking. I am on my legs. I have spoken half a sentence and you get up. I think, you want to compete ; that is all.

[Mr. Speaker]

I am not clear in my mind where this, if it continues, will lead to. The concerned Minister must say that this is not relevant or, "I am not able to answer about law and order." If they demand this, then the Law Minister will have to be here; the Home Minister will have to be here; the Finance Minister will have to be here; everybody will have to be here. It will be a dangerous precedent and it will be impossible for any government, not only this government, to function.

SHRI SONAVANE : May I make a submission? You have said about the question of relevance. Who is to decide the question of relevance? It is the Chair which has to decide whether the question is relevant or not and whether it should be allowed or not.

MR. SPEAKER : The question may be an allied question also; or, even if it is relevant, the concerned Minister may not be in a position to answer it. Now, about the nurses, on the point that the police has not taken proper action, it is relevant, hundred per cent relevant, but still the Health Minister may not be able to answer it. If girls are dying and anybody is asking that, it is hundred per cent relevant but the Health Minister may not be able to answer about law and order. Please sit down. Every minute you are getting up.

SHRI SONAVANE : We have got every right to address you. We cannot be cowed down like this.

MR. SPEAKER : Please sit down now. Shrimati Sushila Rohatgi.

SHRI SONAVANE : Let me make a submission. We have got every right to make a submission. We cannot be cowed down like this.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : As it is, there is a great dearth of nurses in the country and the ratio between doctors and nurses is not very compatible. May I ask the hon. Health Minister whether, while the judicial inquiry is going on, he is at the same time prepared to make a thorough probe into all the working conditions—the causes of social security, stability, emoluments and all the conditions

under which nurses are working—so that all the doubts may be removed from this profession and our sisters, who are fighting under great hardship, may not find it difficult to become nurses in future?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I have already answered this question. Two hon. Members put this question and I said that after the inquiry report is received, we shall look into this matter.

SHRI HEM BARUA : The death of these four young girls under mysterious circumstances is a very tragic thing and I expected, the Minister would express his regret and sorrow about this which he has not done. The Minister has said that he has ordered an inquiry to be instituted into this incident. There are contradictory reports in the papers. Over and above that there are certain allegations against or about the working of the Irwin Hospital. In that context, may I know whether the Minister is prepared to expand the ambit of the inquiry and conduct an inquiry into the working conditions of the hospital so as to find out the real truth?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : I have replied to this point. Of course, my hon. friend has simply paraphrased what other hon. Members have already said. I have said that after the report of this judicial inquiry which will certainly be a thorough, inquiry is received, if we consider that certain points about the working of the Irwin Hospital also need to be looked into, we shall look into them.

SHRI HEM BARUA : My question was very specific. He is very good in ordering an inquiry into the incident of the death of the girls, but I want the scope of this inquiry to be expanded so as to inquire into the working conditions of the hospital against which there are many allegations.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : The judicial inquiry will go into the causes and how these things have happened. After that, if necessary, another inquiry will be instituted as the hon. Member has suggested.

DR. SUSHILA NAYAR : A lot of things have been said here by hon. Mem-

bers. Shri Kanwar Lal Gupta and some others, accusing big doctors, small doctors, exploiting the nurses. The death of these nurses is a very sad thing while the judicial inquiry is on, will the Minister see to it that the reputation of the medical profession as a whole is not unnecessarily jeopardised (*Interruption*).

SHRI UMANATH : You are not caring about the innocent girls. You are caring more for the officers, doctors and wealthy persons... (*Interruptions*)

DR. SUSHILA NAYAR : We are extremely sorry and aggrieved that these things should have happened... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Shri Banerjee.

SHRI UMANATH : Girls are being exploited by certain elements... (*Interruptions*) She does not care about them. She cares more about officers and doctors... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : I have called Shri Banerjee.

DR. SUSHILA NAYAR : We want to know the causes; we want to stop such things. But in the meantime, these imputations and sweeping allegations should not be made.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैडिकल प्रोफेशन वालों का यह डाक्टर लोगों का एक कोड आफ कंडक्ट रहना चाहिए... (*व्यवधान*)...

श्री स० मो० बनर्जी : डा० सुशीला नैयर ने मेरा नाम लिया इसलिए मैं साफ कर दूँ कि मैं किसी डाक्टर को व्यथ ही बदनाम नहीं करना चाहता लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरीके से लड़कियों की इज्जत लुटें लेकिन मालूम पड़ता है कि उन्हें लड़कियों की इज्जत लूटे जाने से चिन्ता नहीं है ... (*व्यवधान*)...

DR. SUSHILA NAYAR : I have been working (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Don't get excited. Shri Banerjee.

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे सरूल अफ़सोस है कि यह बड़ी बहन होकर इस तरह से छोटी बहनों का खून हुआ तो उस के बारे में उन्होंने अफ़सोस नहीं किया बल्कि वह उलटे डाक्टरों को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो गयीं... (*व्यवधान*)... अब अगर उन के अपनी लड़कियां होती तो समझतीं कि उन पर क्या गुजरती है ?... (*व्यवधान*)... खैर मैं अब सवाल करता हूँ। क्या मन्त्री महोदय को मालूम नहीं है कि जब वह पिछले दिनों यहीं दिल्ली में अंकटाड कान्फ़स हो रही थी और यहां पर यूनाइटेड नेशंस के रिप्रिजेंटेटिव्स आये हुए थे तो यह नर्सों और ट्रेनी नर्सों को जब-रदस्ती इस के लिए इनफ़्लुएंस किया गया कि वह उन बाहर के प्रतिनिधियों के पास कौल ग्लर्स की हैसियत से जायें ? क्या यह बात भी सही है कि इन दो लड़कियों ने अपनी चिट्ठियों में इन चीजों का हवाला दिया था लेकिन उन के मरने के बाद वह चीजें जानबूझ कर गायब कर दी गईं क्योंकि वह समझते थे कि यह चीजें उन के खिलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती हैं ? क्या यह बात उन के नौलिज में आई है और क्या इनको इंटरव्यू उन्होंने दिया है ? ... (*व्यवधान*)...

श्री सत्यनारायण सिंह : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं यह एलिगेण्डस मैंने भी अखबारों में पढ़े थे बाकी इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब इस सारे मामले को लेकर एक जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है तो बहुत तरह की बातें...

श्री स० मो० बनर्जी : चिट्ठी घाप को मिली है या नहीं ?

श्री सत्यनारायण सिंह : वह चिट्ठी भी है और दूसरी भी बहुत सी बातें हैं। सारा मामला जुडिशियल इन्क्वायरी के सामने जायेगा और सब जांच पड़ताल की जायेगी। माननीय सदस्य बनर्जी और अन्य सभी सदस्यों से मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब

जुडिसियल इन्क्वायरी हो रही है तो कुछ बातें यहां कह कर उस इन्क्वायरी को प्रैजुडिस न किया जाय।

डा० सुशीला नैयर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूँ कि यह इम्मीरल ट्रैफिक का काम एक बहुत बुरा काम है और इसे रोकने के हेतु बनी संस्था की मैं वर्षों तक अध्यक्ष रही हूँ। मैं अभी भी उसके लिये काम करती हूँ लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगी कि इम्मीरल ट्रैफिक के काम को नसैफकी हत्या के काम के साथ डाक्टरों को इनवील्व करने की जो बात की है वह एक गलत बात है। मैं चाहूंगी कि यह इम्मीरल ट्रैफिक को बंद करने का काम मंत्री महोदय और होम मिनिस्टर दोनों करें। हम चाहते हैं कि हमारी औरतों की इज्जत बरकरार रहे और अपनी बहनों की इज्जत हमें इन से अधिक प्यारी है और हम चाहते हैं कि इस के लिए पूरी कार्यवाही सरकार करे और जो भी यह इम्मीरल ट्रैफिक का काम करता हुआ पाया जाय उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाय... (व्यवधान)...

MR. SPEAKER : You can take it up next time.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Sales Tax Revenue in Delhi

*1470. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the leakages in Delhi's Sales tax revenue total Rs. 5 crores annually ; and

(b) if so, the steps taken to check leakages of such magnitude ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1048/68].

Bomb Explosions in West Bengal

*1474. SHRI GANESH GHOSH :
SHRI K. ANIRUDHAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a team of experts or any individual was sent to West Bengal to examine bomb explosion cases in Lal Bazar and Shantiniketan ; and

(b) if so, the composition of the team and its specific jobs ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). No experts were sent by the Central Government. However, the Government of West Bengal appointed a Special Investigation Team consisting of the D.I.G. (Intelligence branch) West Bengal, as Chairman and Director, Forensic Science Laboratory, West Bengal, Inspector of Explosives, Calcutta, Special Superintendent of Police, C.I.D. West Bengal, Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Calcutta and Additional Deputy Commissioner of Police, Detective Department, Calcutta, as Members. The team examined some of the recent cases of bomb explosions in Calcutta and in the districts of West Bengal to find out—

(i) whether the bombs were imported ones, and

(ii) whether there was a common source of supply indicating a joint net-work of saboteurs.

Bills from West Bengal for Assent by President

*1475. SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Bills received from West Bengal between the 1st March, 1967 and 20th November, 1967 for President's assent ;

(b) whether any of them actually received the President's assent ;

(c) if so, when ; and

(d) the details of the Bills received during the above mentioned period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Eight.

(b) Yes, Sir. All of them received the President's assent.

(c) and (d). A statement giving the required information is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1049/68].

Defence Weapons with Dacoits

*1476. SHRI DEIVEEKAN :
SHRI Y. S. KUSHWAH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arms and ammunitions, smuggled from Pakistan and from the Ordnance factory at Jabulpur have been recovered from the dacoits and persons arrested in connection with the communal troubles in India ;

(b) if so, whether any enquiry has been ordered to investigate the arms flow from Pakistan ;

(c) if so, the findings thereof ; and

(d) the steps taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Some arms and ammunitions allegedly smuggled from Pakistan and also pertaining to Defence stocks have been recovered from dacoits. Information regarding recovery of arms from persons arrested in connection with communal incidents, is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). On receipt of a report from the Government of Madhya Pradesh the Director, C.B.I. was asked to look into the problem. The enquiry did not reveal any regular flow of arms from Pakistan.

(d) Security arrangements on the borders have been tightened and special watch is kept on persons indulging in smuggling.

केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान

1477. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले

केन्द्रीय स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान क्या हैं।

(ख) क्या सभी अध्यापकों के लिये एक-से वेतन-मान निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या इन अध्यापकों को केन्द्रीय सरकारी दरों पर महंगाई भत्ता दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) बिबरण सभा पटल पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या LT -1050/68]

(ख) से (घ). निम्नलिखित प्रकार के कुछ अध्यापकों को छोड़ कर, सभी को केन्द्रीय दरों पर समान वेतनमान तथा महंगाई भत्ता दिया जाया है :—(i) प्रतिनियुक्ति, (ii) जिन के बारे में छानबीन चल रही है, और (iii) जिन्हें दया के आधार पर रखने की अनुमति प्रदान की गयी है, जोकि वे योग्यता में कम हैं।

Flying Clubs in U.P.

*1478. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total number of Flying clubs functioning in Uttar Pradesh at present ;

(b) whether there is any proposals to set up a Flying Club at Gorakhpur ; and

(c) if so, the type of training to be imparted there and whether it will include training in flying of Helicopters ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) There is at present only one flying club functioning in Uttar Pradesh, namely Hind Flying Club with head quarters at Lucknow and a branch at Kanpur.

(b) Government of India are not aware of any such proposal.

(c) Does not arise.

Efflux of Indian Scientists to America

*1479. **SHRI KAMESHWAR SINGH:**
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the U.S. Panel's concern at the inflow of Scientists from India ;

(b) if so, the measures taken by Government to check the outflow from India ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) The question presumably refers to a news item entitled "Brain Drain from poorer Nations alarms U.S.A." appearing in the Statesman on March 31, 1968. No precise information is available with Government.

(b) and (c). Indian nationals with scientific and technical qualifications go abroad for advanced studies, study-cum-employment and employment and there is no general ban on this.

A number of steps have been taken to facilitate return of scientific and technical personnel to India. A statement regarding these is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT-1051/68].

C.S.S Officers

*1480. **SHRI YAJNA DATT SHARMA:**
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 45 posts of Deputy Secretary (Selection Grade) and 375 posts of Grade I provided for the C.S.S. Officers were sanctioned in 1955 and 1959 respectively and since then no increase has been made in the numbers in spite of huge expansion of the set-up of the Central Secretariat in the past 12 years ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to review the strength of Selection Grade and Grade I of the C.S.S. taking into consideration (i) the expansion in the Central Secretariat (ii) the fact that C.S.S. officers have avenues of promotion outside the Secretariat and (iii) that all

other organised Services have balanced cadres ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The authorised permanent strength of Grade I of the C.S.S., which was refixed at 375 in 1959, has been reviewed every year there after, but the reviews did not justify and further increase. The review of the authorised permanent strength of this Grade, as on 1st May, 1967, is presently in hand.

The question of review of the authorised permanent strength of the Selection Grade of the C.S.S. is also being considered.

दिल्ली के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र को विदेशी सहायता मिलना

1481. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री टी० पी० शाह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक को विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सहायता का ब्योरा क्या है और समाचार-पत्र का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (घ). गुप्तवार्ता विभाग ने पिछले ग्राम चुनाव में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के उपयोग के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन की अभी जांच की जा रही है।

**Bridge over Rupnarain River at
Kolaghat**

*1482. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) when the newly constructed road bridge at Kolaghat on the Rupnarain river was opened for traffic ;

(b) whether some minor works of construction are still going on ;

(c) the original estimate for construction and whether the estimate was revised; and

(c) if so, the final cost of the construction ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) :
(a) On the 3rd of December, 1967.

(b) Yes, Sir ; only the work on the staircases is still in progress.

(c) The original estimate for its construction amounted to Rs. 112.21 lakhs. No revised estimate has been received from the State Government so far, but it is understood that it is likely to be Rs. 136.00 lakhs approximately.

(d) The final cost will be known only after the accounts are closed finally.

**Proposed visit to India by Pilots
of Pakistan Airlines**

*1483. SHRI N. K. SANGHI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some pilots of the Pakistan Airlines were to visit India, on or about the 20th of March, 1968, at the invitation of their counterparts in the Indian Airlines Corporation and that it had to be cancelled at the last moment ; and

(b) if so, the purpose of the proposed visit and on whose initiative the visit was proposed ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Indigenous Aircraft Industry to augment
the I.A.C. Fleet**

*1484. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have taken any policy decision to rely on the indigenous aircraft industry for supply of aircraft required for use in the I. A. C. ;

(b) if so, the steps taken to modify the types of aircraft produced at the Hindustan Aeronautics Ltd. to the standards required for use in the I.A.C. ; and

(c) how many aircraft produced at the H. A. L. are proposed to be acquired by the I.A.C. for augmenting its fleet during 1968-69 and 1969-70 ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):
(a) and (b). Indian Airlines have placed orders for the purchase of 14 HS-748 aircraft, which are suitable for use without any modifications.

(c) Five aircraft each are expected to be received during 1968-69 and 1969-70.

**Central Inland Water Transport
Corporation**

*1485. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) the States where the Central Inland Water Transport Corporation is running transport services ; and

(b) the total mileage covered by the Corporation so far ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The Corporation is providing light-erage and ferry services and pleasure cruises on holidays within the Calcutta Port. In Assam, the Corporation has been entrusted by the State Government with the Jogihopa-Pancharatna Ferry from the 1st April, 1968. Subject to availability of traffic, the Corporation also provides goods transport services in Assam by river between Dhubri and Dibrugarh, a distance of about 710 kms.

साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जांच आयोग

*1486. श्री यशपाल सिंह :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) अभी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलाहाबाद के मुसलमान निवासियों से जापन

*1487. श्री सरजू पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद के मुसलमान निवासियों से एक जापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापन में लगाये गये आरोपों की जांच कर ली गई है; और

(ग) उसमें क्या आरोप लगाये गए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार ने श्री एम० लाल, सदस्य, राजस्व बोर्ड, को इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के कारणों तथा प्रसारण पर जांच करने के लिये नियुक्त किया है ।

(ग) मुख्यतः आरोप पुलिस तथा न्यायाधिकारियों के पक्षपात-पूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में है ।

Communal Riots in Tinsukia, Assam

*1488. SHRI HEM BARUA :
DR. SURYA PRAKASH
PURI :

SHRI SHIV KUMAR
SHASTRI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that communal rioting broke out recently in Tinsukia, Assam : and

(b) if so, the number of people killed and injured in the incident as also the measures taken by Government to prevent such incidents taking place in a border State like Assam ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
(SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) No one was killed in the riots. Information regarding the number of persons injured is being collected. The State Government have issued necessary instructions to the local officers emphasising the need for constant vigilance and to take adequate preventive measures and firm action to keep communal and anti-social elements under check. The police have registered 48 cases and arrested 273 persons in connection with the disturbances in Tinsukia.

"Farmer's League"

*1489. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Nasik Zila Parishad has drawn Government's attention/passed a resolution against the organisation like "Farmer's League" (translation from Marathi) sponsored by foreign missions ;

(b) whether the Chief Minister or any other Minister of Maharashtra has given any assurance to the Maharashtra Legislature in regard to no extension of missionaries visa permits ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A
resolution passed by the Nasik Zila Parishad stating, *inter alia*, that the activities of the Maharashtra Shekari Mandal, Manmad, and Maharashtra Prabodhan Mandal, Nasik, and all their sub-branches should be immed-

diately stopped, has been received by the Government of Maharashtra.

- (b) No, Sir.
(c) Does not arise.

Voting Rights for Kashmiris

*1490. SHRI INDER J. MALHOTRA:
SHRI BAL RAJ MADHOK :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

- (a) whether it is a fact that there are thousands of people in Jammu and Kathua Districts of Jammu and Kashmir State who have no voting rights to participate in the elections to the State Assembly, but have for Lok Sabha ;
(b) if so, the reasons therefor ; and
(c) the action Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
(SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). For Parliamentary constituencies, the qualifications of voters are the same in Jammu and Kashmir as in the rest of the country. For elections to the Jammu and Kashmir Assembly, under the State Law, voting rights are restricted to permanent residents ; there is no proposal to change this.

Complaint About 'Big Money' Causing Defections

*1491. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

- (a) whether Government are aware of the frequent complaints made by political parties about the use of 'big money' for causing defections in different State Assemblies ;
(b) whether a Madhya Pradesh M.L.A. made a disclosure in the Assembly throwing a bundle of currency notes on its floor to the effect that he was induced to defect in favour of the Congress by the offer of that money ; and
(c) if so, whether Government propose to ask the Committee of Members of Parliament to deal with the problems of defection to enquire into these allegations ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
(SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) Government are aware of the complaints regarding the methods adopted for securing defections in different State Assemblies.

- (b) Facts are being ascertained.
(c) No, Sir.

School Text Book

*1492. SHRI SITARAM KESRI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

- (a) the number of States that have nationalised School Text Books ;
(b) whether complaints have been received of factual errors in the text books and of using the text books for political ends by the State Governments ; and
(c) if so, the steps proposed to have uniform text books all over the country ?

THE MINISTER OF EDUCATION
(DR. TRIGUNA SEN) : (a) All State Governments except Gujarat have nationalised text books production at various stages of school education and in varying degrees.

(b) Complaints were received that some of the textbooks, prescribed for schools in certain States, contained objectionable passages. A Committee to examine this issue has been set up and its report is awaited.

(c) The national Council of Educational Research and Training has a programme of preparing model textbooks in different subjects, and making them available to the State Governments for adoption and adaptation. Some of the State Governments have already prescribed the textbooks prepared by National Council of Educational Research and Training. This includes the Central Board of Secondary Education, Delhi and Delhi Administration.

Indian School of International Studies

*1493. SHRI RABI RAY : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

- (a) whether his attention has been drawn to a news report in 'Patriot' of the 4th April, 1968, that his Ministry is likely

to review early next year the work and programme of the Indian School International Studies ;

(b) if so, whether an expert committee is going to be appointed for the purpose ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b). I have seen the news report. As the Estimates Committee of the Parliament has recently reported on the School, there is no proposal to further review its work through the appointment of an expert Committee.

(c) Does not arise.

University Centre at Rohtak

*1494. **SHRI BENI SHANKER SHARMA :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up a University Centre at Rohtak is under consideration ;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) the stage at which the matter stands at present ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b). The University Centre is already functioning since August, 1966 at Rohtak for post-graduate teaching in English, Economics, Political Science and Hindi.

(c) Does not arise.

India-Africa Shipping Service

*1495. **SHRI BABURAO PATEL :** Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) the number of ships of the shipping Corporation that ply between India and Africa ;

(b) the number of passengers carried annually both ways on the above ships and the amount of revenue collected annually during the last three years ;

(c) whether it is a fact that the passengers on these ships are not given good treatment apart from numerous

discomforts which they have to undergo ; and

(d) if so, the measures taken to lessen the distress of the passengers ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) to (c). A statement is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT 1052/68]

'Jehad'

*1496. **SHRI R. S. VIDYARTHI :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the Pakistani Book entitled 'JEHAD' containing matter likely to promote feelings of enmity between Hindus and Muslims of India and also material prejudicial to the safety and security of India, being sold in the open market throughout the country ; and

(b) if so, the steps taken by Government to stop its sale in India ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). The information gathered so far from the State Governments and Union Territory Administrations does not indicate that the book entitled "Jehad" is being openly sold. A book with that title, written by Khawaja Syed Mehboob Shah Sahib Mahdes Hazarvi, was declared forfeited by the Central Government in their order dated the 7th July, 1966. Another book with same title, written by Mufti-Azam Pakistan Hazrat Maulana Mohammud Shafi Sahib, declared forfeited by the Government of Punjab in their notification dated 29th March, 1968. This notification has been sent to other States and Union Territories for taking necessary action. A copy each of the order and the notification is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT 1053/68]

Instructions have been issued to the Customs authorities for preventing import into India of copies of these two books.

Collection of Road-Tax in Delhi

8538. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) the average number of people standing in queue at ten O'clock in the morning at each of the collection booths for payment of road tax for motor vehicles in Delhi for the year 1968-69 ;

(b) the reasons for which Government discontinued collection of road taxes through Patrol Filling Pumps and whether any assessment has been made of the suffering of the tax payers since the above practice was given up by Government ;

(c) the total number of motor vehicles for which road tax was collected in Delhi during the year 1967-68 and the total number of motor vehicles for which this tax is expected to be collected in 1968-69 ; and

(d) the steps Government propose to take to set the matters right ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) :

(a) 5 to 35

(b) According to the Delhi Administration, which is responsible for collecting road tax, the petrol filling pumps themselves discontinued collection of road tax, on behalf of their customers.

(c) The total number of vehicles, for which road tax was collected in 1967-68, was about 1,07,000. The number of vehicles, for which tax is expected to be collected during 1968-69 is 1,15,000.

(d) According to the report received from the Delhi Administration, 84 counters have been opened for the collection of motor vehicles tax in Delhi, a system of issuing 'tokens' has been introduced to reduce the queues ; tents have also been provided for the convenience of the taxpayers ; the collection centres are supervised by the senior officers of the Directorate of Transport and, when there is heavy rush at any counter ; arrangements are made to immediately start another counter by its side.

Strike by Students of Indian School of Mines

8539. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the strike by the students of the Indian School of Mines is still going on;

(b) if so, their demands;

(c) whether these demands are being considered by Government; and

(d) if so, the steps being taken by Government to bring to an end to the present strike ?

THE MINISTER OF EDUCATION (Dr. TRIGUNA SEN) : (a) The student were still on strike when the school closed for summer vacation on 1-4-1968.

(b) and (c) : A statement is laid on the table of the house [Placed in library. See No. LT-1054/68]

(d) The representatives of the students who saw the officers of the Ministry of Education, were told about the steps taken to meet their demands. The representatives stated that, on their return to Dhanbad, they would advise their colleagues to call off the strike.

Conference of Presiding Officers of Legislative bodies in India

8540. SHRI PRAKASH VIR
• SHASTRI :
SHRI NATH PAI :
SHRI S. S. KOTHARI :
SHRIMATI TARKESHWARI
SINHA :
SHRI BHOGENDRA JHA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of Presiding Officers of the Legislative Bodies in India was held in New Delhi recently ;

(b) if so, the important decisions taken at the Conference ;

(c) the extent to which Government agree to the said decisions; and

(d) the action being taken to give statutory shape to the said decisions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Yes, Sir.

(b) A copy of the resolution passed by the Conference is Laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1055/68]

(c) and (d) : The resolution is being carefully considered.

Boat Accident near Calcutta

8541. SHRI JYOTIRMOY BASU:
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six persons were drowned in a country boat ferry in Jagatdal near Calcutta recently;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take over these ferries and introduce modern river crafts for speed and safety ; and

(d) whether the Central Water Transport Corporation will consider the take-over of these services ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (Dr. V. K. R. V. RAO) :

(a) and (b) : The Government of West Bengal have reported that Chandernagore-Ranirghat country boat ferry, between Hooghly and 24-Parganas Districts, capsized at about 0830 hours on the 14th April, 1968. The boat was carrying 30 passengers and was not overloaded. One dead body was recovered. 18 persons were rescued from water, 8 persons swam ashore and 3 persons are still missing. This ferry is being run under the supervision of the District Magistrate, 24-Parganas. The preliminary enquiries into the accident conducted by the Government of West Bengal do not indicate any lapse.

(c) The Government of West Bengal, considering the possibility of replacing the existing country craft with sails by powered boats; which are less susceptible to storms and gusty winds.

(d) The Central Inland Water Transport Corporation are not considering the question of taking over these services at present.

Arrests of Hippies

8542. SHRI BABURAO PATEL :
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number and names of foreign tourists and Hippies who were arrested in 1967 under the Excise act, Arms Act, etc. for possessing contraband narcotics, drugs and arms and for committing immoral act ;

(b) the result of the cases filed against each of the arrested persons ;

(c) whether it is a fact that these foreigners smuggle various narcotics and drugs and hawk them in the streets of the cities and indulge in various immoral activities ; and

(d) if so, the steps taken by Government to ban their illegal and immoral activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) and (b). The information so far received from various State Governments and Union Territories is furnished in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1056/68]. The information from the remaining States is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) From the available information, it is gathered that foreigners/hippies were arrested mostly for being in possession or selling charas and ganja. No instance of their selling these articles by hawking in the streets of the cities has come to the notice of Government.

(d) In Delhi a special drive was carried out to check the papers etc. of tourists particularly "Hippies" who were suspected to be indulging in such activities. A general watch is also being maintained on such activities.

Kolhapur Airfield

8543. SHRI BABURAO PATEL :
Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the total cost of the proposed scheme to construct an all-weather airfield at Kolhapur for Indian Airlines Corporation and the date by which it is expected to be ready ;

(b) the cost and result of the soil testing done by the Central Water and Power Commission in this regard ;

(c) the number of administrative and other buildings proposed to be built and their estimated cost ; and

(d) the area and the estimated cost of the land proposed to be requisitioned with names of land owners ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) An all-weather aerodrome at Kolhapur is likely to cost Rs. 52 lakhs on a rough estimate. In view of the difficult resources position, this project is not likely to be given high priority. It is not, therefore, possible at this stage to indicate the date by which an aerodrome at Kolhapur may be ready.

(b) The results of the soil tests as well as cost thereof are awaited from the Central Water and Power Commission.

(c) It is proposed to construct a terminal building, garages and residential accommodation, at an estimated cost of Rs. 6.50 lakhs approx.

(d) The Central Public Works Department are carrying out survey in connection with the acquisition of land.

ईसाई धर्मप्रचारक

8544. श्री रामगोपाल शालबाले : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितने विदेशी धर्मप्रचारकों को उनकी गैर-कानूनी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण देश छोड़ने के लिये कहा गया; और

(ख) देश में किन किन विभिन्न स्थानों में विदेशी धर्म प्रचारक काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-मंडल पर रख दी जायगी ।

Central Reserve Police

8546. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the present strength of the Central Reserve Police ;

(b) the number of Scheduled Castes and Tribes separately therein in various grades ; and

(c) the steps taken to give adequate representation to these communities in this Police Force ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c) The percentage of members of the Central Reserve Police, belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to the total strength of the Force, as on the 1st January 1968 is as under :

Class	Percentage of members of Scheduled Castes	Percentage of Scheduled Tribes.
Class I	—	—
Class II	.62	—
Class III	9.94	3.43
Class IV	40.28	6.72
Total for the Force	12.26	3.66

The instructions about reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are applicable only to posts filled by direct recruitment or by promotion through Departmental competitive examinations. The majority of the Class I and Class II posts are filled through other sources and as such these instructions are not attracted in their cases.

The unit commandants who are the appointing authorities for the bulk of the Force, have been specially directed to recruit an adequate number of members of these communities, keeping in view the instructions of Government on the subject.

उत्तर प्रदेश के बान्दा जिले में हत्याये तथा डकैतियाँ

8547. श्री जगदेवर यादव : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बान्दा जिले में 1967

और 1968 के दौरान कितनी हत्याओं की गई तथा कितनी डकैतियां डाली गई और डकैतियों तथा हत्याओं की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त जिले में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ग्रह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बांदा जिले में सन् 1966 में हत्याओं तथा डकैतियों के 90 सत्य मामलों के मुकाबले में सन् 1967 के दौरान 87 सत्य मामले दर्ज किये गये ।

(ख) इन मर्दों के अधीन अपराधों की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में गस्त कड़ी कर दी है । ग्राम प्रतिरक्षा समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है तथा सशक्त बनाया जा रहा है । शस्त्रों के अवैध उत्पादन का पता लगाने के लिये समुचित प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के लिये राजस्थान को सहायता

8548. श्री भीठा लाल भीना : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को कुछ राशि देने के लिये सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और वह कब दी जायेगी; और

(ग) राजस्थान में शिक्षा की उपरोक्त योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार कब तक इस संबंध में अन्तिम निर्णय कर लेगी ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). शिक्षा के माध्यम में

परिवर्तन की सुविधा के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य के निर्माण हेतु, वित्तीय सहायता की योजना के अधीन, भारत सरकार 1967-68 से 6 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा तक जिसमें राजस्थान भी शामिल है, सिद्धान्त रूप में सहायता देने लिए राजी हो गई है ।

(ग) राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजना विचाराधीन है ।

आगोसी घाट पर यमुना नदी पार करने के लिये शुल्क

8549. श्री जगेश्वर यादव : क्या परिवहन तथा नौबहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला बांदा में आगोसी घाट पर यमुना नदी पार करने वाले लोगों से लिये जाने वाले कर को दर्शाने वाली सूची नहीं दिखाई जाती और ठेकेदार मनमाने ढंग से कर वसूल करता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले में जिला परिषद उपयुक्त घाट का प्रबन्ध करने के लिये उत्तरदायी है तथा उपयुक्त घाट का ठेकेदार उस परिषद के अधिकारियों से मिलकर काम कर रहा है;

(ग) क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौबहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री नरेश दर्शन) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Kidnapping Cases in Pak Border

8550. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistani intruders are committing murders and dacoities along the India-Pakistan border, and have already kidnapped Indian citizens, one from Coochbehar District and another from Delhi ; and

(b) the number of Indian citizens kidnapped during the last eighteen years, year-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) There have been instances of trans-border crime from time to time on the Indo-East Pakistan border. Recently one Indian was kidnapped on 5th March, 1968 and another on 26th March, 1968, from the Cooch Behar District of West Bengal. No Indian national has been kidnapped from Delhi.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Nicobarese Commercial Company,
Car Nicobar**

8551. SHRI HUKAM CHAND KACHWAL : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Nicobarese Commercial Company, Car Nicobar, is not liable to pay royalty on exports of copra and betelnuts from Nicobar Islands under exemption given in the Andaman and Nicobar Islands Protection of Aboriginal Tribes Regulation ;

(b) whether such royalty levied previously ran into lakhs of rupees and the actual amount of royalty collected annually ;

(c) whether Government propose to amend the Protection of Aboriginal Tribes Regulation to remove the lacunae in the levy of royalty on exports by tribal trading concerns ; and

(d) if not, what other measures Government propose to take to loss of royalty on exports from Nicobar Islands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Royalty on export of copra and betelnuts purchased from 'reserved areas' in the Nicobar Islands is levied by the Chief Commissioner on a licensee authorised to carry on trade or business in any such area under section 6(1) of the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956. The Nicobarese Commercial Company being partnership concern of tribals themselves is not required to take a licence under the said Regulation for carrying on any trade or business in Nicobar Islands. As such no royalty is being levied on this company.

(b) The amount of royalty recovered from M/s. Car Nicobar Trading Company, Car Nicobar during the year 1966-67 was Rs. 1,44, 613. 70 p.

(c) and (d). The Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation, 1956 was promulgated to provide for the protection of the interests of socially and economically backward aboriginal tribes in the Andaman and Nicobar Islands. As such, there is no proposal under consideration of the Government to amend the Regulation to levy royalty on the tribal trading concerns.

Microoliths

8552. SHRI C. CHITTYBABU : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some microoliths have been found in an exploratory trench at Selbalgiri village in Garo hills district of Assam ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the report of the Head of the Department of Anthropology of the University of Gauhati who conducted the excavation, a very rich Stone Age site yielding a large number of stone tools and pottery has been discovered. It includes a well-developed blade-and-flake industry, a microlithic industry besides a heavy tool industry of stone axes both ground and chipped.

Training to People Against Nuclear Attack

8553. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to train people against nuclear attack ;

(b) if so, the details of this scheme and from which date it will be implemented ; and

(c) whether Government have sufficient reasons to expect nuclear attack on the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (c). The question whether there is a possibility of nuclear attack on India, and if so, from which source and of what magnitude is being examined. Based on this assessment the feasibility of civil defence measures and their nature are proposed to be considered. The entire examination is yet in a preliminary stage.

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में नियुक्तियां

8554. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में अनुसंधान सहायकों तथा अन्य उच्च पदों के लिये सम्बन्धित विषयों का ज्ञान अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में कितने मामलों में इस नीति का पालन नहीं किया गया है ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों जैसे विषयों में शब्दावलि के कार्य के लिए आवश्यक पदों के हेतु विषय की योग्यताएं अनिवार्य हैं। अन्य पद निर्धारित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ऐसे मामलों में निर्धारित शैक्षिक

योग्यताओं में हिन्दी संस्कृत में मास्टर डिग्री शामिल है।

(ख) और (ग). अल्प अवधि की रिक्तियों जिन पर निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति अनिष्पन्न है, उन्हें छोड़कर अन्य विभिन्न पदों को भरने के लिए निर्धारित भर्ती नियमों से विचलित नहीं हुआ। काम को अस्त-व्यस्त होने से बचाने के लिए यह आवश्यक समझा गया था।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग में नियुक्तियां

8555. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को अनुसंधान सहायक (हिन्दी) के पदों के लिये चुना गया था तथा उन्हें वर्ष 1964 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग के हिन्दी विभाग में नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से शब्दावलि आयोग इन अनुभवही व्यक्तियों की सेवायें स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). 1964 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग के पास अपना अलग से कोई सचिवालय नहीं था। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने आयोग को उनके काम के लिये सचिवालय सम्बन्धी आवश्यक सहायता दी थी। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने संघ लोक सेवा आयोग के जरिये 1964 में कुछ अनुसंधान सहायकों (हिन्दी) की भर्ती की थी। वे अब भी सेवा में हैं। इस लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग द्वारा उन्हें स्वीकार करने में आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
हौशंगाबाद में प्राचीन मन्दिरों तथा मसजिदों की मरम्मत

8556 श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1968 में अब तक

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कितने प्राचीन मन्दिरों तथा मसजिदों की मरम्मत की गई है ;

(ख) इस अवधि में मरम्मत सम्बन्धी काम पर कितना खर्च आया है ;

(ग) क्या अब भी ऐसे प्राचीन मन्दिर तथा मसजिद हैं जिनकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है ? और

(घ) यदि हां तो उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ऐसे मन्दिर या मस्जिदें नहीं हैं जो केन्द्र द्वारा संरक्षित हों ।

**Old Monument in Kidwai Nagar
New Delhi**

8557. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that an old monument is situated in the heart of Kidwai Nagar, a Government residential colony in New Delhi ;

(b) whether the monument presents a dilapidated look and contributes to insanitary conditions in the area ;

(c) whether Government propose to beautify the said monument and also maintain a proper garden there ; and

(d) whether Government propose to dedicate it to the memory of the late Rafi Ahmed Kidwai in fulfilment the desire of the residents of Kidwai Nagar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. The monument is in a fair state of preservation.

(c) No, Sir. The monument is surrounded by asphalted roads on all sides except for a small strip of land around the platform. It is not possible to develop any garden worth the name in such a small space.

(d) No, Sir. This Ministry is not

aware of any such proposal from the residents of the colony.

**Directors of National Laboratories/
Institutes**

8558. SHRI KASHI NATH PANDEY: Will the Minister of EDUCATION be pleased to lay on the Table a statement showing the amounts received as Consultation Fee or Royalty by the Directors and officials of the National Laboratories and Institutes under the control of the Council of Scientific and Industrial Research from Industrial concerns in the private sector during the last few years ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में पराठों पर बिक्री कर

8559. श्री हरदयाल देवनुराण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सरकार से सिफारिश की थी कि पराठों पर से बिक्री कर खतम किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). साधारण 'पराठों' को दिल्ली में बिक्री कर से छूट मिली हुई है। भरे हुए मसालेदार पराठे को बिक्री कर से छूट देने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**Foreign aid to Individuals and Parties
for Political Purposes**

8560. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there are any legal or financial restrictions on foreign countries giving aid to individuals or parties in this country for political purposes ; and

(b) if not, the steps taken by Government to check foreign interference in the internal affairs of this country through this process ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). It would be a violation of the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, for the Indian national to receive remittance from abroad except through the authorised dealers, namely, banks handling exchange transactions. This, however, applies to the means through which remittances are received and not the purposes for which such remittances are received. The general question of the use of foreign money in the last general elections and for other purposes is being considered on the basis of the report of the Intelligence Bureau.

Arable Land in Imphal Cantonment

8561. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Imphal Cantonment area occupied by the 4th Bn. Assam Rifles in Manipur has a big arable land popularly known as 'Khuman Lamhang' and whether the land is kept unused for the last many years ;

(b) if so, whether the land is being made available to the local people for cultivation purposes ; and

(c) if not, the reasons for keeping it unused ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). A piece of land known as 'Khuman Lamhang', measuring 140.67 acres, situated west of Imphal river in the Imphal Town area, which was being used for training purposes by the Assam Rifles, has been transferred to the Government of Manipur on the 19th February, 1968.

Of this land, thirty five acres have been allotted by the Government of Manipur for the construction of a stadium and five acres for the Government Press. The remaining land is proposed to be utilized after development for the construction of

buildings for the accommodation of Government offices and for the expansion of Imphal Town.

Delhi Transport Undertaking

8562. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) the number of cases of breakdown of Delhi Transport Undertaking buses in 1967 ;

(b) the number of such cases during the current year so far ; and

(c) the steps taken to reduce the number of breakdowns ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) 65,143.

(b) 13,630 (upto 31-3-1968).

(c) The following steps are being taken by the Delhi Transport Undertaking to improve the situation :—

(i) Efforts are made to improve the maintenance of vehicles.

(ii) The functioning of 14 maintenance points on the line has been made more efficient.

(iii) In order to cope with an increasing number of tyre punctures on line, a special squad for supply of tyres has been set up.

Central Mining Research Station

8563. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the working of the Central Mining Research Station has been reviewed ;

(b) whether the research conducted at this Station has been of practical help to the Industry ; and

(c) the total amount spent on research work done at this Station ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) The working of the Central Mining Research Station was last reviewed by the Third Reviewing

Committee of the C. S. I. R. in 1963. Progress of work of the Station is continually done by its Executive Council and Scientific Sub-Committee which meet normally twice a year.

(b) The work carried out in the various Divisions/Sections of the Station has been practical help to industry. Details of the research work of the Station are given in the Annual Reports of the C. S. I. R., copies of which are laid on the Table of the Lok Sabha every year.

(c) The amount spent on research work, including expenditure on infra-structure, from inception of the Station i.e. 1955-56 to 1967-68 is given below :—

(Rupees in lakhs)

Sl. N.	Budget head	Amount
1.	Recurring	158.716
2.	Capital	72.437
	Total	231.153

रायपुर-जगदलपुर राजमार्ग

8564. श्री लखन लाल गुप्ता : क्या परिवहन तथा नौबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायपुर से जगदलपुर की सड़क एक राष्ट्रीय राजपथ है,

(ख) क्या इस सड़क की नदी क्रासिंगों पर भारी यातायात के लिये पुल बनाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से एक पुल नन्दन मारा झरनी हल्त में नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर यातायात में कठिनाई अनुभव की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो पुराने पुल के स्थान पर एक नया पुल कब तक बन जायेगा ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अमृत बर्शन) : (क) जी हां । रायपुर-जगदलपुर अनुभाग रायपुर-विजयनगर मार्ग, राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 43 का भाग है ।

(ख) सड़क पर मौजूदा पांच पुल कमजोर और संकरे हैं इन में से चार पुलों के

राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग मानक के पुलों द्वारा पुनर्स्थापित किये जाने की मंजूरी दे दी गयी है । इन में से दो पुल निर्माण की अग्रिम अवस्था में है । चतुर्थ योजना के अधीन राष्ट्रीय मुख्य-मार्ग के अवाटनों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद पांचवें पुल के पुनर्निर्माण की परियोजना पर विचार किया जायेगा ।

(ग) और (घ). जी हां । नन्दनमारा नदी पर नये पुल के निर्माण के जून 1969 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में महानदी पर पुल

8565. श्री लखन लाल गुप्ता : क्या परिवहन तथा नौबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में राजीव और नवपाड़ा स्थानों के बीच महानदी पर एक पुल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पुल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अमृत बर्शन) : (क) प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ेगा । मध्य प्रदेश सरकार ने जो मुख्यतः जिम्मेदार है, अभी तक उसके निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Development of Andaman and Nicobar Islands

8566. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether proposals for speedy development of Andamans and Nicobar Islands were placed before the Prime Minister during her second visit to the Islands ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). On her visit to the Andaman and Nicobar Islands in February this year, the Prime Minister was made aware of the proposals for the development of these islands both by the Administration as also by the representatives of the public. The Prime Minister took note of the work being done and was anxious that the proposals pending finalisation should be decided and implemented speedily. Necessary action in this behalf is being taken by the Andaman and Nicobar Administration in its various departments.

Land for Academy of Fine Arts, Calcutta

8567. SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI C. K. CHAKRAPANI :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) how much land has been given to the Academy of Fine Arts, Calcutta by the Central Government ;

(b) the specific terms and conditions re. this land allotment ; and

(c) whether Government have any machinery to ensure compliance of the said terms and conditions ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) No land has been given by the Central Government to the Academy of Fine Arts, Calcutta.

(b) and (c). Question do not arise.

लद्दाख पर पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित हुए व्यक्तियों को प्रतिकर

8568. श्री कुशोक बाकुला : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान ने लद्दाख क्षेत्र में आक्रमण किया था और वह भारतीय राज्य क्षेत्र में बहुत दूर तक घुस आया था उस समय वापस लौटते

समय पाकिस्तानी भारतीय लोगों का सामान उठा ले गए थे और लद्दाख के 'शैम' तथा 'जंकर' इलाकों से ढोरों को भी भगा ले गए थे ;

(ख) यदि हां तो क्या उन भारतीय परिवारों को जिनका सामान पाकिस्तानी उठा ले गए थे मुआवजे के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितना मुआवजा दिया गया था और किसके माध्यम से दिया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन परिवारों को मुआवजे के रूप में धन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 3 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी लेकिन राज्य सरकार ने उसे (उपरोक्त राशि को) नहीं देने दी थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) से (ङ). चूंकि प्रश्न बीस वर्ष पुरानी घटना के बारे में है, विवरण तत्काल प्राप्त नहीं है। विवरण एकत्रित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पाकिस्तानियों द्वारा बाइमेर में एक ट्रक का पकड़ा जाना

8569. श्री श्रींकार लाल बेरवा : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सब है कि पाकिस्तानियों ने राजस्थान की सीमा पर बाइमेर में 29 मार्च की रात को पांच व्यक्तियों समेत एक ट्रक को पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस ट्रक और उन व्यक्तियों को छुड़वाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख). एक सिविलियन ट्रक जिसमें 5 व्यक्ति थे, भूल से 21-22 मार्च, 1968 की रात को गडरा शहर के समीप जब पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस गया था तो पाकि-

स्तानियों द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। तथापि स्थानीय सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ट्रक और उसके 5 व्यक्तियों को 29 मार्च, 1968 को मुक्त करा लिया गया।

Offensive Plan by Hostile Nagas and Mizos

8570. SHRI M. L. SONDHI :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:
SHRI RAGHUBIR SINGH
SHASTRI :
SHRI JUGAL MONDAL :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the rebel Nagas and Mizos are planning a concerted offensive in June in Nagaland, Manipur and Mizo hills; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to meet the situation arising out of this strategy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Government have no such definite information. However, Security Forces are maintaining vigilance and are alive to all possible threats to the security of the country.

Nizam of Hyderabad

8571. SHRI M. N. REDDY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 836 on the 25th March, 1968 and state:

(a) the exact date on which the lists of Private properties were furnished by the late Nizam of Hyderabad and also the dates on which these lists were scrutinized by the then State Government;

(b) the names of the then members of the State Government of Hyderabad (Cabinet Ministers) during whose period the lists were scrutinized and discussions were held by the Central Government; and

(c) the dates or datef on which the Central Government held discussions with the then State Government of Hyderabad on the above lists ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (c). Government do not consider it proper that details relating to the settlement of private property of Rulers should be a matter for public disclosure.

(b) A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-1057/68]

Bomb Explosions in Calcutta

8572. SHRI DEIVEEKAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons were injured and other killed when two bombs burst in central Calcutta on the 29th March, 1968;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted;

(c) whether it is also a fact that two more bombs were recovered from the same place; and

(d) if so, the steps taken to check this increasing incidents of bomb explosions in Calcutta ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Assam-Nagaland Boundary Dispute

8573. SHRI DEIVEEKAN :
SHRI ANBUCHZHIAN :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI SITARAM KESRI :
SHRI H. AJMAL KHAN :
SHRI MEETHA LAL MEENA :
SHRI GIRRAJ SARAN SINGH:
SHRI K. M. KUSHIK :
SHRI O. P. TYAGI :
SHRI RAM GOPAL SHALWALE,

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a boundary dispute between the Assam and Nagaland Governments;

(b) if so, whether recently the Nagaland Government forcibly burnt certain houses in Assam villages ;

(c) if so, whether some parts of Assam have been forcibly taken over by them; and

(d) whether the Centre has been asked to intervene in the matter in view of gravity of the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the information received from the Government of Assam, the Chief Minister of Assam had stated in the State Assembly on 30th March, 1968, that about 200 houses in the Doyang reserve had been burnt down by Nagaland police. On the other hand, the Government of Nagaland have reported that 258 labourers who had been brought to Pangtong village from the plains on Inner-line permits and who were refusing to leave the State on the expiry of the permits were evicted by the Nagaland police as the State Government decided not to extend the permits.

(d) The Assam Government have taken up the matter with the Nagaland Government.

Curfew in Parts of Assam

8574. **SHRI DEIVEEKAN :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that curfew was reimposed on the 30th March, 1968 in certain parts of Assam ;

(b) if so, whether communal troubles are still being created by Pakistani agents there ; and

(c) what assistance Centre has assured to Assam Government to maintain law and order in the State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Curfew was imposed at Tinsukia on 30th March to help maintenance of law and order. It continued on 31st March and partially on the 1st of April.

(b) The State Government have intimated that there is no evidence upto now

to indicate existence of any hand of Pakistani agents.

(c) The State Government's resources of Armed Police have been reinforced by the Government of India to the extent possible.

Special Cell to Expedite Hotel Projects in India

8575. **SHRI DEIVEEKAN ;
SHRI ANBUCHAZHIAN ;
SHRI CHENGALRAYA
NAIDU :**

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Federation of the Hotel and Restaurant Association of India have suggested to Government for the setting up of a special cell to expedite the hotel projects in India ;

(b) the other suggestions made by the President of the Association ; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir. The Federation of Hotel and Restaurant Associations of India at its annual Convention held at Madras in April, 1968 has passed such a resolution.

(b) Other resolutions passed at the meeting relate to (i) making available hotel sites at reasonable rates, (ii) incentives and facilities to be given to the hotel industry, (iii) issue of import licences, (iv) safeguarding the interests of hotels and restaurants located in rented premises, (v) liberalization of Prohibition rules, (vi) reduction in excise fees, (vii) meeting the ration requirements of new hotels and restaurants, and (viii) reconsideration of the Government decision in regard to certain projects.

(c) These will be examined when they are formally referred to the Government.

सेंट्रल स्कूल, दानापुर, बटना

8576. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल स्कूल, दानापुर बटना

(पटना) में कितने लड़के तथा लड़कियां पढ़ते हैं;

(ख) उनमें से कितने उर्दू भाषा भाषी हैं;

(ग) क्या उर्दू भाषा भाषी इन विद्यार्थियों को उर्दू सिखाने की कोई व्यवस्था है तथा इस प्रयोजन के लिए इस स्कूल में अध्यापक नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) : 374 लड़के और 234 लड़कियां ।

(ख) से (ग). उर्दू भाषा भाषी विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय स्कूलों के एकरूप पाठ्य-क्रम में कुछ समय के लिए शास्त्रीय भाषा संस्कृत सिखाने के साथ-साथ केवल हिन्दी और अंग्रेजी के पढ़ाने की व्यवस्था है। अन्य मातृ भाषाएं पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है अतः उर्दू सिखाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी स्कूल में काफ़ी तदाद में ऐसे विद्यार्थी हैं जो कोई और भाषा सीखना चाहते हैं, तो संगठन संबंधित अध्यापक (अध्यापकों) की तनख्वाह का आधा खर्च बरदाश्त करने को तैयार है।

साम्प्रदायिक दंगे

8577 श्री रामाबतार शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 से अब तक भारत में कितनी बार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं;

(ख) उनमें कुल कितने व्यक्ति मारे गये;

(ग) इस प्रकार मारे गये व्यक्तियों में अल्प-संख्यक (मुसलमान) जाति के व्यक्ति कितने थे;

(घ) इन दंगों में कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) अल्पसंख्यक जातियों के व्यक्तियों की कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों तथा दिल्ली नगर निगम के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही

8578. श्री शारदानन्द :

श्री रणजीत सिंह :

श्री कंबर लाल गुप्त :

श्री बृज भूषण लाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के जिस पदाधिकारी के विरुद्ध हाल में पुलिस ने कार्यवाही की है उसका नाम क्या है, उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं तथा पुलिस ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगर निगम के एक सदस्य के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस सदस्य का नाम क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 9 के अधीन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के अधीन जारी की गई निषेधात्मक आज्ञा की अवज्ञा में श्रोताओं को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाने के आरोप लगाये गये थे। पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण मामला समाप्त किया गया है।

(ख) जी, हां, श्रीमान् ।

(ग) श्री राम लाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 436/115 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। उन पर ये आरोप लगाये गये हैं कि उन्होंने सीमापुरी बस्ती के निवासियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए उकसाया था।

Disposal of Leave Applications of Governments Servants

8579. SHRI MANGALATHUMADAM : (a) whether it is a fact that Government servants wishing to proceed long leave to their home towns availing travel concession, are harassed and put to great inconvenience by the Departments concerned in disposing of their leave applications ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) No such instances have been come to the notice of the Home Minister.

(b) Does not arise.

बुलन्दशहर में मकानों का अनधिकृत निर्माण

8580. श्री ब्रह्मानन्दजी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री टी० पी० झाहू :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर के जिला मजिस्ट्रेट के पास बुलन्दशहर तहसील के पाबसारा गांव की ग्रामसभा के कन्या स्कूल के स्थान पर, ग्राम सभा के प्रधान की साजिश से अनधिकृत रूप से मकान बनाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नायब तहसीलदार ने अनधिकृत निर्माण की शिकायतें जांच कर जांच की थी; और

(ग) यदि हां, तो अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। अनधिकृत निर्माण के संबंध में एक शिकायत बुलन्दशहर कलकटरी में 22 मार्च, 1968 को प्राप्त हुई थी। ग्राम सभा के प्रधान की दुरभिसंधि सिद्ध नहीं हो सकी थी।

(ख) नायब तहसीलदार ने जांच की और रिपोर्ट दी कि दो व्यक्ति भूमि पर अनधिकृत निर्माण में लगे हुए थे।

(ग) ग्रामे निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है और बेदखली का मुकदमा शुरू कर दिया गया है।

Unemployment Among Town Planners and Architects

8582. SHRI ANBUCHZHIAN :
SHRI CHENGALRAYA
NAIDU :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute problem of unemployment among the Town Planners ;

(b) the number of such persons annually qualifying the two-year course of Planning and Architecture ;

(c) whether it is a fact that Planning Commission in their report had mentioned that 2,000 town planners would be provided jobs during the Fourth Plan period ; and

(d) if so, how far this has proved true ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR, TRIGUNA SEN) : (a) According to the Directorate General of Employment and Training, only 5 Town Planners were on the live registers of employment exchange on 31-12-1967.

(b) According to the reports received from institution, 51 persons qualified as town planners in 1967.

(c) and (d). According to the Committee of Planning Ministers, the demand for Town Planning personnel at various

levels for 1966-1975 was estimated as 2,100 some years back. Since the revised Fourth Plan has yet to be formulated, no precise estimates are available at this stage of the requirements for town planners during the plan period.

साम्प्रदायिक दंगे

8583. श्री महाराज सिंह भारती : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितने स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए थे तथा इन साम्प्रदायिक दंगों में से कितनी घटनाओं में विदेशी तत्वों का हाथ था; और

(ख) साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये राजनीतिक स्तर पर सरकार क्या उपाय कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय किया गया है जिसके निष्कर्ष साम्प्रदायिक शक्तियों को नियन्त्रण में रखने के उपाय खोजने में उपयोगी सिद्ध होंगे।

Chief Commissioner of Andaman and Nicobar Islands

8585. SHRI VISHWA NATH PANDEY : Will the Ministry of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands was recently involved in a contempt of court proceedings in the Calcutta High Court ;

(b) if so, the facts of the case ;

(c) the court's decision in the above proceedings ; and

(d) at what stage is the original writ petition of M/s. R. Akoojee Jadwet & Co. about their trading rights in the Nicobar Islands out of which the above contempt Proceedings arose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). In the wake of Government's decision that the licence of M/s. Nancowrie Trading Company need not be extended beyond 30-9-1967, the said company obtained an interim injunction from the Calcutta High Court in September, 1967 restraining the Andaman and Nicobar Administration from interfering with the trade and business of the company. However, to meet the needs of people in those islands, the Andaman and Nicobar Administration opened certain civil supply stores.. M/s. Nancowrie Trading Company moved the Calcutta High Court for contempt of the orders issued by the Court and as a result the High Court issued a rule asking the Administration to close the stores till the rule was decided. Later on, the Court made its rule absolute and fined the Chief Commissioner and the Deputy Commissioner rupees fifty each which was remitted by the Court on an oral apology tendered by the Solicitor General. An appeal has been filed in the Appellate side of the Calcutta High Court. The matter is *sub-judice*.

(d) The contempt of court proceedings arose in the case of writ filed by M/s. Nancowrie Trading Co. and not M/s. R. Akoojee Jadwet & Co. However, M/s. R. Akoojee Jadwet & Co. have filed a separate writ petition in the Calcutta High Court. In this case, no regular hearing of the writ petition has yet taken place though some interlocutory matters have been heard.

C. S. S. Grade I Association

8586. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 238 on the 18th August, 1965 to state :

(a) whether any reply has been sent to the C. S. S. (Gr. 1) Association in reply to the Resolutions passed by the Association in June, 1965 ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Being Resolutions, no formal reply was

sent by Government. The demands made by the Association were, however, discussed with their representatives in their meetings with senior officers of the Ministry.

Departmental Promotion Committees

8587. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that service matters of officers of all other Central Services like I. A. & A. S., I. D. A. S., Indian Postal Service are dealt with by the Officers belonging to these Services ;

(b) whether it is also a fact that in all Departmental Promotion Committees set up for higher appointments in the above Departments, majority of members belong to the administrative service concerned with a Member of the U. P. S. C. as Chairman ;

(c) whether it is also a fact that the above facility is not available to Officers of the Central Secretariat Services ; and

(d) if the answer to parts (a), (b) and (c) above in the affirmative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Smugglings of Foreign Goods into Mizo Hills

8588. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani gangs are busy in smuggling foreign goods into Mizo hills ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No reports of smuggling of foreign goods by Pakistani gangs into Mizo Hills have been received.

(b) Does not arise.

Regrouping in Mizo Hills

8589. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Villages in Mizo Hills have been regrouped ;

(b) if so, whether it has brought the desired result ; and

(c) the number of villages and persons that have come under regrouping ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) This measure has succeeded to a large extent in its objective.

(c) Between January and February, 1967, 100 villages involving a population of 45107 were regrouped into 18 centres.

Shiva Sena

8581. SHRI KANWAR LAL GUPTA: SHRI T. P. SHAH : SHRI MURASOLI MARAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri Bal Thakre, the Shiva Sena Chief, which appeared in the "Hindustan Times", dated the 4th April, 1968, in which he has denied that the capitalists are financing the Shiva Sena in Bombay ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) Enquiries have been made from the State Government. They have stated "There is a suspicion that the Shiva Sena Organization is being backed by local business interests. However no evidence is forthcoming to substantiate the allegations that the organization is being backed by capitalists".

सेंट्रल स्कूल, कोटा में अध्यापकों की कमी

8592. श्री ओंकार लाल बेरबा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों की कमी के कारण सेंट्रल स्कूल कोटा, राजस्थान, में विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार के वेतन मानों के अनुसार वेतन नहीं दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों के सभी अध्यापकों को संगठन द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के अनुसार वेतन दिए जाते हैं, जो पूर्णरूप से दिल्ली के वेतनमानों पर आधारित होते हैं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार

8593. श्री ओंकार लाल बेरबा : क्या गृह-कार्य मन्त्री 22 मार्च, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब-रजिस्ट्रार (भवन), दिल्ली के कार्यालय में इस समय कोई काम बाकी नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस कार्यालय (काश्मीरी गेट) में चौथे सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय के लिये जगह उपलब्ध है और कमरा संख्या 14-15 खाली पड़े हैं जहां चौथे सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो चौथे सब-रजिस्ट्रार के लिये एक अन्य कार्यालय खोलने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सब-रजिस्ट्रार (भवन) समेत सभी सब-रजिस्ट्रारों के कार्यालय में पर्याप्त मात्रा में कार्य लंबित पड़ा है । इस कारण तथा लोगों को असुविधा रोकने की दृष्टि से चौथे सब रजिस्ट्रार का कार्यालय खोला जा रहा है । काश्मीरी गेट स्थित सब-रजिस्ट्रार (भवन) के कार्यालय में कमरे खाली पड़े हैं तथा नया कार्यालय वहां अथवा अन्यत्र खोला जाए इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Accident Investigation Section

8594. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Accident Investigation Section is proposed to be taken out of the purview of the Director General of Civil Aviation and placed directly under the Ministry of Transport or under any other Ministry considered suitable ; and

(b) if so, the action taken in the matter so far ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) and (b). The question of separation of the Accident Investigation Branch from the organisation of the Director General of Civil Aviation, in implementation of a recommendation of the Estimates Committee, is under examination.

मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय

8595. श्री रामावतार शर्मा :

श्री रामगोपाल शालवाले :

श्री शशि भूषण बाबुपेयी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश

में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा यह कहाँ पर स्थापित होगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख). भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मध्य प्रदेश विधान सभा ने एक उप-स्ताव पास किया है कि राज्य सरकार को जब उसकी वित्तीय स्थिति अनुकूल हो जाए राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर पुल

8596. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन तथा नौबहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में अनूपशहर तहसील में गंगा नदी पर एक पुल बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पुल के निर्माण के लिये एक योजना तैयार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त वर्शन) : (क) और (ख). प्रस्तावित पुल उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुख्यतः जिम्मेदार है, सूचित किया है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने नरोरा के निकट निर्माणाधीन गंगा बांध के ऊपर सड़क यातायात के उपयोग के लिये एक सड़क पाटन के निर्माण की बंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन

8597. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन तथा नौबहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन की बुसन्दशहर और दिल्ली के बीच चलने वाली बसों में जैक आदि औजार नहीं दिये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस के खराब हो जाने अथवा पहिया पंचर हो जाने पर जैक आदि औजारों के न होने के कारण इन बसों के यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और

(ग) यदि हां, तो इन बसों के लिये जैक आदि उपकरण नहीं देने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त वर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला

8598. श्री जशवि भूषण वाग्पेयी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना व्यय किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राष्ट्रीय खेल कूद संस्था को ग्वालियर में स्थानान्तरित करने का है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क)

(i) 9 मास का नियमित पाठ्यक्रम 29

(ii) 9 मास का उपस्थिति पाठ्यक्रम 33

(iii) 4½ मास का संक्षिप्त पाठ्यक्रम 55

जोड़ : 117

(ख) 9 मास के पूरे पाठ्यक्रम पर 1967-68 के दौरान लगभग 6200 रुपये की गणना की गई थी।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Clash between Manipur Rifles and Hostile Nagas

8599. SHRI HEM BARUA :
SHRI HIMATSINGKA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a heavy exchange of fire took place between the Manipur Rifles and Naga hostiles on the 1st April, 1968 in the Southern part of Tamenglong Sub-division of Manipur ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). On the 1st April 1968, there was an exchange of fire between the security forces and the Naga hostiles near Nonei village in Tamenglong sub-division of Manipur for half an hour, after which the hostiles withdraw. There was no casualty on either side. A case has been registered by the Police.

Bomb Explosion in Shillong

8600. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a big bomb explosion in SHILLONG on the night of the 1st April, 1968 ; and

(b) if so, the details of the incident ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). On the night of 1st April, 1968, an explosion took place in a cinema hall under construction at Shillong. Some minor damage was caused to the southern wall of the building and glass panes of the doors of a car parked near the site were shattered. The total loss is estimated at Rs. 200/-. The case is under investigation.

Integration of three Sub-Division of Manipur with Nagaland

8601. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Naga National Organisation has demanded integration of the three cease-fire sub-Divisions of Manipur with Nagaland ;

(b) whether the Manipur Territorial Council has protested against this ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The Naga Nationalist Organisation, in Nagaland has been urging the integration of contiguous Naga areas with the State of Nagaland. The Prime Minister had received a telegram from the President, Manipur Congress expressing concern about press reports regarding the reported agreement between Naga Nationalist party and the Government of India about the merger of three Hill Sub-Divisions of Manipur with the State of Nagaland. There is no truth in reports that any agreement has been reached by the Government with the Naga Nationalist Party regarding these three Hill Sub-Divisions of Manipur.

अलमोड़ा में लाठी चार्ज

8602. श्री मधु लिमये : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1968 की रात को होली के अवसर पर अलमोड़ा में पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज किये जाने की और दिलाया गया है, जिसमें सेना का एक जवान, प्राविशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी का एक जवान तथा आम जनता के कुछ लोग घायल हो गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट अथवा मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना लाठी चार्ज किया गया था और पुलिस ने अपने आप लोगों को मारा-पीटा था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अल्मोड़ा में पुलिस द्वारा कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Recovery of Dead Body of a Woman

8603. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the news item published in the 'Indian Express' is true that a woman's dead body was recovered by the Delhi Police from Mundkar Nulla (Nangloi Mundka Railway Station) ;

(b) whether it is a fact that some person had killed the woman many days back and threw the dead body and that it had decomposed so much that it was difficult to recognise the same ; and

(c) if so, whether Government have looked into the matter and arrested the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The identity of the deceased and the cause of death could not be ascertained in the post-mortem examination as the dead body was in an advanced state of decomposition and bore no marks of injury.

(c) Enquiries are being made in the matter. So far none has been arrested.

Expenditure on Enquiry Commission into Mahatma Gandhi Murder Conspiracy

8604. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) since when the one-man commission is enquiring into the Mahatma Gandhi murder conspiracy ;

(b) the expenditure incurred on the said commission till the 31st March, 1968 ; and

(c) when the Commission is likely to submit its final report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The commission was set up on the 23rd March, 1965.

(b) From 23rd March 1965 to 31st March 1968 an expenditure of Rs. 46,109.12 Naya paise has been incurred.

(c) Efforts are being made to complete the work of the Commission by the 30th June, 1968.

पूर्व जम्मू के डोडा जिले में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

8605. श्री श्री० प्र० त्यागी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला की यात्रा की पूर्व संध्या को पूर्व जम्मू के डोडा जिले में पाकिस्तान फिफय कालमिस्टों (पाकिस्तान समर्थक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों) ने राष्ट्रपति अयूब खां के चित्र तथा पाकिस्तान समर्थक इश्तहार बांटे थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन राष्ट्र-विरोधी तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह सूचित किया गया है कि जनमत मोर्चा का एक कार्यकर्ता किश्तवार में राष्ट्रपति अयूब खां के चित्र बेच रहा था। इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी।

Functioning of Council of Scientific and Industrial Research

8606. SHRI D. C. SHARMA : SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to appoint a Committee of Members of

Parliament, Scientific experts and some others to go into the overall functioning of the Council of Scientific and Industrial Research and suggest ways and means of improvement wherever necessary ;

(b) if so, the constitution of the Committee, its terms of reference and scope of work ; and

(c) when it is likely to submit its report ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee is not constituted yet.

(c) Does not arise.

Intimidation of Loyal Teachers In Delhi

8607. **SHRI D. C. SHARMA :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether any cases of harrassment and intimidation of school children and loyal teachers by their colleagues, who joined the recent strike in Delhi, have been brought to notice of Government ;

(b) if so, whether the same has been inquired into ; and

(c) the steps taken in the matter.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Some ases of cthis nature were brought to the notice of the Delhi Administration.

(b) and (c). The cases were enquired into, but meanwhile with the improvement in the atmosphere in schools and gradual return to normalcy, the Administration did not consider it necessary to take action in individual cases. However, a circular letter was addressed by the Directorate of Education, Delhi Administration to the Principals of the Schools in connection with this matter.

All Party Meeting Against Anti-National Activities

8608. **SHRI SAMAR GUHA :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether Government propose to convene a meeting of all political parties

to jointly denounce anti-national and subversive activities of the Maoists, as exhibited through 'Mao-Tse-Tung Zindabad' slogans, posters in West Bengal, the Jorhat incident and to mobilize public opinion against them ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir. We are hopeful that nationalist opinion will assert itself, isolating those who are being influenced by a pernicious ideology.

(b) Does not arise.

Financial Aid to Olympic Association

8609. **SHRI SITARAM KESRI :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the Indian Olympic Association has approached Government for suitable financial aid to hold the 1970 Asian Games ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are unable to agree to the proposal.

Arrests of Employees of Chinese Embassy

8610. **SHRI RABI RAY :**
SHRI B. N. SHASTRI :
SHRI R. R. SINGH DEO :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Chowkidar and a Driver of the Chinese Embassy who were wanted for the alleged kidnapping of an Indian Policeman on the 6th March, 1968 were arrested on the 3rd April ;

(b) if so, their names and the charges against them ; and

(c) the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Two Indian employees of the Chinese Em-

bassy, namely, Kafil Ahmed, a Driver and Bir Bahadur, a Chowkidar, were arrested on 3rd April, 1968 in a case under Section 365 IPC on the charge of wrongful confinement of constable Ghanshyam Parshad of the Central Reserve Police.

हिन्दी में आदेशों का जारी किया जाना

8611. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों द्वारा मुद्रित करके अथवा साइकलोस्टाइल करके जारी किये जाने वाले ऐसे वार्षिक, त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक तथा ऐसी अवधि के बाद जारी किये जाने वाले जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाये निदेशों, आदेशों तथा परिपत्रों की संख्या कितनी है जो "सामान्य आदेशों" की श्रेणी में आते हैं; और

(ख) ऐसे कितने "सामान्य आदेश" केवल अंग्रेजी में जारी किये जाते हैं तथा उन्हें हिन्दी में जारी न किये जाने के क्या कारण हैं तथा राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन्हें जारी करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस सामग्री को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के तुल्य नहीं होगा। राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं।

विदेशी धर्मप्रचारकों के राष्ट्र विरोधी कार्य

8612. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आसाम में कुछ विदेशी धर्म प्रचारक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हुए पाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो 1968 में अब तक देश में कितने विदेशी धर्म प्रचारक पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दो को देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था।

Demand for Separate High Court for Manipur

8613. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Manipur Bar Association has submitted a memorandum urging Government to set up a separate High Court for Manipur in place of the present One-Judge Judicial Commissioner's Court ;

(b) whether the same has been considered ; and

(c) if so, the decision taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) It is not proposed to establish a separate High Court for Manipur.

Non-Assamese Central Government Employees in Assam

8614. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that non-Assamese Central Government employees are being harassed by the Assam Government, Assam Police and unsocial elements ;

(b) whether it is also a fact that not only the civilians but the military personnel who are non-Assamese are being harassed and several persons have been arrested without any offence being committed by them ;

(c) whether it is a fact that tension is still prevailing since the 26th January, 1968 disturbances ; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (d). Facts are being ascertained from the State Government.

Demands of Lachit Sena

8615. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Lachit Sena of Assam has demanded that 90 per cent of Jobs in State and Central Governments industries, both public and private, should be reserved for persons belonging to Assam and the same should apply to other States in the country ;

(b) whether they have also demanded that contracts, loans, licences for industries, trade and commerce, allotment of land, admission to educational institutions should be made only to Assamese ;

(c) whether these demands have been looked into ; and

(c) if so, with what results ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Lachit Sena has demanded that all employment either in the State or Central Government establishments must go to the Assamese people. It has also demanded that the State Government must provide sufficient land to the indigenous peasants.

(c) and (d). Government are making efforts to ensure balanced regional development but the demand to restrict employment opportunities in any State to the people of that State will not be in accordance with the Constitution.

Fires in Assam

8616. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether one person was killed and 72 families were rendered homeless by fires in different parts of Assam on the 30th and 31st March, 1968 ;

(b) if so, the estimated loss ;

(c) whether any Central assistance has been sought in the matter ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) and (b). According to information so far available, one woman died, 32 houses and 2 bazars were gutted and 64 families rendered homeless.

Estimated loss is Rs. 34,000.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Air India Publicity Work

8617. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. J. Walter Thompson Company, an advertising agency with 40 per cent foreign holdings, earned a commission of Rs. 5,18,433.77 on the publicity work of Air India during the four years ending 1965-66 ;

(b) whether it is also a fact that Clarion McCann Advertising Services, Delhi, a foreign advertising agency, earned a commission of Rs. 1,95,000 in two years ending 1965-66 on the publicity work of Indian Airlines Corporation ;

(c) the precise reasons why Government do not patronise 100 per cent Indian Advertising Agencies of which there are many competent and well-organized ones when the national policy of Government is to support Indian enterprise in every field ; and

(d) how long Government propose to continue the present state of affairs and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :

(a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Air-India function in a highly competitive field and they require advertising agents of a calibre which can satisfy their requirements. M/s. J. Walter Thompson Company had been handling satisfactorily their advertising for nearly 30 years, and Air India would, therefore, prefer to continue having the services of this Company,

especially as they are one of the outstanding advertising agents in the world.

Clarion McCann is treated as an Indian agency having foreign collaboration. They have their branches at the four regions where I.A.C function. Further, this company had been giving satisfactory service to the Corporation.

Government do not propose to interfere with the decisions of the Corporations in such matters.

Christian Missionaries

8618. SHRI BABURAO PATEL : Will the Ministry of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Centre has given any advise to the Government of Madhya Pradesh for implementing various recommendations contained in reports of Nyogi and Rege Commission regarding activities of Christian Missionaries ;

(b) if so, the attitude taken by the State Government in this regard ; and

(c) whether the Centre proposes to further direct the State Government to enact suitable legislation to give effect to salient recommendations of the two reports ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). Since the Niyogi and Rege Committees were appointed in 1954 by the then Government of Madhya Pradesh and Madhya Bharat respectively, it was primarily for the State Government to consider their Reports. This was also done by them. In doing so they had requested for the reactions of the Central Government, which were supplied to them.

Madras Government's Opposition to Formation of All India Services for Engineers

8619. SHRI CHANDRA JEET YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madras have opposed the Central Government's plan to form an All India Service for Engineers ; and

(b) if so, the reasons given by the

State Government and the reaction of the Central Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have said that they do not intend to participate in new All India Services which relate to subjects strictly within the purview of the States. The reply of the State Government is under consideration.

West Bengal Inland Waterways

8620. SHRI JYOTIRMOY BASU : SHRI BHAGBAN DAS : SHRI GANESH GHOSH : SHRI MOHAMMAD ISMAIL :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Government have received a copy of the Survey Report submitted by the Calcutta Metropolitan Planning Organisation on Inland Waterways in West Bengal ; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) The Calcutta Metropolitan Planning Organisation has submitted to the Government of West Bengal a report on Inland Waterways. A copy of the Report has been received by the Government of India.

(b) The development of Inland Waterways other than those declared as National waterways is the responsibility of the State Governments. The Government of West Bengal have intimated that the Report referred to in this question is under the consideration of the State Government.

Airport at Balurghat

8621. SHRI JYOTIRMOY BASU : SHRI BHAGBAN DAS : SHRI GANESH GHOSH : SHRI B. K. MODAK :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is an airport at Balurghat in West Bengal ;

(b) if so, the purpose for which it was built ; and

(c) whether there is any proposal to run air services between Balurghat and Calcutta ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) Yes, Sir. There is an aerodrome at Balurghat fit for operation by Dakotas.

(b) After partition, Balurghat aerodrome was used as an emergency aerodrome between Calcutta and Siliguri to avoid over-flying Pakistan territory. It has also been used as an emergency aerodrome between Calcutta and places in Assam.

(c) No Sir.

Scheme to Assist Indian Authors

8622. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state ;

(a) whether Government have any scheme for assisting Indian authors ; and

(b) if so, the broad details thereof and the number and names of those who have been assisted so far ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving details of the various schemes and the names and the numbers of authors assisted under them is laid on the Table of the house. [*Placed in Library. See No. LT-1058/68.*]

Shanti Sewa

8623. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are not giving any help to Shanti Sewa of the Sarvodaya people ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if not, the kind of assistance given to it by Government so far and what have been its successes and in which areas ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (c). The Shanti Sena is not functioning in Nagaland,

Manipur, Tripura, Laccadive, Minicoy, Amindivi Islands, Dadra and Nagar Haveli and Pondicherry. The Governments of Haryana, Goa, Daman and Diu and Chandigarh Administration did not receive any request from Shanti Sena for financial assistance. Information regarding the remaining States and Union Territories is being collected.

Arrest of Foreigners

8624. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of foreigners arrested in India within the last five years showing their nationalities ;

(b) the charges framed against them and their terms of imprisonment ; and

(c) how many are still in jail at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली पुलिस

8625. श्री राम चरण :

श्री बबेन सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह नीति बनाई है कि दिल्ली राज्य पुलिस में सिपाही आदि की भरती उन लोगों में से की जाये जो दिल्ली की सीमा की 200 मील की परिधि के क्षेत्रों में जन्म से रह रहे हों ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्राधार क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से नये भरती किये गये लोग शारीरिक तथा ऊंचाई के बारे में अपेक्षित स्तर को पूरा नहीं करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् । निर्धारित शारीरिक स्तरों का पालन कड़े रूप में किया जाता है । केवल विशिष्ट मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी जाती है ।

Voting Rights of Kashmiris

8626. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration the question of voting rights to be given to the residents of Kashmir who went from other parts of India and settled there ;

(b) if so, whether the views of the Government of Jammu and Kashmir have been invited in this case and if so, their views ; and

(c) the reaction of Government thereto and when a decision in the matter is expected to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) For Parliamentary Constituencies, qualifications of voters in Jammu and Kashmir are the same as in the rest of the country. For the Jammu and Kashmir Legislature voting rights are restricted to permanent residents; there is no proposal to change this position.

(b) and (c). Do not arise.

Nehru University, New Delhi

8627. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken about the facilities to be started in and policy of affiliation of Colleges to the proposed Nehru University in Delhi ;

(b) whether any staff has been recruited for the running of the University, and if not, when it is proposed to be done ;

(c) whether any date-line has been fixed for the opening of the University ; and

(d) if so, which ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) No, Sir.

(b) No staff has yet been recruited. This will be done after the Vice-Chancellor is appointed.

(c) and (d). While no date-line has been fixed, efforts are being made to open the University as soon as possible.

उन्नाव में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों

8628. श्री राम चरण :

श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन्नाव जिले में पुलिस द्वारा गांवों के उजाड़ दिये जाने के बारे में 4 अप्रैल, 1968 के दैनिक "मिलाप" के पृष्ठ 2 पर छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस की ज्यादतियों के कारण सभी ग्रामवासियों ने उन्नाव जिले में उसानी, रामबक्सखेड़ा तथा मक्का खेड़ा गांवों को खाली कर दिया है;

(ग) क्या पुलिस वाले इन गांवों में महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और घरों तथा भनाज के भण्डारों को आग लगा रहे हैं;

(घ) क्या बलात्कार के परिणाम स्वरूप एक महिला मर गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ) : राज्य सरकार ने इन मामलों में अदालती जांच के आदेश दिये हैं । यदि आवश्यक हुआ तो अदालती जांच समाप्त होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

मध्य प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्तियां

8629. श्री गं० च० दीक्षित : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में मध्य प्रदेश के कितने छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां दी गई थी तथा विदेशों में भेजा गया था;

(ख) उन छात्रवृत्तियों के लिए कितने छात्रों ने प्रार्थनापत्र भेजे थे, और

(ग) उन छात्रों में से कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए चुना गया था ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 12, जिसमें एक वह भी शामिल है जिसे अभी जाना है।

(ख) 8,900

(ग) 478

मध्य प्रदेश में जाने वाले विदेशी नात्री

8630. श्री गं० च० दीक्षित : क्या पर्यटन तथा असेनिक उद्घरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 में मध्य प्रदेश में कितने विदेशी पर्यटक आये थे ?

पर्यटन तथा असेनिक उद्घरण मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन विभाग पर्यटक सम्बन्धी आंकड़ों को अखिल भारतीय आघार पर रखता है अलग-अलग राज्यों के आघार पर नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य में आये विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में न्यायाधीश

8631. श्री गं० च० दीक्षित : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की राय के अनुसार इस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ख) क्या मुकदमों की बढ़ती संख्या तथा अन्य निर्णयाधीन मामलों के अलावा काफी

संख्या में विचाराधीन चुनाव दाचिकाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार को उच्च न्यायालय की राय की जानकारी नहीं है। राज्य सरकार को नियमों तथा निपटान को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या का पुनरीक्षण करने तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है। फिर भी राज्य सरकार से अभी तक ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

Cases Against Foreigners

8632. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of foreigners along with the names of their countries against whom cases are lying in the Indian Courts as on the 31st March, 1968;

(b) the names of such foreigners who left the country pending Court cases against them; and

(c) the action taken by Government to proceed further in such cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं

8633. श्री मोठा लाल मीना : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1967 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग (इलाहाबाद) की स्नातक परिषद से साहित्य सम्मेलन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को मान्यता देने के लिए शिक्षा मन्त्रालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्या मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, जून 1967 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (इलाहाबाद) स्नातक परिषद, नई दिल्ली से साहित्य सम्मेलन की "सम्पादन कला विशारद" परीक्षा को मान्यता देने के सम्बन्ध में एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रेषक को सूचित कर दिया गया था कि केवल हिन्दी विषय की परीक्षाओं को ही मान्यता देने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

Government of India Overseas Scholarships

8634. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) the number of applicants for Government of India Passage Grants, received from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes and Backward classes students for the year 1967-68; and

(b) the number of applications sanctioned out of these and the number of students who were not admitted to foreign Universities and the reasons for not admitting ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) During the year 1967-68, nine applications were received for Passage Grants for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) Of the nine applicants, four were selected for Passage Grants. Of these four, one candidate was not given the Passage Grant since he was selected for a scholarship under Overseas Scholarship Scheme for Scheduled Castes/Tribes, etc., which included cost of Passage also. Of the remaining three candidates who have been sanctioned Passage Grants two have already secured admissions, while the third one is yet to finalise the admission. Passage Grant is made only after the admission has been secured by the student.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

8635. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से अब तक प्रति वर्ष नगर निगम के सीमा-क्षेत्र में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इस दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितने व्यक्ति हताहत हुये और मारे गये;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितनों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये; और

(घ) न्यायालयों द्वारा उनमें कितने व्यक्तियों को डंड दिया गया तथा कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मन्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

शिलांग में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बैरकों में आग लगाया जाना

8636. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आदिम जातीय लोगों ने शिलांग में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ बैरकों में आग लगा दी थी जैसा कि 2 अप्रैल, 1968 के 'हिन्दुस्तान' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 31 मार्च, 1968 को शिलांग में आसाम पुलिस द्वारा जुमारियों के एक गिरोह पर छापा मारने के परिणामस्वरूप

एक भड़प में एक भीड़ के कुछ सदस्यों ने कुछ खाली बैरकों पर मशाल वाले तीर चलाकर उनमें आग लगा दी। ये बैरक पहले रिजर्व पुलिस के कब्जे में थी, उन्हें, उन्होंने जनवरी, 1968 में खाली कर दिया था। वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की नहीं थी।

(ख) इस सम्बन्ध में आसाम पुलिस ने 8 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं तथा मामले की जांच की जा रही है।

पाकिस्तानी राष्ट्रियों की गिरफ्तारी

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1968 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ यह समाचार सही है कि मार्च, 1968 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के मुलतानपुर जिले में कुछ छीपे पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके पास से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये गये थे ; और

(ग) कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये हैं और वे कब से छिपे रूप से भारत में रह रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री : (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुअ्तिल अधिकारी

8638. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-कार्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 5053 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों तथा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किन कारणों से मुअ्तिल किया गया था ;

(ख) मुअ्तिल किये गये उक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारी अभी तक मुअ्तिल हैं ;

(ग) क्या उन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच कर ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (घ). अधिकारियों को पद के दुरुप्रयोग, ईमानदारी की कमी, गबन, अविवेकी आचरण इत्यादि के आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया था। कार्यवाहियों की जांच रही है।

(ख) तीन।

“Gopala Sena”

8639. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the "Hindustan Times," dated the 26th March, 1968 that the "Gopala Sena" has now a strength of 15,000 volunteers who are trained by the ex-military personnel;

(b) whether the Government of Kerala are utilising huge amounts of public money for propagating party ideology and for spreading anti-centre propoganda and the Gopala Sena is playing a leading role;

(c) whether the activities of the Sena are posing a threat to the Civil liberty of the population in the State; and

(d) if so the reaction of Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to the state Government public money is not being utilised for propagating party ideology and for spreading anti-centre propoganda. The State Government have further stated that the activities of the CP (M) volunteer

corps do not pose a threat to civil liberties.

(d) The Central Government are keeping a close watch over the activities of the volunteer corps organised by the CP (M).

Militant Group of Communists

8640. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI PREM CHAND VERMA :
SHRI ONKAR LAL BOHRA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the "Hindustan Times" dated the 2nd April 1968 that the extremist section of the Communist Party will form itself into a new militant group on the lines of the Chinese Red Guards; and

(b) if so, Government's reaction in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) (a) : Yes, Sir.

(b) Government are keeping a close watch on the activities of the extremists.

Foreigners Visiting Mahesh Yogi's Ashram At Rishikesh

8641. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Russians have approached the Ashram of Mahesh Yogi for meditation;

(b) if so, the names of the other countries from which persons are coming to the ashram;

(c) whether Government are keeping a watch on the activities of the foreigners; and

(d) whether Government have detected some suspects; and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(a) Persons from U. S. A., Germany, Sweden, Norway, Denmark, German Democratic Republic, United Kingdom, Canada, Australia, Ireland and West Indies have visited the ashram.

(c) and (d). The Government maintain vigilance and no espionage activities on the part of any foreigner have come to their notice so far.

Madakasira of Andhra Pradesh

8642. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Madakasira people and Panchayati in Andhra Pradesh have passed a Resolution and also urged Government expressing their desire to join Mysore State; and

(b) the grounds on which they have urged to join Mysore and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have no information on this subject.

(b) Does not arise.

Fire in Barracks of 14 Madhya Pradesh Armed Police at Nefabari, Jorhat

8643. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some barracks housing 14 Madhya Pradesh Armed Police at Nefabari in Rowriah near Jorhat were recently completely gutted by fire ;

(b) if so, the causes of the fire ; and

(c) whether arms and ammunitions were also destroyed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The cause of the fire is being enquired into.

(c) No, Sir.

Flights Cancelled by Indian Airlines Corporation

8644. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of flights cancelled during the last one year by the Indian Airlines Corporation ; and

(b) the loss suffered by the Airlines as a result thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) The number of flights cancelled due to various reasons during the year 1967 was 1847 out of 42483 as detailed below :

Strikes and Bandhs	382
Bad weather	901
Other operational reasons	564

Total	1847

(b) The loss of revenue due to cancellation of flights on account of strikes/bundh during the year 1967 is estimated at Rs. 25 lakhs. It is not possible to assess the loss of revenue due to other reasons.

Pak. Infiltrators in Assam

8645. SHRI K. P. SINGH DEO : SHRI ONKAR LAL BOHRA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Pakistani infiltrators traced in Assam in 1967 ;

(b) the number of the infiltrators deported to Pakistan ;

(c) the steps taken by Government to deport the remaining Pakistani infiltrators in Assam ; and

(d) the measures taken by Government to check Pakistani infiltration in Assam ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(d) Suitable measures have been taken for detection and eviction of Pakistani

infiltrators and for prevention of further infiltration. These measures include strengthening and increasing the number of border outposts and intensifying patrolling of the border.

I. A. S. Cadres in States

8646. SHRI AHMED AGA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the normal pattern of constitution of I. A. S. Cadre in the States ;

(b) whether the same pattern is applicable to the State of Jammu and Kashmir ;

(c) the nature and posts which are normally encadred in I. A. S. in other States but have not been encadred in Jammu and Kashmir State ; and

(d) the present sanctioned strength of the I. A. S. Cadre in Jammu and Kashmir State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The normal composition of the I. A. S. Cadres in the States is as follows :

1. Senior posts under the State Government ... A
 2. Senior posts under the Central Government ... B
 3. Posts to be filled by promotion and selection in accordance with rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of A & B ... C
 4. Posts to be filled by direct recruitment A+B-C ... D
 5. Deputation Reserve @ 20% of D ... E
 6. Leave Reserve @ 11% of D ... F
 7. Junior posts @ 20.60% of D ... G
 8. Training Reserve @ 10.59% of D ... H
-
- Direct recruitment posts (D+E+F+G+H) ... I
- Promotion posts ... C
-
- Total authorised strength (I+C) ... J

(b) The I.A.S. Cadre of Jammu and Kashmir is also of the same pattern except that :

(i) the number of posts to be filled by promotion and selection in accordance with Rule 8 of the IAS (Recruitment) Rules, 1954 is 50% of the senior posts in Jammu and Kashmir for 10 years from 4-9-58 as against 25% in other States ; and

(ii) the number of senior posts under the Central Government is $33\frac{1}{3}\%$ of the posts under the State Government in the case of Jammu and Kashmir as against 40% in other States.

(c) Normally, all posts of Collectors and other superior administrative posts of Commissioners, Members of Board and Revenue, Secretaries to Government e.g. some posts of heads of departments and Deputy Secretaries are included in the I.A.S. cadre of State.

All such posts except posts of Deputy Secretaries have been included in the cadre of Jammu and Kashmir.

(d) The present sanctioned strength is 51.

एयर इन्डिया और एयरलाइन्स कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

8647. श्री मोलहू प्रसाद : क्या पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय क्रमशः एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेणी वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असेनिक उड्डयन मन्त्री (डॉ० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्रीद्योगिक उपक्रम

8648. श्री मोलहू प्रसाद : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन जिलावार कौन कौन से श्रीद्योगिक उपक्रम चल रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय अवधि में प्रत्येक जिले में कौन कौन से श्रीद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने का विचार है और इनमें से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना परिव्यय होगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी श्रीद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने का है ताकि इस क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर किया जा सके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर लाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) से (घ). अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश की सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

श्रीद्योगिक उपक्रम

8649. श्री मोलहू प्रसाद : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन जिलावार कौन-कौन से श्रीद्योगिक उपक्रम चल रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक जिले में कोन-कोन से औद्योगिक उप-क्रमों की स्थापना करने का विचार है और इनमें से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना परिव्यय होगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने का है ताकि इस क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर किया जा सके और पूर्वी उत्तर प्रदेश की पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर लाया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री : (श्री के० एस० रामास्वामी (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

श्रमिक विद्यापीठ

4650. श्री मोल्लू प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों को शिक्षा देने के लिये दस श्रमिक स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इन में प्रत्येक विद्यापीठ पर कितना व्यय करने का विचार है तथा वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ,

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से फैली बेरोजगारी तथा उसके पिछड़ेपन को दृष्टि से अन्य राज्यों के सामान बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में कोई श्रमिक विद्यापीठ खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) (क) और (ख). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् ने यूनेस्को के

सहयोग से लगभग दस श्रमिक विद्यापीठ (पालीवेलेंट सैन्टर्स) मार्गदर्शक प्रायोजना के रूप में सामान्य शिक्षा (जिसमें साक्षरता भी शामिल है) व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक शिक्षा (नागर, सांस्कृतिक और सौंदर्यशास्त्र के पहलुओं सहित) के मिले जुले पाठ्यक्रम चलाने के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अब तक एक केन्द्र ने बम्बई में काम शुरू कर दिया है और दूसरा केन्द्र दुर्गापुर में शुरू करने का प्रस्ताव किया है। जहाँ तक शेष का संबंध है शुरू किये जाने वाले केन्द्रों की कम से कम संख्या उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार निश्चित की जायगी। अनुमान है कि प्रथम वर्ष में हरेक केन्द्र पर लगभग 90,000 रु० की लागत आएगी और हरेक बाद के वर्ष में 60,000 रु० की लागत आयगी।

(ग) और (घ). शेष केन्द्रों के विनिधान के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

Sales Tax Tribunal in Delhi

8651. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the proposal regarding the appointment of Sales Tax Tribunal in Delhi has been considered ;

(b) if so, the decision taken in the matter ; and

(c) the stage at which the matter stands at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). The matter is under consideration of the Delhi Administration.

Wage Board for Hotel Industry

8652. SHRI N. K. SANGHI :
SHRI B. N. SHASTRI :
SHRI R. R. SINGH DEO :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the President of Federation of Hotel Industry has

suggested that a Wage Board on an all-India basis be set up for the Industry and that the price of foreign liquor served to tourists be subsidised by reducing the excise and other duties ; and

(b) whether Government have any plan for rationalisation of the structure of charges in hotels and boarding houses of the different star categories of hotels ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The Hotel Review and Survey Committee set up by this Ministry to classify hotels and approve restaurants has been asked to review the rates charged by the hotels which are classified under the star-system, with the object of determining a rational system for standardizing the rates in each category.

Indian Institute of Historical Studies

8653. **SHRI K. ANIRUDHAN :**
SHRI UMANATH :
SHRI C. K. CHAKRAPANI :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5661 on the 29th March, 1968 and state :

(a) the names of the projects of the Indian Institute of Historical studies financed by the Asia Foundation and the amount of grant to each project ; and

(b) the number of foreigners employed in each Project ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): (a) and (b). Information is being collected.

Preventive Detention Act in Jammu and Kashmir

8654. **SHRI A.K. GOPALAN :**
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI VISWANATHA
MENON :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Government employees were

arrested in January, 1968 under the Preventive Detention Act in Jammu and Kashmir ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the reasons for their arrest ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). According to information received from the Government of Jammu and Kashmir, no Government employee was arrested in January 1968. In December 1967, however, 63 Government employees were arrested and detained under the J & K Preventive Detention Act with a view to preventing them from acting in a manner prejudicial to maintenance of public order; all these have since been released.

Material for Working Artists

8655. **SHRI A. K. GOPALAN :**
SHRIMATI SUSEELA
GOPALAN :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) the total value of imported artists' materials brought by Lalit Kala Akademi during the years 1965/1966 for distribution amongst the working artists in India ;

(b) how much of it was sent to West Bengal ;

(c) the method of distribution of such materials ; and

(d) the precautions adopted to prevent misuse ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN): (a) The total value of the artists' material imported by the Akademi during the years 1965-66 and 1966-67 for distribution amongst the working artists in India was as under :

1965-66	Rs. 20,899.63
1966-67	Rs. 17,388.31

(b) Out of the amounts mentioned above, material sent to West Bengal was :—

1965-66	Rs. 2294.90
1966-67	Rs. 2138.64

(c) The material is distributed through the State Akademies and well established art organisations recognised by the Akademi in States where there are no State Akademis.

For this purpose the country has been divided into four zones as under :

- (1) *Northern.* Comprising Rajasthan, Punjab including Himachal Pradesh and Haryana, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Delhi. Except in Delhi, there are State Akademis in all the four centres and the material is distributed through them. In Delhi the distribution is done through All India Fine Arts and Crafts Society and the Delhi Silpi Chakra and in certain cases by the Akademi direct.
- (2) *Southern.* Comprising of Andhra Pradesh, Madras, Mysore and Kerala. In all these States, there are State Akademis and the distribution of material is done through them.
- (3) *Eastern.* It comprises West Bengal, Bihar, Orissa, Assam and Nagaland. Since the State Akademi in West Bengal has been established only recently, the material meant for artists in West Bengal and Nagaland used to be distributed through the Akademy of Fine Arts, Calcutta. In Orissa and Assam it is distributed through the respective State Akademis.
- (4) *Western.* It comprises Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Goa and as such the material in Maharashtra and Goa is distributed through the Bombay Art Society, Bombay which is one of the oldest art organisations in that area. In Gujarat and Madhya Pradesh, where there are State Akademis, the material is distributed through them.

Within the zones, each distributing centre is allotted a quota in proportion to their assessed requirement based on the demands of the practising artists *vis-a-vis* the

stock available with the Akademi. To determine the quota, each distributing centre is requested to give adequate publicity not only among their members but also to the individual artists of their respective areas and to obtain their applications in the forms prescribed by the Akademi. On receipt of the applications from each distributing centre, the position is reviewed by the Akademi and the allocations are decided in the manner suggested above. On each fresh import by the Akademi, a circular is sent to all the distributing centres enclosing a copy of the material available for sale and the prices fixed by the Akademi.

The material is distributed through the distributing centres on the condition that they submit a proper account of distribution of material together with signed receipts from the artists. No further material is supplied to any distributing centre, unless the requirements of the Akademi regarding the earlier distribution are completed.

In order to ensure that the maximum number of artists get the benefit of imported material, a ceiling to the tune of Rs. 200/- has been imposed by the Akademi for each artist. The Akademi distributes the material directly to the artist members of its General Council.

(d) As stated in (c) above, the fresh material is not issued through the distributing centre unless the details of earlier distribution together with the acknowledgements of the artists are received by the Akademi. The Akademi does not sell the imported material to any of the artists unless his or her application is recommended by the distributing centre of the area concerned. While announcing the arrival of new material, all the State Akademis, recognised art organisations are supplied with a copy of the material available for sale as well as the price list. Each distributing centre is required to collect the cost of the material as per the prices determined by the Akademi together with sales tax @ 5% in case of local artists and 10% for the outstation artist.

Supplier from Assam Coal

8656. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Regio-

nal Research Laboratory at Jorhat has successfully developed a commercial technique to extract elemental sulphur from Assam coal ;

(b) whether the new technique, if exploited fully, will go a long way to provide adequate source of sulphur for the country ;

(c) if so, whether any Central scheme has been formulated to develop the exploiting of sulphur from coal ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b). The Regional Research Laboratory, Jorhat has worked out laboratory processes for the recovery of Sulphur in the form of compounds from Assam Coal. Detailed investigations are under way.

(c) and (d). A Study Group appointed by the Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) has recommended *inter alia* in its report that a detailed scheme for coal based fertiliser project, adopting complete gasification of coal with by-product sulphur recovery should be drawn up by the Coal Board, if necessary, by seeking assistance from the Regional Research Laboratory, Jorhat, the Fertiliser Corporation of India and the consulting firms in the field. This report is under consideration.

Indian Constitution

8657. **SHRI JYOTIRMOY BASU :** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Sheikh Abdullah was one of the signatories of the Indian Constitution ; and

(b) if so, whether he signed it as an Indian citizen ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Yes, Sir.

Nefa Tribesmen Helping Naga Hostiles

8658. **SHRI M. L. SONDHI :**
SHRI C. CHITTYBABU :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have received

reports indicating that some tribesmen of NEFA are co-operating with the Naga Hostiles in their nefarious activities ; and

(b) if so, the measures being taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यक

8659. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस सम्बन्ध में संविधान के विभिन्न उपबन्धों के अतिरिक्त भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के आशवासित सुरक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच भी की जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Tomb of Zauq in Delhi

8660. **SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the Tomb of Zauq, the Great Urdu poet and Ustad of Bahadur Shah Zafar, the last Mughal Emperor in Amarpuri, Delhi, has been converted into a public lavatory ; and

(b) if so, the steps being taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b). This Minis-

try has no such information. The tomb is not a centrally protected monument.

Subordinate Executive Service of Delhi

8661. SHRI NIHAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Grade II Officers of the Subordinate Executive Service of Delhi Administration, who have been promoted to Grade I after the enforcement of Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967 ;

(b) the number of Grade II Officers of the Subordinate Executive Service of the Delhi Administration, who were promoted to Grade I posts on ad hoc basis before the enforcement of the Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967 and are still continuing on the same posts ; and

(c) the number of Grade II Officers of Subordinate Executive Service of the Delhi Administration, who have been regularised on duty posts and on non-duty posts separately, after the enforcement of the Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA).: (a) Nil

(b) 28

(c) Whereas no officer has been regularised against any Duty Post, two officers have been regularised as Industries Officers against non-Duty posts.

भारतीय जहाजरानी उद्योग

8662. श्री क० नि० मधुकर : क्या परिवहन तथा नौबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजरानी के मामले में विश्व के उन्नत देशों में भारत का स्थान क्या है; और

(ख) जहाजरानी उद्योग का विकास करने के लिये जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हाल में किये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) उन्नत समुद्री देशों में भारत का स्थान 17वां है।

(ख) नौबहन उद्योग के विकास के लिये अध्यक्ष, राष्ट्रीय नौबहन मंडल द्वारा हाल ही में कोई विशेष सुझाव नहीं दिये गये हैं। और इस लिये संस्कार द्वारा उनके क्रियान्वयन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले में यमुना नदी पर पुल

8663. श्री निहाल सिंह : क्या परिवहन तथा नौबहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी पर पुल बनाने पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि उस पुल के ऊपर से गुजरने वाली प्रत्येक बस, बैलगाड़ी, तांगे से प्रति फेरा 75 पैसे तथा प्रत्येक यात्री के बस किराये के अतिरिक्त 25 पैसे चुगी ली जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह पुल किसी गैर-सरकारी व्यक्ति से बनवाया गया था अथवा सरकार ने बनाया था;

(घ) पिछले पांच वर्षों में अब तक चुगी से कितनी धनराशि वसूल की गई है तथा इस कर को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने पुल हैं जहां पर कर लिया जाता है ?

परिवहन तथा नौबहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त बर्षन) (क) से (ङ): उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और क्या समय सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दिल्ली में स्कूलों के लिये खेल के मैदान

8664. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने स्कूलों तथा कालेजों

के पास हाकी तथा फुटबाल खेलने के लिये खेल के मैदान नहीं हैं ;

(ख) क्या दिल्ली की पुरानी तथा नई बस्तियों में बालकों के लिए खेल के मैदानों की व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन को इस बारे में कोई भुक्ताव मिले हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिवेण सैन) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उत्तर प्रदेश में मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र अलग बनाने की मांग

8665. श्री हरदयाल बेबगुल :

श्री महन्त बिबिजय नाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की मजलिसे-मशबूरात के प्रधान डा० ए० जे० फरीदी ने उत्तर प्रदेश में करनलगंज में एक सांविजनिक सभा में राज्य के मुसलमानों के लिए एक पृथक मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बनाये जाने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

मद्रास में हिन्दी के अध्यापक

8666. श्री हरदयाल बेबगुल : क्या शिक्षा मंत्री, 22 मार्च, 1968 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 4730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में

हिन्दी के अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं तथा वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्त के लिए जो राशि निर्धारित की थी उसे खर्च नहीं किया गया है तथा वह वापिस कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति न करने के बारे में क्या कारण दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) : जी ; नहीं । मद्रास सरकार ने 1966-67 के दौरान 120 हिन्दी अध्यापकों को नियुक्त किया था और इसके लिए केन्द्रीय सरकार से 90,000 रुपये का अनुदान प्राप्त किया था । वास्तविक खर्च 97,814 रुपये हुआ था । राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि पिछले वर्ष और 1967-68 के दौरान नियुक्त अध्यापकों को आगे चलाने के लिए 1967-68 में 1,80,500 रुपए खर्च होने का अनुमान है । इस लिए राज्य सरकार ने 1967-68 के लिए 1,80,500 रुपए के अनुदान की मांग की है, जिस पर स्वीकृति के लिए यथा समय विचार किया जायगा ।

Code of Conduct in Dealing with
M P. and M. L. As

8667. SHRI INDER J. MALHOTRA:
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions to all Officers both at the Centre and in States ; with respect to the code of conduct in dealing with Members of Parliament and State Legislatures ; and

(b) if so, the nature of the instructions issued ?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b).
Instructions were issued in August, 1957,
impressing on all officers of the Govern-
ment of India the need to observe courtesies

in their dealings with Members of Parliament. A copy of the instructions is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1059/68]

Apart from the instructions mentioned above, a draft Code to regulate the relationship between Members of Parliament and of State Legislatures and the Administration (both Central and State) is also under consideration. A copy of the draft Code was placed on the Table of the House on 21.3.1967 in fulfilment of the assurance relating to Starred Question No. 630 dated 24.8.1966.

Sheikh Abdullah

8668. SHRI INDER J. MALHOTRA:
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to have a second round of talks with Sheikh Abdullah and his men ; and

(b) if so, the nature of the specific issues that will be discussed between the two parties ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) and (b). The Government have not received any proposal for talks from Sheikh Abdullah.

Mangalore Port

8669. SHRI INDER J. MALHOTRA.
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) the stage at which the construction of an all-weather major port at Mangalore stands at present ;

(b) whether any representation with respect of rehabilitation and other compensation made to people uprooted from the areas has been received ; and

(c) if so, the action taken in that regard ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO):

(a) All the preliminary works relating to the Mangalore Harbour Project have already been completed. Some marine

works, namely, the excavation of the harbour area and the construction of a portion of the breakwaters are in progress.

(b) and (c). Representation have been received from the persons whose lands have been acquired both in respect of rehabilitation and compensation for the acquired land.

As regards rehabilitation, the representations received were passed on to the State Government, as the subject is their concern. The measures taken by the State Government for the rehabilitation of displaced persons comprise allocation of house sites free of cost, removal and transport of building materials free of cost, ex-gratia payments, grant of three years' rent to 'Chalgeni' tenants, grant of community amenities like, wells, market places, roads, schools and places of worship.

As regards the payment of compensation for the acquired land, the amount of compensation is fixed by the land acquisition officers on the basis of the sale statistics available with them and awards made by the courts while disposing of the references under the Land Acquisition Act.

Leakage of Question Papers in Andamans

8670. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether question papers of the final examinations of the Senior Basic Classes of the Diglipur Senior Basic School in the Andaman and Nicobar Islands leaked out ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether action has been taken against the negligent persons ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir. Question papers of Centralised examination of Class VIII for Senior Basic School, Diglipur did leak out ;

(b) Question papers kept in the office room were stolen by removing sliding bolts of the room ; and

(c) The police have registered a case under sections 457/480 I. P. C. Police investigations and departmental enquiry are proceeding to bring the culprits to book.

Out Break of Fire in C.S.I.R. Building

8671. **SHRI BEDABRATA BARUA :**
SHRI D. N. DEB :
SHRI GADILINGANA
GOWD :
SHRI S. K. TAPURIAH :
SHRI RAMACHANDRA
VEERAPPA :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in the Council of Scientific and Industrial Research Building in the first week of April, 1968 ;

(b) if so, the amount of loss ;

(c) whether any investigation has been made in the matter ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir. There was a fire in one of the rooms;

(b) to (d). The matter is under investigation.

Marine Services

8672. **SHRI BEDABRATA BARUA :**
SHRI D. N. DEB :
SHRI RAMACHANDRA
VEERAPPA :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Committee has been appointed by Government to go into the question of scales of Pay and Allowances of Officers of Marine Services of various ports ; and

(b) if so, the terms of reference thereof ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes, Sir. A Committee has been appointed to go into the question of scales of pay and allowances of Officers of Marine Services of the major ports of Calcutta, Madras, Cochin, Kandla, Vishakhapatnam, Mormugao and Paradip.

(b) The terms of reference of the Committee are to enquire into and make recommendations on the scales of pay and

allowances of the officers of the Marine Services of the Major Ports referred to ?

University Courses in Military Science

8673. **SHRI P. R. THAKUR :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1245 on the 20th April, 1966 and state :

(a) the names of the Universities along with the corresponding Departments conducting the Courses in Military Science ; and

(b) the main features of the syllabus followed by each of them in this respect ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Facilities for the study of Military Science are offered by the Departments of Military Science in the Universities of Allahabad, Gorakhpur and Poona.

Similar facilities are also provided in some of the affiliated colleges of the following Universities :—

1. Agra
2. Gorakhpur
3. Indore
4. Jabalpur
5. Jiwaji
6. Meerut
7. Panjab
8. Punjabi
9. Poona
10. Ranchi
11. Calcutta.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—1060/68].

राजस्थान में पर्यटकों के लिये सुविधाओं की

अवस्था

8674. श्री श्रीकांत ज्ञान मोहरा : क्या पर्यटन तथा अतिथि उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटकों के लिये सुविधाओं संबंधी योजनाओं का स्वरूप क्या है और इस संबंध में आगामी वर्ष में कुल कितनी धन राशि खर्च किये जाने की संभावना है;

(ख) राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, रजकपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भाब, अजमेर, जयसमुन्द, रामसमुन्द, हल्दी घाटी तथा मंडौर इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा रमणीक स्थानों पर पर्यटकों को परिवहन तथा जलपान संबंधी क्या क्या सुविधायें दी गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चित्तौड़ जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान पर पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन तथा अस्तैनिक उद्घटन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राजस्थान सरकार ने 1968-69 के दौरान प्रारम्भ की जाने वाली पर्यटन विषयक स्कीमों का व्यौरा अभी तक सूचित नहीं किया है। 1968-69 के दौरान भाग I के अन्तर्गत जयपुर-भरतपुर-बीकानेर क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये एक लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, तथा भाग II की स्कीमों के अंतर्गत 10-50 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

(ख) दूसरी और तीसरी योजना की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर जाने और आवास की सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी :—

1. भरतपुर में रेस्ट हाउस।
2. सिलीसेड़ में रेस्ट हाउस का सुधार।
3. जयपुर में पर्यटक बंगला (श्रेणी II)।
4. उदयपुर में पर्यटक बंगला (श्रेणी II)।
5. माउंट अरारत में पर्यटक बंगला (श्रेणी II)।
6. चित्तौड़गढ़ के किले में कैंटीन।

परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। इसलिये इस

प्रयोजन के लिये किसी फण्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ग) और (घ). चित्तौड़ के लिये यातायात बहुत है परन्तु वहां मुख्यतया देशी यात्री जाते हैं जिनके लिये मध्यम मूल्य की और अधिक आवास व्यवस्था की आवश्यकता है।

इन जगहों पर आवास-व्यवस्था उपलब्ध है :—

1. पर्यटक रेस्ट हाउस
2. पी० डब्ल्यू० डी० डाक बंगला
3. सिंचाई विभाग का डाक बंगला

इसके अतिरिक्त, चित्तौड़गढ़ में भारतीय ढंग के होटल और घमशालाएं हैं।

चित्तौड़गढ़ में सरकारी सराय में सुधार करने के लिये 1968-69 की वार्षिक योजना के भाग II में 50,000/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

All-India Services

8675. SHRI M. N. REDDY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number and category of services that have been approved and recognized as All-India Services in the recent past and the category of services which are not yet made All-India Services ;

(b) the reasons for the delay in making the other Services as All India Services and the time required for taking a final decision in the matter ; and

(c) whether services of agricultural Graduates and scientists have been recognized as All India services, and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) In the recent past, the constitution of the following All India Services has been provided for by amending the All India Services Act, 1951 :—

1. Indian Service of Engineers (Rig- gation, Power, Buildings and Roads) ;

2. Indian Forest Service ;
3. Indian Medical and Health Service.

Of these, the Indian Forest Service has already been constituted with effect from 1.7.1966. Steps are being taken to constitute the other two.

(b) The Rules and Regulations relating to the constitution of All India Services are framed by the Government of India only after all the State Governments concerned have been consulted and the advice of the Union Public Service Commission has been taken. The process of consultation with the States takes time as the State Governments can formulate their views after having the draft Rules considered in the concerned Departments of the State Government including the Finance Department. The draft Rules together with the view of the different State Governments are then communicated to the Union Public Service Commission for their advice. It is only after all these formalities are completed that the necessary Rules can be notified and further action taken to constitute the Service.

It is difficult to indicate at this stage the time that would be taken in creating these new All India Services.

(c) No. A Resolution under article 312 of the Constitution was passed by the Rajya Sabha in March, 1965, with regard to the creation of the Indian Educational Service and the Indian Agricultural Service. The All India Services Act, 1951 has however not yet been amended to provide for the constitution of these two Services.

Radars at Air Ports

8676. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to install some high power air route surveillance radars at some Air Ports in the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) and (b). It is proposed to install Long Range Air Route Surveillance Radars

(A.R.S.R.) at the airports at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras.

Kabuli Money Lenders

8677. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the money-lending business being carried on by Kabuli money-lenders in India ;

(b) if so, the number of such foreign money-lenders carrying on the money-lending business in the country ;

(c) whether Government propose to curb such trade by Kabuli money-lenders ; and

(d) if so, the steps taken by Government in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(c) and (d). Apart from the restrictions imposed by the Money-lending Acts in force in the various States, starting of new and expansion of existing business of money-lending is discouraged. For this purpose, entry into and stay in India of Afghan nationals is regulated under the law relating to foreigners.

Issue of Identity Cards to Muslims in Border Areas

8678. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue Identity Cards to Muslims living in areas bordering on Pakistan ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have received any representation suggesting the issue of such identity cards ; and

(d) if so, from whom ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d). A suggestion for the issue of Identity

Cards to Muslims residing in border areas so that the police may not treat them in any way as foreigners, was made at the meeting of the Informal Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs held on the 29th February, 1968. The matter is under examination.

Boards of Members of Air-India and I. A. C.

8679. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of Members constituting the Boards of members of the Air India and the Indian Airlines Corporation ;

(b) the qualifications of these persons and their dates of appointments and re-appointments, if any ; and

(c) their remuneration and duties ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): (a) to (c). The required information is given in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1061/68].

Naxalbari Type Extremists in A. P.

8680. SHRI J. MOHAMED IMAM :
SHRI C. MUTHUSAMI :
SHRI GADILINGANA GOWD :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Naxalbari type of extremists are at large in Srikakulam and other Districts of Andhra Pradesh ;

(b) whether pamphlets on Mao's thoughts in *Tulugu* and Mao's portraits are being freely circulated and displayed in various parts of Srikakulam ; and

(c) whether Government have taken note of this development and the action, if any, proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Attention is invited to reply given to parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 5687 on 29th March, 1968.

(b) Information is being collected.

(c) Adequate measures have been taken by the Government of Andhra Pradesh to

curb unlawful activities and to maintain law and order in the area,

Merger of I.F.A.S. with I.F.S.

8681. SHRI GADILINGANA GOWD :
SHRI C. MUTHUSAMI :
SHRI J. MOHAMED IMAM :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether a plan was mooted out to merge the Indian Frontier Administrative Service with the Indian Foreign Service; and

(b) If so, whether that plan has been shelved and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Private Educational Institutions

8682. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many private educational institutions in the country have become commercial centres and are making profits exploiting the people in the name of institutions ; and

(b) the steps proposed to stop this profiteering in all Private educational Institutions ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) and (b). At its meeting held in October, 1964, the Central Advisory Board of Education brought this matter to the notice of the Government and recommended that :—

“States should take necessary action, including legislation to prevent unauthorised people from setting up institutions, conducting examinations, awarding diplomas and certificates and adopting names such as Universities, Vice Chancellors, etc. The Board suggested that the Government of India should prepare a draft Bill for this purpose to serve as a model to the State Governments. The Bill should provide that any private party starting an educational institution should obtain the permission of the Government to do so.

The Universities should before recognizing or affiliating a college ensure that the managements of private institutions have the resources to establish and maintain proper standards. If any institution is found to be functioning on a commercial basis and is found guilty of non-ethical practices, the Universities should disaffiliate such institutions."

The Ministry of Education circulated the above recommendations to the State Governments/Union Territories and also forwarded a model Bill to regulate and control the activities of such Institutions. The Government of Madras has already enacted this measure and the matter is under the consideration of the other State Governments. As regards Union Territories, the Manipur Administration has also enacted this measure. The enactment of the measure for other Union Territories (which are without Legislative Assemblies of their own) including Delhi is under consideration; a bill for the purpose is at present being scrutinized in the Ministry of Law.

गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर सजा में छूट

8683. श्री प० ल० बाबुलाल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर बन्दिनों को सजा में छूट देने का विचार रखती है तथा क्या सर्वोदय नेताओं ने इस प्रकार की छूट देने की प्रार्थना की है;

(ख) क्या सर्वोदय नेताओं ने केन्द्रीय सरकार से डाकुओं के छोड़ने तथा उनके विरुद्ध मुकदमों के वापिस लेने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का क्या विचार रखती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिष्णु चरण शुक्ल) : (क) से (ग). गांधी जन्म शताब्दी की राष्ट्रीय कमेटी ने गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर जेल अपराधियों की

सजाएं घटाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है। जेल राज्य का विषय होने के कारण इस आवेदन को राज्य सरकारों आदि को विचारार्थ भेज दिया गया है।

सर्वोदय नेताओं से इस विषय में कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

Fire at Indian Freighter 'Vishva Vir'

8684. SHRI C. CHITTYBABU :
SHRI SHIVA CHANDRA JHA:

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Freighter 'Vishva Vir' caught fire at Bangkok on the 5th April, 1968 ;

(b) if so, whether it is also a fact that jute goods and animal hides worth more than Rs. 25,000 were burnt ; and

(c) if so, the cause of the fire ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO) :

(a) to (c). On the 5th April, 1968 fire was detected in the starboard deep tank number 4 of m. v. 'Vishva Vir', when jute bales were being loaded from a barge. The following quantities of cargo, damaged on account of fire and water flooding for extinguishing the fire, were discharged at Bangkok prior to sailing :

Jute	... 1500 bales
Kapok	... 200 bales
Timber	... 235 bundles.

Damage to other cargo, if any, will be ascertained at the ports of discharge in Japan. Money value of damage to cargo is still to be assessed. The cause of the fire is being investigated.

Dredger for Kerala Ports

8685. SHRI C. CHITTYBABU : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first Dredger made in India has been launched in Kerala for the use of minor ports ;

(b) if so, the cost of the Dredger ; and

(c) the ship-yard where it was built ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (PROF. V. K. R. V. RAO): (a) to (c). A 12" cutter suction dredger has been built by Messrs Brunton and Company in their yard at Cochin in collaboration with Messrs I. H. C. Holland, at a cost of about Rs. 24.10 lakhs for supply to the Government of Kerala for use in their minor ports. The trials of the dredger are scheduled to commence on the 29th April 1968. This is not the first dredger to be built in India as dredgers have been built in the past indigenously in collaboration with foreign concerns.

Cyclone Warning Station, Madras

8686. SHRI C. CHITTYBABU: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Cyclone Warning Station is proposed to be set up at Madras ;

(b) the total expenditure likely to be incurred on the scheme ; and when it is likely to be set up ;

(c) whether Government are getting any aid from any foreign country for the purpose and if so, from which country ; and

(d) the capacity of the radar system to be installed at this station ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) and (b). A scheme for the setting up of a Cyclone Warning and Research Centre at Madras and installation of storm-warning radars at various stations on the east and west coasts of India, was included in the draft Fourth Plan of the India Meteorological Department. It has not however been possible to take it up so far due to non-availability of funds. According to the latest assessment, the total expenditure on the scheme is estimated at Rs. 240.67 lakhs over a period of four years.

(c) No, Sir, not for this scheme.

(d) The range of the radar is 400 kilometres.

Theft in Salar Jung Museum, Hyderabad

**8687. SHRI H. N. MUKERJEE :
SHRI GEORGE FERNANDES :**

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether the attention has been drawn to certain articles in "Anticorruption" weekly of Hyderabad in January, 1968 regarding the alleged theft of exhibits in Salar Jung Museum ;

(b) whether the allegations against certain officials of the Museum made therein have been examined ; and

(c) the steps, if any, taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The loss of art objects from the Salar Jung Museum was referred to the local Police as well as to the Central Bureau of Investigation. The Central Bureau of Investigation have recently suggested departmental action against two employees of the Museum. The Salar Jung Museum Board is being asked to take action in this behalf as the disciplinary authority. The Salar Jung Museum Board appointed a high power Committee to examine the various allegations against the Director and other officers. According to the Report of the Committee the allegations were not in effect charges against the Director and other officers but are in the nature of bringing to the notice of administration certain lacunae in the rules. The existing Security arrangements have been tightened. The Board has appointed a Sub Committee to review the rules and to reinforce these arrangements a full time Security Officer has been appointed.

Ajanta-Ellora Frescoes

8688. SHRI H. N. MUKERJEE ; Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an article in "Indian and World Events" (Delhi) of March 17, 1968 entitled "Ajanta-Ellora Frescoes on the verge of ruin" ;

(b) whether it is a fact that all the site museums under the Archaeological

Survey suffer more or less for lack of adequate measures for preservation, research work and watch and ward ; and

(c) the real position in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Adequate measures are taken for preservation of the exhibits in all the site museums under the Archaeological Survey of India. No permanent arrangements for conducting research on an organised basis, However, exist there, but on request from individual scholars, all possible facilities for the study of antiquities, their photographing, etc. are afforded. Watch and ward arrangements have been made at the museums as best as possible within the limitation of funds available to the Survey, although these can by no means be regarded as adequate. Strengthening of such arrangements will be undertaken whenever adequate funds become available.

Secretaries in the Government of India

8689. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of Secretaries in the Government of India drawing Rs. 4,000 and those in the I.A.S. Scale ;

(b) the grounds for selection to those posts, if they are not given according to seniority ;

(c) whether Government propose to leave the selection to the U.P.S.C. ;

(d) the number of cases where Government have ignored the rule that posts in the Secretariat may be held only for three or five years : and the reason therefor ; and

(e) whether Government would ensure the strict observance of the rule of rotation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Secretaries (including Special Secretaries) drawing pay of Rs. 4,000 p.m.....34
Rs. 3,500 p.m:..... 8

(b) Posts of Secretaries are filled on the basis of merit from among the eligible officers.

(c) No. Sir, as the scheme for staffing senior administrative posts including those of Secretaries to Government has already been formulated in consultation with U.P.S.C.

(d) The rule which prescribes the period of tenure for various Secretariat posts also provides for extension of tenure in the public interest. There are 62 officers holding Secretariat posts in whose cases, their continuance beyond the normal tenure has been considered necessary in the public interest.

(e) The tenure rule is observed and extensions of tenure are granted only to the extent considered absolutely necessary and in the public interest.

Wooden Statues in Mekkekattu Temple in South Kanara District

8690. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wooden statues, some measuring 15 feet in the Mekkekattu temple in Barkur Magne of South Kanara District are to be shifted to a museum in Delhi ;

(b) whether Government are aware of the public resentment over the replacing of the original statues by replicas, currently being made at the temple ; and

(c) if so, whether government propose to provide a suitable accommodation for these Statues at the site itself ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The Archaeological Survey of India has been requested to make enquiries and submit a report.

Liquor Shop at Paradeep Port

8691. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether recently a liquor licence of the Orissa Government had undertaken

construction of a building for a liquor shop within the Paradeep Port area without any prior permission of the Paradeep Port Trust ;

(b) whether an emergent meeting of the Port Trust was held recently to consider the situation ; and

(c) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO):

(a) Yes, Sir.

(b) A special meeting of the Paradeep Port Trust Board was called on 4.4.1968 but could not be held for want of quorum.

(c) The matter has been amicably settled by discussion between the State Government officers and the Chairman of the Port Trust. It has been agreed that the licences will vacate the plot on which he had started construction and that the port would lease out a house to him on the other side of Atharbanki creek till the 31st March, 1969.

Senas

8692. SHRI K. P. SINGH DEO :
SHRI BEDABRATA BARUA :
SHNI D. N. DEB :
SHRI RAMACHANDRA
VEERAPPA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have recently issued certain directions to State Governments to curb the activities of various Senas in the country ; and

(b) if so, the reaction of the State Governments thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Central Government are in touch with the State Governments regarding any infungement of the law by volunteer organisations styled as Senas. The State Governments are taking appropriate action under the law to deal with breaches of the law.

Construction of a Jetty at Areal Bay

8693. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state ;

(a) when the project for the construc-

tion of a Jetty at Areal Bay in North Andaman Island was sanctioned, and the stage of the construction now ;

(b) the reasons for the inordinate delay in completing the project ;

(c) what facilities exist now for embarkation and disembarkation of passengers and handling of cargo ; and

(d) when the project is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The sanction for construction of jetty at Areal Bay was accorded in July, 1967. Hydrographic survey, wind and wave observations for a complete cycle of one year to decide location of jetty, finalisation of design, collection of construction material and plant etc. have been completed. Casting of R.C.C. piles and driving piles for jetty is in progress.

(b) The progress of work has been according to programme and there has been no delay in construction work.

(c) Embarkation and disembarkation of passengers and handling of cargo from ship to shore and *vice versa* is being done with the help of *dinghies* on contract basis as no jetty is capable of berthing inter-island ferry vessels.

(d) Construction of the jetty is expected to be completed by December, 1969.

Settlers in Andaman Group of Islands

8694. SHRI K. R. GANESH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of settlers and others in the Havelock, Neil, Baratang and Kadamtalla Islands in the Andaman group and when were these settlements started ;

(b) the frequency of ferry services to these Islands and whether these are adequate ; and

(c) whether there are proposals for the extension of ferry services ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) A statement is laid on the Table of the House

(b) and (c) The normal frequency of

ferry service for Baratang and Uttara (Kadamtala) is twice a week while for Havelock and Neil it is once a week. The Andaman and Nicobar Administration have

a proposal under consideration to introduce a biweekly ferry service from Port Blair to Rangat via Neil and Havelock instead of weekly service.

STATEMENT

Name of Place	Year of commencement of Settlement	Number of settlers	Population according to 1961 Census
Havelock	1955	181 families	897
Neil	1967	86 families	—
Baratang	1959	143 families	730
Kadamtala	1954	153 families	698

Kidnapping of Indians by Pakistanis in Barmer

8695. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Harijan woman and her son of village Padanria in Barmer district were kidnapped by Pakistanis in the first week of April, 1968;

(b) whether 271 heads of cattle and four camels had also been lifted by the Pakistanis from the Districts of Jaisalmer and Barmer during the same period; and

(c) if so, the steps taken to recover them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) (a) : On the night between 28th and 29th March, 1968, one Harijan woman and her son were taken away from Padaria (not Padanria) Village, District Barmer, by an Indian national to Pakistan.

(b) 270 sheep and goats were lifted by Pak criminals on the night between 20th and 21st March 1968 from the Barmer area. Five camels were also lifted from the Jaisalmer area on the 28th March 1968.

(c) The kidnapped Harijan woman and her son and all the lifted sheep goats, and camels have since been retrieved.

Coastal Shipping Services

8696/ SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether his Ministry have taken

any steps to improve and expand the coastal shipping services in the country;

(b) if so, with what result ;

(c) the rate of growth in the coastal shipping tonnage in the country; and

(d) the factors hampering the growth of the coastal shipping services ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V.K.R.V. RAO): (a) to (c). The coastal tonnage which stood at 1.19 lakhs GRT at the time of independence, steadily rose to 4.11 lakhs GRT as on 31.12.1964. Thereafter there has been a decline and the tonnage as on 1.4.68 is only 3.35 lakhs GRT. However problems relating to coastal shipping are under constant review of Government.

The National Shipping Board has set up a study group on 8.9.67 to study the current problems of coastal shipping and make recommendations for its development. The study group has submitted its report to the National Shipping Board on 4.4.68 and the Board is currently seized of the matter. Government will consider the report, after they have received the comments and recommendations of the National Shipping Board on the same.

(d) The main factors which have hampered the development of coastal shipping are—

(i) Uncertainty regarding the availability of bulk cargoes particularly coal;

(ii) Non-availability of foreign exchange for the acquisition of ships from abroad;

- (iii) Lack of enthusiasm among coastal shipowners because coastal freight rates do not, according to them, yield an economic return; and
- (iv) A measure of under-utilisation of capacity due to delays at ports and draft restrictions particularly at Calcutta.

Memorandum from Mining Students of Banaras Hindu University

8697. SHRI GEORGE FERNANDES:
SHRI YASHPAL SINGH :

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether he has received a Memorandum from the Secretary, Mining Students' Committee of the Banaras Hindu University;

(b) if so, the grievances and demands listed therein; and

(c) the steps Government propose to take to resolve these grievances ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes Sir. The Memorandum received is on behalf of the Mining Engineering Students of the Indian School of Mines, Dhanbad, and Banaras Hindu University.

(b) and (c) A statement is laid on the table of the House [Placed in Library. See No. LT—1062/68]

Bridge near Amta in West Bengal

8698. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether a bridge was sanctioned near Amta on Damodar River in the Third Plan Budget of West Bengal;

(b) whether the construction work of the said bridge has started; and

(c) if not, when the work is likely to be started and completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

"Mushvarat"

8699. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new organisation of Muslims called "Mushvarat" has been set up by one Dr. Faridi in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether it is also a fact that aims and principles of the said organisation are anti-Indian and pro-Pakistani;

(c) if so, whether there is any proposal under the consideration of Government to ban this organisation; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

India-Thailand Air Services

8700. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH :
SHRI BEDABRATA BARUA :
SHRI D. N. DEB :
SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA :
SHRI SWELL :

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been reached between India and Thailand for the restoration of air services:

(b) if so, the number of weekly flights of each country to the other ;

(c) the terms of the agreement ; and

(d) the reasons for discontinuation of the air services during the last year ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) Thai Airways International have been authorised to operate not more than seven services a week in each direction to or through India. Of these, not more than four services shall be operated to or through Delhi. Reciprocally, Air India has been authorised to operate not more

than seven services per week to or through Thailand.

(c) The Agreement provides for immediate resumption of air services by the designated airlines of the two countries. Thai Airways have been granted traffic rights in India at Calcutta and Delhi. Additionally, they have also been granted traffic rights between Kathmandu and Indian points. Reciprocally, Air India has been granted traffic rights at Bangkok on a route via Tokyo to New York across the Pacific.

(d) Air India's services through Bangkok and Thai Airways services to Calcutta were discontinued from 1st November, 1967 as no agreement was reached during the two rounds of negotiations held earlier at Bangkok. However, in terms of the agreement now reached, Air India have resumed services through Bangkok from 19th April, 1968 and Thai Airways resumed their services to Calcutta from 25th April, 1968.

शेख अब्दुल्ला द्वारा काश्मीरी पंडितों को जनमत संग्रह मोर्चे में शामिल होने का निमन्त्रण

8701. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए शेख अब्दुल्ला ने काश्मीरी पंडितों को जनमत संग्रह मोर्चे में शामिल होने का परामर्श दिया;

(ख) क्या यह भी सच है कि शेख ने उन्हें घमकी दी कि यदि वह जनमत संग्रह मोर्चे में शामिल नहीं हुए तो वह इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अल्पसंख्यकों के बचाव के बारे में क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार से पूछ-ताछ की गई थी। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार तारीख 6 अप्रैल, 1968 को रैनवारी, श्रीनगर में अपने भाषण के दरम्यान शेख अब्दुल्ला ने अल्प संख्यक समाज के लोगों

को राय बुमारी मोर्चा (प्लेबिसिट फ्रंट) में शामिल होने की सलाह अवश्य दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे हिन्दुओं के अधिकारों के लिये मुसलमानों ने पाकिस्तान का सामना किया था, उसी तरह हिन्दुओं को भी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिये भारत का सामना करना चाहिये और यह कि वे सलाह देंगे और यह उन पर निर्भर है कि वे उसे मान कर चलें अथवा नहीं।

(ग) जम्मू-काश्मीर राज्य में शांति है। राज्य शासन अल्प-संख्यकों की रक्षा के अपने उत्तर दायित्व के प्रति सजग है और भारत सरकार हर जगह अल्प संख्यकों की रक्षा के लिये हर संभव कदम उठायेगी।

इलाहाबाद में हिन्दुओं की गिरफ्तारी

8702. श्री रामगोपाल शालबाले : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद के प्रमुख संगठनों ने इलाहाबाद में हिन्दुओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध सरकार को एक ज्ञापन-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बिद्याचरण शुक्ल) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश व्यापारिक प्रतिष्ठान (चेम्बर आफ कामर्स) की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें हाल में इलाहाबाद में हुई घटनाओं के कारण व गति-विधि का वर्णन था।

(ख) राज्य शासन ने राजस्व मंडल के सदस्य श्री एम० लाल को इलाहाबाद में हुई घटनाओं के कारण व गतिविधि की जांच के लिये नियुक्त किया है।

पुलिस गार्ड का पाकिस्तान भाग जाना

8703. श्री राम गोपाल शालबाबे : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम-नागालैंड सीमा पर नियुक्त एक पुलिस गार्ड पाकिस्तान भाग गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक कांस्टेबल जो आसाम-नागालैंड सीमा पर नियुक्त गश्ती दल का सदस्य था 21 मार्च, 1968 से लापता है। उसके पाकिस्तान को चले जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) कांस्टेबल को खोजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Yardi Committee Report

8704. DR. MAHADEVA PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Yardi Committee was formed in May, 1967 ;

(b) whether it is also a fact that the report was released to the Press before its presentation to the Lok Sabha ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) Yes, but the Study-group was set up in April 1967.

(b) Government have not released the report of the group to the Press.

(c) Does not arise.

Scheduled Castes & Scheduled Tribes in I.A.S. & I. P. S.

8705. SHRI P. R. THAKUR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Caste candidates selected for appointment to the I. A. S. and I. P. S. each year from 1950

to 1967 with their State-wise break-up ; and

(b) the corresponding number of the Scheduled Tribes appointed during the same period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Two statements giving the requisite information are laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1063/68]

Amount spent due to Police Strike in Delhi

8706. SHRI DEVEN SEN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred in connection with the Police agitation in Delhi, in April, 1967 by way of gathering paratroops and other forces of B. S. F., C. R. P., M. P. P. and J & K paratroops ; and

(b) the total number of such paratroops and other Forces thus gathered at that time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) No paratroops were deployed in April, 1967 in connection with the Police agitation in Delhi. The cost of gathering the various police forces is being collected from the authorities concerned and will be laid on the Table of the (Sabha) House.

(b) 4,558 police personnel belonging to B. S. F., C. R. P. & Madhya Pradesh police were gathered in Delhi in April, 1967.

संसदीय कार्य करने वाले व्यक्ति

8707. श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में कुछ व्यक्तियों को केवल संसदीय कार्य के लिये नियुक्त किया गया है जिसका परिणाम यह है कि वे ही इस काम को कर सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में संसदीय सहायकों (पार्लियामेंटरी

ग्रसिस्टेंट) को ग्रन्य ग्रसिस्टेंटों से ग्रधिक वेतन दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
ग्रौर

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मन्त्रालयों के ग्रन्य कर्मचारियों को भी इन पदों पर लगाया जायेगा ताकि उन्हें भी लाभ हो सके यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 4 रुपये प्रतिदिन का विशेष भत्ता 500 रुपये से कम वेतन लेने वाले सहायक को तथा 3 रुपये प्रतिदिन का विशेष भत्ता उच्च श्रेणी लिपिक को पूर्णकालिक संसदीय कार्य करने के लिए दिया जाता है । यह भत्ता समयोपरि भत्ते के बदले में है तथा संसद अधिवेशन की अवधि में ही मिलता है । 500 रुपये प्रति-माह या उससे अधिक वेतन लेने वाले व्यक्तियों को यह विशेष भत्ता नहीं मिलता है ।

(ग) विशेष भत्ता, कार्य के अतिरिक्त घंटों में अमसाध्य कर्तव्यों के कारण हानिपूर्ति के रूप में दिया जाता है ।

(घ) अनुदेश पहले ही विद्यमान है कि ऐसी परिस्थितियों, जिनमें कार्य कुशलता के हित में ग्रन्य व्यवस्था करना उचित हो, को छोड़कर संसदीय सहायकों के पदों पर नियुक्तियां योग्यता प्राप्त तथा समर्थ व्यक्तियों में से बारीबार की जाएं तथा इस क्रम की अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो ।

नेशनल फिटनेस कोर के इन्स्ट्रक्टरस

8708. श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फिटनेस कोर के 2000 फिजीकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टरों ने फरवरी, 1968 में सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है तथा एक प्रदर्शन भी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का व्यौरा क्या है ;
ग्रौर

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) वे पंचकुइयां रोड से भेरे निवास तक जुलूस बना कर शांतिपूर्वक गये ग्रौर निम्नलिखित मार्गों का एक ज्ञापन पेश किया :-

i) नेशनल फिटनेस कोर को केन्द्र के अधीन रहने देना ;

ii) इस योजना को संसदीय कानून द्वारा सांविधिक योजना बनाना ; ग्रौर

iii) नेशनल फिटनेस कोर के वर्तमान महानिदेशक, जिसे 7000 कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त नहीं है, को हटाकर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त ।

(ग) इस सम्बन्ध में 23 फरवरी, 1968 को शिक्षा राज्य मन्त्री श्री भागवत भा आजाद ने लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था जो नेशनल फिटनेस कोर के विकेन्द्रीकरण से संबंधित था । सरकार व्यौरे की जाँच कर रही है । सरकार तीसरी मांग को स्वीकार नहीं करती ।

आजाद हिन्द फौज का स्मारक

8709. श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री 1 मार्च, 1968 के अतारंकित प्रश्न संख्या 2397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आजाद हिन्द फौज का एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिये अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर-सिंह) : (क) ग्रौर (ख). यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली परिवहन का किराया

8710. श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन में छोटे मार्गों पर किराया बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किरायों में की गई इस वृद्धि से कितनी आय होने की सम्भावना है तथा छोटे मागों पर यात्रियों को राहत देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). इस समय दिल्ली परिवहन संस्थान के विचाराधीन किसी भी मार्ग पर किराया बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी 1 अप्रैल 1968 से संस्थान ने 15 मार्गों पर इक्सप्रेस सेवा चालू की है जो संस्थान द्वारा चलाई गई संपूर्ण सेवाओं के 5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। इन एक्सप्रेस सेवाओं पर यात्रा की दूरी का विचार किये बिना 5 पैसा प्रति यात्री अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है।

नई दिल्ली में कुतुबमीनार में पेय जल की व्यवस्था

8711. श्री निहाल सिंह: क्या पर्यटन तथा अर्सेनिक उद्घटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में कुतुबमीनार में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके फलस्वरूप भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस बस्ती के दुकानदार और निवासी पानी का एक ग्लास 5 अथवा 10 पैसे की दर से और मटका भर पानी 75 पैसे अथवा एक रुपये की दर से बेचते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपयुक्त व्यवस्था को समाप्त करने और वहां पर पेय जल की संतोषजनक व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा अर्सेनिक उद्घटन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुतुबमीनार पर मुक्त पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने तीन पैसे ग्लास के हिसाब से ढंडे (रिफ्रिजरेटेड) पानी की भी व्यवस्था की है।

(ख) पुरातत्व से आरक्षित ग्रहाते की सीमाओं में इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Communal Riots in Rourkela

8712. SHRI LATAFAT ALI KHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Afghan nationals killed during the communal riots on the 21st March, 1964 at Rourkela (Orissa) ;

(b) the details of their property burnt and looted ;

(c) the number of representations received by Central Government for payment of compensation ;

(d) the amount of compensation paid in this connection and the details thereof ; and

(e) in case no compensation has so far been paid, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Employment of Foreign Crooners and Cabaret Artistes in Hotels

8713. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have considered the complaints of foreign tourists regarding the lack of entertainment in hotels and restaurants in the country ;

(b) whether Government are considering relaxation in issue of foreign exchange for employing crooners and cabaret artistes from foreign countries for entertaining foreign tourists ; and

(c) whether Government have also considered the question of setting up of "casinos" to attract foreign tourists and foreign exchange ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):
(a) Yes, Sir. The Hotel Industry has been urged to provide such entertainment with indigenous talent, and a tentative allocation of Rs. 50.00 lakhs had been made in the draft Fourth Five Year Plan for the provision of entertainment for tourists.

(b) From a general assessment made of complaints from tourists regarding the lack of entertainment, it is noticed that foreign tourists express a preference for entertainment which reflects the local colour and talent of the country. Also western style entertainment can be provided with indigenous artistes. In view of this no relaxation is being considered for allocating strictly limited foreign exchange resources for the employment of cabaret artistes from foreign countries.

(c) No, Sir.

Restrictions on Visiting Tourist Places in West Bengal

8714. **SHRI S. K. TAPURIAH :**
SHRIMATI JYOTSNA
CHANDA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether restrictions continue for tourists in various areas in West Bengal ;

(b) the other areas in the country which are placed under similar restrictions;

(c) the reasons for such restrictions ; and

(d) how do these restrictions affect the promotion of tourism in West Bengal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). Under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, foreigners desiring to visit Darjeeling, Cooch Bihar, Jalpaiguri, Malda and West Dinajpur Districts of West Bengal ; Uttarkashi, Chamoli and Pithoragarh districts of Uttar Pradesh, Kinnaur, Lahaul and Spiti districts of Himachal Pradesh ; all districts of Assam ; and the

Union Territories of Tripura and Andaman and Nicobar Islands are required to obtain special permits.

(c) For reasons of security.

(d) Permits for visits to places of tourist interest in West Bengal are granted liberally to tourists.

Seizure of Copies of "Mother India"

8715. **SHRI SUBRAVELU :**
SHRI KAMALANATHAN :
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government had ordered the seizure of copies of the Bombay Monthly 'Mother India' April, 1968 issue ;

(b) the date of publication of the issue and the date of issue of the order of seizure ; and

(c) the number of copies seized ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The Lt. Governor of Delhi has by virtue of Notification No. F.2 (42)/68-C/H(G) dated the 8th April, 1968 under Section 99-A Criminal Procedure Code 1898 declared forfeited to Government every copy of the April 1968 issue of 'Mother India' and all other documents containing copies, re-prints and translation of extracts from the said magazine.

(c) Five copies have been seized in Delhi so far. Information regarding seizure in other States and Union Territories is being collected.

"Care"

8716. **SHRI JYOTIRMOY BASU :**
SHRI BHAGBAN DAS :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a foreign organisation named "CARE" has been allowed to work in villages in West Bengal which is a border State under the pretext of helping food production ;

(b) if so, whether this organisation has any connection with Asia foundation ; and

(c) other details thereof ? .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Facts about the work being done by CARE in West Bengal are being ascertained from the State Government.

(b) Government have no such information.

(c) Does not arise.

I.A.C. Viscounts

877. **SHRI GEORGE FERNANDES:** Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Indian Airlines Corporation have finally decided to use the two Viscount Planes—'Raj Hans' and 'Pushpa Hans' which have been in their care for nearly a year now ;

(b) if not, the reasons therefor and what is their disposal ; and

(c) the net loss incurred by the I.A.C. so far in maintaining these two Viscounts and on account of their parking charges ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH):

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The aircraft required modifications to make them suitable for civil use, which are being carried out. The question of loss does not arise.

The Corporation has also so far paid Rs. 3,550/- as parking charges.

Foreign Scholarship to Scheduled Tribes for Study Abroad

8718. **SHRI KARTIK ORAON :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state ;

(a) the total number of foreign scholarships granted to the members of Scheduled Tribes for Study Abroad after the Independence ;

(b) the total number of scholars out of them who have been converted to Christianity at the time of availing of the opportunity for grant of scholarship for study abroad ; and

(c) the total amount spent so far for the purpose of grant of foreign scholarships for studies abroad to these scholars ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) During the last five years, nine scholars belonging to Scheduled Tribes have been selected and sent abroad. Besides, nine other candidates have been awarded scholarships and their admissions to suitable institutions are being finalised. It is not possible to give information for earlier years as most of the relevant records have already been destroyed.

(b) Information is not available.

(c) In addition to the Passage cost both ways and equipment grant of Rs. 500, the average annual expenditure incurred on a scholar which covers tuition fees, maintenance allowance, books etc. is 3,000 dollars approximately in USA and 650 pounds approximately in U.K., the two countries to which these scholars are mostly sent.

Commission for Scientific and Technical Terminology

8719. **SHRI ONKAR SINGH :** Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) the names of private Presses through which the Commission for Scientific and Technical Terminology is getting the manuscripts printed :

(b) whether they have been categorised Class A, B and C ;

(c) whether any such presses have been paid at rates admissible to Class A presses; and

(d) if so, the reasons therefor and the action taken against the person responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SHER SINGH) : (a) The Commission does not maintain a standing list of printing Presses, as the work of printing is allotted to the lowest rates by calling tenders from the open market.

(b) to (d). Does not arise.

केन्द्रीय मन्त्रालयों में हिन्दी अधिकारी

8720. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति ने इस बात पर बार-बार जोर दिया है कि प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभाग में हिन्दी अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिएं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मन्त्रालयों, संबद्ध तथा अधीन कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं ;

(ग) इन कार्यालयों में हिन्दी के काम की देख-रेख करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(घ) इन कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कुल 41 मन्त्रालयों/विभागों में से, 21 में हिन्दी अधिकारी पहले से ही कार्य कर रहे हैं । अन्य 15 मन्त्रालयों/विभागों में से प्रत्येक में एक-एक अधिकारी अपनी सामान्य ड्यूटी के अनिश्चित हिन्दी का कार्य देख रहे हैं । शेष 5 मन्त्रालयों/विभागों में हिन्दी का कार्य अभी इतना नहीं है कि हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति की जाये । सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों में साधारणतः हिन्दी अधिकारी नहीं होते हैं ।

(घ) प्रत्येक मन्त्रालय/विभाग के आकार और प्रशासनिक संगठन को ध्यान में रख कर ही हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ।

Hindi Advisory Committee

- 8721. SHRI JAGANNATH RAO JOSHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Advisory Committee has at page 37 of its report dated 10th July, 1967 observed that

Government have not attached importance to the work of propagation of Hindi ;

(b) whether on the same page, the Committee has also observed that the pay scales of the Hindi Assistants doing translation work should be higher than that of other Assistants ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). No report has been issued by the Hindi Advisory Committee. The Honourable Member has perhaps in mind p. 37 of the report prepared by Hindi Adviser where reference has been made to sufficient importance not being given to Hindi work and to the need for improving the pay scale of the Hindi Assistants ;

(c) Copies of the Report of the Hindi Adviser have been sent to the concerned Ministries for necessary action.

विभिन्न मन्त्रालयों में हिन्दी में कार्य

8722. श्री शारदा नन्द : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी सलाहकार द्वारा व्यक्त किये गये इस मत की जानकारी है कि भारत सरकार के मन्त्रालयों में और विशेषतया सिचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में हिन्दी में उतना काम नहीं किया जा रहा है, जितना किया जाना चाहिये था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मन्त्रालयों में हिन्दी सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों के पदों की संख्या बहुत कम है तथा एक मन्त्रालय का सारा काम दो अथवा तीन कर्मचारियों को करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए एक योजना बनाने का सरकार का विचार है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हिन्दी सलाहकार ने सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में हिन्दी के काम की कम मात्रा के सम्बन्ध में अपने विचार दिये हैं। उन्होंने, रिपोर्टों के घटिया हिन्दी अनुवाद जो अदक्ष कर्मचारियों की सहायता से किये जाते हैं और हिन्दी के छोटे-छोटे पत्रों के भी विचार करने से पूर्व अंग्रेजी अनुवाद कराने की परिपाटी की और भी, ध्यान दिनाया है।

(ख) मंत्रालयों में हिन्दी सहायक अनुवादक पूर्णतः हिन्दीका काम नहीं कर रहे हैं। वह मुख्यतः अनुवाद ही करते हैं, क्योंकि हिन्दी का अन्य काम अनुभागों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की सहायता से किया जाता है।

(ग) और (घ). सभी मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी का काम करने के लिए अपेक्षित स्टाफ है, जिस में हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल हैं। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। राज्यभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य अनुदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

हिन्दी प्रसिस्टेंट और हिन्दी स्टेनोग्राफर

8723. श्री शारदा नन्द : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में तीसरी श्रेणी के हिन्दी प्रसिस्टेंटों को 3 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद स्थायी बना दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तीसरी श्रेणी के हिन्दी स्टेनोग्राफर 12 वर्ष का सेवा काल पूरा करने के बाद भी अस्थायी हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). जुलाई

1966 में जारी किये गये आदेशों के अधीन श्रेणी III पदों के हिन्दी सहायक, जिन्होंने 1959 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास नहीं की थी किन्तु जिन्होंने 1-9-1959 को उस पद में कम से कम तीन साल की सेवा की थी, उपयुक्त होने और स्थायी पद उपलब्ध होने पर स्थायी होने के पात्र हो सकते हैं।

हिन्दी स्टेनोग्राफरों (श्रेणी III) को, जिन्होंने दीर्घ काल की सेवा की है, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट देने तथा स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हिन्दी स्टेनोग्राफर

8724. श्री शारदा नन्द : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मन्त्रालयों में काम करने वाले तीसरी श्रेणी के हिन्दी स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त किये गये और 10 वर्ष से भी अधिक सेवा वाले हिन्दी स्टेनोग्राफरों के लिये उनके स्थायीकरण के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना अवनिवार्य करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां, श्रीमान्। हिन्दी स्टेनोग्राफरों (श्रेणी-III) के पद पृथक होने के कारण तदर्थ आघार पर मन्त्रालयों/विभागों द्वारा भरे जाते थे।

(ख) 1955 में जारी किये गये आदेशों के अधीन तदर्थ आघार पर नियुक्त हिन्दी स्टेनोग्राफरों को स्थायी होने का पात्र बनने के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी आवश्यक थी। स्थायीकरण के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना कोई नई अपेक्षा नहीं है। तथापि हिन्दी स्टेनोग्राफरों (श्रेणी-III) के दीर्घ सेवा काल को ध्यान में

रखते हुए स्थायी करने के लिये उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से छूट देने का प्रश्न श्री परीक्षाधीन है।

**बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
के तदर्थ पदोन्नतियाँ**

8725. श्री नारायण स्वरूप शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में हाल में बारह सहायक शिक्षा अधिकारियों की तदर्थ आचार पर वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को संघ सेवा आयोग के माध्यम से ऋब भरा जायेगा ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में 12 नहीं किन्तु 11 सहायक शिक्षा अधिकारी प्रबन्ध अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आचार पर पदोन्नत किये गए हैं।

(ख) नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आचार पर कार्य के हिन में तब तक के लिए की गई हैं जब तक कि संघीय लोक सेवा आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नामित व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जाते।

(ग) ये पद भर्ती के नियमों को अंतिम रूप देने के बाद उनके अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाएंगे।

केन्द्रीय प्रकाशन संगठन

8726. श्री नारायण स्वरूप शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के

तत्वावधान में केन्द्रीय प्रकाशन संगठन बनाने की एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस योजना पर कितना वार्षिक खर्च होने की संभावना है; और

(घ) योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं। अभी तक नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग में पाण्डुलिपियों की छपाई

8727. श्री नारायण स्वरूप शर्मा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के पास बहुत सी पाण्डुलिपियां पड़ी हैं, जिन्हें प्रकाशन के लिये नहीं भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितनी पाण्डुलिपियां छापे जाने के लिये पूरी तरह तैयार हैं और वे किन-किन तारीखों को प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ पाण्डुलिपियां, जो अन्य पाण्डुलिपियों के बाद में प्राप्त हुई थीं, छापे जाने के लिये भेज दी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) ऐसी कोई पाण्डुलिपि आयोग के पास नहीं है जो प्रत्येक प्रकार से पूरी हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। यह सच नहीं है कि प्रत्येक प्रकार से पूरी कुछ पाण्डुलिपियां, जो दूसरी पाण्डुलिपियों के बाद में प्राप्त हुई थीं, छपाई के लिए भेज दी गई थीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Birbal Sahni Institute of Palaeobotany

8728. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of EDUCATION be pleased to state :

(a) whether it is fact that a Committee has been appointed to enquire into the working of the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Lucknow ;

(b) if so, the personnel of the Committee and their findings so far ; and

(c) whether Central Government are taking over the Institute and if so, the expenditure involved in doing so and the liabilities of the Institute at present ?

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T.1064, 68*].

(c) The report of the Committee is under consideration.

Lachit Sena

8729. SHRI D N. PATODIA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Central Government have been informed by the Government of Assam, about the steps taken by them either to ban the "Lachit Sena" or to curb its activities ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) and (b). The State Government have issued detention orders under the Preventive Detention Act, 1950, against 29 persons suspected to be involved in giving publicity to leaflets of Lachit Sena. Out of this 26 have already been detained.

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 4915 DATED 19.4.1968 REGARDING INQUIRY OFFICERS OF DELHI ADMINISTRATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : On 19th April, 1968, in reply to question No. (Un-

starred) 7915 by the Hon'ble Member Shri K. P. Singh Deo I had mentioned that in a certain disciplinary proceeding Shri K.C. Consul, Assistant Director, Industries, Delhi Administration had held only two hearings. However on verification it was detected that the number of hearings held by Shri Consul were six and not two.

12.24 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री रवि राव (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे उद्योग मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद के खिलाफ स्वाधिकार भंग करने का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की।

यह जो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ वह प्रमाण के साथ रखता हूँ। मुख्य चीज यह है कि हम जो संसद में आये हैं तो संसदीय प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिए आये हैं। अब मेरा जो स्वाधिकार भंग का सवाल है उस का इस बुनियादी सवाल के साथ ताल्लुक है कि हमारे देश में संसदीय प्रजातन्त्र आया एक सच्चाई और सत्य पर आधारित होगा या वह झूठ, गलत बयानी और डेलीबरेट मिस्लीडिंग स्टे.मेंट पर आधारित होगा ?

आप के सामने यह जो दो बयान श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से दिये गये हैं, एक तो 2 अप्रैल का और दूसरा 24 अप्रैल का, इन दोनों बयानों से मैं आपके सामने यह साबित करता हूँ कि यह स्वाधिकार भंग के सवाल के लिए प्राइमफेसी केस है।

अध्यक्ष महोदय, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का 2 अप्रैल का शीर्ट नोटिस बरेडचन इस प्रकार का था ?

"Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Professor M. S. Thacker, the Chairman of the Committee appointed to investigate into the question

[श्री रवि राय]

of issue of industrial licences to private monopoly houses in the country has accepted the directorship of the Bank of India and is attending its meeting ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद उसके जवाब में कहते हैं :

"(a) and (b). The facts regarding the question are that it is understood that Professor M. S. Thacker, Chairman of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, was invited informally to a meeting of the Board of Directors of the Bank of India on the 28th March, 1968, to let them know his decision on the offer made to him of Directorship on the Board of the Bank. After telling them that he required three to four weeks to consider his decision, Professor Thacker came away from the meeting. Subsequently, the Government have been informed that he has declined the offer. In the circumstances, it is not proposed by Government to take any further action in the matter."

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो एक जुमला है ही हैज डिक्लाइंड दी और, उस जुमले की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे तो बाद में श्री उमानाथ और प्रोफेसर रंगा के सवाल और दूसरे सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री जी ने इस को दुहराया है ही हैज डिक्लाइंड दी और। लेकिन असल सवाल यह है कि हमको लगता है कि 2 अप्रैल, को जब सदन में यह चीज आई और आप ने जैसे सदन के रुख को देख कर मंत्री जी को बताया कि इस के ऊपर जांच होनी चाहिए तो हम को लगता है कि शॉर्ट नोटिश क्वेश्चन जब आया तो मंत्री जी के दिमाग में यह चीज आई कि कैसे उसको घपले में डाल दें और संसद के सामने गलत बयानी करें। सवाल यह है कि जब इस पर इस सदन में बहस हो रही थी तो ठेकर साहब उस वक्त अमरीका में थे

और वहाँ से लौटने के बाद उनकी जो चिट्ठी अखबार में छपी उस चिट्ठी में से मैं यहां कोट करना चाहता हूँ। मैं स्टेटसमेंट से उस में से कोट कर रहा हूँ। ठेकर साहब उस में यह फरमाते हैं :

"In a letter to the Minister of Industrial Development, Prof. Thacker said the Minister would recall that he did not have any objection to his continuing as a honorary Chairman of the Committee and accepting directorship of the Bank. He further said that the whole complexion of the discussion on April 2nd in Lok Sabha would, perhaps, have changed if one important fact that 'I have taken prior permission of the Government to consider the offer of directorship had been disclosed.'"

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : On a point of order, Sir, I am referring to Rule 225 about the mode of raising a question of breach of privilege. While raising a question of privilege...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : You have allowed it, Sir. There cannot be any point of order.

SHRI R. D. BHANDARE : I am on a point of order under Rule 225, the mode in which it could be raised. While raising it, he is dealing with the whole subject matter. He should confine himself to— one or two minutes.....

MR. SPEAKER : A short statement.

SHRI R. D. BHANDARE : He is dealing with the merits of the case.

MR. SPEAKER : I would have myself rung the bell if you had waited for a minute more.

श्री रवि राय : माननीय सदस्य को धीरज रखना चाहिए। मैं पांच मिनट में खत्म किये देता हूँ।

SHRI R. D. BHANDARE : Therefore, my submission is that some sanctity should

be attached to the Rules. He is going into the whole matter from A to Z.

MR. SPEAKER : The point is, according to the Rules, a short statement can be made. If 25 people get up, then a discussion will come at that stage and the motion will be moved and, then, I will fix time. What is a short statement, 1 minute or 2 minutes or 4 minutes, you should leave it to me. It may be 2 minutes or 4 minutes or so. It is not one hour. I am sure about it.

SHRI R. D. BHANDARE : The whole thing, from 'A' to 'Z', is being discussed. That is the point that I am raising.....
(Interruptions).

MR. SPEAKER : They will also have a chance afterwards. Mr. Rabi Ray.

श्री रवि राय : यह प्राइमा फेसी केस है, इसको बतलाने में मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैं श्री ठाँकर का बयान पढ़ रहा था। वह फरमाते हैं कि :

"He further said that the whole complexion of the discussion on April 2nd in Lok Sabha would perhaps have changed if one important fact that, 'I had taken prior permission of the Government to consider the offer of directorship' had been disclosed. In his letter he further said, his going to Bombay was also within the knowledge of the Government. After obtaining your clearance, I also discussed the matter with my two colleagues and in view of the position taken by them, I had offered to resign the Chairmanship of the Committee..."

उसके बाद जब 24 तारीख को श्री अहमद बयान देते हैं तब वह अपने बयान में फरमाते हैं कि उन के बम्बई जाने के पहले हम को मालूम नहीं था कि बैंक की मिटिंग में जा रहे हैं, लेकिन दो मिनट बाद वह कहते हैं कि बम्बई जाने के पहले मेरी उन से मुलाकात हुई थी। जब बम्बई जाने के पहले मुलाकात हुई थी तब यह बात साफ हो गई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह स्वाधिकार भंग का प्राइमा फेसी केस है।

मैं पार्लियामेन्टी प्रैक्टिस के पृष्ठ 115 से पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। वह उद्धरण इस प्रकार है कि :

"The House may treat the making of a deliberately misleading statement as a contempt. In 1963, the House resolved that in making a personal statement which contained words which he later admitted not to be true, a former member had been guilty of a grave contempt."

इसलिये मेरा पहला मुद्दा यह है कि श्री अहमद ने जान-बूझ कर सदन में गलत बयानी की थी, दूसरा मुद्दा यह है कि इसमें जो त्रिकोण चलता है अफसर शाही, मंत्री और करोड़पतियों का, वह सदन के सामने आ जायेगा जब आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपर्व करेंगे। इस लिए मैं अनुमति चाहता हूँ इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्व किया जाय।

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : May I just... (Interruptions).

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : इस स्टेज पर कोई भाषण नहीं होगा। मंत्री महोदय को केवल यह निवेदन करना है कि उस का आक्षेप है या नहीं।

MR. SPEAKER : I will give him a chance to speak later. Now, is there any objection to leave being granted? That is the point... (Interruptions). It is not a question of leave being granted to be sent to the Privileges Committee; it is for moving it... (Interruptions).

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : We object.

श्री मधु लिमये : अनुमति मांग रहे हैं। उस के बाद प्रस्ताव आयेगा।

MR. SPEAKER : Those in favour of leave being granted to move the motion may please stand up...

SOME HON. MEMBERS rose—

MR. SPEAKER : I find that the number is more than 25. Now, Mr. Rabi Ray will move the Motion. A number of members have given notice, but only one of them will move.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“यूँ कि इस सभा की राय में औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कानून मंत्री के द्वारा 2 अप्रैल, 1968 के दिए गए उत्तर से उनके द्वारा सदन के विशेषाधिकारों का भंग हुआ है या नहीं इसकी विशेषाधिकार समिति के द्वारा जांच कराने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है, इसलिए यह सभा यह मामला विशेषाधिकार समिति पर सौंप देने का निर्णय करती है तथा समिति को निर्देश देती है कि जल्द से जल्द के पहले दिन यह अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करें।”

MR. SPEAKER : Motion moved :

“Whereas in the opinion of this House, it clearly appears necessary to inquire whether a breach of privilege of the House has been committed or not by the Minister of Industrial Development and Company Affairs by the reply given by him on the 2nd April, 1968, this House, therefore, resolves to refer this matter to the Committee of Privileges with instructions to report on the first day of the next session.”

The motion is now before the House for discussion.

How much of time would the hon. members like to have for this ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : It is a very important matter.

MR. SPEAKER : It is because of its importance that I allowed it to be moved. Shall we have two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. SPEAKER : We shall have two hours.

Mr. Rabi Ray,

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसल में जो प्रस्ताव आप के सामने रखा गया है मैं उसके सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने जान-बूझ कर संसद से यह सारी जानकारी छिपाने की कोशिश की है। यह मामला संसद की सजगता और आप के इंटरवेंशन की वजह से सदन के सामने आ गया, वरना हम को लगता है कि दोनों चीजें साथ-साथ चलतीं।

12.36 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री ठंकर इंडस्ट्रियल पालिसी कमिशन के चेअरमैन भी बनते और उसके साथ-साथ बैंक के डाइरेक्टर भी बनते। इस सारे किस्से के बारे में मैं अपना राइट रिजर्व रखता हूँ और बहुत खरम होने के बाद जवाब में जो कुछ कहना होगा वह कहूँगा।

SHRI RANGA (Srikakulam) : Mr. Deputy Speaker, Sir.

श्री जगु निम्बये : एक बिनती है। समय पहले से निर्धारित कर दिया जाये ताकि सब को मौका मिले।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have got two hours. Just 5 to 7 minutes, not more than that for each Group.

श्री जगु निम्बये : इस तरह समय बांटिये कि सब को मौका मिले।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will try to accommodate.

SHRI RANGA : Mr. Deputy-Speaker, Sir, we are concerned now with the manner in which a Minister has to behave towards his subordinates and colleagues, towards his subordinates and others who have to co-operate with him in his Ministry and also towards this House and towards the country. I am not particularly anxious, as I said yesterday, we are not particularly anxious to go for any one of these Minis-

ters and this Minister in particular and try to pillory them. We are concerned with the propriety. All these four or five years, we have been concerned with this and three or four Ministers have had to go, not because the Prime Minister was not in love with them, but because it so happened that the Prime Minister found it impossible to allow those colleagues of theirs to continue to be Members of the Cabinet under those circumstances, under those unfortunate circumstances in which they placed themselves. Here is a Minister, Sir, who is not a novice to this job; he had been a Minister for many years in Assam, his own State, and he was one of the important Ministers also, second only in importance, I suppose, after the Chief Minister. Afterwards he had been here with us for some years. Therefore, there can be no such excuse as to be trotted out that he is not aware of what is happening here, the conventions that the House, the standards that the House and the public except of a Central Cabinet Minister and, therefore, he made a mistake.

It is quite clear on the face of all the facts that I have before me—and much of these facts, I think, are already public property—that the Minister has behaved badly and has not placed all the truth before this House and has, because of his interest in the Cabinet and in his own position, tried consciously or unconsciously, to mislead the House, and therefore, under such circumstances, such a Minister should have been asked by the Prime Minister, herself, on the examination of the facts, to part company with the Cabinet. Since they have not performed their duty, their obvious duty, it is the duty, of this House to consider in what manner they can deal with this Minister and the Cabinet under this set up.

What is the latest position? The latest position is that the Minister is supposed to have informed Prof. Thacker—this is my information:

“Since I had always treated you as my colleague, I could not put it more strongly at that time but did expect that you would appreciate the position of the Government and take a considered decision. Your letter dated 21st March, 1968, was, therefore, based on a mis-comprehension...”

Actually, Sir, Dr. Thacker behaved, according to me, properly.

He was not a Government officer. He did not get any pension when he was retiring from that Planning Commission or some other office and he came in there only for a particular period. Thereafter he did not apply for this chairmanship as a kind of applicant, as so many of the people are doing even for Ministerships. He was invited to be the Chairman. Afterwards he told them about his own personal difficulties because he had to go out and there was no other job for him, he had to maintain himself, and an offer of that bank was made to him and therefore he sought the advice of the Minister as well as the advisers. And who were his advisers? The Secretary of the Ministry, Shri Wanchoo, and the Secretary to the Committee, Shri Rathee. These two officers were quite clear in their minds that there would be no impropriety if only Dr. Thacker was asked to serve in an honorary capacity not drawing any salary at all but at the same time he can be allowed to continue to function as Chairman as also director of that bank. Whether it was right or wrong, is another matter.

SHRI R. D. BHANDARE: You are badly defending him.

SHRI RANGA: Badly defending whom? I am not interested in defending Dr. Thacker. Rather I am interested in accusing the Minister here. Here was this poor Dr. Thacker. It was not his job to make up his mind whether it was right or wrong. His job was to place all the facts squarely before the Minister, as well as his advisers, and he placed those facts. It is not contended that he had hidden anything at all. When the Chairmanship was offered to him he was entitled to three months leave and he could continue to draw that salary. He was not to draw anything from the Licensing Committee. Here, what was the advice that was given to him? The hon. Minister might say that it is not any of his job. But I say, it is his duty to have advised Dr. Thacker properly. And what was the proper advice he could have given? Now they have found that it would be necessary for Dr. Thacker to resign or to work as an

[Shri Ranga]

honorary Chairman. They could have told him that, and they have actually told him that he could function as an honorary Chairman without drawing any salary at all. And it was on that understanding that Dr. Thacker had functioned taking successive steps which he took thereafter.

Sir, why did this Government allow him to go to Bombay when he continued to be the Chairman? Afterwards he was allowed to go to New York and he continued to be the Chairman. He was also allowed to consult his colleagues about the propriety of his position. If they had felt that it was wrong, they need not have allowed him to take all these steps. All these things were placed before the Government. It is not as if anything was kept as a secret. Therefore it is not right for the Government to say that Dr. Thacker has misled them. They cannot say so. The next thing is, has Dr. Thacker hidden anything? I am quoting from what I consider to be the Minister's letter to Dr. Thacker dated the 21st April. He said 'You have been my colleague and I could not be harsher than this or softer than this.' That is exactly where the Minister comes in. He has got to be the hardest man and the harsnest man even towards his own son, towards his own wife, towards himself if he were to function as an upright Minister. If he finds that his wife or his son is likely to mislead him into wrong action or he is himself likely to take wrong action, he should be harsh. It is at that stage that my hon. friend the Minister has gone wrong, Sir. Instead of giving proper advice he misled him. Instead of directing him not to accept the job, he rather encouraged him to accept the other job. It was his duty not merely to discourage but to ask him not to accept it, not to consider it at all. He did not do that.

SHRI F. A. AHMED : He has not accepted it.

SHRI RANGA : He has not accepted later. And what is more? That is my point. It was because of the misbehaviour, the uncowardly behaviour, the uncharitable, unchivalrous behaviour of this Minister that he was obliged to resign from that

job and at the same time he was forced to accept here the position of not being an honorary chairman and thereafter he was embarrassed to such an extent and placed in such an embarrassing situation in the eyes of this House by the wrong and false statements made by the Minister, that this distinguished scientist and engineer who has had a meritorious career behind him was obliged to lose both that Directorship as well as the honorary Chairmanship of this Committee. The hon. Minister himself says that Prof. Thacker had not accepted it. So, Prof. Thacker has lost both the positions.

Now, the hon. Minister stands here condemned for having broken faith with his own colleague....

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : On a point of order...

SHRI RANGA : The next thing is that he comes here and gives this wrong information.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : On a point of order. With all due respect to Shri Ranga, I would submit that this is a privilege motion, and he has to draw the attention of the House to the question in what manner the hon. Minister was able to mislead the House or to whatever wrong statement has been made. Prof. Ranga has now gone about championing the case of Prof. Thacker. He is free to do so, and we have no objection. But I want your ruling clearly on this point that he should confine himself to the propriety of the privilege motion.

SHRI RANGA : Prof. Thacker has already stated it. My hon. friend Shri Rabi Ray has already read out a certain portion from his last letter. Prof. Thacker has said :

"I have never tried to do anything unbecoming of the status and the position I have had the privilege of occupying in Government."

SHRI GOVINDA MENON : Did the Minister say that he had done any such thing?

SHRI RANGA : Here is a Minister who comes and says this that he has misled the House ; he says that he had advised him, he had asked him and he had even warned him not to accept it but he did not do so. I consider that to be an untruth, to put it at the lowest.

The third point is this. How has he behaved towards the country as a whole ? How does the country look upon these Ministers and this Ministership ? The country expects a Minister to keep faith with this House as well as with his colleagues in the Ministry. This Minister has failed in keeping faith with this House as well as with his colleagues. And what is more, he has failed to maintain the standards that this House as well as the country had expected of him.

Therefore, I plead that this should be sent to the Privileges Committee.

SHRI GOVINDA MENON : On a point of order. As far as I have been able to see, there are about eight privilege motions. All these motions refer to a statement made by the Minister on the 2nd April. The debate in this House would become very easy if hon. Members would point out which particular statement or statement of fact in the answer on the 2nd April...

श्री मधु लिमये : चर्चा के दौरान में साफ होगा ।

SHRI GOVINDA MENON : ...or which particular statement made by him on the 2nd April is objectionable, is false and has misled the House. I say this after hearing for some time what Shri Ranga has been saying. I have not been able to see which particular statement in the answer which was given on the 2nd April was objected to...

श्री मधु लिमये : ये तो भाषण दे रहे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his point of order.

SHRI GOVINDA MENON : My point of order is this. On a privilege motion based on a statement referred to in the motion, the objectionable portions in that

statement should be referred to so that the hon. Minister may answer.

MR. DEPUTY-SPEAKER : As he has rightly stated, the main question is whether he has by his two statements misled the House, but to prove that the statements were not truthful to his knowledge completely...

SHRI GOVINDA MENON : Which statement ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The statements made by the Minister. Members will naturally refer to Prof. Thacker. I cannot completely prevent reference to Prof. Thacker. Reference to Prof. Thacker is bound to come in. That cannot be completely banned. But I would suggest that Members should not devote more time on that. They can just refer to it to prove what they want to prove and nothing beyond that.

SHRI GOVINDA MENON : I would respectfully ask with respect to what portion in the statement these things are relevant.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I entirely agree that that must be pin-pointed. Shri Nahata.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I have to go at 2 p.m. If you could accommodate me and give me a chance to speak just now, it would help me.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Shri Nahata is already on his legs. What is this you are being asked to do ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He will finish in 5 minutes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : If you do not accommodate us, we will not in future permit such accommodation sought by the other side.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already called Shri Nahata. I will call you after him.

श्री अमृत नाहाटा (बाइमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न उस दिन से उठा, जिस दिन ग्रसबारों में हम ने पढ़ा कि ठाकर साहब ने एक चिट्ठी मिनिस्टर साहब को लिखी है, जिस में उन्होंने कहा है कि अगर मिनिस्टर साहब सदन को यह बता देते कि बम्बई जाने से पहले ठाकर साहब ने मिनिस्टर साहब से बैंक की डायरेक्टरशिप स्वीकार करने की इजाजत ले ली थी, तो शायद सदन में ठाकर साहब की इतनी आसोचना नहीं होती। ठाकर साहब कहते हैं कि वह मिनिस्टर साहब की इजाजत लेकर बम्बई गए और उन्होंने बैंक की डायरेक्टरशिप स्वीकार की। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ठाकर साहब उनके पास आए और उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या वह बैंक के डायरेक्टर बनें या नहीं। मिनिस्टर साहब ने इस सदन को बताया कि उन्होंने ठाकर साहब को जवाब दिया कि आप बैंक की डायरेक्टरशिप स्वीकार करें या न करें, यह आप का जाती मामला है, लेकिन आप को यह सोचना पड़ेगा कि आप बैंक की डायरेक्टरशिप भी स्वीकार करें और इस कमेटी के चेयरमैन भी बने रहें, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं।

उस के कुछ दिनों बाद ठाकर साहब मिनिस्टर साहब के पास आए और कहने लगे कि मैं बम्बई जा रहा हूँ। ठाकर साहब बम्बई गये थे इस कमेटी के चेयरमैन के नाते। उस का खर्चा उन्होंने इस कमेटी से चांज किया। बम्बई में वह महाराष्ट्र सरकार की गाड़ी में बूमे। वह इस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इस कमेटी की एक मीटिंग एटैन्ड करने के लिए जा रहे थे। अगर वह मिनिस्टर साहब से यह कह गये कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बैंक के डायरेक्टर्स की मीटिंग एटैन्ड करने के लिए जा रहे थे। ठाकर साहब ने मिनिस्टर साहब को यह तो नहीं कहा कि मैं बैंक के डायरेक्टर्स की मीटिंग एटैन्ड करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा

है, वह वहाँ इस कमेटी से सम्बन्धित एक मीटिंग को एटैन्ड करने के लिये गए थे।

बम्बई में उन्होंने बैंक के डायरेक्टर्स की मीटिंग एटैन्ड की, वापस आए और मिनिस्टर साहब को बताया कि मैंने वह डायरेक्टरशिप स्वीकार कर ली है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप ने यह अच्छा नहीं किया है। जब ठाकर साहब को यह मालूम हुआ कि मिनिस्टर साहब नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बैंक की डायरेक्टरशिप और इस कमेटी की चेयरमैनशिप दोनों साथ नहीं चल सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। उन्होंने दिल्ली से बैंक वालों को बम्बई टेलीफोन किया कि डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स में मेरी उपस्थिति और मेरे स्वागत का जो खिन्न है, उसको मिनट्स से निकाल दीजिए। फिर उन्होंने मिनिस्टर साहब को कहा कि अच्छी बात है, मैं बैंक की डायरेक्टरशिप छोड़ देता हूँ।

हजारी रिपोर्ट के आधार पर, सरकार की लाइसेंसिंग पालिसी की जांच करने के लिए, यह कमेटी बनाई गई और ठाकर साहब उसके चेयरमैन बने। इस कमेटी के कार्य के सिलसिले में कुछ मालूमात बाहर आई, जो ठाकर साहब को मालूम थीं। मुझे निश्चयपूर्वक मालूम है कि जिन लोगों के खिलाफ यह कमेटी जांच कर रही थी, ठाकर साहब ने उन्हें कहा कि आपके खिलाफ बड़ी खतरनाक रिपोर्ट तैयार होने वाली है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : As has been rightly pointed out, the main issue should be pinpointed. Incidentally, he can refer to Prof. Thacker. That is all right. He has raised a point which is very relevant. Beyond that, he should not go.

SHRI AMRIT NAHATA : I am trying to be very relevant.

मैं बिल्कुल रिलेवेंट बात कर रहा हूँ। मैं कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कर रहा। मैं अधिकार-

पूर्वक कह सकता हूँ कि ठाकर साहब ने उस कमेटी के चेअरमैन होने के नाते अपने अधिकार का दुरुपयोग करके, जिन लोगों के विरुद्ध बड़े जांच कमेटी कर रही थी, उनको बताया कि आपके खिलाफ रिपोर्ट बन रही है। उन लोगों के कोशिश करके ठाकर साहब को बैंक का डायरेक्टर बनाया।

सारे देश के बड़े उद्योगपति, बिग बिजिनेस का यह पदार्थ है कि यह कमेटी कोई जांच न कर पाये; वे इस कमेटी को खत्म करना चाहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब से सरकार ने श्रीर इस मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम को खत्म किया जायेगा, कम्पनीज पोलीटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं दे सकेंगी, बिड़लाओं के कुछ कारनामों की जांच की जायेगी और यह लाइसेंसिंग पालिसी एन्वायरी कमेटी बाकी यह मालूम करेगी कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस कैसे दिये गए, तब से बड़े उद्योगपति इस मंत्रालय के खून के प्यासे ही रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन को यह फैसला करना है कि क्या ठाकर साहब का कहना सही है, एक वॉलफ़ कानफ्लेट लैकी जांच बिग बिजिनेस का कहना सही है, एक ऐसे व्यक्ति का कहना सही है, जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, या मंत्री महोदय का कहना सही है, जिन्होंने ठाकर साहब को साफ कह दिया था कि या तो बैंक के डायरेक्टर बनो और या कमेटी के चेअरमैन रहो, दोनों बातें साब नहीं चल सकती हैं।

इन सबों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने इस सदन के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि ठाकर साहब ने जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया और बिग बिजिनेस के कहने पर अपने आप को बेच दिया, उनके बड़े कामों की निम्ना की जानी चाहिए और इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव को ठुकरा देना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would again warn hon. Members on both sides. One point must be made very clear at the outset. I am trying to make it clear. (Interruption) No, no. I have already said. Now, in regard to how Mr. Thacker behaved, there are other extraneous matters not relevant to the issue. The first statement and the second statement—you have got to reconcile the two. I am asking you all not to ask about the Thacker affair too much. You should not refer to it.

श्री कंबर भास गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय मैं आप से सोलह घंटे सहमत हूँ। सवाल केवल यह है कि मंत्री महोदय ने एक बात तो यह कही है कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि जब प्रोफेसर ठाकर बम्बई गए, तो वह बैंक की मीटिंग एटेंड करने के लिए गये थे और दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि उन्होंने प्रोफेसर ठाकर को कभी यह क्लीयरेंस चिट नहीं दी कि वह बैंक की डायरेक्टरशिप मंजूर कर सकते हैं। उन्होंने इन दो बातों को बिल्कुल क्लैटली डेनाई किया है।

ठाकर साहब का कहना है, जो प्रश्नकारों में छपा है, कि मंत्री महोदय ने मुझे क्लीयरेंस चिट दे दी थी—मंत्री महोदय ने स्वयं दी थी, उनके डिपार्टमेंट ने दी थी और उनको इस बात का ज्ञान था।

श्री कसूराम बाहुरा : वह झूठ है।

श्री कंबर भास गुप्त : उन्होंने अपने रेसिगनेशन के पत्र में भी लिखा कि प्रश्न सदन में यह बात रख दी जाती, तो जिस ढंग से वहां पर बहस हो रही थी, उस में एक दूसरा मोड़ आ जाता।

मैं मानता हूँ कि जब तक हम यह एस्टाब्लिश नहीं करेंगे कि मंत्री महोदय ने गलत बयानी की है, तब तक प्रिविलेज मोशन नहीं बनेगा। मैं यह साबित करूंगा कि मंत्री महोदय ने किस तरह से गलत बयानी की है, कोर्टस की ट्रिब्यूनल किया है और कुछ तथ्यों को छिपाने की कोशिश

[श्री कंवर लाल गुप्त]

की है। अगर मैं प्राइमा-फेसी केस साबित कर दूँ, तो मेरे सामने की पार्टी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि इस मामले को प्रिविलेज कमेटी या हाउस की कमेटी में भेज दिया जाये, ताकि इस बात की जांच हो सके कि तथ्य क्या हैं। मैं प्राइमा-फेसी केस साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि ठाकर साहब बम्बई में बैंक की मीटिंग एटेंड करने के लिए गए। कमेटी के सेक्रेटरी, श्री राठी, ने 25 मार्च, 1968 को इन को पत्र लिखा है मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस को कान्ट्राडिक्ट करें।

श्री अमृत नाहाटा : यह पत्र कहां से लाये ?

श्री कंवर लाल गुप्त : यह मन्त्री महोदय ने मुझे दिया।

May I quote with your permission.

"The Chairman mentioned to Shri Wanchoo that he was going to —

SHRI F. A. AHMED : Letter to whom ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question whether it was addressed to Minister or to someone else would be relevant.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Letter addressed to Shri Wanchoo, Secretary of the Department.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all right.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It says :

"The Chairman mentioned to Shri Wanchoo that he was going to Bombay on 28th March, 1968. Shri Rathee was also going with him as they were meeting the representatives of the Maharashtra State Financial Corporation. The Chairman, in addition,

was also attending to his personal matter which he discussed with Shri Wanchoo."

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह है कि मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि उन्होंने क्लियरेंस चिट नहीं दी थी, लेकिन वांचू साहब ने एग्री किया है कि वह डायरेक्टर बन सकते हैं और राठी साहब ने 19-3-68 को इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी, उस में भी उन्होंने कोट किया है-

"I spoke to you before. And this has a further reference to my discussion with you this morning on the question of Prof. M. S. Thacker, Chairman, Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, taking up Directorship of a Bank in the Private Sector."

आगे वह लिखते हैं:-

"And as I told you, he has to work for his living. You were good enough to appreciate this point and it would be better now than after the Committee's work is over and kindly agreed to recommend to the Minister that Prof. Thacker be allowed to take up Directorship on the condition that he will cease to draw any emoluments from the date he starts getting remuneration fees from the other source."

आगे वह लिखते हैं:-

"I also mentioned to you that Prof. Thacker is to avail of refused leave for four months. You felt that there should be no objection to Prof. Thacker taking up the work during the period of the leave provided he starts drawing remuneration from the Bank only after he has exhausted his leave and is no longer in receipt of leave salary."

आगे वह लिखते हैं:-

"Prof. Thacker had requested a meeting with the Minister of Industrial Development and Company Affairs and is meeting him at 5 p.m. tomorrow, the 20th March 1968, and I shall be grateful if you would kindly speak to

the Minister before they meet and obtain the approval of the Minister to these arrangements."

अब इसका मतलब है कि बांधू साहब ने तो एग्जीसिवेट कर के मान लिया, उन्होंने कहा कि आप मंत्री महोदय को कह दीजिये, ताकि मंत्री महोदय भी इस चीज़ को मान लें ... (व्यवधान) ...

अब मीटिंग के बाद प्रो० ठाकर ने...

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : On a point of order, Sir. He is quoting from a number of letters extensively. They should be all placed on the Table. He is reading one sentence from here and one sentence from there.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am prepared to lay it on the Table.

इप के बाद प्रो० ठाकर ने मंत्री महोदय, को एक चिट्ठी 21 मार्च को लिखी-20 ता० की मीटिंग के बाद उन्होंने मंत्री महोदय को लिखा-मैं इस को भी पढ़ देता हूँ, यह दो तीन लाइनों में है-

"In continuation of my D.O. No. ... so and so dated so and so, many thanks indeed for giving me the time yesterday to meet you. I am grateful to you that you have been kind enough to appreciate my position and to agree to what Rathee, Secretary of our Committee, had sent to Shri Wanchoo in his D.O. No. so and so dated so and so, concerning my personal matter."

अध्यक्ष महोदय, 19 ता० को राठी साहब ने जो पत्र लिखा था, उस में उन्होंने लिखा था... (व्यवधान) ...

श्री शशि भूषण बाजपेयी : (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी चिट्ठी है, गलत है या सही है, इसका क्या सुबूत है... (व्यवधान)

श्री सच्चु लिमये : वह इस का प्रोबैन्टिकेट प्रमाणित करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : When the Minister replies, he can contradict it.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : The hon. member said :

"वह आदमी के दलाल हैं ।"

It is a most objectionable and he must withdraw those words.

श्री शशि भूषण बाजपेयी : इस बात को क्या गारन्टी है कि यह चिट्ठी सही है, मुझे बताइये ।

श्री कंबर लाल गुप्त : 21 ता० को राठी साहब ने कन्फर्मेशन का लैटर लिखा-

"I was also present".

यह चीट्टी उन्होंने बांधू साहब को लिखी थी-

"The Minister was kind enough to appreciate the question and was pleased to agree."

इस का मतलब यह है कि राठी साहब ने जो चिट्ठी लिखी उस से साफ जाहिर है कि उन्होंने एग्जी कर लिया है । इन सब बातों का मतलब यही है, मैंने यहां पर सारी पोजीशन साफ कर दी है ।

अब मैं यह पूछना चाहता हूँ-जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने कभी क्लियरेंस चिट नहीं दी थी, तो क्या यह केवल ओरल बात थी.? आपके पास चार-पांच चिट्ठियां आईं, क्या आपने कभी कन्ट्राडिक्ट किया कि आपने इस बात को एग्जी नहीं किया था, यदि आपने किया था तो क्या आप उस चिट्ठी को सदन के सामने रखेंगे । केवल ओरल बात कहने से कि मैंने क्लियरेंस चिट नहीं दी थी, यह सब बाद की कहानी है, तो क्या राठी साहब ने वैसे ही लिख दिया था । कल आपने राठी साहब की चिट्ठी को कोट किया था और उसमें कहा था कि राठी साहब ने लिखा था कि उन्होंने उस को रिजैक्ट कर दिया है । जब आप अपना सहारा राठी साहब की चिट्ठी से लेते हैं तो क्या राठी साहब की चिट्ठी गलत नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इन्होंने

[श्री कंबर लाल गुप्त]

कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिससे यह जाहिर होना हो कि इन्होंने क्लियररेंस चिट नहीं दी थी। बल्कि मैंने आपको प्रूफ दिया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात को साफ करें। अध्यक्ष महोदय, इंगलैंड में प्रोफ्यूमो का केस हुआ था, जिसमें गलत बयानी की गई थी, बाद में जब "क्लियर" के साथ उन का सम्बन्ध जाहिर हो गया, तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। मैंने प्राइमफेसी केस यहां पर पेश कर दिया है, ये जो प्रोफ्यूमो यहां पर बैठे हुए हैं, अब इन को इस्तीफा दे देना चाहिये।

आखिर में, मेरा कहना यह है कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो इसकी इन्कवायरी करे। अगर कांग्रेसवाले इस को वोट-डाउन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वह एक पोलिटीकल डिसेज़न होगा और मैं मांग करता हूँ कि अगर ये इस को वोट-डाउन करें, तो फिर रूल 227 में आपको पावर है, आप अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस को प्रिविलेज कमेटी को भेज दें।

13 10 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at ten minutes past fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

QUESTION OF PRIVILEGE—Contd.

श्री कंबर लाल गुप्त : एक दो मिनट मैं बोलूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am very sorry ; you have concluded. Shri Chandra Jeet Yadhav.

श्री प्रेम चन्द्र वर्मा (हमीरपुर) : मुझे भी बोलना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER ; I have already called Shri Chandra Jeet Yadhav.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कंबर लाल गुप्त ने इस में दो प्रश्न उठाये हैं। इनका मुख्य रूप से आरोप यह है कि मंत्री महोदय ने तथ्य को छिपाया और इस सदन के अन्दर उन्होंने गलत-बयानी की। इसकी पुष्टि में उन्होंने दो पत्र यहां राठी साहब के पढ़े...

एक माननीय सदस्य : तीन पत्र।

श्री चन्द्रजीत यादव : तीन पत्र राठी साहब के पढ़े।

श्री मधु लिमये : जी नहीं, एक पत्र ठाकर साहब का था।

श्री चन्द्रजीत यादव : राठी साहब ने जो पत्र मंत्रालय को लिखे उसमें एक पत्र ठाकर साहब का भी था जोकि उन्होंने खुद लिखा था। तो उन्होंने उन पत्रों की चर्चा यहां पर की और उसमें कहा कि धूँ कि आपने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है इसलिये हम आपके अगुआ हैं और उन्होंने आगे की कार्यवाही करनी शुरू की। लेकिन कहीं भी कोई पत्र जो कि मंत्रालय की तरफ से हो या मंत्री की तरफ से हो, उसकी कापी उनके पास नहीं है और न उन्होंने इसकी पुष्टि ही की है।

श्री कंबर लाल गुप्त : क्या आपके पास है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not interrupt him. When the time comes the Minister will contradict it. He is within his right to say that there is no letter or anything to show that the Minister has written it.

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, ऐसे लोगों के ऊपर, जिनके कन्डक्ट के ऊपर एतराफ था, हम समझते हैं कि ठाकर साहब देश के पूंजी

पतियों के एजेन्ट के रूप में काम कर रहे हैं, इसी लिये इनके कान्ट्रैक्ट पर हमने एतराज किया था और राठी साहब का खुद का कान्ट्रैक्ट सस्पेंशन था, इसलिये इस्तीफा देकर वह भी विभाग से चले गये, तो ऐसे आदमियों के पत्र के उद्घरण आप यहां पर दे रहे हैं और उन पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे अफसोस तो इस बात का है। विशेषाधिकार होता क्या है ? विशेषाधिकार का अर्थ यह होता है कि इस सदन के सम्मान की, गरिमा की रक्षा की जाये। सदन के अन्दर कोई गलत-बयानी नहीं होनी चाहिये। इस सदन के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिससे सदन की प्रतिष्ठा पर आघात लगे, चोट लगे। हर सदस्य और मंत्री का अधिकार है और यह परम्परा भी है कि सदन के अन्दर हम जो बात कहते हैं, यह सदन का और इसके सदस्यों का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, कि उस बात को कोर्ट के अन्दर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बयान देते हैं कि मैंने बहुत साफ तरीके से 29 तारीख को ठंकर साहब से कह दिया था कि आप बैंक की डायरेक्टरशिप और इस कमेटी की चेयरमैनशिप, दोनों पदों पर साथ साथ नहीं रह सकते हैं।

श्री कंबरलाल गुप्त : कोई डाक्यूमेंट है आपके पास ?

श्री अन्नाजीत साहब : इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अगर 29 तारीख को ठंकर साहब को कह दिया जाता कि आप इस कमेटी के चेयरमैन भी रह सकते हैं और अवैतनिक रूप में डायरेक्टरशिप भी स्वीकार कर सकते हैं—आरोप यही है—तो ठंकर साहब सीधे जा करके बैंक की डायरेक्टरशिप को स्वीकार कर लेते क्योंकि मंत्री जी ने इजाजत दे दी थी लेकिन वू कि मंत्री जी ने यह बात नहीं कही बल्कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप दोनों पदों पर नहीं रह सकते हैं इसीलिये नैक्स्ट डे, 30 मार्च को राठी साहब खुद लिखते हैं :

"The next day i.e. the 30th March, 1968 the Secretary of the Ministry of Industrial Development was informed by Shri K. L. Rathee, Secretary to the Inquiry Committee, on behalf of Prof. Thacker, both verbally and in writing that Prof. Thacker had decided not to accept the Bank's offer. The terms in which Shri Rathee communicated this were as follows :—"

I quote the letter :—

"Before leaving for New York this morning, Professor Thacker asked me to inform you that he has decided not to accept the Directorship of the Bank of India which was offered to him in a meeting held at Bombay on the 28th March, 1968".

अगर मंत्री महोदय ने इजाजत दे दी होती तो फिर वे पत्र क्यों लिखते ? वू कि मंत्री जी ने उनसे साफ-साफ कह दिया था कि आप दोनों पदों पर साथ-साथ नहीं रह सकते हैं इसलिये उसके दूसरे दिन ही ठंकर साहब के मंत्री, राठी साहब ने पत्र लिखा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मंत्री महोदय ने 29 मार्च की मीटिंग में ठंकर साहब से साफ-साफ कह दिया था कि आप दोनों पदों पर साथ-साथ नहीं रह सकते हैं और यही बयान वह सदन में भी देते हैं। फिर कहां मंत्री साहब किस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं ? फिर राठी साहब के पत्र से यह निष्कर्ष निकालना कि नहीं, राठी साहब कहते हैं कि वू कि मंत्री महोदय ने अनुमति दी थी इसलिए उस को स्वीकार कर रहे हैं यह सदन को भ्रष्टाचार करना है और यह एक गलत निष्कर्ष निकालना है। यह तो नम्बर 1 है।

नम्बर 2 यह कि मंत्री महोदय इस सदन के सामने एक बक्तव्य देते हैं, कंबरलाल गुप्त बक्तव्य दिया करते हैं इस सदन के सामने। एक आदमी कोई भी पत्र बाहर लिखता है या कोई भी बात ऐसी लिखता है जिसके अन्दर हम खुद जांच करते हैं कि उस आदमी का कान्ट्रैक्ट सस्पेंशन से भरा हुआ है, प्रश्न यह है कि सदन किस बात का विश्वास करेगा ? मंत्री महोदय जो कहते हैं उस का वह विश्वास करेगा या बाहर कोई आदमी कुछ कहता है उस का यह विश्वास करेगा ? मैं मंत्री महोदय से ही नहीं

[श्री चंद्रजीत यादव]

कहता बल्कि इस सदन का कोई भी सदस्य जो इस सदन के अन्दर कहता है उस के ऊपर आप भरोसा करेंगे या कोई अदमी सदन के बाहर आरोप लगाता है उसके ऊपर भरोसा करेंगे ? मैं समझता हूँ कि इस सदन के एक, एक सदस्य का यह विशेषाधिकार है कि जो बात वह सदन के अन्दर कहता है जिम्मेदारी से कहता है और हम उस की बात को उस के मुकाबले में जो बाहर कही जाती है सदन के अन्दर दिये गये उस बयान को स्वीकार करेंगे। यह परम्परा है और यह विशेषाधिकार भी है। इसलिये राठी साहब के उस पत्र के ऊपर-यह निष्कर्ष निकालना कि यह हम को मिस्लीड किया गया है यह खुद हमारे विशेषाधिकार के खिलाफ बात कही जाती है।

तीसरा आरोप यह है कि मंत्री महोदय का जो पत्र ठंकर साहब और राठी साहब को जिसमें यह कहा था कि श्रुं कि आप सहमत हो गये हैं और उस का यहां मंत्रालय से कोई कंट्रिडिक्शन नहीं हुआ है इसलिए यह आप का सब से बड़ा ऐतराज है। आप का सब से बड़ा ऐतराज यह है कि जब राठी साहब ने एक पत्र लिखा, यह पत्र उन का 21 मार्च का है ... (व्यवधान) किस तारीख का है ? खैर 19 से 23 मार्च तक का है। अब श्रीमन्, आप यह सुन लें कि 19 से 23 मार्च का यह पत्र है। आप यह समझते हैं कि एक हफ्ते के अन्दर उस का खंडन किया जाना चाहिये था। 23 मार्च का खत लिखते हैं राठी साहब और वह खत आता है उद्योग विभाग के सचिव के पास... (व्यवधान) सुन लीजिये। जो राठी साहब का खत है वह उद्योग विभाग के सचिव के पास आता है और ठंकर साहब का जो है वह मिनिस्टर के पास है (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट ग्रोफ आर्डर है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा खत सीधे मंत्री जी के पास पहुँचा है ? वही मैं बतला रहा हूँ। वह यह खत है। वह खत है प्रोफेसर ठाकर साहब का। 20 तारीख को मुलाकात होनी है। 21 तारीख को यह चिट्ठी जाती है प्रोफेसर

ठाकर साहब की श्री फखरुद्दीन अली ग्रहमद के नाम पर, सचिव के नाम से नहीं और उस चिट्ठी में वह लिखते हैं :

"In continuation of my D.O. No.... Many thanks indeed for giving me time yesterday to meet you. I am grateful to you that you have been kind enough to appreciate my position and to agree to what Mr. Rathee, Secretary of our Committee, had said to Shri Wanchoo concerning my personal matter."

यह प्रोफेसर ठाकर साहब का पत्र इन के नाम से 21 तारीख को गया (व्यवधान)...

श्री चन्द्रजीत यादव : 21 मार्च को ठाकर साहब पत्र लिखते हैं जिस पत्र में मंत्री महोदय को रैफ़स देते हैं। पहला पत्र मंत्री महोदय को नहीं आया। वह पत्र जिसका कि रैफ़स दिया जा रहा है वह विभाग के सचिव के नाम था। मंत्री महोदय अगर उस पत्र का जवाब देते तो उस में केवल इस बात का रैफ़स दिया गया था कि जो हम ने पहला पत्र आप के विभाग के सचिव को लिखा है उस बीच में अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। मंत्री महोदय उस पत्र को देखें जोकि सचिव के पत्र के संदर्भ में दिया गया है उस पत्र को उन्होंने भेजा इसी हफ्ते के अन्दर। दूसरा इण्टरव्यु आप से इस बीच में एक हफ्ते के अन्दर सीक हुआ। ठंकर साहब का इन से दूसरा इण्टरव्यु हुआ। उस इण्टरव्यु में बहुत स्पष्ट तरीके से मंत्री जी ने इस बात को बतला दिया कि आप दोनों पदों के ऊपर एक साथ नहीं रह सकते। उसी का यह नतीजा था कि 29 तारीख को साफ यह बता दिया तो 30 तारीख को उन्होंने इस बात का निराण्य करना था कि क्या वह कमेटी के चेयरमैन रहेंगे या बैंक के डाइरेक्टर रहेंगे। मंत्री जी ने साफ कह दिया था कि दोनों में एक पद पर रहना है। अब यह आप का फ़सला करना निज का काम है कि आप चेयरमैन रहना चाहते हैं या आप बैंक के डाइरेक्टर रहना चाहते हैं ? एक हफ्ते के बाद ही वह इस बात का

निर्णय करते हैं और मंत्री महोदय से स्पष्ट तौर पर बतला दिया कि हम दोनों पदों पर नहीं रहना चाहते। हम को चेयरमैन रहना है इस लिये हम डाइरेक्टरशिप ऐक्सैप्ट नहीं कर सकते। अब इस में क्या गलती हो जाती है? एक हफ्ते के अन्दर यह कहना कि उस का उन्होंने खंडन नहीं किया उस का एक रैफ़स दिया गया है। विभाग के सचिव के नाम है तो यह एक बहुत फ़ार फ़ेचैड कनक्लूजन होगा। वृ कि आरोप लगाना है मंत्री महोदय के ऊपर इसलिए यह कह दिया कि एक हफ्ते के अन्दर आप ने हमारे पत्र का उत्तर नहीं दिया मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही गलत परम्परा होगी। इन परिस्थितियों में श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के भंग होने का यहां प्रश्न पैदा नहीं होता।

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज आप को बतलाना चाहता हूँ। वह जो हमारी हाल में छपी प्रिन्टिस एंड प्रोसीज्योर आफ पार्लियामेंट नामक पुस्तक है वह एक अच्छी व उपयोगी पुस्तक है। विशेषाधिकार के बारे में एक सही बात उस में कही गई है :

"If any statement is made on the floor of the House by a member or a Minister which another member believes to be untrue, incomplete or incorrect, it does not constitute a breach of privilege. If an incorrect statement is made, there are other remedies by which the issue can be decided. A breach of privilege can arise only when the member or the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly."

यह बहुत महत्वपूर्ण बात इस में लिखी हुई है। यह मैंने उस पुस्तक के पेज 216 से उद्धृत की है। अब यहां पर मंत्री महोदय ने न तो सदन को मिस्लीड करने की बात की है और न ही उन्होंने कोई गलत या भूठा स्टेटमेंट दिया है। ऐसी स्थिति में इसमें विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को विशेषाधिकार

समिति के पास न भेजें क्योंकि इसमें कोई विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न नहीं बनता और इसलिए इसे यहीं पर समाप्त कर दिया जाय।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बातें कहना चाहता हूँ। सब से बुनियादी बात को ही मैं लेता हूँ बाकी जितनी गलत बयानियां हुई हैं उन को मैं छोड़ देता हूँ। एक मात्र सवाल यह है कि 20 तारीख को जब प्रोफेसर ठाकर साहब मंत्री महोदय से मिले तब दोनों के बीच में जो बात हुई तो क्या मंत्री महोदय ने उनको अपनी सम्मति दी थी कि वह बैंक आफ इंडिया के डाइरेक्टर का पद ले सकते हैं? यह सवाल इस में है कोई मैं छोटे-मोटे सवालों में नहीं जाता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह चेयरमैन रह कर डाइरेक्टर बन सकते हैं? अब इसके लिए सबूत क्या सामने आया है? राठी साहब कोई राजनीतिक नेता नहीं हैं। मेरा ब्याल है कि वह सरकारी आदमी हैं..... (व्यवधान) अब बनने जा रहे है राजनीतिक नेता न? मैं यह कह रहा हूँ कि वह समझ नहीं रहे हैं बातों को। खैर, जैसा मैंने कहा सब से बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रोफेसर ठाकर और श्री राठी जो कि सरकार का हिस्सा थे और इस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोफेसर ठाकर और राठी अगर बड़े पूंजीपतियों के दलाल हैं, यह आरोप किया जाता है, यहां पर किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पूंजीपतियों के कामों की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष इन को और राठी साहब को सेक्रेटरी बनाने का यह काम जिस मंत्री और सचिव ने किया है वह पूंजीपतियों के सब से बड़े दलाल हैं। अब आप ही नियुक्त करते हैं और आप को शर्म नहीं आती यह कहने में कि वह दलाल हैं। दलालों को आप नियुक्त करते हैं और पूंजीपतियों के कामों पर चादर बिछाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस आरोप का मैं पहले खंडन करना चाहता हूँ।

[श्री मधु लिमये]

उपाध्यक्ष महोदय, तीन सत्र के तीर पर यहां पर कागजात पेश हुए हैं। एक प्रोफेसर ठंकर साहब की मुलाकात को लेकर 24 घंटे के अन्दर और उनके द्वारा भेजी हुई चिट्ठी। दूसरे वांचू साहब के नाम से राठी साहब का लिखा गया पत्र, दोनों सरकारी नौकर हैं, दोनों जैसा मैंने कहा वह सरकार के अंग हैं इस लिए राठी साहब द्वारा वांचू साहब को लिखा गया पत्र। इतना ही नहीं इन के पास जो उन की मंत्रालय सचिव के लिए बैठक हुई उस की रपट भी मौजूद है। मंत्री महोदय की ओर से कोई कागजात कोई उसकी रपट पेश नहीं की गई है। न आप लोग कर पाये हैं और न ही मन्त्री महोदय कर पायेंगे इसके बारे में मुझे बिल्कुल शक नहीं है।

अब सवाल यह आता है कि वह कैसे हुआ कि 20 को सम्मति देने के बाद 27 और 29 मार्च को जो बैठक हुई उस में मंत्री महोदय ने इस बात का विरोध किया ? इस का स्पष्ट उत्तर मैं देना चाहता हूं। इस बीच में समिति के दूसरे दो सदस्य हैं उनके साथ चेन्नरमैन-ने बात की। मंत्री महोदय ने मुझे क्लियरेंस दिया है और इसलिए मैं बैंक आफ इंडिया की डाइरेक्टर-शिप स्वीकार ने वाला हूं। उसमें डाक्टर परांजये शुरू में कुछ नहीं बोले। लेकिन मोहन कुमारमंगलम को मैं इस बात के लिए धम्यबाद देना चाहता हूं कि इस में श्रीचित्तव नहीं है इस बात की ओर उन्होंने प्रो० ठाकर का ध्यान खींचा, और जब कुमारमंगलम साहब ने एतराज किया तब उनकी आंखें खुलीं और उन के ध्यान में यह बात आई कि 20 तारीख को तो यह सहमति वे दी गई, लेकिन जब कुमारमंगलम साहब कहते हैं कि इस में श्रीचित्तव का अंग होता है तब आकर वह ऐसब आन्ड इन्फोर्माइडो है और उस का अस्सर क्या होगा यह मंत्री महोदय के दिमाग में आया। मैं हर चीज के लिए मंत्रियों को जिम्मेदार नहीं कहता। लेकिन अभी-अभी

मैंने एक किताब देखी है "बी पावर आफ दी ब्राइव मिनिस्टर" जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के एम० पी० मि० बकले की लिखी हुई है। उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य है जिस को मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। जिस से आप को बात का पता चल जाय। मैं हर दोष के लिये मन्त्रियों को जिम्मेदार ठहराने वाला नहीं हूं, लेकिन जैसा आप ने कहा है, अगर कुछ सरकारी नौकरों की इसमें कांस्पिरेसी है, तो मन्त्री का दोष है या नहीं है, यह तय करने की जगह मह नहीं है। यह प्रिविलेज कमेटी में तय होना चाहिये।

आप इस वाक्य को देखिये:

"The twentieth century has seen an immense extension of the administrative powers of government. Both developments have given power to bodies which are irresponsible in the sense that they are not subject to democratic direction. The former has immensely increased the power of the Civil Service....."

* * *

"Oddly enough the strict application of the doctrine of ministerial responsibility which still exists in theory....."

केवल हाउस आफ कामन्स में ही नहीं, यहां भी वही थियूरी चल रही है।

".....has actually added to the power and invulnerability of the Civil Service. For the Minister alone....."

मैं "एलोन" शब्द पर जोर देना चाहता हूं

"For the Minister alone to be judged to be accountable to Parliament for actions of which he may have no knowledge (and of which he might disapprove if he had) is another example of the conflict between myth and reality in our constitutional practice which actually prevents Parliament from carrying out one of its traditional functions of redressing grievance. For under our practice the civil servant who in many cases is actually responsi-

ble for decisions cannot be questioned on them."

मुझे यह इत्सा मिली है कि यह जो सारे पत्र बांचू साहब के पास गये—एक तो सीधा मंत्री जी को गया था, उस के लिये कुछ कहा ही नहीं जा सकता—लेकिन जो पत्र बांचू साहब के पास गये थे, मुझे पता लगा है कि उन के उपर नोटिंग है "सीन एंड डिस्पीच आफ"। अगर सचमुच यह नोटिंग है तो मुझ को तो उस को देखने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी सारे कागजात मंगा सकती है, प्रिविलेज कमेटी बांचू साहब को बुला सकती है, प्रिविलेज कमेटी प्रो० ठाकर को बुला सकती है, प्रिविलेज कमेटी कुमारमंगलम साहब को बुला सकती है, और उन की गवाही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है कि कुमारमंगलम साहब ने, मंत्री महोदय ने जो पहले सहमती दी, लेकिन बाद में जो ऐतराज किया इस लिये मंत्री महोदय 27 और 29 मार्च को बदले है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन मामलों में सफाई इस सदन में बहुमत के आधार पर की जायेगी ? यह जो हमारे यंग टाक्स हैं यह आये दिन वामपन्थ की बात करते हैं लेकिन यह नकली वामपन्थी हैं ।

श्री शशि नूबरल वाजपेयी : अगर यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया तो दुनिया यह समझेगी कि यह सभा ठाकर और पूंजीपतियों के दलालों के प्रागे झुक गई ।

श्री मधु लिमये : अगर आप में हिम्मत है तो इस को भेजिये । अगर आप की राय में यह प्रो० ठाकर, पूंजीपतियों, राठी और बांचू साहब की कॉस्पिरेसी है और यह बिल्कुल निष्पाप और मासूम बच्चे हैं...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : दूध के घुले हैं ।

श्री मधु लिमये : हां, दूध के घुले हुए हैं तो यह तो प्रिविलेज कमेटी कह सकती है । लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे

फखरुद्दीनअली अहमद साहब प्रिविलेज समिति से भागने के लिये बहुमत का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया का यह निर्णय होगा कि वह अपराधी हैं और उन को हटाना चाहिये । आप तो प्रोफ़ुयुमो से भी गन्दा काम इस वक़्त कर रहे हैं । आप ने यह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एम्बवायरी कमेटी क्यों बिठलाई है । आज जो यह नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था है उस के अन्दर नौकरशाही में, सरकार में बहुत ताकत और शक्ति इकट्ठी हो गई है, केन्द्रित हो गई है, और हर दफे उस का दुरुपयोग किया जाता है, और इसीलिये इस की जांच करने के लिये एम्बवायरी कमेटी बँठी है । क्या अब आप एम्बवायरी कमेटी के अध्यक्ष और सचिव के ऊपर खुद उन की नियुक्ति करने के बाद कीचड़ उछालेंगे ? क्या उनको नियुक्त दांडेकर ने किया था, मैंने किया था ? इस तरह की बात की जाती है और उस के बाद उन के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है । यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय, वहाँ दुनिया कहेगी यह सरकार कायर है, यह गुनाहगर है, यह पूंजीपतियों से मिली हुई है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shrimati Tarkeshwari Sinha.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Mr. Deputy-Speaker. I beg your pardon. I do not want to interrupt.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nath Pai, I have looked to Acharyaji. Your intervention is not necessary. I will call him just now.

SHRI NATH PAI : Very strange for me to claim that. I am going to make a totally different submission. This is the second time that I have heard an hon. Member accusing another hon. Member of being a 'dalal' of Mr. Thacker. (Interruptions) Discharging his duty we can disagree with hon. Mr. Madhu Limaye.

SHRI MADHU LIMAYE : I did not appoint Mr. Thacker.

श्री नथ पाई : बार बार कहा जाता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : All these expressions are not in good taste.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ यहां कहा जा रहा है उस से आज के इस मोशन का कोई ताल्लुक नहीं है। इस मोशन का ताल्लुक इतनी बात से है कि हमारे मन्त्री महोदय ने जो कुछ यहां कहा वह सही नहीं कहा। अगर हम इन सारे वाक्यात को देखें और मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस को देखें या और बाकी चीजें भी जो हर अखबार में आई हैं, जैसे श्री ठंकर की चिट्ठी या राठो साहब की चिट्ठी, जिस का हवाला हमारे मन्त्री महोदय ने दिया है, उन चीजों को देखने से यह बात साफ हो जाती है कि जो कुछ मन्त्री महोदय ने कहा, उसी तरह से घटनायें घटीं।

अगर माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ा होगा और मैं समझती हूँ कि सब ने पढ़ा होगा, तो वह पायेंगे कि मन्त्री महोदय ने उस में ही कहा है कि श्री ठंकर ने इस की चर्चा कभी किसी समय उन से की थी कि उन के पास इस बात की सूचना आई है कि बैंक आफ इंडिया वाले उन्हें डाइरेक्टर बनाना चाहते हैं। इस का मन्त्री महोदय ने स्वयं इकार किया है, माना है, कि उन्होंने इस की चर्चा की थी। परन्तु यह सवाल उठता है कि इस बात को आम तरीके पर कहने और इस बात की सूचना किसी खास मौके पर देने में, जब वह बैंक की मीटिंग में जा रहे थे, बड़ा फर्क हो जाता है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उस दिन कहा कि जब श्री ठंकर बम्बई जा रहे थे तब मुझ से मिले। जाने के पहले उन्होंने यह नहीं कहा कि वह बैंक की मीटिंग में जा रहे हैं। अगर बैंक की मीटिंग में वह परमिशन ले कर जाते, मिनिस्टर साहब से इजाजत ले कर जाते, तो बम्बई से आ कर 29 तारीख को मिनिस्टर साहब से मिलने की उन को क्या जरूरत हो सकती थी? एक बार अगर इजाजत मिल गई तो उस के बाद 29 तारीख को उस

की इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। (व्यवधान) मुझ को बोलने दीजिये और जो कुछ मैं कह रही हूँ उस को सुनने की कोशिश कीजिये। मैं यह भी उदाहरण दे रही हूँ कि अगर मेरी या मधु लिमये साहब की मन्त्री महोदय से दो दिन पहले किसी चीज के बारे में बात होती है, तो दो दिन बाद उस की पुनरावृत्ति करने की क्या जरूरत हो सकती है? यह स्वाभाविक चीज मानने की हो सकती है और उस को हम मानें। 27 तारीख को मिले। कहा यह जा रहा है कि 27 तारीख को मिनिस्टर साहब ने उन्हें अनुमति दे दी और बैठक में जा कर इस बात को कह देने की कि हां आप डाइरेक्टरशिप मान लीजिये। ठंकर साहब 29 तारीख को आये। 29 तारीख को फिर मिनिस्टर साहब से मिले और मिनिस्टर साहब से मिल कर उन्होंने बात की। मिनिस्टर साहब में और ठंकर साहब में जो बात हुई उस को या तो मिनिस्टर साहब जानते हैं या ठंकर साहब जानते हैं। इस संसद की बहुत सी मान्यताएं रही हैं। पर आखिर क्या मान्यता है? संसद के जो विशेषाधिकार हैं उन का मकसद क्या है? मकसद यह है कि संसद में हम लोगों को पूरी छूट है बात करने की। जो बात हम यहां कहते हैं पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। बाहर वाले किसी भी व्यक्ति को सदन के सदस्य से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है इस बारे में कि वह क्या कह रहा है। मधु लिमये जी जानते हैं कि पिछले दिनों संसद में यह घटना घटी थी। बाहर वाले व्यक्ति ने संसद सदस्य श्री लिमये द्वारा कही गई बात को काटा। लेकिन संसद ने लिमये जी की बात को माना, उस व्यक्ति की बात को नहीं माना। पचांस करोड़ आदमी हैं इस देश में। उनकी बात को संसद सदस्य की बात से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। यही हमारा विशेषाधिकार है। इस में मंत्री भी आते हैं और सदस्य भी आते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों के एक समान विशेषाधिकार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हैं। जो बात हम यहां कहते हैं

उसी की मान्यता होगी उस वक्त तक जब तक कि बाहर वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे तरीके से, डाकुमेंट्स के बेसिस पर या कागज पत्रों के बेसिस पर उसको डिसप्रूव न कर दे। उस बात को भी डिसप्रूव हाउस में ही करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैंने आपको चिट्ठी लिखी या चिट्ठी नहीं भी लिखी। आठ दिन के बाद मैंने दूसरी तरह की चिट्ठी लिखी और उस में उस चिट्ठी का हवाला भी दे दिया जो मुझे माफिक गुजरता है और उसको साइक्लोस्टाइल करवा कर दोनों चिट्ठियों को सब को बांट दिया तो क्या इसको एवीडेंस माना जा सकता है कि मैंने पहली चिट्ठी लिखी थी। इसको एवीडेंस नहीं माना जायेगा। मैं चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के और चाहे मन्त्री हों इस बात को देखें। पार्लियामेंट में अगर कोई मन्त्री या कोई सदस्य बाहर वाले किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को काटता है तो सदस्य अथवा मन्त्री द्वारा कही गई बात को मान्यता दी जाती है। इसलिए प्रो० थंकर या मि० राठी जो भी बाहर कहें उसको मन्त्री महोदय की बातों के ऊपर जा कर मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह हमारा प्रिवलेज है, मन्त्री महोदय का प्रिवलेज है, सदस्यों का प्रिवलेज है।

यह तो मन्त्री महोदय की बात है। अगर मैं रहती और हमारे विरोधी दल के सदस्य रहते और अगर वे किसी बात को यहां रखते और बाहर इस तरह की कोई दूसरी बात कोई अफसर कहता तो ईमानदारी के साथ मैं आप से पूछना चाहती हूँ क्या आप यह कहते कि अफसर जो कह रहा है वह ठीक है या विरोधी दल का सदस्य जो कह रहा है वह ठीक है और अगर आप यह कहते कि अफसर जो कह रहा है वह ठीक है और सदस्य जो कह रहा है वह गलत है तो मैं नहीं समझती हूँ कि यह उचित होता। यह संसद की परम्परा नहीं रही है। संसद की परम्परा यह रही है कि सदस्य जो कह रहा है उसको वह ठीक माने।

एक बात और मैं कहना चाहती हूँ। थंकर साहब कोई बच्चे तो थे नहीं। राठी साहब भी बच्चे नहीं थे। अगर मान भी लें कि मिनिस्टर साहब के साथ उनकी बातचीत में तय हो जाता है तो प्रो० थंकर राठी साहब से क्यों कह कर जाते कि मिनिस्टर साहब को यह सूचना आप दे दें कि हमने बैंक आफ इंडिया की डायरेक्टरशिप लेने के पक्ष में अपना इरादा बदल दिया है, हम उसको मान नहीं रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने संसद में क्या कहा? उन्होंने कहा कि थंकर साहब ने जब वह मुझे 29 तारीख को मिले तो यह नहीं बताया कि हम इसको विचाराधीन रखे हुए हैं, हमने इसको अंडर कंसिड्रेशन रखा हुआ है और मिनिस्टर साहब ने उन से कहा कि आप अंडर कंसिड्रेशन रखें, इसका अधिकार आपको है, आप की यह अपनी बात है आप चाहें तो बैंक आफ इंडिया की डायरेक्टरशिप ले लें, लेकिन मुझे एतराज है या नहीं यह बात अलग है। लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंक की डायरेक्टरशिप लेना कोई पाप नहीं है। या किसी कम्पनी की डायरेक्टरशिप लेना कोई पाप नहीं है। हमारे पार्लियामेंट के सदस्य भी कितनी सारी कम्पनियों के डायरेक्टर हैं। इस में कोई पाप नहीं है। लेकिन वह इंडस्ट्रियल पालिसी लाइसेंसिंग इनक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे और एक महत्व के पद पर थे। थंकर साहब के बारे में इतना कुछ यहां कहा गया है कि कोई हिसाब नहीं। यह बहुत आसान है पार्लियामेंट में किसी के ऊपर छाँटा उड़ाना...

श्री मधु सिन्घे : आपके लोग उड़ा रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे ऊपर उड़ाने की हिम्मत आप में नहीं है।

श्री मधु सिन्घे : भाषा का अर्थ भी नहीं जानती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका खुलासा कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस के लोग थंकर साहब पर उड़ा रहे हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं उस में जाना नहीं चाहती। सवाल यह है कि डायरेक्टर-शिप उन्होंने स्वीकार नहीं की, यह उनकी अपनी राय की बात थी। लेकिन मधु लिमये जी या हम में से अगर कोई किसी कम्पनी का डायरेक्टर बने तो हमारे लिए कोई यह दुर्गुण या डिसकवालिफिकेशन नहीं है। सवाल इतना ही है कि क्या थंकर साहब के लिए यह मुनासिब था कि वह डायरेक्टर भी बनते और इस लाइसेंसिंग इनक्वायरी कमेटी के चेयरमैन भी बने रहते जोकि एक बहुत महत्व की कमेटी है? लेकिन जब वह राठी साहब को लिख कर भेज देते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है इसको जानने के लिए ज्यादा विभाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। मिनिस्टर साहब ने अगर उनको कहा होता कि आप ने खूब किया और अच्छा किया कि जा कर डायरेक्टरशिप ले ली तो दूसरे दिन राठी साहब को चिट्ठी क्यों आती मिनिस्टर साहब के पास कि थंकर साहब ने विचार किया है और वह डायरेक्टर नहीं बनेंगे। इस वास्ते मैं समझती हूँ कि मिनिस्टर साहब ने जो कहा सही कहा।

इस में प्रोप्राइटी का सवाल भी आता है। थंकर साहब के लिए इन हालात में क्या करना उचित था? कुमारमंगलम साहब से उनके क्या रिस्ते थे, उसका हमें हवाला नहीं देना है। लेकिन मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनका उत्तर पाने के पहले ही उन्होंने चिट्ठी प्रेस को दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों में नहीं हूँ जिन को बहुत जानकारी इन सब बातों की रहती है कि परदे के पीछे क्या होता है। इस में मेरी दिलचस्पी नहीं है। परन्तु इतना जरूर मैं कहना चाहती हूँ... थंकर साहब किस तरह से आए, कौन उनको लाया, कुमारमंगलम का या और किसी का जोर उन पर चल रहा था, या किस का जोर किस पर चल रहा था, या किस के यहां कौन बात हुई या कौन बात नहीं हुई, किस के यहां नाश्ता या खाना खाया, इस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है और न ही संसद् को कोई मतलब है... पर जो एक मुनासिब बात थी वह यह थी कि मिनिस्टर साहब का जवाब

पाने के पहले उनको अपनी चिट्ठी बाहर नहीं करनी चाहिये थी। हालांकि एक बात के लिए थंकर साहब की दाद दी जानी चाहिये। उन्होंने जब सुना या जब उनको पता लगा कि पार्लियामेंट में उनका विरोध हुआ है और जब उनको पता चला कि संसद ने उनके बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और उनके इस कार्य से कमेटी के सम्मान को धक्का लगा है तो उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय कर लिया। वह डायरेक्टर हों या न हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी बला से, वह चाहें तो दस कम्पनियों के डायरेक्टर बन सकते हैं, और उस में कोई पाप भी नहीं है, परन्तु अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी इनक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से पार्लियामेंट के सदस्यों ने इस बात को उठाया तो एक शरीफ आदमी के सामने यही विषय रह जाता था कि वह अपना त्यागपत्र उस पद से दे दें। मैं समझती हूँ कि संसद को उनकी इस कार्रवाई के लिए तारीफ करनी चाहिये कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बिना मजबूर किए दे दिया। सरकार ने उन से त्यागपत्र मांगा नहीं, उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया नहीं, मिनिस्टर साहब ने कोई पत्र नहीं लिखा थंकर साहब को लेकिन खुद ही थंकर साहब ने महसूस किया कि उनके ऊपर अगर आंच आई है तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिये और त्यागपत्र देकर मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक सिद्धान्त की रक्षा की है और एक बहुत बड़ा महत्व का रास्ता अपनाया। इसके लिए थंकर साहब को हमें गाली नहीं देनी चाहिये। उनकी इस कार्रवाई का हमें स्वागत करना चाहिये। इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन कोई आदमी इन हालात में अगर त्यागपत्र देता है तो वह बहुत ऊंचा सिद्धान्त पैदा करता है और जो एक स्वस्थ परम्परा है, उसकी वह रक्षा करता है।

श्री मधु लिमये : शेर तो सुनाइये कोई।

श्री नाथ पाई : शेर हम उन से सुनना चाहते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अगर आप राजा दें तो मैं सुना देती हूँ ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : No. If I permit it, I will have to allow Shri K. L. Gupta. That can be recited in the Central Hall, not here.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I should like to make it clear that I and my group do not hold any brief either for Prof. Thacker or for the Minister in charge of the particular department. The questions is whether in reply to questions the other day on this subject, the Minister misled the House or concealed some of the facts which he should not have done.

Before coming to the real question, may I say that Prof. Thacker's antecedents should have been verified before making him Chairman of this Committee? I had said in this House when the Short Notice Question came up that before coming to the Scientific Research Ministry, Prof. Thacker was employed in, and was subscribing to the ideology of, the private sector. I had no illusion in my mind even then. I know that during those days I wrote many letters to the Secretary of the particular Ministry, when he was controlling the Scientific Research Ministry and was Director of the Survey of India. I pointed out how he was helping certain business houses.

I charge the Minister with appointing the same Prof. M. S. Thacker, said to be one of the biggest scientists—I doubt very much his scientific genius—as Chairman of such a big Committee and that too to investigate the affairs of a very big business house. Whether there is a privilege motion, or no privilege motion, who have gained out of it? The Birlas. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The time is limited. I will not give you more than five to seven minutes. If you go to other matters I will have to stop it. (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE : The investigation was going on against Birlas, not against Mr. Modi. So, I ask, is it true? So many letters were read, Mr. Rathee's

letter to Mr. Wanchoo and so on. After reading those letters, after hearing them, it is quite obvious that there was serious bungling. Who has done this bungling, whether it is Mr. Wanchoo or the Minister Shri F. A. Ahmed, knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, is a matter to be decided. Mr. Thacker had no business to approach the department for accepting the directorship of a particular bank which is controlled by the big business-houses the conduct of whom was under enquiry.

Then, is it a fact that when this question was referred to Mr. L. K. Jha, the Governor of the Reserve Bank, he also heard it? I am told that Mr. Jha rang up the Deputy Prime Minister, Shri Morarji Desai—the Finance Minister and said, "I have no objection." Shri Morarji Desai also said—I am speaking subject to correction and if I am wrong I am prepared to correct myself—that now that the Banking Bill is coming after social control which was sought to be imposed on banks, there will be no difference between the State bank and the Reserve Bank or other banks. So, naturally there was no objection if he accepts the directorship of a particular bank.

I want a clear answer to this House. Let the hon. Minister answer this point. I plead—and I support the motion—that this matter should be referred to the Privileges Committee because we want to know what was happening to the underworld. We want to know what was happening between Mr. Thacker, Shri F. A. Ahmed and Mr. Wanchoo. Is it like the old Mundhra episode? What was that? We want to unearth what was happening behind the scene.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : You will never discover.

SHRI S. M. BANERJEE : I know; when Shri Kripalani became the Chairman of the Anti-Corruption Committee and then resigned: I asked him why. He said "I would have become corrupt if I remained." I know the reason. Now, I want the whole thing to be unearthed. I therefore request that this matter should be referred to the Privileges Committee, and anybody who is guilty, whether he is the Minister or anybody else, he should gracefully and peace-

[Shri S. M. Banerjee]

fully resign even at this stage. (*Interruption*) Mr. Thacker should never have been brought to work as Chairman of this Committee and should never be allowed to continue in this Committee. With these words I support this motion and say that it should be referred to the Privileges Committee.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the copy of the motion which has just now been circulated, the motion by Shri Rabi Ray, reads as follows :

"Whereas in the opinion of this House it clearly appears necessary to enquire whether a breach of privilege of the House has been committed or not by the Minister of Industrial Development and Company Affairs by the reply given by him on the 2nd April, 1968, this House, therefore, resolves to refer this matter to the Committee of Privileges with instructions to report on the first day of the next session."

The Members of this House will now be called upon to vote on this motion, and I am amazed to find that nobody who supported the motion referred to any passage in the statement made by the Minister on the 2nd April, which was either false—

श्री मधु लिमये : 24 अप्रैल के वक्तव्य को भी देखिये ;

SHRI GOVINDA MENON : —or which was calculated to mislead the House.

The hon. member wants me now to look into the 24th April statement.

श्री मधु लिमये : क्यों नहीं ? उसी में से एराइज किया है, उत्पन्न हुआ है ।

SHRI GOVINDA MENON : That can not be. This is a privilege motion with respect to certain statement made by the minister on a certain date.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The motion is clear.

SHRI GOVINDA MENON : 7 out of the 8 motions are dated 23rd April. These cannot be with respect to the statement made on the 24th April. The eighth motion by Mr. Limaye is dated 24th April, but it says :

"In response to the short notice question No. 15 answered on the 2nd April, MR. F. A. Ahmed; Minister for Industrial Development and Company Affairs stated..." etc.

This motion was given at 10 A.M. on that day. If rambling statements are made, if statements which were not made on 2nd April are referred to, if statements made by others with respect to other matters are referred to, if it is alleged that if some members of this House vote against the motion; they would be doing it out of political motives, that is not correct. Some of us on this side will vote against the motion because in the statement made by the minister on 2nd April, I have not been able to see from the official record...

SHRI J. B. KRIPALANI : How can you see ?

SHRI GOVINDA MENON : It may be my inability. If the hon. member is able to see, I am very happy. He will be able to see things which are not there. The record is clear. The question raised by Mr. Panigrahi was :

"Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) Whether Professor M. S. Thacker, the Chairman, of the Committee appointed to investigate into the question of issue of industrial licences to private monopoly houses in the country has accepted the directorship of the Bank of India and is attending its meetings ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?"

The written answer read out by the minister was :

(a) and (b). The facts regarding the question are that it is understood that Professor M. S. Thacker, Chairman of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, was invited informally to a meeting of the Board of Directors of the Bank of India on the 28th March, 1968, to let them know his decision on the offer made to him of Directorship on the Board of the Bank. After telling them that he required three to four weeks to consider his decision, Professor Thacker came away from the

meeting. Subsequently, the Government have been informed that he has declined the offer. In the circumstances, it is not proposed by Government to take any further action in the matter.

I fail to see anything which is false or which was calculated to mislead the House in this answer. If the wise Mr. Kripalani could find anything in this which was calculated to mislead the House, I have no objection. Experienced Members of Parliament like him should have some basis before making allegations here. I have not been able to understand from any of the speeches made here which of the three statements in this answer was deliberately false and calculated to mislead the House. Is it false to say that he went to attend informally a meeting of the Board of Directors of the bank? It is admitted to be correct. Is it not correct that he said that he would answer sometime later? Is it not correct that before he went to New York, he informed, through Mr. Rathee, the minister that he does not propose to accept the directorship of the Bank of India?

15 00 hrs.

These are the three statements made. We are told that these statements are false and are calculated to mislead the House and therefore there should be an inquiry in the Committee of Privileges. Is the Committee of Privileges a body to inquire into matters which are not relevant to the issues raised? Is the privilege of this House which is very important to the Members of the House and to the House to be so lightly treated that anything could be sent to the Committee of Privileges? If some of us would vote against it is because we want to see that the privilege of having a privilege for the Members of the House should be preserved as a sanctified privilege and it should not be tossed about or attempted to be tossed about like this.

The hon. Member, Shri Limaye, when he found difficulty said that we should refer to the statement of 24th April. Why not the statement of 30th April which would come later? We are now on the question of the statement of 2nd April. I will come to the subsequent answers in answer to supplementaries. The next answer made by the Minister is so far as the

visits of Professor Thacker to any house of the monopolists are concerned. He said he had no information. That was in reply to Shri Umanath. Another question was by Shri Banerjee, whether he does not know that Shri Thacker's antecedents were of a certain character. To that also he said that he had no information.

What is it that should be sent to the Privileges Committee? We heard many speeches here. With due respect to those who made these speeches, those who supported the motion—some of our friends opposed the motion—covered a very wide ground most of which was irrelevant (*Interruption*). They are irrelevant because the motion is with respect to the statement made on 2nd April. Do not get offended with me when I throw the torch light on the true facts in the debate. It was said that the Minister might have agreed at a certain stage....

SHRI MADHU LIMAYE : Why "might have agreed", he agreed.

SHRI GOVINDA MENON : He might have agreed at a stage that he might hold both the things. I do not know. And, it was suggested that it was at the instance of Shri Kumaramangalam that later the Professor thought that he would resign. I do not think it is so. But assuming it is so, is it a matter to be sent to the Committee of Privileges?

श्री मधु लिमये : और कौन सा प्रश्न है ?

SHRI GOVINDA MENON : Now, it has been from statements made here and from letters read out—I do not know from where those letters came, and there was objection to the use of the word 'dalal' and all that—I do not use that word but letters were read out...

SHRI MADHU LIMAYE : Do you challenge those letters?

SHRI GOVINDA MENON : I do not say. I say they have come and they are very suggestive...

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Not 'suggestive' but 'subjective'.

श्री मधु लिमये : सबर्जेक्टिव क्या है ?
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर है ।

SHRI GOVINDA MENON : I do not say you are a 'dalal'.

श्री मधु लिमये : दलाल के ऊपर प्वाइन्ट ऑफ़ ऑर्डर नहीं है। आपके मन में दलाली है, मैं क्या करूँ। जिस माननीय सदस्य ने यह पत्र रखा, उन के ऊपर एसपर्शन कास्ट करने, लाइन लगाने की कोशिश की गई है कि यह आर्थेन्टिक है या नहीं है। क्या ये इस को चैलेंज कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : When objection was raised earlier I said then and again say it is for the Minister concerned to contradict it.

SHRI MADHU LIMAYE : Let him say that. Why should the Law Minister insinuate.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The only person who can contradict it is the Minister. We cannot say whether it is correct or not.

SHRI MADHU LIMAYE : Let him deny it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In his reply not now. There is no point of order.

SHRI MADHU LIMAYE : Why is the Law Minister insinuating. It is for the Minister of Industrial Development and Company Affairs to say whether it is correct or not.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Limaye may please refer to the resolution. He is well within the ambit of the resolution.

SHRI GOVINDA MENON : I am extremely sorry that...

श्री मधु लिमये : क्या वह इस तरह से आरोप कर सकते हैं कि लैटर कहां से आया है, यह सही है या नहीं.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I should say that he has said nothing about it.

श्री मधु लिमये : उन को लैटर रखने का अधिकार है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He only referred to the contradictions.

श्री मधु लिमये : आप लैटर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म करना है, वह करिये, लेकिन इनसि-नुएट न कीजिये।

SHRI GOVINDA MENON : I am extremely sorry, I have been misunderstood.

श्री कंबर लाल गुप्त : जो लैटर मैंने यहां पर रखा है, उस पर माननीय मंत्री यह कहें कि मैं किसी की दलाली करता हूँ... (व्यवधान)... क्या यह भाषा इन के लिये ठीक है ?

SHRI GOVINDA MENON : I did not say that.

श्री कंबर लाल गुप्त : क्या यही इन का स्टैंडर्ड है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nobody has said that. It is in bad taste. He has not used that word. Let him conclude now.

SHRI GOVINDA MENON : I did not use the word 'dalal' and I do not want to use it. Shri Madhu Limaye took it as if I made an insinuation against him. I am very sorry. I did not want to make any such impression.

SHRI HEM BARUA (Mangolia) : He says. I do not want to call him a *dalal*. That is an indirect way of insulting the House and the members also.

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परसनल एक्सप्लेनेशन के लिये कहना चाहता हूँ। मैंने किसी आनरेबिल मेम्बर को दलाल नहीं कहा है। मैं दलाली के पेशे को बुरा नहीं समझता हूँ। मैंने ठक्कर को जरूर कहा था कि वह बिग-बिजनेस के दलाल हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even then I said it is not in good taste. I observed it. When we are discussing a serious matter we should not use such terms.

SHRI GOVINDA MENON : I have not used that word, I will not use that word and I do not want to use that word. I am very sorry that whatever I said has been taken to be an insinuation of Shri Madhu Limay. That was not my intention. All that I say is that with respect to the statement made by the Minister on the 2nd April these letters are irrelevant. Subsequently, other things are built up and questions are being raised whether, as a matter of fact, the Minister did consent to Shri Thacker occupying both the places. All that I say is it is all irrelevant. I do not believe it is true. And if it were true, there is no reason why the Professor before going to New York should inform the Minister "after all I do not take up that job." Before going to New York, he gives the information to the Minister saying that he will not take up that job. It means "after all, I am not going to take that job"; that is what it means. Therefore, I would submit with very great respect to the eight hon Members...

SHRIMATI TARKESWARI SINHA : The hon. Minister should understand what is being said in the House. All that has been said by Shri Yadhav. Now he is saying everything said here has been irrelevant. He should understand what is being said in the House.

SHRI GOVINDA MENON : Therefore, what I mean is that the hon. Members who have moved this motion should confine themselves to what has been said by the Minister on the 2nd April. And if there are members here who think that the statement made here on the 2nd April is not complete, that is a different matter. That does not give an occasion for raising a privilege issue. Shri Yadhav read out from page 216 of that book, a passage based upon the ruling given by the Speaker of the Third Lok Sabha. Under these circumstances, I think this motion does not deserve to be sent to the Committee of Privileges.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I think this is a very

simple question. There have been so many names mentioned, Shri Thacker, Shri Wanchoo and Shri Rathee and I do not know them from Adam. But I am surprised that one Congressman says that this Thacker is an honest man while another Congressman says : no, he is the *datal* of big business. And my poetic sister praised him in one sentence and condemned him in another.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : I praised his resignation.

SHRI J. B. KRIPALANI : She praised him in one sentence and condemned him in another. But I must say that is poetic licence which is allowed. But when this question is voted upon, if this is voted upon at all, then they (Congressmen) will all be together. They have been contradicting each other here about the character of a person. But when they vote, they will vote solidly together. If they have such divergent views about one person whose conduct is being discussed here and if they vote in one way only, I ask : Are they going to be honest to themselves ? If they are not honest to themselves, how are they going to be honest to the country ?

AN HON. MEMBER : They are honest to the Party.

SHRI J. B. KRIPALANI : They are honest to the Party not to the nation.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : My colleague, the lady Member, has asked me to say to you that your speech is completely irrelevant.

SHRI J. B. KRIPALANI : It is for you, Sir, to decide whether my speech is relevant or not. It is not for my poetic sister and she is not supposed to be a messenger of others here. She has her own independent existence.

What I want to say is this. This is a very simple question. The hon. Minister could have said that he saw no harm in a particular person occupying these two posts but afterwards he realised that it should not be so. There is nothing in that. There would have then been no discussion at all. It is quite possible. I say that such a thing is permissible that afterwards when my

[Shri J. B. Kripalani]

attention is drawn to it and I say it is not permissible to hold two positions. The matter would have ended there. This is a simple matter. Prof. Thacker was a member of the Planning Commission. The Planning Commission was appointed by Pandit Jawaharlal Nehru. Was he a good judge of men or a bad judge of men or did he purposely put perverse people in office? Why did not the Minister know something about his (Thacker's) credentials before he appointed him? On that day, if you remember, I had said that this report should not be sent to prof. Thacker or to anybody and that it should be sent to the Planning Commission who had authorised Prof. Hazare. But I say even the Planning Commission did not authorise him. Nobody authorised him. It was an irrelevant report. I do not know why the House is concerned with it. If it has concerned itself with it and they have contradicted each other and if the Congress Members are going to show a united front when, if at all this is to be put to the vote, I say, they are not honest to themselves.

Another thing is: Why should they be afraid of putting this matter before the Privileges Committee? After all, in the Privileges Committee also, the Congress Members are in a majority. They can vote together there also if they are voting here together.

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I correct him? The Privileges Committee Reports are not based on a majority or minority.

SHRI J. B. KRIPALANI: If the whip can have currency here, if the whip prevails here, what is there to check them from having the whip there also? Here also, they are contradicting each other. Therefore, I would suggest that this is not a question which should be left to the House to decide. It is a question for the Presiding Officer to decide whether it should go or not to the Privilege Committee.

That is your function. You are delegating that function to a party which is not true to itself, which is not true to each other and which votes only in one way. It is perfectly wrong. You will be quite justified in deciding on your

own judgment whether this thing should be referred to the Privileges Committee. Our Law Minister has said that both the parties have been talking non-sense. I believe him in this. He is perfectly right. I have no quarrel with him. I agree with him. It is your bounden duty to decide this question yourself and not shirk the responsibility. If you shirk it, it will be said that you are siding with one side or the other.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But for the hon. Member's remark, I would not have intervened. As the hon. members know, the report of the Privileges Committee comes before this House and this House is supreme. Therefore, whether I should exercise my discretion or judgment at this stage, though the Chair or the Presiding authority could exercise that, for failure to exercise that discretion, the hon. Member should not say that the Presiding authority is inclined towards this side or that side. That is not correct.

Mr. Rabi Ray's motion was circulated a little late. Mr. Kanwar Lal Gupta is moving an amendment to that which I am permitting him to do.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I beg to move.

That in the motion moved by Shri Rabi Ray, after "2nd insert" and "24th".

MR. DEPUTY-SPEAKER: The amendment is before the House.

Ms. Umanath. He should be brief.

SHRI UMANATH (Pudukkottai): You said in the beginning that time will be given for each Group. I will take only that time.

The central point, so far as this particular privilege motion is concerned, is the conduct of the Minister and not that of Mr. Thacker. So far as Mr. Thacker is concerned, he had been a Trojan horse in the committee and now he is a dead horse. There is no use whipping the dead horse.

With regard to the Minister's conduct, the Law Minister was saying so much that we must limit ourselves to the reply of the Minister made on the 2nd April. Of course, now that amendment is there. He wanted to know which portion constituted a breach of privilege. I am now relying only on the reply of 2nd April itself. On 2nd April, the hon. Minister, towards the end, in reply to Prof. Ranga's question—as I said, towards the end only—made this statement where he says :

"Just before his departure for New York, he came and told me that this is the position and asked for the Government's reaction. I said, if he becomes the Director of the Bank, it would be in possible for him to remain as the Chairman of this Committee".

It is only here, only once, he has made this statement and that too, towards the end.

According to the statement, at the very first instance, the Minister told him that he should never be on the other committee he must resign in that case. This is the statement made; I am touching that portion.

The point for determination now is whether at the very first instance the Minister told him like this or at the first instance he told him something different and that was suppressed in the House on 2nd April when he replied. That is the question for determination... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : Just a repetition.

SHRI UMANATH : It may be a repetition. It cannot be helped.

With regard to that point, I am convinced so far as the records go that the Minister had actually accepted that there is no harm in serving as Director while remaining as the Chairman here. On the basis of the records—I go by the records—the sequence has been explained. The first sequence is prior to 20th.

One Secretary, that is the Secretary of that Committee, writes to the Secretary to the Ministry whereby he requests the Secretary of the Ministry to recommend to the Minister to permit Mr. Thacker to serve as a Director while

remaining here. This is the first letter. Second is the 20th meeting between Mr. Thacker and the Minister. The third is the confirmation letter.

Now the point is : Shri Chandra Jeet Yadav said, 'Are you to rely on these letters'? No, I am not relying on the letters. I am relying on the conduct of the hon. Minister *vis a vis* the letters. I am there. What was the conduct of the Minister? The third letter clearly says, 'I am glad that in yesterday's meeting you accepted such and such thing'. Now, according to the Minister, at the very first meeting, he said, 'You cannot be there'. Now, here is a letter which says that he accepted just the opposite. The first thing that the Minister should have done was to write 'No, you are wrong. I am contradicting this position. You are wrong'. He did not do that. Shri Kanwarlal Guptaji rightly put it 'Why it was not contradicted'. It is so because the contents were true. You know, Sir, in official correspondence—I am seriously on that point—when two people meet and talk orally, either there will be joint minutes or minutes will be circulated between both the parties or there will be a note on which both the parties will sign or the last method is that one party will write to the other party, 'This is what we understood' and that closes the whole thing. Sir, here the Minister did not contradict because...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member's time is up.

SHRI UMANATH : Why, Sir? You said in the beginning...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only 5 or 7 minutes. Now please try to conclude.

SHRI UMANATH : So, Sir, the point is this : because the contents were true, he did not contradict.

The second point is what Shri Limaye said. That is also what I came to understand that on the letter there is a noting by Mr. Wanchoo. According to my information, that noting by Mr. Wanchoo is 'File'. You know in official correspondence if on the file a noting is made to 'file', that means that it is accepted, the whole

[Shri Umanath]

thing is finished and there is nothing more to pursue; it is closed. (*Interruptions*) This is the strongest point. I want the hon. Minister in his reply to tell us how he would explain these two positions. The 30th reply, I would say, is an afterthought. That is the clear position. It was an afterthought.

Now another thing I would like to bring to the notice of the hon Law Minister is with regard to the 2nd April statement where the hon. Minister said about his first meeting just before his departure for New York that he came and told him, 'This is the position' and asked for Government's reaction. The impression given by the Minister is that the first meeting of Mr. Thacker with his proposal and for his reaction was just before his departure to New York, that is 27th-29th and it means that the first meeting was on the 28th. So, my second point is that so far as the reply of 2nd April by the Minister is concerned—for the attention of the hon. Law Minister who is now unlawfully going through some other papers—the reply is unfortunate for him and that the reply is that the first meeting was on the 28th. On the 2nd April when he was replying, he was actually suppressing the fact of the first meeting on the 28th.

SHRI NATH PAL : *Suppressio veri suggestio falsi.*

SHRI UMANATH : Finally, on the question of susceptibility, the hon. Minister misled the House and here also I am referring to his 2nd April statement. On the 24th he said that was a revelation to him. 'It was a shocking revelation' he said. At the first meeting, that was on the 24th, he said that Mr. Thacker said, 'I am in financial difficulties'. That was on the 24th. I was surprised. In the first meeting he said 'I was in financial difficulties. I had to make certain security for the future. So I want to accept the Directorship of the Bank'. Although the statement of the Minister says that Mr. Thacker is susceptible to weaknesses in views of his financial difficulties, yet on 2nd what did he say? He misled the House by saying on the 2nd, 'I do not for a moment believe that a person of his stature and status

would fall a prey to such temptations'. Is it not misleading the House on the susceptibility of Mr. Thacker? All this means that the Minister has misled the House and I say this must go to the Privileges Committee because so many letters have been quoted, minutes of the Enquiry Committee are also in the picture, also the meetings between the Minister and Mr. Thacker are there, then written editorials of newspapers are there calling the Minister without using the word 'liar', but there are editorials in leading newspapers that he has misled the Parliament.

But this is the position. The question is whether this House can merely by a majority take a decision in such cases. So many letters are being quoted. So many minutes and records of committees are mentioned here. Our people will have this feeling that here is Parliament which, without going through the minutes, is deciding things by majority vote, and this will be spoiling the reputation of this Parliament in the entire country and in the entire world.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am sorry to state that this whole discussion has been more influenced by certain ideological predilections and it is being used so as to bring in some political colour on this entire matter. Sir, on one thing I must say what I feel, and that is, I am not happy with regard to the composition of this Committee itself. As a matter of fact, my humble submission is that the hon. Minister should have been very careful in constituting this Committee. This committee consisting of Dr. M. S. Thacker and Shri Mohan Kumaramangalam had more than what looked on the surface. All this trouble started with this composition of this committee and the moment it has begun to function. So, Sir, I do not want to attribute any motives and say this man is honest and that man is dishonest. What I want to say is, Professor Thacker has committed an act of impropriety more than dishonesty. Here is a matter between the hon. Minister and Professor Thacker and this matter has come up for discussion whether the Minister can agree to his taking up the directorship

of that Bank. And, during the course of conversations it is evident and it is clear, and it has been substantiated by later facts, that the Minister has clearly stated to Professor Thacker that it is not only improper but it also goes against the position he holds that he should not accept this Directorship of the Bank. This has been later substantiated by the Secretary when he has written in writing and also verbally that Professor Thacker has decided not to accept this position. Sir, here all the factors come into being. The correspondence is all one-way traffic. Mr. Rathee writes to Mr. Wanchoo; and even Mr. Wanchoo writes to Mr. Rathee. The Minister is not at all in the picture. By the correspondence that has been written it is now our hon. friends' right to draw certain implications and meanings that the hon. Minister has been misleading this House! Sir, it is all entirely false.

If the hon. Members demanded that there should be an enquiry constituted into this whole episode I am one with them. But if they want to take this up under the garb of Privilege motion, I am entirely against it. It does not at all constitute any breach of privilege because the Minister, in the course of his statement, has stated facts, and subsequently also he has never made an attempt to mislead the house nor has he committed any breach of the privilege of the House. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri Srinibas Misra.

SHRI NATH PAI : Before Shri Srinibas Misra starts, may I make one submission? Do we take Shri P. Venkatasubbaiah seriously when he makes this sporting offer? Here is a very senior Member of the ruling party who has thrown a challenge at us ..

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : He is the secretary of the Congress Party.

SHRI NATH PAI : He is a senior Member, none-the-less.

I think you, Sir, have heard him very clearly; he threw a challenge at us that he was prepared to accept an independent inquiry. Whose inquiry was it? Was it his inquiry or else whose inquiry was it?

MR. DEPUTY-SPEAKER : He said 'independent committees'. I had followed him. He said that there could be an independent committee to go into this whole affair. That is what he has said. It is a personal view that he has expressed.

SHRI NATH PAI : Since he is a senior Member, I wanted to know whose offer it was.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot allow this cross-examination now.

SHRI NATH PAI : I am not asking you, but I am asking the hon. Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a personal viewpoint that he has expressed.

SHRI NATH PAI : Then, let them say that they resile from it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Let me make it very clear to Shri Nath Pai. What I said was this. If hon. Members want I have said let there be an independent inquiry constituted. I meant an inquiry by Government into all those matters.

SHRI NATH PAI : We welcome this clarification. Inquiry by Government? That is the best joke of the year. I never knew such a strange sense of humour before.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : It appears that the Law Minister has underscored the privileges of this House. He wants to say that privilege is so valuable that it has to be preserved by all means. Is it contradictory with the privilege that the matter in respect of which a privilege of this House has been alleged to have been broken by the Minister concerned should be examined by the Privileges Committee? I agree with him that the matter is so great and that the privilege of this House is so valuable. So, I submit that it should be examined by a committee of this House. What objection could the Law Minister have to this?

The hon. Law Minister also wants that in a debate in this House, there should be charges framed against the Minister detailing them one by one and pointing out

[Shri Srinibas Misra]

that he is guilty of such and such a thing, but that has not been done.

SHRI NATH PAI: I shall do it later.

SHRI SRINIBAS MISRA: Had he read the privilege motions which had been submitted, he would have found that there were some in which the charges had been framed pointing out that such and such a sentence which was uttered by the Minister on the 2nd April was false, that such and such a sentence misled the House and so on.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would request the hon. Member to read the motion. There is no such thing there. It only wants that an investigation should be made. There is no question of charges being made that such and such a thing was false and so on.

SHRI NATH PAI: He is making them now.

SHRI SRINIBAS MISRA: The Law Minister had said that there were no specific charges which had been made. I would like to point out that Shri Umanath had brought forward some definite charges, and let the hon. Minister exercise his right of reply under natural justice. Then, there are other charges also in regard to the statements made in this House on 2nd April. I would like just to quote. The hon. Minister said:

"Subsequently, the Government have been informed that he declined the offer."

Here, the word 'he' refers to Prof. Thacker.

The second statement which he made was:

"Since he has not accepted the directorship of the bank, the question of replacing Prof. Thacker does not arise."

This is intended to mislead the House.

Then, in answer to Shri Chandra Jeet Yadav, he had stated:

"But before leaving, he told me that he had declined the offer."

The fourth statement which he made in reply to Shri Ranga was:

"He has not accepted the offer."

I would take these things one by one. First, I shall take up the last one. That is glaringly not true that he has not accepted the offer. Subsequent events have shown that he was about to accept the offer. According to the hon. Minister, the standard of proof in these matters must be records. Some records and some documents were sought to be placed by an hon. Member from our side of the House, and no contradiction has yet come. My hon. friends opposite do not say that the letters are false and they do not say that they are fabricated. Once the records are there and there is no contradiction, the House must take those documents as true and correct copies of the letters that were exchanged.

While answering the calling attention-notice on the 24th inst., this was the statement that the hon. Minister made.

"If it had been a fact that I had agreed to Prof. Thacker continuing as Chairman of the Committee even after becoming a Director of the Bank, surely there would have been some communication by the Government to him or to the Committee to that effect".

So the hon. Minister accepts that for proving his acceptance of Prof. Thacker's dual role, there must be some document on record. As there is no record, so that has not happened. This is his argument. I would like to point out that this argument can hold good for proving that the statement made by the Minister on 2 April is false. Had he declined the offer or the terms and conditions of Prof. Thacker accepting this dual role, there should have been something on record. The hon. Minister does not come forward with any statement, anything on record, to show that he told Prof. Thacker: 'You cannot act in this dual role'. What does it mean? It only means that with his connivance, Prof. Thacker had accepted, or was about to accept, the directorship.

The correspondence between Shri Rathee and Shri Wanchoo would show that the terms and conditions of this dual

role were also mapped out. The hon. Minister had accepted that. On the 20th, it is accepted that Prof. Thacker met the hon. Minister. On the 21st, in confirmation Prof. Thacker writes to the Secretary of the Ministry that this was the conversation; it has reference to a previous letter wherein the terms and conditions were set out.

After 21st, what becomes the position? The Secretary to the Ministry knows that Prof. Thacker is about to accept the directorship of the Bank of India. But how is it that the Minister does not know? How is it that the Minister who gets the answers and brief from the Secretary to answer in this question does not know this? How is it that he can say 'I do not know anything about it'? How can the Minister here make such a statement unless he wants to mislead the House? How could he make a statement like that, that 'I do not know whether he has accepted'? Rather he has made a contradictory statement saying that he has not accepted.

Therefore, my contention is that whatever the Minister has stated in these four sentences is either designed to mislead the House or is false. So I support the Motion for reference to the Privileges Committee.

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are several requests for the floor. Shri Dandeker had written to me also. Shri Sheo Narain will resume his seat.

SHRI SHEO NARAIN: Have I no right to speak in this House?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have already exceeded the time.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): My name is there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Several names are here. I will call the Minister. We have to conclude this by 4 P.M.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar): May I have a few minutes?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. I am very sorry. There is no time. I was in-

clined to give some time to Shri Dandeker because he had written to me at the beginning itself. But if I do that, I will have to allow others from either side. Members will excuse me.

SHRI NATH PAI: We will always excuse you.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): The House has had the benefit of hearing the views of many members so far as this Motion is concerned.

The relevant point under it is whether I made any statement on 2nd April which was either false or could be interpreted as one which had misled the House to take up a certain position.

SHRI J. B. KRIPALANI: Nobody is misled—that is wrong.

SHRI F. A. AHMED: Sir, I would like to say that so far as the question of any statement on the basis of which the House was likely to take a decision is concerned, that was not the issue on the 2nd April. Certain questions were put to me and I replied to those questions, and today I stand by what I stated on that day. Therefore, the question today is whether on the 2nd April, I had stated—*[Interruption]*—Mr. Gupta, you will please give me this indulgence. When you were speaking I did not utter a single word and I gave you full opportunity. I am here now in the place of an accused and I hope you will not deny me the principle of natural justice for what I have to say. Now, the only question is whether I gave false information to the House on the 2nd April.

SHRI J. B. KRIPALANI: Knowingly.

SHRI F. A. AHMED: Knowingly or unknowingly,—that question does not arise. I would only say that the question is whether I gave any false information to the House on that day. I would not like to repeat or read what has been said. There was the question whether Prof. Thacker had accepted the directorship of the Bank of India and, if so, what action the Government proposed to take. My reply to the first question was that Prof. Thacker was offered the directorship of the bank and he

[*Shri F. A. Ahmed*]

went to Bombay and informed in an informal meeting of the Board of Directors that he wanted three or four weeks' time and later he has informed me that he has not accepted that offer. And therefore the question of taking any action against him does not arise.

Now, in what particular manner, so far as these three statements are concerned, have I given information on facts which today are being denied by me, or, am I saying something different from those facts? I stand by every word of what I stated on that day. You will also remember that on that day, a large number of hon. Members took part and they actually criticised the conduct of Prof. Thacker. I said that he is a man of integrity, a man of such status and stature that I did not doubt about his honesty, and when I said that I did not propose to take any action against him, there was the opinion practically from all sections of the House that such a person should not be allowed to remain in office, and even the Speaker was pleased to say that Government should reconsider the decision of keeping Prof. Thacker in this post. This is what happened on that day.

Now, I would like to say this : in reply to the last question put by Mr. Rangra, I would like to repeat what I said in reply to that question. "As I have already pointed out he has not accepted the offer of becoming the Director of the bank .."—is this fact denied, and did I give wrong information so far as this fact is concerned ?

SHRI UMANATH : It was wrong information because on the 20th, you uttered to the contrary.

SHRI F. A. AHMED : I am making a statement on the 2nd April, and on the 2nd April I am making this statement that he has not accepted the offer of becoming a Director of the bank. Supposing he had accepted earlier, how could he give me the information that he has not accepted on the 30th ? I have not been able to understand the reasoning of the hon. member. If he had accepted on the 22nd, how could he send me a letter saying he is not accepting the offer of the bank, on the basis of which I made that statement ?

Just before his departure for New York,

he came and told me, after he had been to Bombay, he came and told me that he had taken three or four weeks' time from the bank. I said, if he becomes a Director of the Bank,—till then he had not become—it would be impossible for him to remain as the Chairman of this committee. Where is the inconsistency or falsehood in this ? On that day, none of the members had asked me whether Prof. Thacker had seen me on 20th and what I had told him or whether he had seen me on the 27th and what I had told him. I only referred to the meeting which I had on the 29th and when he said that he has taken three or four weeks' time, I said he could not remain as Chairman of this committee if he become a Director of the Bank. The next day, he said he has declined the offer. Where have I misled the House or made a wrong statement which can be taken exception to by any member ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. member should not read newspapers in the House like that.

SHRI F. A. AHMED : In this connection, I would refer to the observation made by Kripalaniji where he said that there was no harm in the minister having one opinion at one time, but if subsequently he had changed his opinion and communicated that opinion to Mr. Thacker and also the House, there would have been no breach of privilege. Assuming for the sake of argument that what is being alleged on the 21st is correct, on the 29th this position was there and the position of the Government was made clear to him that it would be impossible for him to remain as the Chairman of this committee.

SHRI MADHU LIMAYE : The cat is out of the bag.

SHRI NATH PAI : He stands self-condemned now.

SHRI F. A. AHMED : I am referring to Kripalaniji's observation that if later the minister had said this, there would have been no breach of privilege. At least he is convinced that there is no breach of privilege which I have committed so far as this matter is concerned.

श्री मधु लिमये : आप एडमिट कर रहे हैं क्या ?

SHRI F. A. AHMED : Admit what ?

श्री मधु लिमये : यही जो कृपालानी जी ने कहा है कि आपने बीस तारीख को स्वीकृति दे दी थी ।

SHRI F. A. AHMED : He had put in a hypothetical question and I had replied to that. (*Interruptions*).

Therefore, I humbly submit that so far as the facts are established, so far as the facts stand on record of the 2nd April and of what I have stated today, there is not a single fact from which it can be said that I said something which either misled the House or which was not correct. Therefore, I have not committed any breach of privilege and I am really very much distressed that without any substance the motion should have been placed before the House, that without even a *prima facie* case being there this motion should have been placed before the House.

Now I would like to refer to some of the observations that have been made during the course of this debate. I would first of all like to refer to the observation made by the hon. Member. He said that I am a person who has been in the legislature of Assam and in Parliament and he expected a better conduct from me. I can tell the hon. Member that I need not take any advice from him. I have had more than 33 years of parliamentary life both in the State legislature, in the Rajya Sabha and also in the Lok Sabha. I do not remember a day when on any single occasion I showed any disrespect to either the State legislature or to the Parliament. I had been all these 33 years time trying to see how the dignity of the House should be maintained. I think, Sir, that has been the experience of hon. Members of this House. I have been trying to do my job scrupulously. If I had committed any wrong, if I had given a wrong statement I would have been the first person to come before the House and say that I had given a wrong statement and I would like to correct it.

Secondly, some letters have been read by my hon. friend, Shri Kanwar Lal Gupta.

I do not know what is the source from which he got those official letters.

SHRI MADHU LIMAYE : Source is not important, its contents are important.

SHRI F. A. AHMED : I do not know the source from which he got those official letters. That itself indicates that those people who have come forward with this motion for reference to the Committee of Privileges have not come with clean hands.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इन को तहजीब सिलाइये । यह क्या तरीका है ? हर दो मिनट के बाद यह खड़े हो जाते हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Once a point of order is raised on a specific issue when certain expressions are being used from this side, I cannot just shut them out. I must listen to him.

SHRI BUTA SINGH (Rupar) : That is your weakness.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not a question of weakness, it is a question of fairness.

SHRI NATH PAI : Sir, an insinuation has been made about your weakness. We strongly repudiate this insinuation.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे व्यवस्था के प्रश्न में कोई दम नहीं है, तो आप उस को अस्वीकृत कर दीजिये । मुझे कुछ नहीं कहना है । यह इस सदन की गौर हाऊस आफ कामन्स की परम्परा रही है कि सदस्य इस तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं । किस लिए ? - इस लिए कि सत्य की प्रतिष्ठापना हो । तो यह अच्छा काम करने वालों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं है । (व्यवधान) अगर ये लोग पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को नहीं जानते हैं, पार्लियामेंट के सदस्यों के कर्तव्य को नहीं

[श्री मधु लिमये]

जानने हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन को यहाँ बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब कोई सदस्य इस सदन और जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो उनके बारे में इस तरह का लांछन लगाना बिल्कुल अप्रतिजनक है कि चूँकि वह सोर्य नहीं बताते हैं, उसी से यह पता चलता है कि उनके हाथ गन्दे हैं। मैं माँग करना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय बिला-शर्त इन शब्दों को वापस लें।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बे-ईमानदार हैं, तो ये बतायें कि उनको खत कहां से मिला।

श्री मधु लिमये : नहीं बतायेंगे।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग घोड़े में आ कर पैसे वालों से इस तरह की खबरें लेकर आते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If a certain expression is used and objection to that is taken by senior Members from this side, am I not to listen to them? (Interruptions)

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इन से ज्यादा वोट ले कर आए हैं। ये सीनियर कब से हो गये?

श्री मु० अ० खाँ (कासगंज) : चार साल इनको पालियामेंट में आए नहीं हुए, आप ने इन को "सीनियर मेम्बर" कैसे कह दिया?

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ़ आर्डर है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is very simple. You must listen to him. The Minister has stated "you have not come here with clean hands".

AN HON. MEMBER : What is wrong with it?

श्री शशि भूषण बाजपेयी : बहुत सही कहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I want to be fair. If you read the resolution, they have not raised anything of this sort. The only thing is that the method used for procuring the document may not be clean. But that is within their rights. If one says "because the motion is brought forward, therefore, your hands are not clean", that is correct. That is the point. Now, let the Minister conclude his speech..... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : May I appeal to the House to allow the Minister to conclude his speech?

SHRI NATH PAI : He must first withdraw those words about unclean hands.

SHRI RANGA : This should not be difficult for the Minister. He can withdraw those words. Because, only a few minutes ago, by inadvertence he used the word 'dishonest' instead of 'honest' and he was able to correct himself. We accepted it with good humour. So, he should be prepared to be chivalrous this time also and withdraw those words which are unbecoming of him and which are not proper to us..... (Interruptions).

श्री शशि भूषण बाजपेयी : जैसी इनकी पालिसी काली है, वैसे ही दिल भी काले हैं। ये समाजवाद को दफना रहे हैं।

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पायंट आफ़ आर्डर रोज़ किया था, लेकिन आपने मुझे नहीं बुलाया। जब आपने सब को मौका दिया, तो फिर मुझे क्यों मौका नहीं दिया? श्री रंगा को आप ने क्यों बुलाया? वे लोग हल्ला करते हैं, इसी लिए आप उनको मौका दे देते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give him an opportunity and listen to him later.

SHRI J. B. KRIPALANI : This is not a question only for this occasion. It raises questions of permanent importance, whether

the Members of Parliament, in discharging their duty, are entitled to get information from any quarter in order properly to serve the country and to serve the Parliament. This is the question that has got to be decided. As the editors of papers, so also the Members of Parliament are not required to disclose the source from which they got their information. This is a permanent issue which you have to decide.

16 00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I quote the ruling given by my predecessor. On this point, there is a clear ruling. (Interruptions).

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : I want to make a submission... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a question of the right of Members of this House. It is a fundamental issue. I am not going to permit anyone.

SHRI AMRIT NAHATA : When I asked Shri Kanwarlal Gupta, from where he got the letter, he said that he got it from the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am reading the ruling given by my predecessor which was delivered from the Chair.

"It is a fact that a document which is treated by the Government as secret or confidential can be obtained through leakage or stealth or in an irregular manner. But the Chair would not compel the Member to disclose the source from which copies have been obtained by him."

So, the ruling is quite clear. This is the ruling.

SHRI CHANDRA JEET YADAV : But it has to be authenticated. (Interruptions).

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Sir, it will not be possible for Members of the House to function if they are not able to get information from whenever they can get it. So long as

no corrupt methods are employed, that is, bribery or otherwise—if there is bribery employed, it can be said it is wrong—if anybody gives them, I do not think any source can be disclosed or we can ask for it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, this chapter is closed now. Let the hon. Minister conclude now. (Interruptions) The Deputy Prime Minister has made the position clear. He has supported the ruling.

श्री शशि भूषण बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जो बान में कहेंगा उस पर आप रुलिंग दे सकते हैं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Minister should be asked to withdraw those words.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whatever he has to say, let him say. I have already given the ruling. I have read out the earlier ruling. The Deputy Prime Minister also has upheld it. In such a situation, I would request the Minister to say whatever he has got to say.

SHRI MORARJI DESAI : I have to to accept the ruling. Where is the question of my upholding it ?

SHRI F. A. AHMED : If the hon. Members will have a little patience, I would just say that I had not asked a question or asked anyone to disclose the source of information. As Prof. Ranga has appealed to me, if it has really hurt the feeling of some of the hon. Members, I unconditionally withdraw it but... (Interruptions) But I hope and trust that they will also take into consideration my own feeling when I have been subjected to a motion for which there is no substance.

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल एक ही चीज सामने रखना चाहता हूँ। मेरा मुख्य आरोप था उद्योग मंत्री फखरुद्दीन खली अहमद के खिलाफ कि इन्होंने जान-बूझ कर और कौन्सेन्साली सदन को गुमराह किया है और यह चीज आज के वितर्क से साबित हो चुकी

[श्री रवि राय]

हैं। आज सारे सदन के सामने श्रीर दुनिया के फखरुद्दीन अली अहमद (..... व्यवधान).....

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज जो सदन के सामने नहीं आई, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 27 और 29 ता० को ठक्कर साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई, यानी उनके अमरीका जाने से पहले यह मुलाकात हुई, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि उस आफिशियल डेलीगेशन के सदस्य के नाते इन्होंने उन को अमरीका क्यों भेजा। जब ये खुद कहते हैं कि ता० 29 को सूचित कर दिया था, तो फिर उन को न्यूयार्क जाने की इजाजत क्यों दी गई? जब संसद में यह चीज ता० 2 को उठ गई, तो फिर उन को न्यूयार्क से दोबारा बुलाया गया—यह एक नई बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लेटिन वाक्य है—
सप्रेशियो वेरी, सजेस्टियो फालशी।

इस का मतलब है—सत्य को छुपाना और असत्य को सूचित करना। 20 तारीख के बारे में खुद मन्त्री महोदय कोई सफाई नहीं दे पाए हैं, क्यों कि उन के पास कोई तर्क नहीं है। जैसा मधु लिमये जी ने कहा—हम को कुमारमंगलम जी को धन्यवाद देना चाहिए, क्यों कि ये तथ्य वे उनके सामने लाये। 20 तारीख को इन्होंने बाकायदा ठक्कर साहब को कह दिया था कि तुम दोनों जगह काम कर सकते हो। इस लिए मैं आपके सामने.....

श्री शशि भूषण वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। उन्होंने कुमार मंगलम का जिक्र किया है, उन्होंने कोई इतिला नहीं दी—न मिनिस्टर को और न किसी को। बैंक आफ इंडिया के डायरेक्टर्स ने ठक्कर को रिश्वत दी है।

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कांग्रेस दल से प्रार्थना करना चाहता हूँ—एक सेकण्ड के लिये वह भूल जाय कि वह कांग्रेस

दल के सदस्य हैं और हम लोग भी भूल जाय कि हम विरोधी दलों के सदस्य हैं—आज संसदीय प्रजातंत्र को इस देश में बलशाली बनाना है—यह प्रश्न हमारे सामने है। सच्चाई के ऊपर, सत्य के ऊपर यह संसदीय प्रजातंत्र आधारित होगा या भूठ, गलत बयानी, मिसलीड करने पर यह चलेगा? इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ—मोरारजी भाई बैठे हुए हैं, वह उप प्रधान मंत्री हैं और इस समय सदन के नेता के नाते बैठे हुए हैं—वे इस पर कांग्रेस दल को कोई व्हिप न दें और कांग्रेस दल ठन्डे दिमाग से हमारे मोशन पर वोट डाले। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस को बहुमत का सवाल मत बनाइए, संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने के लिये हिन्दुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि एक मन्त्री अपनी गलत बयानी के लिये माफी मांगता है या नहीं और कांग्रेस इस को मानती है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस मोशन को मान लें।

SHRI NATH PAI : Before you proceed to take the vote, I rise on a point of order I draw your attention to rule 227 which says :

“Notwithstanding anything contained these rules, the Speaker may refer any question or privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report.”

MR. DEPUY-SPEAKER: Sir, before you call upon the House to vote on this, under this Rule 227 of the Amended Rules—page 103—I want you to read first Rule 226 and then come to Rule 227 which reads :

“Notwithstanding anything contained in these Rules, the Speaker (which includes Deputy-Speaker also) may refer...”

AN HON. MEMBER : The word used is ‘may’.

SHRI NATH PAI : My submission, therefore, to you is this :

There is a misapprehension on the part of the hon. Minister as also on the part of some others that we are trying to bring an indictment to-day. The motion is not saying that he is guilty of telling an untruth. The motion is that there is a doubt about this statement and, therefore, it may be referred to the Privileges Committee for ascertaining the truth. (*Interruptions*)

Let us understand it. The hon. Minister, Sir, in his reply said, 'I stand as an accused'. He completely misunderstood our intentions. We say that we believe that the statements which have been made by him on two occasions contradict each other. The matter has been brought so much before the House that it needs, Sir, the cool and calm reflection of the Privileges Committee. Though they will use the majority, I want to appeal to the Deputy Prime Minister to refrain from the consultations that he is having with his colleagues... (*Interruptions*) He is agreeing, he is likely to agree, it seems. (*Interruptions*) That is what he is saying. I want to make an appeal to the Deputy Leader of the Government—whatever be his status, he is the Deputy Prime Minister here—that just as he has upheld the ruling given by you with good grace, let him not use the majority. He knows this is not a party issue and for ascertaining the truth the House is not the forum.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have gone beyond the scope of the point of order.

SHRI NATH PAI : I am making an appeal to you to use your discretion and refer the issue to the Privileges Committee. But I am asking him to agree with my submission : let us not try to pass a judgment, let it not be said that when an issue of privilege comes, the Congress Party with its majority invariably vote it down. I want you, Sir, in case he disregards my appeal, to use your inherent discretion and refer this issue to the Privileges Committee as this discretion is vested in you.

SHRI R. D. BHANDARE *rose*—

MR. DEPUTY-SPEAKER : You want to argue.

SHRI R. D. BHANDARE : I am not arguing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please be very brief.

SHRI R. D. BHANDARE : Neither I am accusing him, Sir. Since the hon. Member could not speak on the main motion, therefore, I think... (*Interruptions*) Any way I am not accusing him.

Rule 226, once it is applied, Rule 227 is redundant and cannot be resorted to and no request could be made. That request would be a compulsion in the sense of playing on the mind of the Chair and playing on the minds of hon. Members. Therefore, once Rule 226 is invoked, 227 cannot be applied.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have heard the hon. Member. (*Interruptions*) A very pertinent point has been raised. The rule says: 'Notwithstanding anything...' That means the recognition of an inherent right in the Chair. (*Interruptions*) Regarding the privilege issue, as I said during the course of the debate, if I were to exercise my judgment on this issue, it would have been far better to exercise it at an earlier stage. You will agree with it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Better late than never.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even if it is referred to the Privileges Committee, for which a demand from this side has been made, ultimately, the Privileges Committee's report will have to be approved by this House.

SHRI J. B. KRIPALANI : Therefore, I suggested that at the earlier stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So, so far as the privilege issue is concerned, the final judgment is to be delivered by this House. The House has a right to refer it back to the Committee or modify it, whatever they like. As a rule we come before this House. That you know. (*Interruptions*) Therefore, Mr. Nath Pai, though your point is very relevant and you have made an appeal, at this stage it would not be proper on the part of the Chair to exercise its own judgment.

Now I will put it to the vote of the House.

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि इसको आप प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Nath Pai has appealed to the Deputy Prime Minister. (Interruptions).

श्री एम० एम० जोशी : इस चर्चा के बाद जब ऐसे तथ्य हमारे सामने आये हैं तो जैसा हमारे मित्र ने कहा कि इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, जहां तक इन बातों का प्रश्न है हम सब एक हैं, इस लिए यह उचित होगा कि यह देखने के लिये कि तथ्य क्या है, इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया जाये । (व्यवधान).....

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, सत्य का तकाजा है कि आप इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दीजिये ।... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY-SPEAKER : I entirely agree. It is the privilege of the House ; but now at this stage, I am not exercising it. Now the question is... (Interruptions)

SHRI PILOO MODY (Godhra) : When these rules were framed what the framers of the rules had in mind was that when a case was brought before the House for enquiry, by merely possessing a brute majority it cannot be brushed aside. It is for that reason that this discretion was given to the Chair. Now, after having heard the arguments you still insist in not using the discretion that has been given to you. I think it is a grave miscarriage of the proceedings of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he had read the rules he would find that there is no such thing. Now, I have to put it to the vote.

श्री रवि राय : उपाध्यक्ष महोदय, सत्य का तकाजा है कि आप इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दें ।..... (व्यवधान).....

इसका डिस्क्रिशन आप को है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put it to the vote.

AN HON. MEMBER : You may put it to the vote, Sir.

श्री शिव नारायण : हमारी प्रार्थना है कि आप वोट कराइये ।

SHRI J. B. KRIPALANI : Here in the discussion Members wanted you to exercise your discretion. Now I can only plead with them that it is not a matter in which the party can issue a whip. At least they should not issue a whip and at least they can allow Members to vote as like.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put the amendment to the vote of the House. The question is :

That in the Motion moved by Shri Rabi Ray after "2nd" insert "and 24th"

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will put the main motion to the vote of the House. The question is :

"Whereas in the opinion of this House, it clearly appears necessary to inquire whether a breach of privilege of the House has been committed or not by the Minister of Industrial Development and Company Affairs by the reply given by him on the 2nd April, 1968, this House, therefore, resolves to refer this matter to the Committee of Privileges with instructions to report on the first day of the next session."

Let the lobby be cleared.

The Lok Sabha divided :

16.24 hrs.

DIVISION No. 15

AYES

Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Amin, Shri Ramchandra J.
Banerjee, Shri S. M.
Singh, Shri Bansh Narain
Basu, Shri Jyotirmoy
Berwa, Shri Onkar Lal

Bhagaban Das, Shri
 Bharat Singh, Shri
 Brij Bhushan Lal, Shri
 Brij Raj Singh Kotah, Shri
 Chakrapani, Shri C. K.
 Chandra Shekhar Singh, Shri
 Dandeker, Shri N.
 Deo, Shri R. R. Singh
 Desai, Shri C. C.
 Desai, Shri Dinkar
 Devgun, Shri Hardayal
 Digvijai Nath, Shri Mahant
 Fernandes, Shri George
 Ghosh, Shri Ganesh
 Girraj Saran Singh, Shri
 Goel, Shri Shri Chand
 Gowd, Shri Gadilingana
 Gowder, Shri Nanja
 Guha, Shri Samar
 Gupta, Shri Kanwar Lal
 Haldar, Shri K.
 Jha, Shri Shiva Chandra
 Joshi, Shri S. M.
 Kalita, Shri Dhireswar
 Karni Singh, Dr.
 Khan, Shri H. Ajmal
 Khan, Shri Ghayoor Ali
 Kothari, Shri S. S.
 Koushik, Shri K. M.
 Kunte, Shri Dattatraya
 Kushwah, Shri Y. S.
 Limaye, Shri Madhu
 Madhok, Shri Bal Raj
 Maiti, Shri S. N.
 Majhi, Shri Mahendra
 Mangalathumadom, Shri
 Meghachandra, Shri M.
 Misra, Shri Srinibas
 Modak, Shri B. K.
 Mody, Shri Piloo
 Mohamed, Imam Shri J.
 Molahu Prasad, Shri
 Naik, Shri G. C.
 Naik, Shri R. V.
 Nair, Shri Vasudevan
 Parmar, Shri D. R.
 Paswan, Shri Kedar
 Patil, Shri N. R.
 Ram Charan, Shri
 Ramji Ram, Shri
 Ranga, Shri
 Rao, Shri V. Narasimha
 Ray, Shri Rab
 Reddy, Shri M. N.
 Samanta, Shri S. C.
 Santosham, Dr. M.
 Satya Narain Singh, Shri

Sequeira, Shri Erasmo de
 Sharma, Shri B. S.
 Sharma, Shri N. S.
 Sharma, Shri Yogendra
 Shastri, Shri Ramavatar
 Shastri, Shri Raghevir Singh
 Solanki, Shri P. N.
 Somani, Shri N. K.
 Sundar Lal, Shri J.
 Tapuriah, Shri S. K.
 Thakur, Shri Gunanand
 Umanath, Shri
 Vajpayee, Shri Atal Bihari
 Xavier, Shri S.

NOES

Achal Singh, Shri
 Agadi, Shri S. A.
 Ahmed, Shri F. A.
 Arumugam, Shri R. S
 Babunath Singh, Shri
 Badrudduja, Shri
 Bajaj, Shri Kamalnayan
 Bajpai, Shri Shashibhushan
 Barua, Shri Bedabrata
 Barua, Shri R.
 Barupal, Shri P. L.
 Baswant, Shri
 Besra, Shri S. C.
 Bhagat, Shri B. R.
 Bhagavati, Shri
 Bhakt Darshan, Shri
 Bhandare, Shri R. D.
 Bholu Nath, Shri
 Birua, Shri Kolai
 Buta Singh, Shri
 Chanda, Shri Anil K.
 Chanda, Shrimati Jyotsna
 Chatterji, Shri Krishna Kumar
 Chaturvedi, Shri R. L.
 Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
 Chavan, Shri D. R.
 Chavan, Shri Y. B.
 Choudhury, Shri J. K.
 Damani, Shri S. R.
 Das, Shri N. T.
 Dass, Shri C.
 Desai, Shri Morarji
 Deshmukh, Shri B. D.
 Dhillon, Shri G. S.
 Dhuleshwar Meena, Shri
 Dinesh Singh, Shri
 Dixit, Shri G. C.
 Dwivedi, Shri Nageshwar
 Gajraj Singh Rao, Shri
 Ganesh, Shri K. R.

Gautam, Shri C. D.
 Gavit, Shri Tukaram
 Ghosh, Shri P. K.
 Ghosh, Shri Parimal
 Gupta, Shri Lakkan Lal
 Hanumanthaiya, Shri
 Hari Krishna, Shri
 Hazarika, Shri J. N.
 Hem Raj, Shri
 Jadhav, Shri Tulshidas
 Jagjiwan Ram, Shri
 Kamble, Shri
 Kumari, Kamala Kumari
 Kasture, Shri A. S.
 Katham, Shri B. N.
 Kavade, Shri B. R.
 Kripalani, Shrimati Sucheta
 Krishna, Shri M. R.
 Krishnan, Shri G. Y.
 Kureel, Shri B. N.
 Kushok Bakula, Shri
 Laskar, Shri N. R.
 Mahadeva Prasad, Dr.
 Maharaj Singh, Shri
 Mahida, Shri Narendra Singh
 Malhotra, Shri Inder J.
 Malimariyappa, Shri
 Mandal, Shri Yamuna Prasad
 Mane, Shri Shankarrao
 Mehta, Shri Asoka
 Mehta, Shri P. M.
 Melkote, Dr.
 Menon, Shri Govinda
 Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
 Mirza, Shri Bakar Ali
 Mishra, Shri G. S.
 Mohammed Ismail, Shri
 Mohsin, Shri
 Mrityunjay Prasad, Shri
 Mukerjee, Shrimati Sharda
 Nahata, Shri Amrit
 Naidu, Shri Chengalraya
 Nayar, Dr. Sushila
 Pahadia, Shri Jagannath
 Panigrahi, Shri Chintamani
 Parmar, Shri Bhaljibhai
 Partap Singh, Shri
 Patel, Shri Manibhai J.
 Patel, Shri Manubhai
 Patil, Shri Anantrao
 Patil, Shri C. A.
 Patil, Shri Deorao
 Patil, Shri S. D.
 Radhabai, Shrimati B.
 Raghuramaiah, Shri

Raj Deo Singh, Shri
 Rajasekharan, Shri
 Ram Dhan, Shri
 Ram Dhani Das, Shri
 Ram Subhag Singh, Dr.
 Ram Swarup, Shri
 Ramshekhar Prasad Singh, Shri
 Rao, Shri Jaganath
 Rao, Shri K. Narayana
 Rao, Shri J. Ramapathi
 Rao, Shri Thirumala
 Raut, Shri Bhola
 Reddy, Shri P. Antony
 Reddy, Shri R. D.
 Rohtagi, Shrimati Sushila
 Roy, Shrimati Uma
 Sadhu Ram, Shri
 Saha, Dr. S. K.
 Saigal, Shri A. S.
 Sait, Shri Ebrahim Sulaiman
 Saleem, Shri M. Y.
 Salve, Shri N. K. P.
 Sangni, Shri N. K.
 Sapre, Shrimati Tara
 Sarma, Shri A. T.
 Sayyad, Ali Shri
 Sethi, Shri P. C.
 Sethuramae, Shri N.
 Shambhu Nath, Shri
 Shankaranand, Shri
 Sheo Narain, Shri
 Sheth, Shri T. M.
 Shukla, Shri Vidya Charan
 Siddheshwar Prasad, Shri
 Sinha, Shri R. K.
 Sinha Shrimati Tarkeshwari
 Sonavane, Shri
 Sudarsanam, Shri M.
 Supakar, Shri Sradhakar
 Surendra Pal Singh, Shri
 Sursingh, Shri
 Suryanarayana Shri K.
 Swaran Singh, Shri
 Tarodekar, Shri Y. B.
 Tripathi, Shri K. D.
 Tula Ram, Shri
 Uikey, Shri M. G.
 Venkatasubbaiah, Shri P.
 Verma, Shri Prem Chand
 Yadav Shri Chandra Jeet

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result*
 of the Division is : Ayes : 78 ; Noes : 145-

The motion was negatived

*The following Members also wanted to record their votes :

AYES : Sarvashri J. B. Kripalani, Nath Pai, Mohammad Ismail, A. Sreedharan and D. N. Deb.

NOES : Sarvashri M. A. Khan, Ankineedu, M. N. Naghnoor and Parthasarathy.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notification re : Market Loans floated

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : I beg to lay on the Table a copy of Ministry of Finance Notification No. F. 4(4)—W. & M./68 published in Gazettee of India dated the 25th April, 1968, regarding Market Loans floated by the Central Government in 1968-69 (Hindi and English versions). [Placed in Library. See No. LT—1044/68].

Shipping Development Fund (Loans) Amendment Rules

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND COMMUNICA-TIONS (DR. RAM SUBAGH SINGH) : On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao, I beg to lay on the Table a copy of the Shipping Development Fund (Loans) Amendment Rules, 1968, published in Notification No. G. S. R. 665 in Gazettee of India dated the 6th April, 1968, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [Placed in Library. See No. LT—1046/68].

Notification under All India Services Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :—

(1) The Indian Police Service (Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers) (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1968, published in Notification No. G. S. R. 690 in Gazettee of India dated the 13th April, 1968.

(2) The Indian Administrative Service (Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers) (Appointment by Competitive Examination) Amendment Regulations, 1968, published in Notification No. G. S. R. 691 in Gazettee of India dated the 13th April, 1968.

(3) The Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Amendment

Regulations, 1968, published in Notification No. G. S. R. 692 in Gazettee of India dated the 13th April, 1968. [Placed in Library. See No. LT—1045/68].

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

(i) Minutes

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Bairampur) : I beg to lay on the Table Minutes of the Thirteenth to Nineteenth Sittings of the Committee on Government Assurances.

(ii) Second Report

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I beg to present the Second Report of the Committee on Government Assurances.

(iii) Evidence

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I beg to lay on the Table a copy of the Evidence before the Committee on Government Assurances.

16.25 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

Fifty-fifth Report

SHRI P. VENKATASUBBIAH (Nandyal) : I beg to present the Fifty-fifth Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the Seventy-third Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on the erstwhile Ministry of Food Agriculture (Department of Agriculture)—(Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Nineteenth and Twentieth Reports

SHRI MANUBHAI PATEL (Dabhoi) : I beg to present the following Reports of

[Shri Manubhai Patel]

the Committee on Public Undertakings :—

(1) Nineteenth Report on action taken by Government on the recommendations contained in Eighth Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on Townships and Factory Buildings of Public Undertakings.

(2) Twentieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the First Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on National Buildings Construction Corporation Limited.

16.26 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : Sir, Government Business in this House during the week commencing 29th April, 1968, will consist of :

- (1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
- (2) Discussion and voting on Demands for Grants (Uttar Pradesh) for 1968-69.
Demands for Grants (West Bengal) for 1968-69.
- (3) Consideration and passing of The Civil Defence Bill, 1967 The Pondicherry (Extension of Laws) Bill, 1967.

The Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill, 1967.

- (4) Consideration of motions for modification of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968, given notice of by Sarvashri Srinibas Misra and Madhu Limaye on Thursday, the 2nd May, 1968, at 5-30 P.M.

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur) Even after the Finance Bill will be over...

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not yet over.

SHRI S. M. BANERJEE : He has referred to pending business being taken up next week first. I am sorry that two or three items which we wanted to be discussed have not been included.

First, we have demanded a discussion on automation. There is a motion pending. It should be allowed.

Second, if there is no time to have a proper discussion, almost all members belonging to this side practically, have requested the Home Minister through the Speaker to make a statement on the hunger strike by policemen. They are going on suffering.

Thirdly, there is President's rule in Haryana and more than 200 government employees have been victimised. The Governor does not listen to them. He says that popular government is coming. I would only request the Minister to convey to the Home Minister our demand that he should make a statement about these Haryana Government employees. Over 200 of them have been victimised. I can produce documents. Naturally, when elections are in the offing there, every Minister goes there and makes tall promises. I am told even the Prime Minister is there. Instead of coming to the Lok Sabha she is touring Jhajjar and Karnal constituencies. So let there be a statement by the Home Minister about the Haryana government employees.

16.29 hrs

[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

I was saying that there are three or four important items which we wanted included in next week's business. The first thing is that there should be a statement on the hunger strike resorted to by policemen.

In Delhi. This is a very important matter. 42 MPs have sent in an appeal to Home Minister. Calling attention notices and Short Notice questions on this are not allowed. After all, we should be concerned about the fate of these employees.

Either a discussion should be allowed or a statement should be made by the Home Minister.

The second thing is that we have tabled a motion on automation. Automation has been introduced not only in the LIC but in all other public undertakings. It has become a menace. Let there be a discussion on automation. A motion is there, and Dr Ram Subhag Singh promised at the Business Advisory Committee that he would have no objection if the motion was discussed.

The third thing is the hunger-strike. Today is the 27th day of the hunger-strike of the Government employees in Haryana. The Governor has refused to meet them. When there is no Assembly there, I would request the hon. Home Minister to make a statement here regarding the hunger-strike.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : May I submit that about a month ago the Minister had promised that after the finance Bill is finished he would take up some of the no-day-yet-named motions. Many of them are pending. May I submit that during this session not a single no-day-yet-named motion has been taken up. My submission is that the Minister of Parliamentary Affairs should enable the House at least to take up one or two no-day-yet-named motions. Otherwise it would appear that there is no purpose served by these motions even after having accepted them to come before the House. May I request the Minister to kindly find some time to bring some of these no-day-yet-named motions before the House ?

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : I support what Shri Kothari has said. At the beginning of the session we tabled a number of no-day-yet-named motions and a meeting was held when some of these motions were selected for discussion. Now we are reaching the fag-end of this session and so far not a single one of these motions has been taken up. I would suggest that at least some of them must be discussed in the House, before the House adjourns.

Secondly, we find that in the capital city where lakhs of Government servants live, in the Ramakrishnapuram area and other colonies of Government servants, and when summer has started, there is no water. The women and children are

crying there. Calling Attention Notices have been given; short notice question have been given, and they are not accepted. I would like the Minister of works, Housing and Supply to make a statement about the water situation, particularly in Ramakrishnapuram which is the biggest colony of Government servants.

Then the police question is there. Whatever the Home Minister may say, the fact remains that thousands of people are under trial; some of them are on hunger-strike; the trials are being lengthened and other irregularities are being committed. Some statement about that also should be made in the House.

About Haryana, Haryana is being ruled by the President now, and there is a lot of discontent among the Government servants there. Some of them have gone on hunger-strike. Hundreds of thousands of them are victimised. Some statement about that situation should also be made in the House and some discussion should be there. All these four items should come up before the House in the next week.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, पुलिस वालों और आटोमेशन के बारे में जो कुछ कहा गया है उसका समर्थन करते हुए मुझे एक ही बात और कहनी है। 10-15 दिनों से पूर्व रेलवे की कई गाड़ियां वक्त पर नहीं चल रही हैं। कई गाड़ियां कंसल की गई हैं और कड़्यों के रुकने की स्थिति है। उन की कुछ शिकायतों पर ध्यान न दिये जाने के कारण वहां के लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रेलवे मंत्री जी मुसाफिरों को जो अइचन हो रही है उसके बारे में और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में एक बयान दे। हमारे गृह मंत्री भी यहां बैठे हैं। वह कई दिनों से पूरे हिन्दुस्तान में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मैं चाहता हूं कि पिछले 10-15 दिनों में इलाहाबाद में और दूसरी जगह पर जो दंगे हुए हैं उनके ऊपर भी एक बयान आये ताकि इस मसले पर सदन में बहस करने का मौका हम को मिल सके।

श्री श्रीकान्त गोयल (बण्डीगढ़) : सभा-पति महोदय, जहां तक हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न है, उस सिलसिले में हम माननीय गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि होम मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री बण्डीगढ़ जाने वाले हैं और वह राज्यपाल से बातचीत करेंगे। वहां के दो कर्मचारियों ने 31 मार्च से भूख हड़ताल कर रखी है। 12 अप्रैल को उन को बण्डीगढ़ से गिरफ्तार कर के झज्जाला जेल में भेजा गया। वहां के गवर्नरने एक बड़ा मजहकालेख बयान दिया जब उन्होंने यह कहा कि वह लोग जेल के अन्दर बड़े भजे में हैं और आराम से खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां पर पार्लियामेंट के मेम्बरों का एक बफत मिलकर आया। उनकी स्थिति इस प्रकार से नाजुक है कि जिस दिन कचेहरी में उन की पेशी भी उसी दिन डाक्टर ने लिखा हुआ दिया कि वह वहां से भूख करने के काबिल नहीं हैं और कचेहरी में जा कर पेशी नहीं भुगत सकेंगे। आज उन की इस प्रकार की स्थिति है।

दूसरा जो बंच है वह भी गिरफ्तार किया गया है। तीसरा बंच हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज इस बात की जरूरत है कि हमारे गृह मंत्री जी बीच में पड़ कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। मामला यह है कि दरअसल उन को दो किस्में दे दी गई हैं। नौ महीने के एरियंस देने का प्रश्न है। या तो स्वयम् गृह मंत्री इसका कोई हल निकालें या फिर गवर्नर से इसका प्रयास करवायें। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह निश्चित रूप से कोई स्टेटमेंट यहां पर भ्रमले सप्ताह दें क्योंकि हरियाणा के कर्मचारी बड़े एजिटेटेड हैं। उन का मन काम में नहीं लगता है। चुनाव सर पर खा रहे हैं। अब धरमद चुनावों को एक दिन के बजाय दो दिनों में करावे का निश्चय गृह मंत्री ने किया है। इन सब बातों पर निश्चित रूप से कोई बयान प्राना चाहिये।

SHRI UMANATH (Pudukoattai) : I support the demand that some time must be found next week for a discussion on automation and the police hungerstrike reactions are there in the policemen who are in service. There should be a discussion on that so that there may be some intervention by the Home Minister and a settlement may be made.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं पुलिस के सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए चिट्ठियां लिखी हैं, 42 या 43 एम पीज ने चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन अफसोस यह है कि उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। ऐकनालेज तक नहीं किया। इस से हमें लगता है कि या तो उन के प्रति उन की हमदर्दी नहीं है या फिर वह इस को दबा देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह इस सवाल पर कोई ब्यक्तव्य इस सदन में रखें कि उन की पुलिस के मामले में क्या नीति है। ताकि उन लोगों के असन्तोष को दूर किया जा सके। सिविल लाइन्स में जो उन का ट्रायल हो रहा है वह भी बहुत गलत ढंग से हो रहा है। 6 एम पीज ने जा कर उस को देखा है और इस की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस मामले पर बहस नहीं होगी तो फिर सारी बात गड़बड़ हो जायेगी।

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been placed before the House. I would like to know whether the Minister of Parliamentary Affairs would be able to find some time before the end of this session to discuss that report also.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I would also like to say that the police hunger-strike and communal situation should be discussed in this House.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Shri Sonavane is a member of the Business Advisory Committee. Mr. Banerjee said some

assurance was given. I can assure the House that whatever assurance was given in the Business Advisory Committee, that will be honoured. Whatever decision the committee takes, for that we will find time. Most of the opposition leaders are there on the Business Advisory Committee.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ने ऐक्यूज नहीं किया है। मैं ने तो यही कहा है कि फाइनेन्स बिल के बाद ग्राटीमेशन के बारे में भी कंसिडर किया जाय।

DR. RAM SUBHAG SINGH : This is the business for the week commencing on 29th. In that week, The Finance Bill will have to be passed and also the UP and West Bengal budgets will have to be passed. I do not think there will be any time left for anything else in that week. I am sorry it is not possible to accept the suggestions made.

SHRI BAL RAJ MADHOK : There should be a discussion on communalism. That is communalism; who is encouraging it, etc. are vital matters. There should be a full-scale discussion in this House on that so that levelling charges that somebody is doing it may stop.

16.40 hrs.

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the separation of judicial and executive functions in Union Territories.

THE CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the separation of judicial and executive functions in Union Territories."

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN : We now proceed to Private Members' Business.

16.41 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Twenty-ninth Report

SHRI K. M. Koushik (Chanda) : Sir, I beg to move :

"That this House agrees with the Twenty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th April, 1968."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That this House agrees with the Twenty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th April, 1968."

The motion was adopted.

16 41½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of article 217)

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI M. N. REDDY : Sir, I introduce the Bill.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 25.4.68.

LABOUR (PARTICIPATION IN MANAGEMENT) BILL*

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidental thereto.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for participation of employees in the management of industrial or commercial undertakings in which they work and for other matters incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 90, 92 etc.)

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI SRINIBAS MISRA : Sir, I introduce the Bill.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 6)

SHRI MANIBHAI J. PATEL (Damoh) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, साधारण तौर पर किसी भी निजी सदस्य के विधेयक को पेश करने का जब सवाल आता है तो उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये और यह जो सिद्धान्त है इसको हमेशा इस सदन ने माना है। यह जो विधेयक है यह सदस्यों के भत्ते और तनख्वाह के बारे में है। सैलेरी एंड एलाउंसिस आफ मॅम्बरज़ आफ पार्लियामेंट के बारे में विधेयक है। यह एक छोटा सा बिल है। इस बिल के द्वारा यह मांग की गई है कि पहले दर्जे के डिब्बे में जगह नहीं मिलती है तो एयर कंडिश्ड कोच में सदस्य को जगह दी जाए। इस सुभाव का मैं सख्त विरोध करना चाहता हूँ।

आज इस तरह की सुविधा जिन लोगों को हासिल है, चाहे वे मंत्री हों, अफसर हो या रेलवे फंडेशन के कर्मचारी हों, उसका भी मैं घोर विरोध करना चाहता हूँ। इस तरह की सुविधा किसी को भी नहीं दी जानी चाहिये। अगर कोई एयर कंडिश्ड कोच में जाना चाहता है तो पैसा दे कर जा सकता है

श्री प० ला० बाळूपाल (गंगानगर) : थर्ड क्लास में चलो।

श्री मधु लिमये : इसको भी करिये। हमारे दल की तरफ से तो कई बार मांग की गई है कि बीस पच्चीस साल तक जब तक इस देश का निर्माण नहीं हो जाता है रेलों में, बसों में एक ही दर्जे की मुसाफिरी की इजाजत हो। इस बात को तो हमने बार बार कहा है। इस में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब और सुविधायें अगर बढ़ाने की मांग आती है तो मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप किस दर्जे में यात्रा करते हैं।

श्री मधु लिमये : मेरे यहां आने के पहले आप लोगों ने जो सुविधा दे रखी है उससे मैं कोई ज्यादा सुविधा की मांग नहीं कर रहा हूँ और न मैंने कभी की है। लेकिन मेरी यह मांग है कि इस तरह की एयर कंडिशन कोच में प्रवास करने की इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिये, न अफसरों को होनी चाहिये, न मंत्रियों को होनी चाहिये, न रेलवे फंडेशन के जिन व्यक्तियों को एयर कंडिशन कोचिज के पास दिये गए हैं, उनको होनी चाहिये। ऐसा करके उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है और इस कारण से ट्रेड यूनियन आन्दोलन नहीं बढ़ता है (इंटरप्रांज)

मैंने तीसरे दर्जे की बात की है और तमाम लोगों के लिए बात की है...

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : Sir, are we discussing the merits of the Bill ?

श्री मधु लिमये : मैं मैरिट्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं डिटेल् में नहीं जा रहा हूँ। आपके पेट में इतना दब क्यों हो रहा है ?

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : आप तो खुद फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं।

श्री मधु लिमये : तो उसका मतलब है कि हवाई जहाज से भी मुफ्त जाओगे, एयर-कंडिशन से भी मुफ्त जाओगे ?

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : डिफेंस तो दे रहे हैं।

श्री मधु लिमये : उनका बिल क्या है यह आपको मालूम नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डिफेंस दे कर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं या एयर कंडिशन कोच से जाना चाहते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन मुफ्त में मैं नहीं चाहता हूँ कि

कोई चाहे मन्त्री हो या अफसर हो या ट्रेड यूनियन का आफिशल हो या सदस्य हो, वह प्रवास करे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह इसको वापिस ले लें।

MR. CHAIRMAN : I will now put it to the vote of the House. The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

Those in favour may please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS : 'Aye'.

MR. CHAIRMAN : Those against it may please say 'No'.

SOME HON. MEMBERS : 'No'.

MR. CHAIRMAN : I think 'Ayes' have it.

SOME HON. MEMBERS : No, Sir ; 'Noes' have it.

MR. CHAIRMAN : Let us have division. Let the lobbies be cleared.

Now, the lobbies have been cleared. I put it to vote. The question is...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में इस बात पर भ्रम है कि किस विधेयक पर चर्चा हो रही है।

एक माननीय सदस्य : कोई भ्रम नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी जा रही है और एक विधेयक श्री बरूपाल का है। मुझे ऐसा लगता है यह स्पष्ट किये बिना इस बारे में मतदान कराना कठिनाई पैदा कर सकता है।

MR. CHAIRMAN : Let me remove the confusion if there is any. There are two Bills. This is by Shri Manibhai J.

[Mr. Chairman]

Patel concerning the air-conditioned travel facility. This is at the introduction stage. There is another Bill by Shri Barupal which is coming for consideration later on. It is, perhaps, confusing for the Members to know as to which Bill is under consideration. Is the hon. Member prepared to withdraw the Bill ?

श्री मधु लिमये : मेरी विनती है कि वह वापस लें।

SHRI MANIBHAI J. PATEL : No, Sir.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

The motion was negatived

16.53 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new section 86A)

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

The motion was adopted.

SHRI S. S. KOTHARI : I introduce the Bill.

16.59½ hrs.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

(Amendment of sections 3, 6 etc)

By Shri P. L. Barupal

श्री ए. ला. बारूपाल (गंगानगर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद

सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय, लोक सभा के गत अधिवेशन में संसद सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार मैंने वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम प्रस्तुत किया था। उस के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों की अलग अलग रायें थीं। हमने यह कोशिश की कि हम विरोधी दलों का सहयोग लें और उन के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर हम सब मिल कर इस बिल को किसी तरीके से पास करें। (अध्यक्ष) माननीय सदस्य अपने अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं उन से ज्यादा सोशलिस्ट हूँ। इस विधेयक के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित किया और हमारे कम्युनिस्ट भाई, जिन में श्री ज्योतिर्मय बसु, श्री एच. एन. मुंकरजी,...

श्री इन्द्रजीत महोत्रा (जम्मू) : नाम क्यों लेते हैं ?

श्री ए. ला. बारूपाल : अच्छा, मैं नाम नहीं लेता हूँ। सब पार्टियों के लोगों ने युनैनिमसली यह तय किया कि आवश्यक एमेंडमेंट्स दे कर इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाये। मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इन की दुरंगी चालें ठीक नहीं हैं।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Who is having double standards ?

श्री ए. ला. बारूपाल : मैं अंग्रेजी नहीं समझता। माननीय सदस्य हिन्दी में बोलें।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : On a point of clarification.

श्री ए. ला. बारूपाल : मैं चाहता हूँ कि सब माननीय सदस्य मिल कर इस बिल को पास करें।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

There are some amendments. Mr. Banerjee has given an amendment...

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Please read it out, Sir. Let them know what it is.

MR. CHAIRMAN : The hon. members will understand it. The amendments of Mr. S. M. Banerjee, Mr. Tridib Kumar Chaudhari and Mr. Jharkhande Rai are for circulation.

Is Mr. Banerjee moving his amendment ?

SHRI S. M. BANERJEE : Yes. I move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the first day of the next session."

MR. CHAIRMAN : Mr. Jharkhande Rai is not here.

Mr. Tridib Kumar Chaudhary. Is he moving his amendment.

MR. TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampore) : Yes, I move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 2nd September, 1968."

MR. CHAIRMAN : Mr. Gadilingana Gowd.

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool) : My Party has given freedom of speech and vote on this Bill to all the members of the Party.

About a fortnight ago, an informal Committee representing all parties was constituted and it had about four sittings. This Committee has unanimously agreed to recommend some facilities...

AN HON. MEMBER : No; not unanimously.

SHRI GADILINGANA GOWD : It was unanimous. What can I do if they

deny afterwards ? I would like to be very frank. Let me be true to my conscience. I would not go back on the unanimous decision that has been taken by the committee. The amendments moved by Shri Tenneti Viswanathan, etc., most of them, have been unanimously agreed.

If you want the Members of Parliament to work honestly and efficiently, to serve the people, all these facilities are necessary. This committee has not recommended either an increase in salary or an increase in the daily allowance. I may submit to you for your information that this committee consisted of Mr. Rabi Ray, Mr. Kanwar Lal Gupta, myself on behalf of the Swatantra Party, Mr. Kandappau on behalf of the D.M.K.... This was a unanimous decision. I am now told that most of the recommendations made by this committee can be implemented by the Government by amending the rules, by referring the matter to the Joint Committee.

I, therefore, appeal to the Government to refer this matter to the Joint Committee on Rules so that proper facilities are given to Members which, I am sure, will enable Members to serve the people more effectively.

MR. CHAIRMAN : You want the Bill to be referred to a Joint Committee.

SHRI GADILINGANA GOWD : Joint Committee of both Houses.

MR. CHAIRMAN : Of Rules ? I wanted to be clear. The hon. Member, if I have not misunderstood him, has made a reference that it should be referred to a Joint Committee on Rules. That is what the hon. Member said.

17 00 hrs

SHRI GADILINGANA GOWD : The Joint Committee of the Houses meant for giving facilities to Members of Parliament.

MR. CHAIRMAN : Joint Select Committee ?

SHRI GADILINGANA GOWD : Joint Committee .

MR. CHAIRMAN : Is there any amendment or is it just a suggestion ?

SHRI GADILINGANA GOWD : It is a suggestion.

श्री मधु लिमये (मुंनेर) : अध्यक्ष महोदय, इस के लिये जो मेरा सुझाव है, उस को बारूपाल जी और यह सारा सदन मान जाय, तो इस पर ज्यादा विवाद नहीं होगा। मेरी यह राय है कि इस शकल में इस बिल को न ज्वान्ट पार्लियामेन्ट्री कमेटी के पास भेजना चाहिये और न लोक मत संग्रह करने के लिये भेजना चाहिये। इस बिल को वापस लिया जाय और यह सदन एक प्रस्ताव करे—उस प्रस्ताव के अनुसार आप 10-11 सदस्यों की एक कमेटी बनायें। उस कमेटी की जो यूनिमस रिक्मेन्डेशन्स होंगी, उस पर सरकार स्वयं बिल प्रस्तुत करे—यह मेरा सुझाव है इस बिल को केवल बहुमत के द्वारा पास करना अच्छा नहीं होगा। इस लिये मेरा अनुरोध है कि आप मेरे सुझाव को मान लें।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : There has been some controversy going round this Bill. Originally it was thought that no controversial Bill relating to the Members' emoluments and salaries should be pushed through the House. So this is a matter on which the Government itself should have taken the initiative having regard to the consensus of opinion as ascertained by it. But the Government some how feels that it is all the job of the Members.

So far as the Ministers' emoluments and salaries are concerned, the Members should interest themselves and vote with them, but when it comes to the perquisites of the Members the Government have very nicely said, 'It is all Members' business and if all the Members agree, we will put through any amendment which you desire'.

Very well. Now it has been suggested that a Committee may be appointed. That was what was exactly done, though informally. In the initial stages I was not there. Members representing various Groups were present; there was some difference of opinion on some points; but ultimately, excepting on one or two points, I believe, the amendments that stand in my

name and in the name of some others, represent the consensus of opinion. (Interruptions) and also they represent the consensus of language. The language itself was not mine, nor was it that of the hon mover of the Bill.

There were others who did it though one or two of them are obliged to be silent now. When all this was done and I personally thought that there was some unanimity about this, and if there was any small difference that could be rounded off by the opposition leaders, by the leaders of the various groups meeting together. I am not sure whether that has been done. If that has been done perhaps this controversy would not have arisen. But even now I feel that there are several points on which there is agreement. It is true, Sir, that some of the requests looked like exaggerated claims of these hon. Members. Every day we hear Members say that we are sovereign, we are a sovereign Parliament and all that and Members naturally believe, some of them wrongly believe, that they should also have some decent perquisites. That is the sum of their fault. But if there is opposition, my humble suggestion is it is open to the Government to move the amendment to say that this Bill could be referred to the Joint Rules Committee where these things could be discussed. Many of the things which have been suggested and which are hardly controverted are things which could be done very well by the change of rules. Amendment of the Act is not necessary for all these things. And if the Committee is unanimous, perhaps to the extent of the unanimity the Government can adopt them. If it is a Joint Select Committee we would have to wait for long time. The Rajya Sabha must open and all these things will have to be done. But what I submit is this, that the Committee can go into the matter. We need not start exchanging words, because it is easy to criticise each other and the game has already started in that corner. I don't want to do that. What I submit is this. If the Minister of Parliamentary Affairs can move an amendment referring it to that committee we need not discuss the details here. The Members are already there in the Committee and they can discuss these things and in whatever they do, of course the

whole House will agree to it. Only let it not be said by the public or let it not be told by some of our own Members that we are making some exaggerated claims about ourselves.

17.07 hrs

[*Mr. Speaker in the Chair*]

Personally, Sir, I am one of those who believe that we need not have started the salary system at all. Even today I will be quite ready if you say, "You will have no salary at all. You come here at Government expense, live in some hotel, they will give you D. A. and you go home. There are no other perquisites". It is not necessary that they should have perquisites nor is it necessary and proper in that case to burden them with as much work as is demanded of the Members of Parliament. It is easy for us to say that in this poor country we should not claim anything. There are hundreds of arguments and I can argue in that light. But it is also necessary for us to see whether by our own experience we are able to discharge to the best satisfaction of our conscience all the responsibilities that are devolved upon us. Personally, Sir, I can cite my own case. I have been in public life since 1921 or 1922. Even since then I have been spending what I had in my house excepting for a brief period of three or four years; I think we have been most of spending on our own. There is nothing wrong in so spending because we have come on our own, nobody has invited us to come to public life. However, some Members of Parliaments of the world have believed that Members of Parliament should have some perquisites in order to keep them comfortable, in order to make them a little more responsive, and also to fix responsibility upon them, that they shall discharge the duties which devolve upon them after elections. Therefore it is only in that light that certain perquisites are being given in the Parliaments of the world.

It is true that we are a poor country. It is equally true that many of us are poor. Therefore, instead of going into all those details now, I would again request the Minister for Parliamentary Affairs to move an amendment to refer it to the joint committee and whatever is

done, whether it is more or less or if the Joint Committee says, no, there shall be no further prerequisites, we shall all be happy. If this falls through we will not be sorry. If it passes we need not worry ourselves further on this matter.

MR. SPEAKER : Regarding this Bill, I do not think that the matter can be referred to the Rules Committee. If hon. Members want, they can have it referred to a separate committee consisting of the same Members.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : A joint meeting of the Rules Committees of both Houses.

MR. SPEAKER : It is not the Rules Committee; there is already a committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : I beg to be excused for having given a wrong name to the existing committee.

SHRI SEZHIYAN (Kumabkonam) : Sir, without going into the merits of this Bill, which is not desirable at this stage, I want to correct one wrong impression that has been created as if the Members or representatives of different parties worked in a committee and came to certain conclusions and some Members or some parties have now backed out.

As far as my party is concerned, I can explain the position. Regarding the other parties, let them explain their position themselves. Shri S. Kandappan was representing our party, and he came and reported to us what was happening. He told us that such and such were the suggestions put forward. For example regarding the pension scheme of Rs. 250, he said that our party would not accept it. I think he had converted some others also to that view.

AN HON. MEMBER : It is there in the bill.

SHRI SEZHIYAN : I do not want to quarrel over whether it is in the Bill or not. In the amendment given notice of Shri Tenneti Viswanatham and others this pension of Rs. 250 is there. Regarding

[Shri Sezhayan]

PTO, servant's pass etc. also we had said that we would not agree. I do not want to go into these details at this stage.

I only want to put it on record now that there had been unanimity. Let us not say that all these things had been agreed to unanimously.

Even now, I would submit that there is no clear conception in the mind of the hon. Mover or the other Members in regard to the provisions in the Bill. Some say that it should be referred to a Joint Committee, some others say that it should be referred to the Joint Rules Committee and so on. We do not have any precedents for referring a Bill to committee which is not constituted specifically for the purpose of having that Bill referred to it. Of course, if we want to refer it to a Committee I think it could be done.

But I want to urge that there should not be any undue haste in regard to the passing of this Bill. People should not think that we are in a hurry to vote something for ourselves. It is true that we do require certain facilities. What those facilities should be, how they should be given and so on are matters to be gone into. I am not against facilities, but let us not be in a hurry to pass this thereby giving the impression to the outside world that we are very much in a hurry and before the 11th May, we want to vote for ourselves something.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka) : Who is in a hurry.

SHRI SEZHIYAN : Prof. R. K. Amin is not a hurry. I would submit that many things need careful consideration. In regard to facilities such as telephones etc. also we are agreeable, but how these facilities should be given should be gone into in a detailed way by the representatives of the parties or by a committee consisting of Members nominated by you or elected by the House, so that afterwards Members cannot come and say that this had been agreed to unanimously, that had not been agreed to unanimously and so on. At present, it is possible that somebody might have agreed to something at first but afterwards gone back on it. But as far as my

party is concerned, I have explained the position.

The Bill contains a provision for a daily allowance of Rs. 50. I do not think that anybody has yet agreed to this provision.

Further, most of the things have not been very happily worded. There are some portions in a clause to which we may agree while there are other portions to which we do not agree. So, voting here would be a very difficult affair. Therefore, everything needs very careful consideration. So, I suggest that it should be gone into by a committee appointed by you or elected by the House, and if that is done, we would be agreeable to that course.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में श्रीर जो संशोधन पेश किये गये हैं उन के बारे में अपनी राय स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। अगर किसी के मन में यह बात है कि पार्लियामेंट के सदस्यों के जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अगर उनको कुछ सुविधाओं की जरूरत है तो उनको वह सुविधायें न दी जायें, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन कर्तव्य के साथ हमारे ऊपर दायित्व भी बड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : मधु लिमये जी बोल चुके हैं।

श्री मधु लिमये : मैंने प्रस्ताव वापिस लेने की विन्ती की थी। जब आप नहीं मानते हैं तो फिर अब मैं बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर एक बड़ा दायित्व भी है और वह दायित्व यह है कि जनता के प्रतिनिधि के नाते हम लोग अपने अधिकारों का और सत्ता का दुरुपयोग न करें और ऐसी सुविधाओं को हड़पने की कोशिश न करें जिनका हमारे कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपदेश दे रहे हैं।

श्री मधु लिमये : इसमें उपदेश क्या है, मैं तो अपनी बात को रख रहा हूँ। (व्यवधान) ये लूट में हिस्सा लेने के लिए आये हैं। सब दुनिया देख रही है, कुछ खयाल करो अपने दायित्व का और जिम्मेदारी का।

तो अध्यक्ष महोदय, तीन सिद्धान्तों को मद्दे नजर रखना चाहिए। एक सिद्धान्त यह कि क्या इस सुविधा से या सुविधाओं से पार्लियामेंट के सदस्य, उनका जो कर्तव्य है, उसको कारगर ढंग से पूरा कर पायेंगे ? दूसरा सिद्धान्त यह है कि क्या इस सुविधा का दुरुपयोग किया जायेगा। बार-बार बात आई है, मोटर गाड़ियों की सुविधा दी गई, तो 800 लोगों ने तीन साल में मोटर गाड़ियां खरीदी। राज्य सभा में प्रश्न का जवाब आया है। कितने सदस्य ऐसे हैं, 800 में से जो गाड़ी का खर्चा करने की स्थिति में हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मोटर गाड़ियों के दुरुपयोग का मामला हमारे सामने आया।

SHRI R. K. AMIN : The leaders take big bungalows and the members are given ordinary flats. What about that ?

श्री मधु लिमये : आग मेरे घर पर चले, मैंने सबसे छोटा मकान लिया है, कोई बड़ा मकान नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सिद्धान्त यह होना चाहिए कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग न हो जैसा कि मोटर गाड़ियों की सुविधा का दुरुपयोग किया गया। यहां पर मकान दिये जाते हैं, कौन नहीं जानता, कई सदस्य ऐसे हैं जो सब-लेटिंग करते हैं। यह लांछन है पार्लियामेंट की सदस्यता पर। (व्यवधान).....

MR. SPEAKER : Let the hon. Member say what he has to say. In this way we cannot carry on the discussion. By shouting and counter-shouting, we cannot proceed.

SHRI SRINIBAS MISRA : I take strong exception to Shri Limaye saying that everybody is sub-letting his flat.

श्री मधु लिमये : मैंने कहा है कि—कौन नहीं जानता। कौन नहीं करता—यह मैंने नहीं कहा है।

MR. SPEAKER : He did not say 'everybody'.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : On a point of order. Whether he has used the word 'everybody' or the expression some members or 'most of the members', I would humbly submit to him that as a responsible member who is also the leader of a Party, by making such statements he is reflecting on the dignity of the House and we are not giving a better impression of ourselves and this august House. We talk of this 'sovereign House', 'august House'.

Such a remark is derogatory to the dignity of the entire House. It is better we avoid such phrases to make our points. We can use better language to make our points. I strongly object to this.

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada) : My submission is, Mr. Madhu Limaye has already given his advance opinion in a long column in the *Hindustan Times* today on the merits of this Bill. I would appeal to him to confine himself to the merits of the Bill without aspersions and help us to have a smooth discussion about it. There is no question of one being more patriotic than another.

MR. SPEAKER : He did not say all Members; he said some Members. (Interruption) All Members, is it so ? (Interruption) No. I do not think so. From what I heard you can verify it from the records—he did not say all Members. Some Members have done it. This was raised earlier also; not now only. Shri Hem Barua or somebody had raised it. Anyway, as suggested by Shri Thirumala Rao, let us not try to insinuate anybody. All Members are hon. Members. There is no dishonourable Member. Let us resume the debate, and let Shri Madhu Limaye confine himself to the point.

श्री मधु लिमये : बिलकुल वही कर रहा हूँ और वही मैं कह रहा था..... (व्यवधान) आखिर यह लोग सब इस तरह से क्यों मुझे

[श्री मधु लिमये]

नोच रहे हैं? जो भी जांच करनी हो उसके लिए हम तैयार हैं.....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि यह मैंने बिलकुल नहीं कहा कि इस सबन के सभी सदस्य ऐसा करते हैं लेकिन इस तरीके के आरोप यहां पर किये गये। कुछ साबित भी हुए.....

एक माननीय सदस्य : क्या साबित हुए ?

श्री मधु लिमये : मोटेर कारों के बारे में कुछ सदस्यों को अभी माफ़ी मांगनी पड़ी है। आप लोग यह जान-बूझ कर मुझे उकसा रहे हैं..... (व्यवधान)

MR. SPEAKER : What is this "Madhu Limaye, Madhu Limaye". Is it a market place ? You are addressing "Madhu Limaye, Madhu Limaye" as if you are addressing a public meeting or some election meeting. You should address the Chair. You should not shout "Madhu Limaye, Madhu Limaye". Even shouting I do not mind, but you are calling him and shouting as though this kind of thing is absolutely parliamentary. For Heaven's sake do not shout like that. You can have your say later on. But let us continue the work in a calm atmosphere. Please do not disturb him. If you do not agree with him, you will have a right to say later on. (Interruption) Whoever wants to speak, he may give me his name through the Whip.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं एक, एक जो यहां पर झुकाव आया है, जिसके कि बारे में कहा जाता है कि सर्वसम्मति से हुआ है जो कि नहीं हुआ है, मैं अपनी राय ने दूंगा। बाद में जो करना हो वह करें।

मैं फस्ट क्लास ए पास का विरोध करता हूँ। यह मौजूदा फस्ट क्लास जब तक यह क्लासेज रहेंगे काफ़ी है। जिस दिन क्लासेज हटा दिये जायेंगे जिसकी कि हमारी मांग है तो वह भी खत्म हो जाय, लेकिन यह फस्ट क्लास ए पास बिल्कुल नहीं देना चाहिए।

पी० टी० भोज० वगैरह नहीं होने चाहिये और उनका मैं विरोध कर रहा हूँ।

इसी तरीके से इन का कहना है कि हवाई जहाज से प्रवास करने की इजाजत दी जाय लेकिन वह जो फर्क है फस्ट क्लास ए पास में और हवाई जहाज की दर में वह फर्क देकर आप जरूर हवाई जहाज से जायें लेकिन पूरा डिफेंस देकर जाइये पहले दर्जे के रेल किराये में तथा हवाई जहाज के किराये में।

पेंशन का जो सुझाव है उस का मैं घोर विरोध करना चाहता हूँ। वह कतई नहीं होनी चाहिये.....

MR. SPEAKER : What is this pension ? I do not understand. Is it life pension ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : At the age of 60.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : In the original Bill itself, it is there.

श्री मधु लिमये : इन के अमेंडमेंट में है। बिल में भी है और इन के संशोधन में भी है। अध्यक्ष महोदय, 12 इन के सुझाव हैं। मुझे उन पर एक, एक वाक्य कह लेने दीजिये।

इस तरीके से एक सुझाव यह दिया गया है कि जो अपने-अपने निजी डाक्टर्स है उन से हम अपनी बीमारी वगैरह के बारे में सलाह मशविरा करें। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जो केन्द्रीय सरकार के अस्पताल हैं चाहे दिल्ली में हों या बाहर। अगर पांडेचेरी में हों और वहां इलाज करना हो तो करें लेकिन निजी डाक्टर से नहीं क्योंकि निजी डाक्टर क्या फीस लेता है इसको आप जानते हैं। उसका खर्चा पार्लियामेंट को नहीं बर्दास्त करना चाहिए।

अब दो, तीन सुविधाएं ऐसी हैं जिनका कि मैं पुरजोर ढंग से समर्थन करना चाहता हूँ क्योंकि सदस्यों के कार्य में उस-से मदद मिलेगी। आज बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह डाक पर खर्चा नहीं करेंगे और उससे मतदाताओं और जनता का नुकसान होगा। इसलिये केवल

पालियामेंटरी और सार्वजनिक कार्य के लिये आप अगर विशेष पोस्टेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि उस से जनता और मतदाताओं का कल्याण होगा।

एक और बात है जिसका कि मैं समर्थन करता हूँ। हम को अपने पालियामेंटरी काम के सिलसिले में स्टेनोग्रफिक सहायता की बहुत जरूरत है जो कि आज उचित मात्रा में हम को नहीं मिलती है। मैं तो यहाँ तक कहने के लिये तैयार हूँ कि पाट टाइम स्टेनोग्रफिक असिस्टेंट्स बिल्कुल मुफ्त कर दी जाय लेकिन मेम्बरों से 100-125 रुपये आप लेकर अगर फुल टाइम भी चाहिये तो आप दे दें लेकिन उसके लिये पालियामेंटरी कोटा हो, पूल हो, वरना उसका दुरुपयोग यह होगा कि हम अपने किसी दोस्त को, ड्राइवर को या अपनी बीवी को कहेंगे कि यह हमारे स्टोनोग्राफर है और उसकी तनख्वाह हम ले लेंगे। जरूरत इस बात की है कि क्वालिफाइड स्टोनोग्राफर्स का पूल पालियामेंट में हो और पालियामेंट के पूल में से आप लोग लें। पूरा भी मुफ्त करेंगे फुल टाइम तो भी मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन ऐसा काम जिससे कि सुविधा के दुरुपयोग होगा वह नहीं होना चाहिये।

एक सुझाव उन्होंने यह दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में या जो अपना स्थायी पता है वहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था की जाय। इसी तरीके से आप क्षेत्रीय दफ्तर में या स्थायी पते पर आप टेलीफोन चाहते हैं और जहाँ तक लोकल कौल का सवाल है कुछ कौल अगर आप मुफ्त कर देंगे तो उस पर भी मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन बाक़ी सारी जितनी सुविधाएँ हैं जैसे मुफ्त पानी और बिजली, मुफ्त में हम को जीप देना इत्यादि तो जिस तरह से बी० डी० ग्राज की बदनामी हो गई उसी तरह हम सब भी बदनाम हो जायेंगे। अलबत्ता 1.50 पैसे मील का चार्ज देकर अगर जीप लेना चाहते हैं तो दे दें लेकिन पूरा किराया उस का देना चाहिये

वरना इस बिल का और संशोधनों का मैं विरोध करूँगा।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : To discharge their duties, Members of Parliament should be given some assistance, but the public should not feel we are misusing our powers of legislation. If Members of Parliament are not to be purchased by Americans, Russians or Chinese or by moneybags, they should be paid at least sufficient daily allowance. Everybody cannot afford to spend from his pocket. Some poor people are also there as members. If they are not paid properly, hereafter only rich people will stand for elections and will come here. Others will not be able to come.

But we should also realise that there are so many poor people and low paid employees in the country and we are notable to do much for them. So, there is no right for us to ask for more salary.

This is my personal opinion. I am not talking about the Congress Party. Regarding daily allowance, they are now paying Rs. 31. It is not at all enough here in Delhi. The cost of living has gone up. We get so many guests during our stay here. We have not only to attend to them but even purchase railway tickets for their return journey and send them back to their places. What we request is, instead of Rs. 31 you may give us Rs. 51 as daily allowance when the Parliament is in session, not at other times. I feel that we should not ask for pension. It is not at all good. We have no right to ask for it. By God's grace we have come here.

MR. SPEAKER : By the voters' grace,

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : By the people's grace we are here. When we are here with their good wishes we should not claim any special pension for us. House rent comes to about Rs. 75 or so. We should not grudge paying this Rs. 75 for A class accommodation and we should not ask for rent free accommodation. The charges for electricity and water if we use only for our own purposes would not be more than Rs. 40 or Rs. 50. If it is used by some others also then it

[Shri Chengalraya Naidu]

will go to Rs. 100 or Rs. 200. We cannot help that.

Coming to postal facilities I feel that service stamps worth about Rs. 50 may be given to the Members so that they may use them to contact their constituencies and also to represent to Government. We are already having a free telephone. In stead of asking for anything more we should be satisfied if wrong claims are not made on us. It is enough if the hon. Minister gives an assurance that wrong bills will not be prepared and the amounts claimed from us.

I do not agree with the suggestion regarding provision of a stenographer. Tomorrow I may show my cook or driver as my stenographer and claim the amount. I know that everybody will not do that. Every Member is an honourable Member of this House and he will not do such a thing. But it is not only enough if you are honest you must appear to be honest also. It will be enough if some more stenographers are added to the pool of stenographers in Parliament so that we may make use of them whenever required.

A suggestion has been made that we should be provided with tractors when we go to our constituencies. This is not a good suggestion. Everybody is not a farmer. Even if we are farmers, why should Parliament Members get this special facility. I can understand asking for a car to tour our constituencies, but is anybody going to travel in his constituency in tractors. This is also an unusual demand and should not be agreed to.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : The suggestion is to give transport facilities and not tractors.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : A class railway pass should be given. But no extra third class tickets should be allowed. The proposal made is to give travel facilities for a Member's family and dependents numbering six at a time to travel throughout India. This is very bad.

I would like to bring to your notice the need to give air travel facilities. It is not a luxury. If a Member wants to discharge his duties properly and be present here to attend the Parliament Session and also

attend to his constituency during week-ends, the time factor is the most important thing.

Saturdays and Sundays are holidays. If we are allowed to go to our constituencies, not every week but at least once in two weeks, by plane, we can go on Friday evening and return on Monday morning. This should be allowed. Now, as it is, for the duration of three months we are allowed only two trips to our constituency, which is quite inadequate. So, we are now not able to discharge our duties to our constituency properly. So, we should be allowed more trips. If the Members want to go to any other place in the country, they must be allowed to pay the difference between the railway ticket and air fare. Between their constituencies and Delhi more trips should be allowed.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I wish to make it clear on behalf of my group.....

AN HON. MEMBER : Which is that group ?

SHRI S. M. BANERJEE : CIP in the Lok Sabha. I want to make it clear that there was no unanimity, no agreement in the committee and the CPI group met yesterday, considered every aspect of the Bill and we have come to the conclusion that this Bill should be opposed, that it cannot be adopted as it is. Some amendments have been brought to this Bill which are said to be unanimous. I am surprised to not that even by those amendments more things have been added which did not appear in the Bill. Let us analyse the various provisions of the Bill.

MR. SPEAKER : Let him not make a big speech.

SHRI S. M. BANERJEE : It starts with the allowance. What is the allowance demanded ? Rs. 50 per day. After asking for everything, pension, free electricity, free house, allowance of Rs. 50 per day, to give it a Gandhian touch, it is said at the end that each member should have a free third class pass for travel by a widow or somebody else. It says :

"Every member shall be provided with two free non-transferable third class sleeping berth railway passes, one in the name of the member and one in the name of his/her spouse, as the case may be, and in the case of a bachelor, widow or widowed member..."

We cannot support the Bill as it is, I realise the difficulties of the Members. I do not say that there are no difficulties. We receive volumes of correspondence and we have to answer them. We have to type the replies. So, we have to engage some stenographer part time, because we cannot afford to pay them full-time. They are necessary. But why should there be a stenographer for each member at a cost of Rs. 200 per month? I charge the Minister of Parliamentary Affairs for not providing stenographers to each group here. This is highly objectionable. Each group, each party should be provided with stenographers.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : The hon. Member is also a party to the people who took the initiative in this matter. After having encouraged them to come to some conclusions, he now says he opposes them.

SHRI S. M. BANERJEE : There was no unanimity there. Even then, I agree, on some points. Suppose some postal facilities are given; I can understand that. But if there is going to be free trunk call, what will happen? They will go on making trunk calls to Bombay and Madras and that facility will be misused. I do not want any concession which can be misused. Then, they are asking for PTO for six members of the family.

Now, this is the amendment by my learned friend, Shri Tenneti Viswanatham and others. What does it say? It says that every Member shall be provided with six PTOs a year for the members of his family and dependants, not exceeding six in number. Sir, we are practising family planning. And we ask PTO for six family members. It is a paradox. I cannot imagine this. What will the people think? They will say, "Look here. The M.P. has a family

consisting of six members and they travel wherever they like throughout the country and they ask the people not to produce more."

Sir, let this Bill be withdrawn and let us appoint a Committee. Let us know the genuine difficulties of the Members of Parliament. Take, for instance, the telephone facilities. 3600 calls are free and they also be free in the constituencies because M. P.'s telephone is a public telephone for everyone.

Sir, I oppose the Bill moved by Shri Barupal. I request you and, through you, the Minister of Parliamentary Affairs to appoint a Committee. (Interruption) Shri Barupal is very angry with me. May I tell him I have not done anything, I have not sold any car with a profit of Rs. 2000 or Rs. 3000? I have not taken any car nor I have sold any car. What I say is let us not lose our temper. Let us not wash dirty linen here. Let us do something which is proper so that the people may be convinced in this country that if we cannot give them a higher wage, we, the M.P.s, do not get much more for ourselves. With these words I oppose the Bill and I suggest that there should be a Committee appointed to consider the whole thing.

श्री सुलाम मुहम्मद बक्सी (श्रीनगर) :
जनाब, मैं इस ऐवान के दोनों तरफ बैठे हुए अपने दोस्तों से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्री पन्नालाल बारूपाल के इस बिल और उस में श्री विश्वनाथन् के एमेंडमेंट्स के बारे में मुक्तलिफ मेम्बर साहबान की जो भी राय हो, लेकिन यह हकीकत है कि जहाँ तक मेम्बरों की सैलेरीज, एलाउंसिज और दूसरी फैसिलिटीज का ताल्लुक है, उन में इजाफा करने की जरूरत है। वह इजाफा कैसे हो और कैसे न हो, मैं इन डीटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं न तो पब्लिक प्लैटफार्म से बोल रहा हूँ और न आज मुझे बोटस की जरूरत है। मुझे इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं है कि लोग मेरे मुताल्लिक यह कहें, "वाह, वाह! बिल्कुल फरिश्ता हम ने भेजा है पार्लियामेंट में, जिस को न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न टेलीफोन

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

की जरूरत है और न कागज की जरूरत है, जो महात्मा बुद्ध की तरह रहेगा और ध्यान करता रहेगा और आसमान से मन्नोसत्वा उतरता रहेगा।”

मैं ऐवान से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वह 1965, 1966 और 1967 की प्राइसिज का आज की प्राइसिज से मुकाबला करे। मुझे मालूम नहीं कि मेरे दोस्त कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। लेकिन मैं बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमें 31 रुपये जो मिलते हैं, अगर उन में कम से कम बीस रुपये और न डालें, तो महज अपना और अपने साथ रहने वाले एक आदमी का भी काम नहीं चल सकता है। अगर कोई गुंबी आमदनी हो, तो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि मौजूदा हालत में घर का काम नहीं चलता है।

सेलेरी को चाहे 500 रुपये से 750 रुपये या 800 रुपये कर लीजिए। लेकिन यह जो बिल लाया गया है, यह इन एम्बेडमेंट्स से काम्प्लीकेटिड हो गया है। मेरे दोस्त, श्री बनर्जी, ने कहा कि यह फ़मिली प्लानिंग का जमाना है। वह तो आईन्दा की बात है। लेकिन आज जिस के जितने बच्चे हैं, उनका क्या होगा? फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वह आईन्दा की बात कर रहे हैं और मैं आज की बात कर रहा हूँ। वह आसमान की बात कर रहे हैं और मैं जमीन पर चलने वाला हूँ, इसलिए जमीन की बात कर रहा हूँ।

मैं अर्ज करूंगा कि इस मामले में पार्लियामेंट के मेम्बरों को एक दूसरे की नुक़्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। और न एक दूसरे पर इल्जाम लगाने चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि हम लोग जो चाहते हैं, बदकिस्मती से उस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उस में कई एक बातों की घबराहट होती है—यह कि कल प्रैस हमारे मुताल्लिक क्या लिखेगा, कल लोग हमारे मुताल्लिक क्या कहेंगे। ठीक है, प्रैस लिखेगा

और लोग कहेंगे, लेकिन वह एक बिल्कुल डिफ़रेंट बात है।

MR. SPEAKER: Is he proposing some Committee? What is his suggestion? He may give his suggestion. He seems to be going to some other subject.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी: मैं इस का बैंकप्राउंड बता रहा हूँ। गवर्नमेंट यह जानती है कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं और मेम्बरों की जरूरियात क्या हैं। मैं चाहता हूँ कि वह दस, बीस उस तरफ़ के मेम्बरों का और दस, पंद्रह इस तरफ़ के मेम्बरों का एक सरवे करे कि टेलीफ़ोन, पानी, बिजली, मकान वगैरह पर कितना खर्च आता है और उस के मुताबिक वह अन्दाज़ा लगाये कि मेम्बरों की क्या जरूरियात हैं, बजाये इस के कि वह मेम्बरों को आपस में लड़ाये और श्री मधु लिमये उठ कर एक बात का विरोध करें, दूसरा समर्थन करे और तीसरा कहे कि मैं यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ तक जाने के लिए तैयार नहीं हूँ।

मेरे आनरेबल फ़्रेंड, मिनिस्टर फ़ार पार्लियामेंटरी एफ़ेयर्स, महज एक तरफ़ के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उन की जिम्मेदारी दोनों तरफ़ की है। पार्लियामेंट की डिमिटी और शान को मेनटेन करना भी उन की जिम्मेदारी है। वह सिर्फ़ एक पार्टी के चीफ़ व्हिप नहीं हैं। वह मिनिस्टर फ़ार पार्लियामेंटरी एफ़ेयर्स भी हैं।

चाहे कोई मेम्बर इस बिल या इस के प्रिंसिपल का समर्थन करे और चाहे विरोध करे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि दिल से हेर एक इस को चाहता है।

श्री मधु लिमये: हम नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, उस का समर्थन करते हैं और जो नहीं चाहते हैं, उस का विरोध करते हैं।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी: फ़र्क इतना है कि कोई चार आने चाहता है और कोई

सोलह घाने चाहता है। श्री मधु लिमये चार घाने चाहते हैं; मैं सोलह घाने या बीस घाने चाहता हूँ।

श्री मधु लिमये : यह सिद्धान्त का सवाल है। यह चार घाने या सोलह घाने का सवाल नहीं है।

श्री गुलाम मुहम्मद बकशी : मैं मिनिस्टर फ़ार पार्लियामेंटरी एफ़ यर्स से दरखास्त करूंगा कि वह तमाम बातों का जायजा ले कर इस सेशन में या अगले सेशन में खुद इस तरह का एक बिल लायें। वह इस बिल को मसूमसे में न डालें। इस का नतीजा बुरा होगा, सारे देश के लिए भी और उन के लिए भी। वह इस बिल के प्रिंसिपल को ऐक्सेप्ट कर लें और तमाम बातों को देख कर कि क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है, खुद एक बिल लायें। मुझे उम्मीद है कि वह हिम्मत से काम लेंगे।

श्री غلام محمد بخشی (شری بنگر)۔ جناب میں اس ایوان کے دوڑوں طرف بیٹھے ہوتے اپنے دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشری پتالان باروپال کے اس بل اور اس میں مشری و سٹوٹا تھن کے ایمینٹ میںس کے بارے میں مختلف میمبر صاحبان کی جو بھی رائے ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک میمبروں کی سلیبز۔ ایلاؤ نسر اور دوسری سلیبز کا تعلق ہے۔ ان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اضافہ کیجئے ہو اور کیجئے نہ ہو۔ میں ان ڈیپلیس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نہ تو پبلک پلینٹ فارم سے بول رہا ہوں اور نہ آج مجھے ووٹس کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے متعلق یہ کہیں ڈاہ۔ واہ۔ بالکل فرشتہ جم سے سمجھائے۔ ریاریٹینٹ میں جس کو سنہ کھانے کی ضرورت ہے۔ نہ پینے کی ضرورت ہے۔ نہ ٹیلیفون کی ضرورت ہے اور نہ کاغذ کی ضرورت ہے۔ جو مہاتما بدھ کی طرح رہینگے اور آسمان سے من و سلوی اترتا رہے گا۔

میں ایوان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 1946/1947 اور 1947 کی پراسنر کا آج کی پراسنر سے مبالغہ کرے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے دوست کہہ رہے ہیں۔ کیسے نہیں کہتے ہیں۔ لیکن میں

بہت سادہ اعلان طریقے سے رہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں 18 روپے جوتے ہیں۔ اگر ان میں کم سے کم میں روپے اور دو مالیں۔ تو عرض اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے ایک آدمی کا بھی کام نہیں چل سکتا ہے۔ مگر کوئی غیبی آمدنی ہو تو انک بات سے۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ موجودہ حالت میں گھر کا کام نہیں چلتا ہے۔ سیلیری کو چاہے 500 روپے سے 450 روپے یا 800 روپے کر لیجئے۔ لیکن یہ جو بل لایا گیا ہے۔ یہ ان ایمینٹنٹس سے کام لیکر بنڈ ہو گیا ہے۔ میرے دوست شری بزی نے کہا کہ یہ فیملی پلاننگ کا زمانہ ہے۔ وہ تو آئندہ کی بات ہے۔ لیکن آج جس کے بیٹے بچتے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا فرق موت اتنا ہے کہ وہ آئندہ کی بات کر رہے ہیں اور میں زمین پر چلنے والا ہوں۔ اس لئے زمین کی بات کر رہا ہوں۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں پارلیمنٹ کے میمبروں کو ایک دوسرے کی سخت چینی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ایک دوسرے پر الزام لگانے چاہیے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں۔ بد قسمتی سے اسکو اچھپا کر نہیں کرتے ہیں۔

اس میں کوئی ایک بات تو ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ کہ کل برس ہمارے متعلق کیا لکھے گا کل لوگ ہمارے متعلق کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ برس لکھے گا اور لوگ کہیں گے لیکن وہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے۔

MR. SPEAKER : Is he proposing some Committee? What is his suggestion He may give his suggestion. He seems to be going to some other subject.

شری غلام محمد بخشی۔ میں اس کا ایک گراؤ ڈیٹا رہا ہوں۔ گورنمنٹ یہ جانتی ہے کہ تمہیں کتنی بڑھی ہیں اور بھرتی کی ضروریات کیا ہیں۔ نہیں چاہتا ہوں کہ وہ دس میں اس طرف کے میمبروں کا اور دس پندرہ اس طرف کے میمبروں کا ایک سرو سے کر کے ٹیلیفون۔ پانی۔ بجلی۔ مکان وغیرہ پر کتنا خرچ آتا ہے اور اس کے مطابق وہ اندازہ لگائے کہ میمبروں کی کیا ضروریات ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ میمبروں کو آپس میں لڑائے اور شری مدھولیے اٹھ کر ایک بات کا درودہ کریں۔ دوسرا سمرٹھن کرے اور تیسرا کہے کہ میں یہاں تک جاننے کے لئے تیار ہوں۔ وہاں تک جاننے کے لئے تیار نہیں ہوں۔

میرے آنر بیل فرینڈ منسٹر فار پارلیمنٹری ایفرز۔ محض ایک طرف کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی ذمہ داری دوڑوں طرف کی ہے پارلیمنٹ کی ڈگٹی اور شان کو مینٹین کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف ایک بار کی کھیت و سبب نہیں ہیں۔ وہ منسٹر فار پارلیمنٹری ایفرسز بھی ہیں۔

چاہے کوئی ممبر اس بل یا اس کے پرنسپل کا مسخ کرے اور چاہے ورورہ کرے۔ لیکن ایسا انداز ہی کی بات یہ ہے کہ دل سے ہر ایک اس کو چاہتا ہے۔

श्री मधु लिमये : हम नहीं चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, उस का समर्थन करते हैं और जो नहीं चाहते हैं, उस का विरोध करते हैं।

श्री غلام محمد کشی - فرقی اتنا ہے کہ کوئی چار آئے چاہتا ہے اور کوئی سولہ آئے چاہتا ہے۔ شری مدعو کیے چار آئے چاہتے ہیں۔ میں سولہ آئے یا میں آئے چاہتا ہوں۔

श्री मधु लिमये : यह सिद्धान्त का सवाल है। यह चार आने या सोलह आने का सवाल नहीं है।

श्री غلام محمد کشی - میں مسٹر غلام محمد کشی ایگزیکٹو سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام باتوں کا جائزہ لے کر اس سیشن میں یا اس گلے سیشن میں خود اس طرح کا ایک بل لائیں۔ وہ اس بل کو مختصر میں ڈالیں اس کا نتیجہ برا ہو گا۔ سارے دیش کے لئے کبھی اور ان کے لئے کبھی وہ اس بل کے پرنسپل کو ایک پیٹ کر لیں اور تمام باتوں کو دیکھ کر کہ کیا کیا ضروری ہے۔ کیا کیا ضروری نہیں ہے۔ خود ایک بل لائیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت سے کام لیں گے۔

श्री तुलशी दास जाधव (वारामती) : अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद मिनिस्टर फ़ार पालियामेंटरी एफेयर्स ने सब पार्टियों के नुमायंदों को बुलाया। वहां बैठ कर सब लोगों के साथ चर्चा हुई और एक कमेटी एपायंट हुई, जिस में हर एक पार्टी का एक एक नुमायंदा लिया गया।

MR. SPEAKER : Was the Committee appointed by the House or by the Government ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : It was not appointed by my Department.

MR. SPEAKER : I am just seeking a clarification. Was the Committee appointed by the Government or by the House ? Who appointed that Committee ? What is the sanctity of this Committee ? Let us hear the hon. Member.

श्री तुलशी दास जाधव : वह एक इनफ़ॉर्मल कमेटी थी। उस को किसी ने एपायंट नहीं किया। हमने सबको बुलाया।

एक दफा मीटिंग नहीं हुई बल्कि चार मतंबा मीटिंग हुई। मुझे उस मीटिंग का कन्वीनर करके भेजा। उस मीटिंग में जो बातें भी निश्चित की गईं वह सभी के विचार से निश्चित हुईं। जो मीटिंग होती थी उनमें पाटर्ची का कभी कोई नुमाइन्दा आ जाता था और कभी कोई नुमाइन्दा आ जाता था। यह बात जरूर है कि वह कमेटी किसी कानून से बंधी हुई नहीं थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि उस कमेटी की मीटिंग में इस बिल पर विचार हुआ और जो अमेन्डमेंट हैं वह भी सभी के विचार से हुये।

दूसरी बात यह है कि इसमें जो पेन्शन का क्लॉज है, भूल बिल में, उसमें कुछ अमेन्डमेंट किये हैं। मैं इन सारी बातों की डिटेल् में तो नहीं जाना चाहता और न किसी पर कोई आरोप लगाने का विचार है। जैसा कि बल्सी साहब ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी कोई दिक्कतें हैं तो कामन पीपुल् से कोई ऐसी मांग करें जिससे कि उनको तकलीफ हो लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि जब लोगों का काम करना है तो उसमें उनको कोई दिक्कत भी न पैदा हो। जिन लोगों की अपनी कोई जायदाद है या अपना कोई व्यापार है उसमें से खर्च करें तो फिर जो बाकी आनेस्ट बर्कर हैं, जिनके पास कोई साधन न हो तो उनको दिक्कत पैदा हो सकती है और फिर एलेक्शन में ऐसे लोग आ सकते हैं जोकि खूब खर्च करें। यह अनडिमाँडिंग बात होगी और जो हमारी सोशलिज्म है उसके खिलाफ जायेगी। मैं इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और न ही इन बातों की डिटेल् में जाना चाहता हूँ बल्कि इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है वह सभी के विचार-विमर्श से हुआ है। उसमें जितने लोग थे उनके ही यह विचार हैं।

MR. SPEAKER : All that the hon. Member has mentioned is good. But that

has no legal sanctity. It was not a committee of the House and it had no status.

श्री तुलशी दास जाधव : पार्लमेन्ट की यह कमेटी है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मेरी रिकॉर्ड से कि ज्वाइन्ट कमेटी ग्रान सैलरीज ऐन्ड ऐलाउन्सेज आफ मॅम्बर्स आफ पार्लमेन्ट से या किसी ग्रौर कमेटी से जिसमें सभी पार्टीज के लोग हों, इसकी जांच करवा लें।

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I do not want to make a claptrap speech nor do I want to speak with a split mind. I have no doubt that the Members of this House draw benefits and emoluments far less than many of the clerks in many of the Parliaments of the world. But keeping in view the millions of moving skeletons in our country whom we represent and also keeping in view the fact that we have the sovereign right to increase benefits for ourselves, my party is opposed to increasing any benefit, any emoluments or salaries just to give a better facility for living our life in a luxurious atmosphere or to increase the so-called standard of our life or to increase our comforts.

But to serve the people, to serve, as I have put it, the millions of the moving skeletons of our country, to serve them in better way, I do feel that our efficiency should be increased.

I want to relate my personal experience. Fortunately, I have not been born with a silver spoon in my mouth. I have taken leave from the University without salary and come here to serve the people, just trying to serve them in an honest way. After 1½ years. I will frankly tell you I feel fatigued, tired and sometimes irritated. I work upto 12 midnight and rise in the early morning to start my work at 6. But what do I find? Everyday such bundles of letters and papers are coming in as I cannot tackle. What can I do? I do not know what is the experience of other friends. I will again frankly make this admission that it is not possible for me even to go through a small fraction of the parliamentary papers we receive; for the last six months, I have not been able to read even a book or write an article. Therefore, trying to serve the people as

much as I could, I feel almost irritated now because I find it has become impossible even to acknowledge the letters we receive. Therefore, we are proving discourteous not only to our electorate but even to ourselves as parliamentary functionaries.

Some of my friends like Shri S. M. Banerjee have their own view on this. He is fortunate in being a trade union leader. I am a Bengali. I get dozens of Bengali letters. If there is one secretary from the pool available, how will he be able to go through the Bengali letters and answer them? Therefore, I feel that every member should be provided with a stenotypist secretary.

Secondly, as has been suggested, free telephone and postal facilities should be allowed.

Thirdly, those who come from rural constituencies—they know how difficult it is to go there and to tour our constituencies and maintain contacts with the electorate—should be provided some sort of transport facilities. This should be provided at least to those who represent rural constituencies.

Lastly, I do not want to go into the merits of this Bill. In my opinion, it has to be changed almost lock, stock and barrel. But I want that a Committee should be constituted taking advantage of your initiative or there may be a Select Committee so that it may go into the merits and see how best we can increase our efficiency to serve the people. This is a matter that has to be coolly thought over and considered as to what are the lines on which we can increase our efficiency to serve our people.

MR. SPEAKER : From what I could gauge from the speeches of all the parties as far...

SHRI UMANATH (Padukkottai) : Not all the parties.

MR. SPEAKER : I know he has not spoken. All are opposed to the Bill as it is. On that, there is no difference of opinion. Shri Jadhav spoke about an informal committee having made some suggestions. But that has no legal sanctity. It was not a regularly constituted Committee of the House or anything of that kind or

[Mr. Speaker]

even of Government. They have made an effort and suggested certain things.

But from the speeches made, it is clear that some facilities are necessary. That is the theme. We do not want pension; we do not want travelling allowance for families and all that. But some facilities, whether it be postal facilities and so on are required. But these cannot be discussed and considered on the floor of the House. Which facilities are necessary, which are not—I do not think it will be possible to consider that here.

If all of you are agreed, some facilities—not salaries or finances or anything—and what those facilities are can be considered by a small committee as suggested. May I request Dr. Ram Subhag Singh to have his say. Let us hear him. Let us clinch the issue.

18.00 hrs.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): I would like to speak—

MR. SPEAKER: Mr. Bhandare, before you came here, all the others have been getting up. Mr. Umanath, representing his party, has not spoken yet. Even his party has not yet spoken.

SHRI R. D. BHANDARE: It is not a question of party. It is a question of a rising new class-conscience, and it should be effectively met. What are the principles underlying the suggestion of giving facilities should be discussed. Only two or three minutes.

MR. SPEAKER: That is what I am saying. They are all unanimous on this: all of them are opposed to the Bill as it is.

SHRI R. D. BHANDARE: I am not opposed to the Bill at all. Therefore I am speaking:

MR. SPEAKER: There is no question of your speaking. I have not permitted you. Will you kindly sit down? There are other Members who have been waiting. I do not think I have given them a chance. Even the Congress party seat me a list.

I have not given them a chance. We have already spent nearly two hours on this. One party has not at all spoken yet. (Interruption). Shri Umanath.

SHRI UMANATH: Sir, at the outset I would like to say that all these things should not have been raised. Our Member, Shri Jyotirmoy Basu, as soon as he saw in the press that our party's name was mentioned and that all parties have accepted certain proposals, clearly stated that this is absolute distortion. That is the first point.

Secondly, he has told that committee—we have to make our position clear—and the members of that so-called committee that whatever proposals were discussed there would be submitted to our party and after the approval by our party will be accepted by us. That has been made clear. When this is the position, this sort of proceeding with the matter was very, very wrong.

So far as the Bill is concerned we tooth and nail oppose this Bill. I am giving just an example. They want two third-class sleeper passes; already we are—apart from free passes—given one TA, one first-class additional TA and one third-class additional TA. If I want to bring my wife, I can purchase a first-class ticket and bring my wife here. (Interruption).

MR. SPEAKER: He is saying on behalf of his party: not your party.

SHRI UMANATH: So, we cannot accept basically all the provisions of the Bill, such as second-class pass, pension, rent-free accommodation, etc. So, we have to oppose it tooth and nail.

Then a proposal has been made that the Bill can be referred to the Select Committee. We cannot accept that proposal because reference to the Select Committee means we have to refer *this* Bill to the Select Committee which we cannot accept at all. It will be wrong. We have no objection to the proposal you made, namely, to have a separate committee with the full sanction of the party as such. Now that this question has come before the House, whatever that committee unanimously decides—that is more important—

can be brought forward here as a Bill. (Interruption). I am making my position clear so far as my party is concerned. There are certain things to be considered. For example, there is the question of telephone. Whatever facility we are getting here in Delhi, if that is extended to our constituency, that would be a thing which would enable us to serve the people better. Similarly; there are the postal facilities. But so far as the amount is concerned, there should be certain provisions by which misuse will not be made. Strong restrictions on that should be placed.

As regards the question of a stenographer, our position is that no stenographer should be provided to each Member of Parliament as such. But we will have no objection if a stenographer is provided to the recognised groups in Parliament as such, just as recognised groups have been provided with offices-rooms here.

Copies of uncorrected debates are given to recognised parties. Like that stenographic assistance also can be given. For that, as you said, there can be a committee and their unanimous recommendations can be accepted.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री यन्नालाल बालूपाल द्वारा प्रस्तुत संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तं अधिनियम, 1954 में जाने संशोधन करने वाले विधेयक का इनटोडो विरोध करता हूँ। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही इस सतह के बिल के पक्ष में थे और यह सहूलियतें संसद सदस्यों को प्रदान करना चाहते थे अपितु जो एक सर्वसम्मत फैसला हुआ था उसमें सभी लोगों की राय ली गई थी और सब की राय से यह फैसला किया गया था और हकीकत यह है कि सब के मुह में इन सहूलियतों को लेकर पानी मारा रहा है लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बिल का इनटोडो विरोध करता हूँ और इस के प्रस्तावक श्री यन्नालाल बालूपाल से दरखास्त करता हूँ कि वह अपने बिल को वापिस ले लें।

MR. SPEAKER : I am trying to put together all the suggestions. There is

already a committee for salaries and allowances of members. You need not refer it to that committee. You may refer it to some other committee. But not an impression be created here that we are quarrelling over salaries, etc. Let it be considered by a committee having some constitutional validity like a committee of the House where all parties are represented.

DR. RAM SUBHAG SINGH : This Bill has proved to be controversial from the very beginning. It had to be introduced after a division. In the speeches made so far today we do not find any unanimity. Mr. Banerjee said about something which goes against the very principle. He was within his competence to say that this Bill be opposed, though he did not altogether rule out some concessions. Mr. Jmanath also suggested that giving stenographic assistance to recognised groups will be a healthier practice. So, this principle of concession has is virtually accepted by everybody. Mr. Limaye also said that some telephone facility at the permanent residence and some stenographic allowance...

SHRI MADHU LIMAYE : I did not say allowance ; I said a post of stenographers be created.

DR. RAM SUBHAG SINGH : He said some stenographic assistance and postal concession may be given. But they would not be dropped from the sky. They will have to be given in terms of money.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : The idea is people outside may not know it !

DR. RAM SUBHAG SINGH : I accept it from our Chairman.

There was no committee constituted either by you, Sir, or by Government. Mr. Barupal, Mr. Jadhav and certain other members belonging to various parties did meet and discuss this problem, and perhaps arrived at some decisions. I am not sure, because I was not a party to that discussion. That committee did meet once in my room in my presence, but I left it there. The suggestion given by Bakshi Ghulam Mohammad is worthy of examination. He is a practical member...

SHRI UMANATH : Others are impractical ?

SHRI RAM SUBHAG SINGH : That is why I mentioned you first. But you mentioned concessions after opposing the Bill.

I know, Sir, the difficulties of hon. Members. I am not totally unfamiliar with the conditions of Members of Parliament because I have been a Member of Parliament here since 1950. We have also to look after our family members (*Interruption*) In my humble opinion the suggestion given by Bakshiji is worth being examined. He suggested a study made of the conditions of Members of all group and parties and see in what conditions they are living.

DR. MAITREYEE BASU (Darjeeling): What about independent Members ? We also need stenographic assistance. But there is always discrimination against independent Members.

DR. RAM SUBHAG SINGH : We may include independents also. I know definitely that conditions of Members are very deplorable. Therefore, I want to be guided by the advice given by hon. Members here. I know their feelings I know the feelings of every Member, even the feelings of those who have not participated in the debate. Therefore, this question as to what concessions and facilities may be given to hon. Members may be gone into by a committee. As you said, there does exist a committee in regard to salaries and allowances of Members. We can have virtually the same personnel. We might with your permission add the name of Shri Barupal and, if you like, I can also now become a member of that Committee. That Committee consists of Members of both the Houses. Six of the members are from Rajya Sabha. They are named by the Chairman of that House. The names of the Members as the Committee is at present constituted are : Shri P. C. Adichan, Shri Kamalnayan Bajaj, Shri A. E. T. Barrow, Shri Himatsingka, Shri N. P. C. Naidu, Shrimati Padmavati Devi, Shri M. B. Rana, Shri Bishwanath Roy, Shri B. S. Sharma, Shri A. Sreedharan. With your permission we

may add the name Shri Barupal and also my name.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH (Parbhani) : And also the name of Shri Bakshi Gulam Mohammad.

MR. SPEAKER : You may put an Independent also.

DR. RAM SUBHAG SINGH : All right, we may have the name of Shri Bakshi Gulam Mohammad. Half of the concessions like medical facilities, housing facilities, telephone facilities, postal facilities and others will have to be gone into by that Committee. Therefore, I want to be guided by your advice. I do not want to impose my will on anybody. I am only saying that it will be convenient if we have the guidance of that committee. But this will be a separate committee altogether.

Not that committee.

SHRI C. C. DESAI (Sabarkantha) : Shri Gowd from the Swatantra Party should be in that committee, because now he is not in that committee.

SHRI SEZHIYAN : There is no member from the D.M.K. there... (*Interruptions*)

SHRI RAM SUBHAG SINGH : The Committee would be constituted by the Speaker and we will request the Chairman of Rajya Sabha to nominate half the members from that House. The membership of every party would be reflected in this Committee.

SHRI RABI RAY (Puri) : In that committee the decision should be unanimous.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : What is the suggestion ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : This will be referred to a Committee to be constituted by the Speaker. In view of this, I would appeal to Shri Barupal to withdraw his Bill.

SHRI UMANATH : About the committee I want to know...

MR. SPEAKER : The Committee will come into being only after the Bill is withdrawn. The Minister has requested the hon. Member to withdraw his Bill in view of his explanation.

श्री प० ला० बाबूपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्यों तथा सदन की भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सदन ने मेरे विधेयक की भावना को मान लिया है कुछ संशोधनों के साथ। इस लिये मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूँ।

MR. SPEAKER : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his Bill ?

SOME HON. MEMBER : Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

18.17 hrs.

MOTION RE : SALARIES AND ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : I beg to move :

"That the question of providing further amenities and facilities in the matter of salary, allowances and other amenities to Members of Parliament in the context of the debate in Lok Sabha on the 26th April, 1968 on the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1967 by Shri Panna Lal Barupal be referred to a Joint Committee of the Houses to be nominated by the Speaker of Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha, for examination and report ;

that the Committee shall consist of 21 members, 14 from this House and 7 from Rajya Sabha ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee ;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that the House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 7 members nominated to the Joint Committee by the Chairman of Rajya Sabha."

MR. SPEAKER : I will now put the motion to the vote of the House.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Sir, I have an objection to the wording of that motion. I am sorry I have to object to that. The motion is for the reference of this matter to the Committee on Salaries and Allowances.

MR. SPEAKER : No, no ; it will be referred to a new committee to be constituted.

SHRI UMANATH : Then, my second objection is this. The motion refers to 'salaries and allowances, amenities and facilities'. It should refer only to 'amenities and facilities'. The words 'salaries and allowances' should not be there. They must be removed. I am very clear on that ... (interruptions).

MR. SPEAKER : Only the name of the Committee is 'Committee on Salaries and Allowances'. That does not mean that every time the Committee meets the salary or allowance is increased. That Committee is existing all these years. It will go into the amenities for members. Now, I will put the motion of Dr. Ram Subhag Singh to the vote of the House. After it is adopted, it has to be sent to Rajya Sabha for their concurrence.

The question is :

"That the question of providing further amenities and facilities in the matter of salary, allowances and other amenities to Members of Parliament in the context of the debate in Lok Sabha on the 26th April, 1968 on the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1967 by Shri Panna Lal Barupal be referred to a Joint Committee of the Houses to be

[Mr. Speaker]

nominated by the Speaker of Lok Sabha and the Chairman of Rajya Sabha, for examination and report ;

that the Committee shall consist of 21 members, 14 from this House and 7 from Rajya Sabha ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee ;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that the House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and Communicate to this House the names of 7 members nominated to the Joint Committee by the Chairman of Rajya Sabha."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : Shri Yashpal Singh
— not here. Shri A. T. Sarma.

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL

SHRI A. T. SARMA (Bhanjanagar) :
I beg to move :

"That the Bill to provide for the constitution of an All India Ayurvedic Medical Council for India, maintenance of an Ayurvedic Medical Register for the whole of India and for matters connected therewith, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the first day of the next session."

Sir, in this connection, I would like to say that a similar Bill was brought forward by me before and withdrawn by me on getting an assurance from the then Minister of Health that the Government would bring forward a Bill on the same lines. That is why I was obliged to withdraw the Bill. But meanwhile, the Government has not done anything. I know the Government had appointed a Committee to draw the rules and regulations for that. But that Committee did not meet at all.

18.21 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Now, the Government is going to have another Committee. But nothing has been done yet. The rules and regulations have not been framed. That is why I am again coming forward with this Bill for sending it to elicit public opinion thereon.

Here, I want to state that while that Bill was discussed, all the Members were in favour of it. There was none to oppose the Bill. About this Bill also, I know, it will have a favourable look of all the Members in the House because it is overdue. The Government has appointed many Committees for improving the indigenous system of medicine in our country. First, the Chopra Committee was appointed ; then, the Dave Committee, the Pandit Committee, and the Udappa Committee were appointed. All the Committees have recommended that there should be a Medical Council to control the indigenous system of medicine. But the Government has remained silent. No action has been taken on the recommendations of all these Committees. That is why I am obliged to bring forward this Bill again.

Now-a-days, there is no organisation of indigenous system of medicine and education thereof. The education varies from one State to another. Even the duration of the course varies from one state to another. There are no universities which follow up the Ayurvedic education and maintain the standardisation of Ayurvedic medicine and treatment. Some universities have introduced Ayurveda system in their curriculum. But they never follow any uniformity among themselves. There are 10 universities which have introduced Ayurveda system in their curriculum. In some universities, the entrance qualification is Matriculation while in others it is Intermediate with Physics, Chemistry and Biology. But the course varies even among those universities. Some universities provide a course for four years and some universities provide a course for five years or six years also. So, there is no standardisation of education. Even there, they have introduced Allopathic element,

They never care for Ayurveda system. If such system is allowed to continue, then Ayurveda system books will not be understood at all after 10 years.

The courses adopted by all these universities never prescribe any text-books; they have prescribed only some syllabi and the Professors prepare notes and teach the students. The products are neither well up in Ayurveda nor in allopathy. In Shri Morarji Desai's language, they are neither fish nor fowl. Shri Sampurnanand has also bitterly criticised this sort of courses and has clearly stated that they are white elephants. Even now what are they doing? They are registering their names as Ayurvedic practitioners, but they never touch even a single medicine of Ayurveda; they always deal with allopathic medicines. It was felt by the Health Ministry that they should eradicate Ayurveda from this country through Ayurvedists and that is why such a course was prescribed and it is still going on. Those who deal with Ayurveda do not know the 'ABC' of Ayurveda. There must be one controlling office, so that Ayurvedic education and treatment are standardised. That is why I have brought forward this Bill.

In this Bill I have tried my best to have representatives from all sorts of organisations. Even these products of integrated course have been absorbed in this Bill. According to the Bill, there will be a Council consisting of all sorts of representatives from the various States, and that Council will be established on the model of the Indian Medical Council, and that Council will control the education and treatment *in toto*. Therefore, I will request the hon. House to accept my proposal and send this Bill for eliciting public opinion.

In this connection, I want to state one more thing. The thing is this. In 1835, Lord Macaulay abolished the Ayurvedic system in this country. Since then, not even a single pie was given to the Ayurvedic system of medicine, and all the allotments were confined only to the allopathic treatment. Even today the position is that only 20 percent of the population is being benefited by the allopathic treatment. For the benefit of only

20 per cent of the population, Government is spending crores of rupees without caring for the 80 per cent of the population which entirely depend on the indigenous system of medicine. At present the Government is allowing only 4 or 5 per cent of the allotment under Health for the improvement of the indigenous system of medicine and for this purpose they have included, in the name of indigenous system of medicine, homoeopathy, unani, Ayurveda, hydropathy, naturopathy and all other siddhas... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may please ..

SHRI A. T. SARMA : I will finish in three minutes:

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he wants, he can have more time. We have to take up the half-an-hour discussion now. The hon. Member may continue his speech on the next occasion.

18.30 hrs.

SUSPENSION OF PRODUCTION OF FILMS IN BOMBAY*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we shall take up the half-an-hour discussion. Shri George Fernandes.

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, सिनेमा का घन्था हिन्दुस्तान के बहुत ही बड़े उद्योगों में से एक है। इस में करीब 100 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इस घन्चे से हर साल करीब 100 करोड़ रुपये का टर्न-ओवर, निर्माण होता है। सरकार को हर साल 70, 80 करोड़ रुपया इस घन्चे से मिलता है, 40 करोड़ रुपया एन्टरटेनमेंट टैक्स के रूप में और 30, 40 करोड़ रुपया एक्साइज, इनकम टैक्स आदि दूसरे करों या इस घन्चे से सम्बन्धित दूसरे उद्योगों के जरिये।

[श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़]

मगर इस घन्घे का महत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इस में कितनी पूंजी लगी हुई है और सरकार को इस से कितना पैसा मिलता है। मेरे ख्याल में सिनेमा आज हिन्दुस्तान के लोगों, और खास कर नौजवानों, के मन पर बहुत ही ज़बर्दस्त असर डालने वाला माध्यम बन गया है। समाज को बनाने की, अथवा बिगाड़ने की, सिनेमा जो ताकत रखता है, वैसी ताकत आज बहुत ही कम दूसरी संस्थाओं के पास है।

लेकिन पिछले एक दो महीनों में इस घन्घे में जो झंझट चले हैं, उन से यह बात साबित हो चुकी है कि इस घन्घे के हर एक स्तर पर, चाहे सिनेमा बनाने वाले लोग हों, उसका वितरण करने वाले हों, उसको दिखाने वाले अर्थात् एक्सहिबिटर्ज हों या उस में काम करने वाले लोग हों, उन सब में काफी गन्दगी है, जिस को साफ करना बहुत ही आवश्यक है। जब दो महीने पहले यह भगड़ा चला, तो हमारे जैसे लोगों ने यह उम्मीद की थी कि सरकार ऐसा कदम उठायेगी, जिस से इस घन्घे में पाई जाने वाली गलतियों और खराबियों को हमेशा के लिए दूर करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन अनुभव कुछ और ही रहा। मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप तो जरूर किया, लेकिन पहली बार उन के हस्तक्षेप को उन्हीं लोगों ने टुकराया, जो यहां से मान कर गये थे। कुछ मरहम-पट्टी तो लगाई गई है, लेकिन में समझता हूं कि बुनियादी दिक्कतों और खराबियों को दूर करने की दृष्टि से मंत्री महोदय ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है।

इस घन्घे में और इन भगड़ों में—पांच, छः अलग-अलग गुट हैं। एक तो सिनेमा बनाने वाले हैं। दूसरे कलाकार हैं, या जो कलाकार कहलाते हैं—उन में से काफी कलाकार नहीं हैं। तीसरे वितरण करने वाले डिस्ट्रिब्यूटर्ज हैं। चौथे सिनेमा दिखाने वाले, सिनेमा थियेटर चलाने वाले एक्सहिबिटर्ज हैं। और पांचवे वे

हैं, जिन के बारे में बहुत कम कहा जाता है, लेकिन जिनके बारे में सब से ज्यादा कहना चाहिये वे हैं पांच लाख से अधिक कर्मचारी, जो इस घन्घे में हर एक स्तर पर, स्टुडियो, दफ्तर और सिनेमा हाउसिज में काम करते हैं।

एक बार जब इस प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो मैंने उन्हीं लोगों की बात उठाई थी। मैंने कहा था कि सिनेमा वालों ने कुछ साल पहले एक फिल्म बनाई थी, “हम सब चोर हैं” कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर इस घन्घे में सब चोर ही भरे हुए हैं। मेरी राय में अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले दो महीनों में इन लोगों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला है। अगर उन्हीं लोगों के बयानों को देखा जाये तो मैंने जो कुछ कहा था, उस का समर्थन उन्हीं के द्वारा हो जाता है।

सब से पहले प्रोड्यूसरों ने भगड़ा शुरू किया, जिसके कारण यह मामला हमारे सामने आया। प्रोड्यूसर्ज ने कहा कि लाखों रुपये खर्च करके उन्हीं जो सिनेमा बनाये, वे चल नहीं पाये, जिससे कई प्रोड्यूसर्ज का दिवाला निकल गया; ऐसे लोगों की मुसीबत में मदद करने के लिये कोई डिस्ट्रिब्यूटर खड़ा नहीं हुआ; ये डिस्ट्रिब्यूटर और एक्सहिबिटर्ज हम पर जुल्म करते हैं। ये प्रोड्यूसर्ज के आरोप थे।

उनके साथ कलाकार कहलाने वाले काफी लोग भी जम गये, क्योंकि उनमें कई लोग ऐसे हैं, जो कलाकार भी हैं और पैसा बनाने के बाद प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक्सहिबिटर्ज पर आरोप लगाये। इसी तरह एक तरफ डिस्ट्रिब्यूटर्ज ने प्रोड्यूसर्ज और एक्सहिबिटर्ज पर और दूसरी तरफ एक्सहिबिटर्ज ने प्रोड्यूसर्ज और डिस्ट्रिब्यूटर्ज पर आरोप लगाना शुरू किया। मैं इन सब की बयानबाजी में से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

डिस्ट्रिब्यूटर्स की तरफ से एक पर्चा निकाला गया, जिस में लाल स्याही में कहा गया है :

“EXHIBITION : RATIONALISE OR NATIONALISE”

उस के बाद उस पर्चे में यह शीर्षक दिया गया है :

“RAMPANT BLACK MARKETE IN THE FILM INDUSTRY”

इस घन्चे के लोग खुद कहते हैं :

“The Producers of today are mere agents of these stars to collect huge amounts for these stars and Music Directors and for themselves.

“The Producers are fully secured in their nefarious games by realising minimum guarantees from their Distributors.

“This corruption reached its peak in the year 1967. The volcano has now erupted. Distributors have revolted to be made victims any more...

“We demand nationalisation which will be highly advantageous to the Government from Revenue side.

“Two lists are enclosed which will give you a true picture of the high amounts charged by stars etc. on the production side on high theatre rentals charged by Exhibitors”

डिस्ट्रिब्यूटर्स वितरकों की ओर से ये आरोप लगाये गये हैं एक तरफ तो प्रोड्यूसर्स पर, दूसरी तरफ कलाकारों पर और तीसरी तरफ सिनेमा चलाने वाले लोगों पर। उन की मांग है कि सिनेमा थियेटर्स का तत्काल राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

एक्सहिबिटर्स ने भी एक पर्चा निकाला है, जो कि मंत्री महोदय को पहुँचाया गया है। उन के कानवीनर, श्री राजेश्वर दयाल, का आरोप है कि हम लोग, एक्सहिबिटर्स, तो बिल्कुल ठीक हैं; हमारा घन्चा बहुत बिगड़ा है, लेकिन उस को बिगाड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, बल्कि डिस्ट्रिब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स हैं।

वे कहते हैं :

“The cost of production and the price charged from the Distributors are being increased by the Producers from year to year without any rational or economic criteria and the Distributors have also been acting as their accomplices in this respect. The only reason for this is that, as a general rule, neither the producer nor the Distributors have any stake or investment of their own”.

आगे वे कहते हैं :

“It is a fact that during the last 7 to 10 years four male artists, four female artists and four music directors, along with their producer friends, have not only made fabulous profits totalling many crores of rupees (a major portion of that out of books) but also controlled the producers bodies like the IMPPA and the Film Guild”...

आगे चल कर वे कहते हैं :

“The facts enumerated above prove beyond any doubt that the exhibitors are made a scapegoat by the unholy trinity of the Producers, the stars and the Distributors for their own sins and wrongs in order to confuse both the authorities and the public”.

एक्सहिबिटर्स ने एक मेमोरेंडम में कुछ आंकड़े भी दिये हैं। वे कहते हैं :

“It is a well known fact that during the last 7 to 10 years the prices charged by the Producers have gone up by 500 to 600 per cent. The following table succinctly depicts this phenomenon :

“Pictures starring Raj Kapoor,

“Devanand or Rajinder Kumar :

1960 में ऐवेरेज मिनिमम गारंटी थी डेढ़ से दो लाख और 1967 में दस से बारह लाख।

“Pictures showing Dilip Kumar :

1960 में ऐवेरेज मिनिमम गारंटी थी दो से ढाई लाख और 1967 में पंद्रह लाख या उस से ज्यादा।

इस से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि असल में इस घन्चे की बीमारी काले पैसे की बीमारी बन गई है। इस घन्चे से सम्बन्धित

[श्री जार्ज फ्रनेन्डीज]

हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से पैसा बनाने और काले पैसे के रूप में कमाने, के काम में फंसा हुआ है। इस लिये हम चाहेंगे कि एक तो इस घन्घे का महत्व समझ कर और दूसरे इस में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के हित का ख्याल रख कर, जिन की जिन्दगी इन बड़े लोगों के आपसी झगड़ों के कारण बर्बाद हो रही है, सरकार इस घन्घे के बारे में अपने रुख को स्पष्ट करे और कुछ ठोस फैसले करे।

मैंने सुना है कि चन्द दिन पहले फिल्म फिनांस कारपोरेशन के चेयरमैन, श्री हिम्मत सिंह की ओर से सरकार को एक नोट पेश किया गया था। मैं आप की इजाजत से उस नोट* को सदन-पटल पर रखना चाहूँगा। मुझे अफसोस है कि इस घन्घे से सम्बन्ध रखने वाले और इस बारे में काफ़ी तज़ुर्बा रखने वाले व्यक्ति ने यह जो नोट बना कर भेजा है, उस पर मंत्री महोदय ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। श्री हिम्मत सिंह ने इस घन्घे की बुराइयों और इस में होने वाले पैसे के गोल-माल के बारे में तो कहा ही है, लेकिन उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि सिनेमाग्रह, सिनेमा थियेटर, का क्या रेट होना चाहिए, इसके बारे में सरकार को कुछ ठोस नियम बनाने चाहिए।

बहुत से सिनेमा थियेटर ऐसे हैं जो सिर्फ विदेशी फिल्में चलाते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ हिन्दी फिल्में चलाते हैं। यह तरीका बदलना चाहिये। सब सिनेमा घर हर तरह की फिल्म चलाने का काम करें—यह उन का दूसरा सुभाव है।

18.40 hrs.

[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

तीसरा सुभाव उन्होंने यह दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का घन्घा है, इसे सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। उन का यह कहना

है कि अगर सरकार इस घन्घे को अपने हाथ में ले ले, तो इस में कोई नुकसान होने की बात नहीं होगी। आज बहुत से प्रोड्यूसर फिल्म कारपोरेशन से मदद ले कर फिल्में बनाते हैं, अगर सरकार इन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का काम अपने हाथ में लेले और किसी कारपोरेशन के जरिये करे, तो फिर मिनीमम गारन्टी की जो बात है, जिसके कारण कि आज काले पैसे की शुरूआत होती है, वह खत्म हो जायगी। आज एक्जीविटस के लेवल पर जो ज्यादा पैसा दे कर फिल्म चलाई जाती है और उससे काला घन्घा पनपता है, वह नहीं हो सकेगा। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस के बारे में अपनी स्पष्ट राय सदन के सामने रखें।

हम बहुत असें से कहते आये हैं कि एक्जी-विशन का काम, सिनेमा थियेटर चलाने के काम का राष्ट्रीकरण हो। हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि इस काम को म्युनिस्पलटी के हाथ में दे दो, राज्य सरकारों के हाथ में दे दो और कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जिससे एक्जी-विशन के काम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो। यदि आप ध्यान से देखें तो काले पैसे की शुरूआत यहीं से होती है, क्योंकि इस के लिये पैसा तो पब्लिक से ही वसूल करना होगा, यदि आप इस घन्घे को अपने हाथ में ले लें तो इस बिमारी को दूर करने में काफ़ी कामयाबी मिल सकेगी। मैं तो यह चाहूँगा कि सरकार इस पर भी अपनी कोई ठोस राय पेश करे।

अब एक आखरी जुमला कह कर मैं खत्म करने वाला हूँ। सिनेमा कर्मचारियों की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहता हूँ—कुछ साल पहले बम्बई में इन कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में एक वी० जी० खेर कमेटी बनी थी, इस कमेटी की ओर से सिनेमा कर्मचारियों के वेतन, उन के काम की सभी चीजों के बारे में कुछ सिफारिशें आई थीं,

*The Speaker subsequently not having accorded the necessary permission, the document was not treated as laid on the Table.

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। के० अन्ववास जैसे आदमी ने, जिनका सिनेमा के घन्घे से बहुत से पहले से सम्बन्ध है, "मैनस्ट्रीम" के ता० 27 के अंक में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने इस घन्घे में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत पर रौशनी डाली है। वह लिखते हैं कि एस्सिस्टेंट कैमरा मैन, जिस की एक मामूली गलती से लाखों रुपये का नुकसान प्रोड्यूसर का हो सकता है, उसको आज 100 रु० से भी कम तनख्वाह मिलती है। जो लाइट का इन्तजाम करने वाले कुली होते हैं, जिनके फोकसिंग करने में, लाइट बनाने में अगर मामूली सी भी गलती हो जाये तो जो सिनेमा में काम करने वाली खूबसूरत लड़की है वह खूबसूरत नहीं रहेगी, बदसूरत दिखाई देगी, उस कुली की तनख्वाह महीने की 50 रु० है। यह हालत इस घन्घे में काम करने वाले कर्मचारियों की है। इस बात का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मजदूर यूनियन नहीं कर रही है, बल्कि इस घन्घे में काम करने वाला एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्वाजा अहमद अन्ववास साहब कर रहे हैं। मैं मंत्री साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे इन कर्मचारियों की हालत को सुधारने का काम करें। एक तरफ दलीप कुमार 18 लाख रुपये लेता है, वहीदा रेहमान 8 लाख रुपये लेती है नूतन 8 लाख रुपये लेती है, राजेन्द्र कुमार 15 लाख रुपये लेता है, राजकपूर 15 लाख रुपये लेता है, दूसरी तरफ ये कर्मचारी जो इन लोगों की तस्वीरों को जनता तक पहुँचाने वाले हैं, कैमरा मैन, एस्सिस्टेंट कैमरा मैन, कुली 50 रु० या 100 रुपये तनख्वाह में वहाँ पर मर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है जो खुद को कलाकार कह कर गरीबों की जिन्दगी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करते हैं, खुद का जीवन ऐसा बतलायेंगे जिस का दुनिया पर असर पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को इतनी बुरी हालत में वहाँ पर डाल रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। सरकार ने भी अपनी

जिम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़ दिया है, अपनी ही बनाई हुई कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने का काम आज तक नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि इस पर तात्कालिक निर्णय किया जाये।

एक आखरी बात - सभापति महोदय— सिनेमा के घन्घे से सम्बन्ध रखने वाले या इस घन्घे में काम करने वाले कुछ लोगों ने मिल कर "दि न्यू सिनेमा मूवमेन्ट" नाम से एक नया प्रयोग शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री साहब ऐसे लोगों से मिलें जो कुछ आदर्श रख कर, सिर्फ पैसे के पीछे न रह कर, काले पैसे का काम न कर के, अच्छा काम करना चाहते हैं। इन लोगों ने जो न्यू सिनेमा मूवमेन्ट का आन्दोलन शुरू किया है आप इसको आन्दोलन कहिये या सिनेमा बनाने का उद्योग कहिये - मन्त्री साहब इनको प्रोत्साहित करें, कुछ पैसे इनकी मदद करें, आर्थिक मदद करें, ताकि यह घन्घा जो बिगड़ा हुआ है, वे इस को सुधारने का काम कर सकें।

SHRI BABURAO PATEL (Shajapur) : Sir, we had a lot of sound any fury from the hon. Member, Mr. Fernandes. He did not tell anything new to the Minister, who is conversant with almost all the aspects and difficulties of the film industry. In fact, had he not been seduced to become a Minister, it was quite possible Mr. Shah would have become a bankrupt producer. He is so fond of art.

MR. CHAIRMAN : He can only put a question.

SHRI BABURAO PATEL : I am associated with the film industry for more than 44 years. If I do not speak, nobody speaks for the industry.

MR. CHAIRMAN : That is a different matter. I too have been in this presiding business for quite a long period.

SHRI BABURAO PATEL : Mr. Fernandes mentioned three different professions—producer, distributor and exhibitor. 82 per cent of the producers have become bankrupt. Nearly 50 per cent

[Shri Baburao Patel]

of the distributors have become bankrupt. But so far not a single exhibitor has become bankrupt. The exhibition end is the money-receiving end and that has to be controlled one way or other.

It is not possible under the present Constitution to control production. That will interfere with the freedom of expression of a citizen. But the Minister can certainly look after the exhibition side, because there are a lot of malpractices of which the Minister is aware. These can be controlled on the ground of monopoly which is being enjoyed by the exhibitors. They virtually blackmail the producers.

MR. CHAIRMAN : I do not want to interrupt an interesting speech. But under the rules, the names are balloted only for putting a question.

SHRI BABURAO PATEL : Then, I will put a question, Sir. Will the minister think of the possibility of including the exhibition trade under the Monopolies Act ?

SHRI ANANTRAO PATIL (Ahmednagar) : What is the long-term solution for the crisis in the film industry ? How to do away with the black money ? Can the Finance Ministry find some way to collect this black money and make arrangements for repayment of this amount to the artistes in their old age ? Producers, distributors and exhibitors have become a vicious circle, each one trying to extract money from the other. How can it be broken ? The State Government are getting crores of rupees by way of entertainment tax. Why should they not build more cinema houses and get more entertainment tax ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, अभी जो संकट फिल्म उद्योग में पैदा हुआ वह टलता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसका कोई पक्का इलाज नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि फिल्मों के निर्माता, उत्सर्ध बन लगाने वाले, वितरण करने वाले और जनता तक उनको पहुँचाने वाले, इन सब

के स्वार्थों में और हितों में इस तरह से ताल-मेल बिठाई जाये कि फिल्म एक कला के रूप में विकसित हो सके और देश में जागृति पैदा करने का काम कर सके ? क्या मन्त्री महोदय इस सुझाव से सहमत हैं कि अगर आज सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करना सम्भव नहीं है तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि जिससे सिनेमा घरों के मालिक अनाप-शनाप किराया लेकर इस उद्योग को बिगाड़ न सकें ? क्या सरकार ने इस दिशा में विचार किया है ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur) : Sir, immediately after the Minister's statement that he had settled the dispute between the distributors on the one hand and the producers on the other there was a strike which continued for some days. May I know why this strike at all was allowed to take place and did the Minister take any steps to prevent it ? May I also know what is the long-term solution to the disputes that are constantly going on between three or four parties in the whole drama ?

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister—

श्री प्रेम चन्व वर्मा (हमीरपुर) : मुझे भी मौका दीजिये ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member did not send his name even.

श्री प्रेम चन्व वर्मा : तो फिर क्या, हम सिर्फ कोरम ही बनाकर बैठे रहें ? फिर तो मैं कह दूंगा कि हाउस में कोरम नहीं है। अगर यही बात है कि हम कुछ पूछना चाहें और आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर मैं कहूंगा कि कोरम नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है कि सदस्य यहां बैठे रहें, उनको दिलचस्पी हो लेकिन उनको मौका न दिया जाये ।

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Member not to behave towards

the Chair in the same manner and in the same trend as he does towards the hon. Ministers here. I am sitting here as the Presiding Officer. I am not concerned whether there is any quorum or not. The hon. Member has no right to speak now. He did not send his name. I hope he will kindly spare me from that agony of taking any stern action. He should respect the Chair at least. I have called the hon. Minister.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. K. SHAH):

Mr. Chairman, Sir, I must admit that even though there is a temporary solution the long-term solution must be found out as otherwise this would not last for more than six months and we will face the same difficulty again. On this point I have no doubt whatsoever. I also agree with the question of employees in this trade. Very few people have spoken about them but it is also very important. A number of hon. Members who have spoken have said something about some employees, but there is a class known as 'extra' and the amount of difficulties that they are undergoing also has to be taken into consideration. It is true that I have not come forward before the House with a long-term solution, but there are certain difficulties. My first difficulty is that these theatres are in different States and I depend upon the States so far as exhibition is concerned. I must be able to persuade all the seventeen States. The problem in one State is not the same as the problem in another State. The problem which Bombay faces is quite different from the problem which Delhi faces or which the theatre owners in the mofussils face. Even the problems of theatre owners in the suburbs of Bombay are different from the problems of theatre-owners in Bombay itself (*Interruptions*). I understand my hon. friend's impatience. But I hope he will not want me to be impatient because if I do something in impatience that would be a wrong thing. Therefore, a thorough sweeping is absolutely necessary. On this point there is no doubt.

I am also trying to find out how the black money reaches the artistes, because it must originate somewhere. I am not pre-

pared to make a definite statement, but it must end at the centre where the money is received. That means, at the exhibition centre some arrangement is made or at the producer's level he is debiting wrong expenses. How is he able to do it? How is he able to pay blackmoney to the artistes? That must be found out. Unless you do this, the remedy will not be correct.

Now I will take up the points raised by various hon. Members. My hon. friend Shri Fernandes said that there is a lot of *ganjaki*. It is there. But by saying *ganjaki* the problem is not solved. It can be solved only by joint action by the Central Government and the State Governments.

श्री जार्ज फर्नेन्डीस : पहले आप तो शुरू करिये, फिर और लोग भी करेंगे ।

SHRI K. K. SHAH: You can use that word. But how do I start with the theatres? Entertainment tax is in the province of the State Government. In the matter of production, the studios are located in the States.

So far as the employees of the studios are concerned, I may point out to my hon. friend what the Central Government have done. The matter is before a tripartite committee consisting of one representative each from the central organisations of employers and workers, the Ministry of Information and Broadcasting, the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation and the State Governments of Maharashtra, West Bengal, Madras and Andhra Pradesh. I have got a report from them indicating a number of difficulties. Who is to be included in the producer and who is to be included in the exhibitor and distributor? Even in this definition they have taken such a long time. Who is an employee and who is the employer? Because, a cinema star is working simultaneously at a number of places. An extra is working simultaneously at a number of places. Who will be the employer of that cinema star or that extra is also a moot point and has got to be decided. In the same way, who is the exhibitor? A number of theatres have been leased out on a long-term basis. Now, those who have taken on a long-term basis, again, they have given it on weekly basis. Some give it on fixed rental basis and some

[Shri K. K. Shah]

give it on sharing basis. In the mofussil it is given on sharing basis and in the cities it is given on fixed rental basis. So far as the Central Government is concerned, a committee has already been appointed for the purpose of deciding the norms for films.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That Committee cannot go into these questions.

SHRI K. K. SHAH : Therefore, I have to enlarge the terms of reference of that committee.

श्री जाजं फरनेन्डीज : आप पूरे घंघे की जांच करने के लिये एक नयी कमेटी बनाइये ।

SHRI K. K. SHAH : Now, all the maladies are known. It is not only a question of the remedy and the Patel Committee has gone into the details.

श्री जाजं फरनेन्डीज : वह बहुत पुरानी हो गई ।

श्री के० के० शाह : पुरानी हो गई, ठीक बात है ।

I must admit it has gone into it.

AN HON. MEMBER : There was no blackmoney at that time.

SHRI K. K. SHAH : I entirely accept the suggestion that—I would not say immediately—as soon as possible there should be a thorough examination.

श्री जाजं फरनेन्डीज : आप कमेटी बनाने का आश्वासन दीजिये । आप पूरे रास्ते हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं ।

SHRI K. K. SHAH : How many committees shall we have ? Should we go on multiplying them ? I will consider this. I am not making any commitment. The committees also take a long time for taking evidence and so on.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What is needed is action. Let the Central Government initiate some action.

19.00 hrs.

SHRI K. K. SHAH : We have initiated action so far as putting up theatres is concerned. These theatres can only be put up by the State Governments.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about Delhi ? You can put up a theatre here. Let a beginning be made in New Delhi.

SHRI K. K. SHAH : For that, I have again to go to Finance. Theatres give a good return. It is correct they give a good return.

Let me tell my hon. friend that he should be happy to know that artistes have realised and a scheme is being formulated by them which will take concrete form in a week or two and they are going to submit that scheme which will, if that scheme goes through, eliminate black marketing so far as artistes are concerned.

I will tell you one of the suggestions. I do not say whether Finance will accept it or not. I do not want to make a commitment. There is a suggestion that if a percentage of the fees charged by artistes is ploughed back into a trust which will make it possible for them to get it back in 15 instalments after they have retired and then pay income-tax on what they get from that fund, they will have to disclose the maximum because, if they want to contribute to this fund a certain percentage of what they are receiving, unless they disclose the maximum, they will not be able to get back their share.

SHRI BABURAO PATEL : Most of them die before retirement.

SHRI K. K. SHAH : Then, it is also not correct to say that distributors and producers have no stake. On account of the minimum guarantee, their stake is less. But the stake is there. The real malady is this. A film which used to cost Rs. 40 to 50 lakhs used to get back Rs. 60 lakhs. Since the cost has gone up and the saturation point has been reached, so far as the receipts are concerned, on account of the number of features being limited, they become flops. Really speaking, they are

not flops. If the cost would not have gone up, if the cost would have remained at Rs. 40 to 50 lakhs and if they would have recovered Rs. 60 lakhs as they used to recover in the past, they would not have become flops.

Here also, I cannot take any side. The complaint of the producers is that the exhibitors have raised the rental. That is also a complaint which does require investigation. It cannot be thrown out.

The suggestion made by Shri Himatsingka will, of course, be taken into consideration. You don't expect me to act on that suggestion all of a sudden. But to say that the distribution should be taken over by the Central Government—I can only say that it can only be taken over by the State Government.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Even the State Government should not take over.

SHRI K. K. SHAH : So far as employees are concerned, that question is under consideration. My hon. friend can rest assured about that. I hope the Committee will complete its deliberations as soon as possible. But there also, there are a number of Acts that are in vogue today. I am not going to pass on the responsibility to somebody else. There is the Factories Act ; there is the Payment of Wages Act ; there is the Employees Provident Fund Act, the Shop Establishment Act, etc. All these Acts are there. There is the National Commission on Labour. (Interruption) This is a State subject.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Put a ceiling on the income of an actor when he is acting in one film.

SHRI K. K. SHAH : Even if you don't put a ceiling and if you only persuade or find out a way so that he discloses the entire income that he receives, that is more important.

Then, I come to the statement made by Mr. Baburao Patel. It is true producers have gone bankrupt. Distributors also have gone bankrupt. It is true that a few exhibitors have gone bankrupt.

SHRI BABURAO PATEL : Not one,

SHRI K. K. SHAH : That is possible. I am not prepared to contradict his statement. But that is because an exhibitor may not get a return. But an exhibitor cannot lose because he gets the rental. Therefore, the risk is on the distributor who gives the minimum guarantee.

SHRI GEORGE FERNANDES : Speculator.

SHRI BABURAO PATEL : Are you going to include it in the Monopolies Act ?

SHRI K. K. SHAH : My hon. friend asks whether I am going to include it in the Monopolies Act. I want more theatres to come up. Any restriction is likely to curtail the number of theatres coming up. Today the cry is 'more theatres', 'more theatres'...

AN HON. MEMBER : You don't have cement for the theatres.

SHRI K. K. SHAH : That can be managed, if you can persuade people to put up theatres.

I accept Mr Vajpayee's suggestion that there should be a long-term solution.

Mr. Supakar was asking 'Why was this strike allowed to take place after settlement ?'. Either I should have patience with them or if I have no patience, I must come forward with some action on the part of the Government. So far as action on the part of the Government is concerned, the studios are located in the States, the theatres are located in the States, the labour regulations are in the hands of the State: I am only passing the film....(Interruptions) and financing. To what extent ? I am not financing very much. But I will take this factor into consideration. Mr Supakar himself, however, agreed that they have come round and the production has started, the screening has started. In Madras also, screening of Hindi films has started. The question that is left is only in the North. It is not in the East or in the South or in the West. The only question is in the North. I hope, they will come round and in a day or two, short-term solution will be found. I am obliged to my hon. friends in this House. I would request them to make an all-sided effort, even with

[Shri K. K. Shah]

the States, so that a long-term solution can be found...

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) :
What about entertainment tax ?

SHRI K. K. SHAH : The entertainment tax also comes under the State. I will try my best. But do you want me to go round to all the 17 States and say, 'charge less' ? The best way would be, as was pointed out by my hon. friends, for

the States to have more theatres, so that the entertainment tax can come down and still the recovery will be large enough.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till Monday.

19.08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 29, 1968/ Vaisakha 9 1890 (Saka)